

अल्प विकास की राजनीति

जी. ए. हीगर

M

दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड
नई दिल्ली बंबई कलकत्ता मद्रास
समस्त विश्व में सहयोगी कंपनियां

© जी. ए. हीगर

प्रथम हिंदी संस्करण : 1977

अनुवाद

वृज शर्मा

Rs 20.00

एस. जी. बसानी द्वारा दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड के लिए
प्रकाशित तथा वी. वरदराजन द्वारा मैकमिलन इंडिया प्रेस, मद्रास में मुद्रित ।

G. A. Heeger: Alpa Vikas ki Rajniti

अल्प विकसित राजनीतिक प्रणाली के अध्ययन में पिछले कई दशकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। 1950 के दशक और 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्ष अल्प विकास के कारण संबंधी, विकास के वैकल्पिक उपाय संबंधी अनेक सिद्धांतों के प्रतिपादन के साक्षी रहे हैं। यद्यपि काम में लाए गए अनेक सिद्धांतों, विशेषकर सरचनात्मक, कार्यात्मक विश्लेषण तथा अवधारणा से उन्हें शोधकार्य में कुछ प्रारंभिक दिशा मिली तथापि विद्वानों ने जल्दी ही यह समझ लिया कि अल्प विकसित राज्य में राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या करने के लिए सिद्धांत और अवधारणाएं दोनों अपर्याप्त हैं, पश्चिमी राजनीतिक परंपरा पर आधारित विभिन्न सिद्धांत तथ्यों की व्याख्या करने के बजाय प्रायः तोड़ मरोड़ ही करते थे।

संभवतः व्यापक सिद्धांत विकसित करने के प्रयत्नों की निरर्थकता महसूस करते हुए अनेक अध्येताओं ने बहुत विशेषीकृत विषयों पर ध्यान देना आरंभ किया। हाल के वर्षों में अल्पविकसित राज्यों की राजनीतिक प्रणाली से संबंधित बहुत ही विशेषीकृत विषय पर स्वरूप चिन्ह संबंधी शोध की बाढ़ सी आ गई है। ऐसी चीजें जैसे स्थानीय राजनीतिक प्रणालियां, जननीति निर्माण के विशिष्ट उदाहरण तथा छोटे समूहों के भीतर खास सामाजिक तथा राजनीतिक बदलाव हाल की तुलनात्मक राजनीतिक शोध की सामग्री बन गई हैं। ऐसे शोधों से हमें अफ्रीका तथा एशिया की राजनीतिक प्रणालियों के बारे में काफी जानकारी मिलती है।

किंतु अल्प विकसित राजनीतिक प्रणालियों पर एक सामान्य चर्चा के लिए यह शोध अकेले पर्याप्त नहीं है। और चूंकि अध्येता नए सामान्य सिद्धांतों को व्यवहार में लाने में हिचकिचाते हैं इसलिए पुराने पड़ चुके सिद्धांत शोध को अब भी प्रभावित करते हैं तथा निष्कर्षों को तोड़ते मरोड़ते हैं। अल्प विकसित राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन में कहा जा सकता है कि दो भाषाओं का विकास हुआ है। विशेषीकृत समस्याओं पर बनी संवरी शोध तकनीकों तथा विवेक्षण विवेचनात्मक विश्लेषण का इस्तेमाल किया जाता है। राजनीतिक प्रणालियों के अधिक सामान्य चरित्रीकरण के लिए पुराने सिद्धांत तथा अवधारणाओं का इस्तेमाल किया जाता

है, जिसे कोई शायद ही कभी संतुष्ट हुआ हो। सामान्य सिद्धांत पर हाल के वर्षों में एकत्रित आकड़ों की विशाल सख्या का प्रभाव नगण्य प्रतीत होता है। पुस्तकें में कुछ ऐसे संबन्धों की रूपरेखा बनाने की कोशिश की गई है जो उपलब्ध आंकड़ों की रोशनी में अल्प विकसित राजनीतिक प्रणालियों के लक्षण प्रतीत होते हैं। दूसरे शब्दों में, यहां सिद्धांत को आकड़ों के अनुसार रूप देने की कोशिश की गई है। परन्तु ऐसा कोई 'महान सिद्धांत' प्रतिपादित करने की चेष्टा नहीं की गई है जिसमें सब कुछ समाहित हो। मैंने स्वयं को जानबूझकर अल्प विकसित देशों की न केवल आधुनिकीकरण की जरूरतों से अपितु अपने समाजों में किसी तरह की राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने की और सीमित समस्या से निबटने में अल्प विकसित देशों की सतत असमर्थता की व्याख्या करने तक सीमित रखा है। मैंने कुछ पुरानी तथा वर्तमान मैक्रांतिक अवधारणाओं को चुनौती देने तथा उन्हें नया रूप देने का प्रयत्न किया है।

स्पष्ट है कि एक छोटी सी पुस्तक में विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की विविधता की चर्चा करने की कोशिश करना काफी जीवट का काम है। जिन लोगों ने अपनी चर्चाओं तथा अपने प्रकाशित-अप्रकाशित शोध के द्वारा मेरी सहायता की उनकी सूची इतनी लंबी है कि यहां उद्धृत नहीं की जा सकती। इस पुस्तक की पादटिप्पणियों में उनके प्रति मेरा बौद्धिक श्रृण अभिलिखित है।

मैं गवर्नमेंट ऐंड फारेन अफेयर्स के बुडरो विलसन विभाग, यूनिवर्सिटी आफ वर्जीनिया के अपने सहयोगियों, विशेषरूप से एल्फेड फर्नबाख, आर० के० रमजानी और रावर्ट बुड का बहुत बहुत आभारी हूँ। इन सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं एक अनुदान के लिए यूनिवर्सिटी आफ वर्जीनिया के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहूंगा, इस अनुदान से डम अध्ययन के शोध और लेखन में आशिक सहायता मिली।

और अंत में अपनी पत्नी गेराल्डाइन के प्रति तो मैं कृतज्ञता ही प्रकट कर सकता हूँ। इस किताब पर काम करते समय मेरी बहुधा बदलती हुई मनस्थितियों का मामना उमने उत्साहपूर्वक और खुशमिजाजी के साथ किया।

जी० ए० हीगर

अनुक्रम

राजनीतिक अल्प विकास और राजनीतिक सुव्यवस्था की खोज

राजनीतिक विकास का सिद्धांत
अल्प विकसित राज्यों में राजनीतिक प्रक्रिया
आक्रांवाद का ह्रास
विकास की राजनीति से सुव्यवस्था की राजनीति तक

राष्ट्रवाद और उसकी देन

... 14

राष्ट्रवाद का पश्चिमी भत
गैर पश्चिमी राष्ट्रवाद और पश्चिमी
गैर पश्चिमी राष्ट्रवाद : एक पुनर्मूल्यांकन
राष्ट्रवादी आंदोलन के स्रोत
शहरी राजनीति और विरोध
ग्रामीण राजनीति और विरोध
परंपराओं की दृढ़ता
संपर्क राजनीति : राष्ट्रवादी आंदोलन की उपलब्धि
राष्ट्रवाद एक राजनीतिक विचार : टिप्पणी
निष्कर्ष

राजनीतिक स्थिरता की खोज

... 45

राजनीतिक केंद्र का गठन करना
राजनीतिक बाह्य परिधि का गठन करना
केंद्र और परिधि के बीच एकता लाने के स्रोत
केंद्र परिधि संपर्क के स्रोत

अस्थिरता की राजनीति	...	75
गुटबन्दी और विरासत निर्माण		
[सांप्रदायिकता की राजनीति		
विशिष्ट व्यक्तियों के मतभेद और सैनिक क्रांति		
सेना सत्ता में	...	107
राजनीति विरोधी		
राजनीतिक केंद्र में एकता और संघर्ष		
परिधि क्षेत्र में एकता और संघर्ष		
निष्कर्ष	...	132
अनुक्रमणी	...	139

राजनीतिक अल्पविकास और राजनीतिक सुव्यवस्था की खोज

अल्पविकसित जनसमुदायों में राजनीति, मुख्यतः सुव्यवस्था की खोज की राजनीति बन गई है। विकास, जो बहुधा अप्राप्त विचार मात्र होता है, एक अप्राप्त लक्ष्य सिद्ध हुआ है। इसके विपरीत, सामाजिक सुव्यवस्था अधिक शाह्य और अधिक आवश्यक है। सुव्यवस्था लाने के कार्य में रत, औपनिवेशिक युग के सैनिक शासनों की बढ़ती हुई संख्या इस बात का एक संकेत है कि विकास की राजनीति, परिवर्तित होकर सुव्यवस्था की राजनीति बनती जा रही है। सुव्यवस्था के लिए इतनी लालसा अधिकांश अल्पविकसित देशों की इस विफलता का परिणाम है कि वे अपने अपने समाज में साधारण सी प्रगति लाने से अधिक कुछ नहीं कर पाए। अल्प विकास के एक अस्थायी या अल्पकालिक स्थिति होने की अपेक्षा स्थायी परिस्थिति बन जाने की आशा है।

राजनीतिक विकास का सिद्धांत

राजनीतिशास्त्र के अधिकांश विद्वानों ने विकास की राजनीति के सुव्यवस्था की राजनीति में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को साधारण सी मान्यता दी है। उनका ध्यान अब भी विकासोन्मुख परिवर्तन की प्रक्रिया की ओर ही केंद्रित है जोकि राजनीतिक विकास की प्राप्ति का माध्यम है। ये विद्वान, विकास को या तो ऐसे पश्चिमी अनुभवों का वित्युपादित संलक्षण मानते हैं जिनकी विशेषता है बढ़ती हुई धर्मनिरपेक्षता, राजनीतिक भूमिकाओं और ढांचों का भेद, समाज के व्यावहारिक आदर्श के रूप में समतावाद का उभरना, और लोगों में अपने अपने पर्यावरण से जूझने की क्षमता में वृद्धि,¹ या फिर ये वैज्ञानिक विकास को, विभिन्न संगठनों को संस्थात्मक

वह परिभाषा या अर्थ जो आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन जैसे शब्दों को दिया गया ।

इस विषय के अधिकांश आधुनिक विद्वानों के लिए सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य भी है और अनिवार्यतः आधुनिकीकरण लाने वाला भी ।⁴ यद्यपि आधुनिकीकरण को बहुधा सामाजिक परिवर्तन का एक रूप कहा जाता है, उदाहरण के लिए, 'उन सभी प्रणालियों का परिवर्तन जिनके द्वारा मनुष्य अपने समाज का संचालन करता है, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रणालियाँ'⁵, लेकिन 'आधुनिकीकरण' और 'सामाजिक परिवर्तन' जैसे शब्द जिस प्रकार विश्लेषण के समय प्रयोग में लाए जाते हैं उससे वे समानार्थक प्रतीत होने लगते हैं । चूंकि परंपरागत समाज परिभाषा के संदर्भ में ऐसा समाज माना जाता है जिसमें स्वयं को ढालने की अनुकूलनशीलता नहीं है, इसलिए यह समझा जाता है कि यह समाज, परिवर्तन होते ही ढह जाएगा,⁶ और इसी धारणा को देखते हुए सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बन गया है आधुनिकीकरण । यहाँ तक कि जहाँ एक ओर इस तर्क की आलोचना यह कहकर की जाती है कि इसमें परंपरा और आधुनिकता को अत्यंत कठोर रूप में दर्शाया गया है वहाँ दूसरी ओर ये आलोचक वास्तव में इस बात को चुनौती नहीं देते कि सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण अवश्यभावी हैं ।⁷ यह कहा जाता है कि मूल धारणा की अपेक्षा परंपराएं अधिक अनुकूलनशील हैं, लेकिन इस अनुकूलनशीलता की अपनी ही स्पष्ट सीमाएं हैं, और अत्यंत लचीली परंपराएं भी सामाजिक परिवर्तन के सामने अनिवार्यतः कमजोर पड़ जाती हैं ।

उपर्युक्त बातें यह सिद्ध करने के लिए नहीं कही गई हैं कि आज सामाजिक परिवर्तन को एक ही दिशा में अग्रसर होने वाला माना जाता है ।⁸ कुछ बातों की दृष्टि से तो इस तर्क को चुनौती नहीं दी जा सकती । जिस प्रकार एक न एक दिन हम सबको यह संसार छोड़ना है, उसी प्रकार कभी न कभी अधिकांश स्थितियाँ अवश्य बदलेंगी । लेकिन सामाजिक परिवर्तन, और परोक्ष रूप से, आधुनिकीकरण को लगभग अनिवार्य मानने में कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि यह अनिवार्यता राजनीतिक विकास की एक निश्चित परिभाषा को जन्म देती है । अर्थात् राजनीतिक विकास के परिवर्तन का सूत्रपात करने वाला (जो अवश्यभावी है) इतना नहीं समझा जाता जितना कि परिवर्तन का संचालन करने वाला, और परिवर्तन तथा उसके परिणामों को सही दिशा में ले जाने वाला ।⁹ इस मत के अनुसार अब्यवस्था, जो नए राज्यों की एक विशेषता बन गई है, उसी परिवर्तन का परिणाम है जो भ्रष्ट संचालन या आधुनिकीकरण की विफलताओं के कारण नियंत्रण से बाहर हो गया है ।¹⁰ एक

क्षण के लिए हम यह तर्क देंगे कि राजनीतिक विकास मंंधी यह मत उस काम को बहुत छोटा मानता है जो नए राज्यों को करना है, और इस मत में अव्यवस्था के कारणों का बडा सीमित सा स्प्टीकरण दिया गया है।

राजनीतिक विकास, परिवर्तन का निर्देशन है, यह धारणा इस बात से झलकती है कि आजकल बडा जोर देकर कहा जाता है कि किसी समाज के राजनीतिक विकास का मानंदड यह है कि उसमें कितनी राजनीतिक संस्थात्मकता है।¹¹ राजनीतिक संस्थाओं को समाज का केंद्रबिंदु माना जाता है चाहे वह समाज पहले से विद्यमान हो या अस्तित्व में आने की प्रक्रिया में हो। ये राजनीतिक संस्थाएं समाज को एकता और संगठन के लिए प्रतीक देती हैं, उसके लक्ष्यों, उद्देश्यों का चुनाव करती हैं, और इन तक पहुंचने के लिए आवश्यक सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराती हैं। राजनीतिक संस्थाएं उन सामाजिक क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं की प्रतिरूप हैं जो स्थिर हो चुकी हैं। ये संस्थाएं समूहों के बीच क्रियाओ-प्रतिक्रियाओ और संघर्षों के लिए एक प्रकार के नियम देती हैं जिससे समाज सभ्य और जनहितकारी बनता चला जाता है। अन्य शब्दों में, संस्थाएं सामूहिक क्रिया-प्रतिक्रिया का संचालन करती हैं। इसी मत के अनुसार, यदि संस्थाएं नहीं हैं तो इसका अर्थ है कि समूहों, के बीच जो भी क्रिया-प्रतिक्रिया होगी, उसके कोई नियम नहीं होंगे। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करेगा।

सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण को अनिवार्य मानने से राजनीतिक विकास की परिभाषा न केवल सीमित बनती है बल्कि अल्प विकास कब तक रहेगा इस अवधि को भी मनमाने ढंग से सीमित कर दिया जाता है। यदि परिवर्तन अनिवार्यतः आधुनिकीकरण लाता है तो राज्यों की अल्प विकास की स्थिति अस्याई होगी। इसके परिणामस्वरूप ऐसे अल्पविकसित राज्यों को 'विलंबित' या अवसृद्ध राज्य समझा जाएगा। इनके लक्षणों और आधुनिक राज्यों की विशेषताओं के बीच भिन्नता से ही अल्पविकसित राज्यों का निर्धारण होगा। विचार का, केंद्रबिंदु आधुनिकीकरण और विकास की परिभाषा है। अल्पविकसित राज्यों की राजनीति पर इसी संदर्भ में विचार किया जा रहा है, कि यह राजनीति उपरोक्त परिभाषाओं के अनुरूप है या नहीं।

अल्पविकसित राज्यों में राजनीतिक प्रक्रिया

राजनीतिक आधुनिकीकरण और विकास के संबंध में सिद्धांतों के होते हुए, या इनके अभाव के बावजूद, यह दोनों लक्ष्य अप्राप्य सिद्ध हुए हैं। विकसित और अल्प-विकसित राज्यों के बीच अंतर और बड़े प्रतीत होते हैं, न कि कम, इस कारण कि

विकसित राज्य बराबर और विकसित होते जा रहे हैं (जोकि वास्तव में है), बल्कि इसलिए भी, जैसा संमुअल हंटिंगटन ने बताया है, कि अल्पविकसित राज्य या तो गतिहीन हो गए हैं या विकास की प्रक्रिया में हैं।

सामाजिक परिवर्तन एक एक कर होता रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि अल्पविकसित समाज जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील थे वही बदल गए। अब स्वयं अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। आधुनिकीकरण और लोकतंत्र जैसे बड़े ध्येयों का स्थान राजनीतिक सुव्यवस्था की मूलभूत खोज ने ले लिया है।

सामाजिक परिवर्तन, अनिवार्य और अततः आधुनिकीकरण लाने वाला होने की वजाय बड़ा बाधापूर्ण और अनिश्चित परिणामों वाला रहा है। परिवर्तन का विरोध करने और पूर्व स्थिति में ही बने रहने की भावना उतनी ही व्यापक लगती है जितना कि स्वयं परिवर्तन। इसके अलावा जहाँ कहीं भी सामाजिक परिवर्तन हुआ है वहाँ न केवल उसके नियंत्रण और परिणामों के संचालन की समस्या उठी है बल्कि और आगे परिवर्तन की संभावना को भी बहुधा सीमित कर दिया गया है।

सामाजिक परिवर्तन के बारे में, कम से कम सिद्धांत रूप में, बड़े प्रशंसनीय शब्दों में सोचने की प्रवृत्ति है। यानी सामाजिक परिवर्तन को संपूर्ण सामाजिक ढांचे का विकल्प बताया जाता है जो किसी एक निश्चित समाज की सभी गतिविधियों का मार्ग निर्देशन एक नए सामाजिक ढांचे द्वारा करता है। इस मत में विकास की एक बड़ी समस्या आधुनिक, सामाजिक और राजनीतिक मंथनाओं के नवनिर्माण की है।¹² इस तरह का तर्क देते हुए बहुधा परिवर्तन के स्वरूप को जैसा कि एक विद्वान ने कहा, सुरतालविहीन बताया जाता है।¹³ परंपरागत समाज बहुत ही स्थानीय सीमाओं में रहते हैं और उनपर परिवर्तन का प्रभाव अलग अलग ढंग से पड़ता है। नए राष्ट्र-राज्य परंपरागत समाज के समूहों में बने हैं। और यदि किसी निश्चित प्रदेश में परंपरागत समाज पर सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे सभी समाजों पर वैसा ही प्रभाव पड़ा। कुछ जनसमूहों पर तो लगभग विल्कुल ही असर नहीं पड़ा है, कुछ पर मामूली असर पड़ा, और कुछ तो अत्यंत प्रभावित हुए। इसके अलावा कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो संपूर्ण रूप से बदल जाएं। सामाजिक परिवर्तन, समाज के कुछ ही भागों पर प्रभाव डाल सकता है (और विभिन्न समाजों पर भी) और यह प्रभाव अलग अलग गति और नींवना का होता है।¹⁴ पुराना और नया साथ साथ चलते हैं। उदाहरण के लिए

किसी जनसमूह अथवा कबीले या समाज का सरदार संभवतः अपनी राजनीतिक सत्ता बहुत हद तक खो दे, लेकिन परंपरागत रीति रिवाजों और सामाजिक वर्गीकरण की दृष्टि से अपना सर्वोच्च स्थान बनाए रखे।

सामाजिक परिवर्तन कभी तेज और कभी धीमी गति से होता है। इस बात का पता कुछ अन्य तरीकों से भी चलता है। उदाहरण के लिए परंपरागत सामाजिक व्यवस्थाओं का परिवर्तन आधुनिक सामाजिक ढांचों में हो रहा है यह अक्सर तब देखने में आता है, जब सामाजिक व्यवस्थाएं और संस्थाएं स्वयं राष्ट्र-राज्य का मूल आधार बन जाती हैं। सामाजिक परिवर्तन अक्सर ऐसे आधुनिक समूहों को जन्म देता है जो परंपरागत जनसमूहों की तरह ही स्थानीय सीमाओं में बंधे रहते हैं। छोटे शहरी मध्यम वर्ग के जनसमूहों का उदय इसी बात का एक उदाहरण है जिनके बारे में आगे चलकर राष्ट्रवाद के द्विपक्ष पर विचार करते समय उल्लेख किया जाएगा। ऐसे समूहों के सदस्यों की संख्या बहुत सीमित हो सकती है और यह उस प्रदेश के अन्य समूहों के साथ आंशिक रूप से कभी कभी संबद्ध हो सकते हैं। अन्य शब्दों में, सामाजिक परिवर्तन सि न केवल निश्चित परंपरागत रूपों की समाप्ति नहीं हो सकती बल्कि इसमें कुछ नए निश्चित समूहों का उदय भी हो सकता है।¹⁵ सामाजिक परिवर्तन से कुछ खास परंपरागत जनसमूहों को दृढ़ता भी मिल सकती है या फिर इन्हें नई सामाजिक व्यवस्था में बदला जा सकता है। भारत में स्थानीय उपजातियां बड़ी जातियों और जातीय संस्थाओं से संबद्ध हैं। अफ्रीका में छोटे कबीले बड़े आदिवासी समूहों में नजर आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में बड़े लोगों और उनके संरक्षित लोगों के आपसी संबंध, वहां के परंपरागत समाज की विशेषता है। इन संबंधों का नई राजनीतिक प्रणाली में महत्व बढ़ता जा रहा है। यहां जिस विशिष्टतावाद और स्थानीयवाद के बराबर बने रहने की बात की जा रही है वह कोई नया विचार नहीं है। जैसा एडवर्ड शिल्स ने कहा है :

नए राष्ट्र जिन विभिन्न जनसमूहों से मिलकर बने हैं उन्हें यदि अलग अलग रूप में देखा जाए तो वे सभ्य समाज नहीं हैं। और अगर संयुक्त रूप से देखा जाए तो भी वे कोई एक सभ्य समाज नहीं हैं। ... इनमें नियमों का पालन करने की वृत्ति नहीं है और न ही यह व्यक्तियों अथवा कार्यों के प्रति ही कोई स्वीकारात्मक भाव रखते हैं जोकि सर्वसम्मति के लिए आवश्यक है। यह तो बहुत सारे दूर-भास के संबंधियों, जातियों, जनजातियों आदि के समूह हैं, यहां तक कि विभिन्न छोटे छोटे प्रदेशों में रहने वाले लोगों के समूह भी हैं, लेकिन यह सभ्य समाज नहीं है। जहां कहीं भी इनका अस्तित्व है वहां इनमें आपसी समानता की भावना होना मूल रूप से आवश्यक है।¹⁶...

अपने आप को उपनिवेशवादी सरकारों के उत्तराधिकारी समझने लगे हैं। आधुनिकतावादी विशिष्ट वर्ग कोई स्पष्ट सुसंगठित सामाजिक वर्ग नहीं है। इनमें विभिन्न जातियों, प्रदेशों, घरानों, आयु और वर्गों के लोग हैं। फिर भी इस विशिष्ट वर्ग में एक तरह से वे लोग हैं जो शासक वर्ग कहला सकते हैं। कुछ खास जनसमूहों द्वारा प्रेरित की गई मांगों को सुननेवाले या समाज के बहुत अधिक बोलनेवाले समूहों के प्रवक्ता होने की वजाय यह विशिष्ट वर्ग राजनीतिक प्रतिक्रिया का सूत्रपात करने वाले होते हैं। आधुनिकतावादी विशिष्ट वर्ग को राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण के अपने प्रयत्नों में काफी स्वतंत्रता है और राजनीतिक दलों जैसी संस्थाएं इस आधुनिकतावादी वर्ग की वृत्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब हैं। दृढ़ रुढ़ियों के संदर्भ में या अन्य आर्थिक तथा सामाजिक भिन्नताओं के संदर्भ में, सामाजिक समूहों पर बहुधा विचार होता है और इन्हें आधुनिकतावादी विशिष्ट वर्ग के कार्यों के लिए जुटाया जाता है। अल्पविकसित राज्यों में राजनीतिक गतिविधि इसी विशिष्ट वर्ग की गतिविधियों के आसपास केंद्रित रहती है। इस वर्ग के अंदर ही एक दूसरे के बीच क्रिया-प्रतिक्रिया का प्रभाव, राजनीति पर और अन्य वर्गों पर भी पड़ता है। नए राज्यों में बराबर सामाजिक विखंडन, इन राज्यों की राजनीति में विशिष्ट वर्ग का होना, और इस वर्ग की कार्यवाहियों के कारण उत्पन्न राजनीतिक गति के लिए सामाजिक विखंडन की वृत्ति, और क्रिया-प्रतिक्रिया, ये सभी ऐसी बातें हैं जिनसे एक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे संस्थाविहीन नहीं कहा जा सकता जहां एक दल दूसरे दल के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। समस्या यह नहीं है कि राजनीतिक संस्थाएं या विधियां संस्थात्मक हैं या नहीं बल्कि यह है कि इन संस्थाओं का स्वरूप क्या है चाहे वह संगठनात्मक हो या न हो।

अल्पविकसित राज्यों में राजनीतिक संस्थाएं विशेषकर 'राष्ट्रीय' संस्थाएं बहुत विभाजनवादी होती हैं।¹⁸ सत्ता और समर्थन स्थानीय होता है और राजनीतिक संस्थाएं तथा संगठन, स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर विशिष्ट वर्ग तथा अन्य समूहों से मिलकर बनती हैं। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक प्रतिक्रिया में विशिष्ट वर्ग का प्रयत्न यही होता है कि वह नए समाज के केंद्र में राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के लिए अन्य वर्गों को साथ मिलाएँ। इसके लिए केंद्र से बाहर के विशिष्ट वर्ग और समाज का समर्थन प्राप्त करने के प्रयत्न किए जाते हैं। केंद्र में नीति और राजनीति के प्रति दलों और विशिष्ट वर्ग की अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है और केंद्र के विशिष्ट वर्ग का प्रयत्न होता है कि यदि यह प्रतिक्रिया प्रतिकूल हो तो असंतुष्ट विचारों वाले व्यक्तियों को किन्नी तरह से राजी कर लिया जाए।¹⁹

राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक आंदोलनों का विकास इस बात

पर निर्भर करता है कि आधुनिकतावादी विशिष्ट वर्ग एक दूसरे के साथ कहां तक मिलना चाहते हैं या मिल सकते हैं और समाज के विभिन्न खंडों को एक दूसरे के साथ कितने संपर्क में ला सकते हैं। उनकी ऐसा करने की क्षमता सीमित है क्योंकि केंद्र में विशिष्ट वर्ग की राजनीतिक क्षमता बहुत कम है। साधन भी थोड़े हैं। आर्थिक दृढ़ता भी उतनी नहीं है जिसके कारण संरक्षण भी सीमित है। दबाव डालकर मनाने के साधन काफी महंगे और अप्राप्य हैं। इसका परिणाम यह है कि संस्थाएं शुरू से ही कमजोर रहती हैं और इनका अस्तित्व केंद्र तथा बाह्य क्षेत्रों के विशिष्ट वर्गों के बीच सौदेबाजी के बड़े नाजुक संबंधों पर निर्भर करता है। आधुनिकतावादी विशिष्ट वर्ग अन्य विशिष्ट वर्गों और सामाजिक प्रुपो के साथ गठबंधन करके अपने कार्यक्रमों के लिए (या सरकारी कार्यक्रमों के विरोध के लिए), और अपने लिए समर्थन जुटाने के प्रयत्न करता है। अल्पविकसित राज्यों में 'मत्ता के लिए बनाए गए मवधों का ढाचा विभाजनीय और छडपुक्त है। माधारण स्थानीय दल, और जातीय समूह प्रमुख महत्व के होते हैं। हर नेता दूसरे नेता के साथ अपने और अपने अनुयायियों के लिए सौदेबाजी करता है २०.....

इस प्रक्रिया में गतिहीनता लगभग निहित है। जहां कहीं भी मिलेजुले संगठन नहीं रहे हैं या नहीं बन पाए हैं वहां विशिष्ट वर्ग के अंदर ही परस्पर सघर्ष के कारण किसी एक व्यक्ति को सामाजिक परिवर्तन की समस्याओं से जूझने का मौका नहीं मिला। जहां मिलेजुले संगठन बने हैं वहां विशिष्ट वर्ग को उनके गठबंधन के कारण शामिल किया गया है और ये संगठन ऐसी नीतियों को लागू नहीं कर सके हैं जो इन विशिष्ट वर्गों की स्थिति या संगठन में शामिल अन्य दलों की स्थिति को चुनौती देने वाली हों। कमजोर संस्थाएं और संयुक्त दलों की राजनीति, बहुधा, पूर्व स्थिति को ही प्रोत्साहन देती है। सरकारें उतना काम नहीं करती जितना कि विगाडती हैं।

यहां एक और बात कहना जरूरी है। आधुनिकतावादी विशिष्ट वर्ग के बारे में अब तक सामान्य रूप से ही विचार किया गया है। इस वर्ग के किसी एक भाग, राजनीतिक अफसरशाही, सैनिक या ऐसे ही अन्य पक्ष, पर विशेष रूप से बल नहीं दिया गया। अमरीकी विद्वानों की यह वृत्ति है कि वे किसी एक राजनीतिक प्रणाली के विभिन्न 'अभिनेताओं', राजनीतिक दल, अफसरशाही, विशेष हितों वाले दल, सेना, को पृथक संगठनात्मक मत्ता मानते हैं। यानी इन्हें विभिन्न विशिष्ट वर्गों के समूह माना जाता है जो अलग अलग विधियों, नियमों और उद्देश्यों को संस्थात्मक बनाना चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि अक्सर राजनीतिक घटनाओं को विभिन्न संस्थाओं और उनकी संगठनात्मक शक्ति के मंदभं में देखने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरण के लिए अफसरशाही या केंद्रीय सत्तावाद, इस प्रणाली का प्रमुख अंग बन जाता है क्योंकि यह

मुसगठित होता है। मेना तभी हस्तक्षेप करती है जब मभी राजनीतिक मस्याएं या तो विफल हो चुकी होती हैं या पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती हैं। इस मत में, नए समाज में विशिष्ट वर्गों के बीच भेदों को बहुत बढ़ा दिया गया है। जो विशिष्ट वर्ग के लोग राजनीतिक केंद्र में महत्वपूर्ण पदों पर पहुँचते हैं उनकी मध्या अपेक्षाकृत बहुत कम है, और प्रणाली की विभिन्न मस्याएं उन्हीं के निर्णयों के अनुसार अपने आप को ढालने में प्रयत्नशील रहती हैं। नए राज्यों की राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख प्रयत्न, सत्ता के अधिकारों को सनाकृष्ट विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों में नीचे की ओर बढ़ाते जाना होता है। केंद्रीय विशिष्ट व्यक्ति, समाज में अपनी मत्ता प्रतिष्ठित करने और इसका व्यापक पालन कराने के प्रयत्न करते हैं। ये व्यक्ति यदि चाहे तो इस प्रक्रिया को आगे चलाने के लिए कई अलग अलग मस्याएं बनाते हैं।

इस तरह के मस्या निर्माण का केंद्रविन्दु है सरकारी मत्ता। जो विशिष्ट व्यक्ति सरकारी पदों पर होते हैं उनमें समाज को अच्छे परिणाम और मेवाएं उपलब्ध कराने की कम में कम कुछ क्षमता तो होती ही है। यह सत्ता होने से, व्यावहारिक रूप में, अमगठित विशिष्ट वर्गों और दलों को एक ढांचा दिया जा सकता है जिससे वे सरकार के आसन तक पहुँचने या उसे नियंत्रण में लेने की दिशा में संयुक्त मस्या के रूप में विकसित हो सकते हैं। महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर नियंत्रण के कारण, मत्ताधारी विशिष्ट व्यक्ति यदि चाहे तो एक राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं, ठीक उमी तरह, जिस तरह इस शताब्दी के प्रारंभ में अमरीकी नगरों में राजनीतिक दल बने थे। ये विशिष्ट लोग, सेना या अधिकारी तंत्र की मस्याओं का समर्थन करने वाले दलों को अस्तित्व में आने से भी रोक सकते हैं। किसी अंश तक इस तरह के निर्णयों में पता चलता है कि निश्चित विशिष्ट व्यक्तियों का पिछला जीवन और सामाजिक परिस्थितिया क्या रही हैं। इस तरह के निर्णय यह भी बताते हैं कि नए राज्यों की राजनीति के बारे में विशिष्ट वर्ग के विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं।

सक्षेप में, अल्पविकसित राज्यों की राजनीति विभिन्न संगठित दलों और मस्याओं के परस्पर सघर्ष का मसला नहीं है। बल्कि यह दलों, गठबंधन, चालों और व्यक्तिगत प्रभाव की राजनीति है।

आशावाद का ह्रास

विकास की राजनीति से मुव्यवस्था की राजनीति तक

राजनीतिक विकास के बारे में जो भी मंडातिक मामूली है उसमें अधिकांश में, कम से कम परोक्ष रूप से, यही कहा गया है कि विकास और आधुनिकीकरण का होना अनिवार्य है। लेकिन अफ्रीका और एशिया के देशों के विशेष अध्ययन से यह देखने

को मिला है कि इनकी प्रवृत्तियों में कुछ स्पष्ट और निश्चित परिवर्तन आया है। बार बार गृहयुद्ध होना, न मुलझने जैसी प्रतीत होने वाली आर्थिक समस्याएं, और संस्थात्मक अस्थिरता, इन सभी बातों से उस आशावाद पर कुठाराघात हुआ है जो 1950 के दशक, और 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में, राजनीतिशास्त्र के वैज्ञानिकों ने व्यक्त किया था। फिर भी विशेष घटनाओं पर बात करते हुए जिन मिद्धांतों का उल्लेख होता है वे पक्षपातपूर्ण हैं और इनमें अक्सर अस्थिरता के सही कारणों का पता नहीं लग पाता। राजनीतिशास्त्र के वैज्ञानिकों में बढ़ते हुए निराशावाद के बावजूद, सामाजिक परिवर्तन, और संस्थाओं के बारे में व्यक्त की गई उनकी धारणाओं में नए राज्यों की राजनीति को समझने में कठिनाई होती है। इस संबंध में एक विद्वान ने लिखा है :

‘बहुधा नए राज्यों की राजनीति का विवरण इस प्रकार दिया गया है मानो इरादे ही तथ्य हो, और शब्द ही सत्यता हो। अफ्रीका में राजनीतिक प्रणालियों के गुण विशेष उस चित्र पर आधारित हैं, जिसे दलों के नेतागण विश्व के सामने प्रस्तुत करते हैं।’²¹

इनके परिणामस्वरूप, दलगत समस्याओं को अत्यंत आधुनिक मगठनात्मक हथियार, और अधिकारी तंत्र को ‘लौह कंकाल’ आदि कहा गया है। अल्पविकसित राज्यों की अस्थिरता को देखते हुए इन धारणाओं को समझना कठिन है।

राजनीतिशास्त्र के वैज्ञानिकों के लिए मुख्यवस्था की राजनीति के बारे में कोई विचारधारा बनाना चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, लेकिन नए राज्यों के आधुनिकतावादी विशिष्ट वर्ग को, धारणाओं में परिवर्तन के बारे में भलीभांति ज्ञान है। वे शेष विश्व के सम्मुख चाहे जैसी भी तस्वीर प्रस्तुत करने के प्रयत्न करें फिर भी सत्ताहृद विशिष्ट वर्ग बहुत पहले से यह जानते हैं कि इनके सीमित साधन और उनकी खडित संस्थाएं अल्प विकास की समस्या को अस्थाई नहीं, बल्कि एक पुराने स्थाई रोग जैसा बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में सत्ता में बने रहना एक अत्यंत कठिन कार्य हो गया है और विशिष्ट वर्ग अब विकास और आधुनिकीकरण की बजाय अपना अस्तित्व बनाए रखने की ओर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। नए राज्यों की संस्थाएं जो कुछ कर सकती हैं कर रही हैं। वे ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती हैं, कि अपना अस्तित्व बनाए रखें।

विकास अब भी एक दुर्बोध और अग्राह्य विचार ही बना हुआ है। कमजोर संगठनों, बदलती हुई मान्यताओं और अनिश्चित स्थितियों की राजनीतिक प्रणाली

में सुव्यवस्था का मतलब केवल अस्तित्व में बने रहना हो गया है, चाहे यह सुव्यवस्था क्षणिक ही क्यों न हो। जैसे तैसे स्थिति से पार पा जाना ही बहुत बड़ी सफलता समझा जाने लगा है।

संदर्भ

1. यह सभ्यत. सबसे ज्यादा प्रचलित परिभाषा है. (जो इस परिभाषा का प्रयोग करते हैं वे आमतौर पर 'राजनीतिक विकास' और 'राजनीतिक आधुनिकीकरण' को समानार्थक और समान रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द मानते हैं). उदाहरण के लिए देखिए जेम्स एम० कोलमैन (संपादक) एजुकेशन ऐंड पालिटिकल डेवेलपमेंट में जेम्स एम० कोलमैन की 'भूमिका', (प्रिन्स्टन: प्रिन्स्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1965); पृष्ठ 15; लुसियन पाई: आफफेट्स आफ पालिटिकल डेवेलपमेंट (बोस्टन: लिटिल, ब्राउन ऐंड कंपनी, 1966), पृ० 45-48; गैब्रील आत्मड और जी० बी० पावेल. कपेरेटिव पोलिटिक्स: ए डेवेलपमेंटल एप्रोच (बोस्टन लिटिल, ब्राउन ऐंड कंपनी, 1966), पृ० 299-332; और क्लाड ई० वेल्च जूनियर (स): 'दि कपेरेटिव स्टडी आफ पालिटिकल माडर्नाइजेशन' देखिए क्लाड ई० वेल्च जूनियर की पालिटिकल माडर्नाइजेशन (बैल्माट, कैलिफोर्निया; वैंड्सवर्थ पब्लिशिंग कंपनी 1967) पृ० 1-16.
2. उदाहरण के लिए देखिए सैमुअल हंटिंगटन. पालिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज (न्यू हैवन: येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1968), एम० एन० ईसेंस्टाट: 'इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऐंड चेंज' अमरीकन सोसियोलॉजीकल रिव्यू, 24, (अप्रैल 1964), 235-247. और एम० एन० ईसेंस्टाट: सोशल चेंज, डिफरेंसिएशन ऐंड इवोल्यूशन, अमरीकन सोसियोलॉजीकल रिव्यू-24 (जून 1964) 375-387.
3. विशेष रूप से देखिए, लुसियन डब्ल्यू, पाई: 'दि नानवेस्टर्न पालिटिकल प्रोसेस', दि जर्नल आफ, पालिटिक्स, XX तीन (अगस्त 1958), 468-486; ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण अध्ययन है, फ्रेड डब्ल्यू० रिग्न, 'एगरेरिया ऐंड इंडस्ट्रीया' विलियम जे० सिफफन (संपादित): टूवार्ड दि कपेरेटिव स्टडी आफ एडमिनिस्ट्रेशन (ब्लूमिंगटन: इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस 1959).
4. पश्चिमी देशों में सामाजिक परिवर्तन को किस प्रकार समझा गया है इसके श्रेष्ठ अध्ययन के लिए देखिए, राबर्ट निम्बेट 'मोशल चेंज ऐंड हिस्ट्री (सदन: आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1969).
5. मैनफ्रेड हालपेन. 'टूवार्ड फरवर माडर्नाइजेशन आफ दि स्टडी आफ न्यू नेशन', बल्ड पालिटिक्स, XVII, 1 (अक्टूबर 1964), 173.
6. उदाहरण के लिए देखिए डेविड ई० ऐंप्टर: धाना इन ट्रांजीशन, (न्यूयार्क: ऐबेनियम, 1963).
7. देखिए लायड सार्ड० रुडाल्फ और सुसन होवर रुडाल्फ: दि माडर्निटी आफ ट्रेडिशन (शिकागो: यूनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस, 1967), विशेषकर भाग एक: और जोसफ आर० गसफील्ड: ट्रेडिशन ऐंड माडर्निटी: मिसप्नेस्ड पोलैरिटीज इन दि स्टडी आफ मोशल चेंज', अमरीकन जर्नल आफ सोसियोलॉजी, LXXII, 4 (1966), 351-362.
8. हम तरह का विश्लेषणात्मक लेखन निश्चय में देखा जा सकता है, विशेषकर पृ० 284-287.
9. यह हंटिंगटन, ईसेंस्टाट, और बाल्मड तथा पावेल के लेखों में सबसे अधिक स्पष्ट है.
10. एम० एन० ईसेंस्टाट. माडर्नाइजेशन: प्रोटेस्ट ऐंड चेंज (गैंगलवुडकिन्गम एन० जे०: प्रेंटिस हॉल, 1966).

12 : अल्प विकास की राजनीति

11. 'हर्टिगटन ने राजनीतिक विकास को आधुनिकीकरण से अलग रखने की दिशा में महत्वपूर्ण योग दिया है. आधुनिक और आधुनिकीकरण वाले राज्य, हर्टिगटन के अनुसार, अपनी क्षमताओं को छोकर (ह्रास) और इन्हीं क्षमताओं को प्राप्त करके भी (विकास) बदल सकते हैं दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विकास, अपरिवर्तनीय नहीं है. लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिकीकरण, हर्टिगटन के विश्लेषण के अनुसार, पूर्णरूप से अपरिवर्तनीय है : और जिन परिस्थितियों के कारण ह्रास होता है वे स्वयं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का परिणाम हैं 'सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन राजनीतिक चेतना लाता है, राजनीतिक मांगों में वृद्धि करता है, और राजनीतिक गतिविधियों में अधिकनाधिक व्यक्तियों को शामिल करता है यह परिवर्तन परंपरागत राजनीतिक संस्थाओं की प्रगति को रोकते हैं इनसे राजनीतिक एमोमिशनो और नई राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण की समस्या बहुत जटिल बन जाती है' (पृ० 5).
12. उदाहरण के लिए देखिए हर्टिगटन
13. सी० एम० व्हिटेकर जूनियर 'ए डिस्ट्रिक्टिकल प्रोसेस आफ पालिटिकल चेंज' बल्ड पालिटिक्स, XIV, 2 (1967), 190-217
14. 'उप सरचनात्मक' परिवर्तन और बहुधा प्रस्तुत होने वाले बाह्य विरोधाभासों के संघर्ष में श्रेष्ठ अध्ययन के लिए देखिए एफ० जी० बेली . कास्ट, ट्राइब ऐंड नेशन, (मैनचेस्टर, इंग्लैंड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस, 1960).
15. 'विशिष्टतावाद' की सबसे अच्छी परिभाषा है किसी जनसमूह द्वारा अपने अस्तित्व और हितों को अत्यंत स्थानीय, और विशेष शब्दों में व्यक्त करने की प्रवृत्ति ज्यादातर इस शब्द को परंपरा का समानार्थक मानकर प्रयोग में लाया जाता है लेकिन जैसा पहले कहा गया है, [तथाकथित आधुनिक दल भी परंपरावादी समूहों से कम विशिष्टतावादी नहीं है.
16. एडवर्ड शिल्स : 'आन दि कपेरेटिव स्टडी आफ दि न्यू स्टेट्स', क्लिफर्ड गील्स ओल्ड सोसायटीज ऐंड न्यू स्टेट्स (न्यूयार्क . फ्री प्रेस, 1963), पृ० 22
17. इस तर्क की विस्तृत व्याख्या के लिए देखिए जेरार्ड ए० हीगर . 'पालिटिक्स आफ इटीप्रेशन : कम्युनिटी, पार्टी, ऐंड इटिप्रेशन इन पंजाब' (पी-एच० डी० डिसेंटेशन : यूनिवर्सिटी आफ शिकागो, 1971), भूमिका.
18. दसवीं विभाजन के संदर्भ में देखिए एम० जी० स्मिथ 'आन सैगमेंट्री लिनिऐज सिस्टम', जर्नल आफ दि रॉयल एन्थ्रोपोलाजीकल इन्स्टीट्यूट-86 (1956), 39-80 . मायर फोर्टम और ई० ई० ईवास प्रिचर्ड : अफ्रीकन पालिटिकल सिस्टम (संजन : आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1940); और ए० डब्ल्यू साऊथाल : एलूर सोसायटी (कैम्ब्रिज इंग्लैंड : डब्ल्यू हैफर ऐंड एस लिमिटेड, 1953).
19. केंद्र और बाह्य परिधि के बारे में विचारों का अध्ययन, एडवर्ड शिल्स की पुस्तक, 'सेंटर ऐंड पेरीफरी', दि लाजिक आफ पर्सनल नालेज : एसेज प्रेजेण्टेड टू माइकल पोलाय्नी (संजन : एटलेज ऐंड कोमनपाल, 1961), पृ० 117-130 में किया गया है.
20. लियोनार्ड विडर ईरान : पालिटिकल डेवेलपमेंट इन ए चेंजिंग सोसायटी (बरकने ऐंड लास-ऐंजिल्स : यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया प्रेस, 1964), पृ० 36
21. हैनरी विएनन : तजानिया : पार्टी ड्रामफार्मेशन ऐंड इकानामिक डेवेलपमेंट (प्रिस्टन : प्रिस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1970), पृ० 5

2

राष्ट्रवाद और उसकी देन

1950 के दशक तक राष्ट्रवाद का अध्ययन मुख्यतः इतिहासकारों का ही विषय था। ऐसा प्रतीत होता था कि राष्ट्रवाद इतिहास के एक खास युग की घटना थी जिसकी समाप्ति होने जा रही थी। निश्चित प्रकार के राष्ट्रवाद उस समय के बौद्धिक व्यक्तियों की अनूठी प्रतिक्रियाओं के रूप में देखे गए और इसी कारण इनकी ओर केवल इतिहासकारों की रुचि रही। पिछले दो दशकों में राष्ट्रवाद का अध्ययन केवल ऐतिहासिक महत्व का अध्ययन ही नहीं रहा बल्कि अब यह इससे बड़े दायरे में पहुंच गया है। अफ्रीका और एशिया में राष्ट्रवादी राज्यों के तेजी से उदय के कारण राष्ट्रवाद को ऐसी मान्यता मिली है जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद से किसी को नहीं मिली।

इस विषय पर किए गए कई अध्ययनों के बावजूद राष्ट्रवाद और इसमें संबद्ध राष्ट्रीयता का सिद्धांत अप्राप्त ही बना हुआ है। बुद्धि को चकरा देने वाले विचारों और परिभाषाओं के आधार पर राष्ट्रवाद के आधुनिक अर्थ के बारे में दो बातें सामान्य रूप से कहना संभव है। पहली यह कि राष्ट्रवाद को आधुनिकतावाद और उसके परिणामों के समरूप समझा गया है। राष्ट्रवाद को पुरानी व्यवस्था को भंग करने वाला माना जा रहा है। अब इसका कारण या तो आधुनिक युग के विकास का सूत्रपात करने वाले विचारों का प्रसार हो सकता है या उन परिस्थितियों का प्रसार, जिन्हें आधुनिकता में संबद्ध किया जाता है, अर्थात्, साक्षरता का विस्तार, मुद्रा की अर्थव्यवस्था, बढ़ते हुए संचार साधन, और नगरों का विकास। दूसरी बात यह कही जा सकती है कि चूंकि राष्ट्रवाद को पुरानी व्यवस्था भंग करने वाला माना जा रहा है इसलिए इसे पुरानी व्यवस्था के अवसान के प्रति भावनात्मक

प्रतिक्रिया अधिक ममज्ञा जा रहा है न कि कुछ निश्चित विचारों के प्रसार का परिणाम।

इन दोनों ही बातों पर इस अध्याय में विस्तृत रूप से विचार किया जाएगा। ये बातें राष्ट्रवाद के न केवल आधुनिक अर्थ को विशेषकर इसके गैर पश्चिमी रूपों को समझने के लिए बल्कि वर्तमान राष्ट्रवादी आंदोलनों और इनसे उपजने वाली राजनीतिक प्रणालियों को समझने के लिए भी मूल महत्व की हैं।

राष्ट्रवाद का पश्चिमी मत

पुराने जमाने से ही पश्चिमी देशों में राष्ट्रवाद को ऐसी धारणाओं का एक समूह माना गया है, जिनमें मूल विचार राष्ट्र-राज्य पर केंद्रित है। इमीलिए राष्ट्रवाद का अध्ययन, मुख्यतः किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के विचारों का, अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों तक पहुंचने की प्रक्रिया का अध्ययन रहा है।¹ कुछ एक सिद्धांतों के रूप में राष्ट्रवाद को उन विचारों के बौद्धिक इतिहास के प्रकाश में समझना संभव था। इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि सिद्धांतों के रूप में यह राष्ट्रवाद किसी एक सामाजिक वर्ग की सीधी सादी भावनाओं से कुछ अधिक था।² राष्ट्रवाद का मबध स्वयं राष्ट्र के स्वरूप से था और साथ ही यह, प्रभुमत्ता, शासनसत्ता और व्यक्तिगत अधिकारों के वैकल्पिक विचारों से भी मबध रहा। राष्ट्रवाद को, न्यायपूर्ण राजनीतिक सुव्यवस्था के व्यापक प्रश्न में संबद्ध माना गया और व्यक्तियों को राष्ट्रों की इकाई इन मदभ्रं में समझा गया कि वे अपेक्षित न्यायपूर्ण सामाजिक सुव्यवस्था को भलीभांति ममझते हैं और उसमें साक्षीदार हैं।

हाल के वर्षों में राष्ट्रवाद के मबध में इस परंपरागत धारणा की यह कहकर कड़ी आलोचना हुई है कि इमने राष्ट्रवाद के विचार को बहुत दुर्बोध बना दिया है। यह तर्क दिया गया है कि राष्ट्रवाद की उपरोक्त धारणा के अनुसार, समाज में इसकी नींव ठोस रूप नहीं ले पाई।³ प्रतीत होता था कि राष्ट्रवाद की धारणा राज्यमबधी दर्शन से जुड़ी हुई है, परंपरागत दृष्टिकोण, राष्ट्रवाद के बाह्य रूप और इममें मदा जुड़े हुए तीव्र सामाजिक परिवर्तन के बीच संबंधों का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे पाया।

राष्ट्रवाद के बारे में परंपरागत धारणाओं के प्रति यह प्रतिक्रिया रही है कि व्यावहारिक प्रमाणों के माथ उन परिस्थितियों को ममझने के प्रयत्न किए गए, जिनमें जनमसूहों ने राष्ट्र-राज्यों की स्थापना की।⁴ कार्ल इयूश ने आधुनिकीकरण और उसकी महंगामी विन्तृत हो रही मंचार व्यवस्था पर बल देते हुए कहा है कि

राष्ट्रीयता को गवने अच्छी तरह इग मंदभं मे गगता जा गकता है कि 'बटून गारे विपर्यो पर किलने प्रभावनाती इग मे एक बटे सामाजिक समूह के मरर्यों के गाय मंपकं किया जा गकता है।' इयूश ने सामाजिक भूमिकाओं, आदतों ओर गंवार सुविधाओं के एक दूगरे की पूरक बनने के मरभं मे 'जनता' के विकास का नरना नैयार किया और अपनी भूमि पर इग जनता की किलनी प्रभुगता है इगके आधार पर 'राष्ट्र' की परिभाषा बतार् है। तो इम प्रकार राष्ट्रवाद, जनता की, प्रभुगता की 'इच्छा' है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता, बदलने हुए सामाजिक पर्यावरण का परिणाम है।

राष्ट्रवाद मे सामाजिक परिवर्तन की भूमिका को मान्यता दिया जाना, इयूश और उनके विचारों मे महमत होने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए पूर्ण रूप मे नई बात नहीं थी। राष्ट्रवाद के अधिकतर विद्वान इतिहासकारों ने राष्ट्रवादी युग में 'उमड़ते हुए जनमूहों' की भूमिका को माना है। लेकिन नई बात यह है कि सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रवाद की परिभाषा ही बन गया है। सामाजिक परिवर्तन, विरोधकर आधुनिकीकरण, और राष्ट्रवाद को, एक दूगरे का अविभाज्य अंग माना गया है। प्राचीन विद्वानों ने दार्शनिकों और राजनीतियों को गही राजनीतिक व्यवस्था और उसमे मनुष्य के स्थान के संबंध मे, एक दूगरे के साथ याद-विवाद में उलझते देखा और आज का विद्वान राष्ट्रवाद को, विचारों और धारणाओं का समूह उतना नहीं मानता जितना कि परिवर्तन की प्रक्रिया मे उपजी एक भावना ममझता है। यास्तप मे राष्ट्रवाद तो परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है। यदि राष्ट्रवाद किसी एक समुदाय मे सदस्यता की परिभाषा देता है, 'हम कौन हैं?' इस प्रश्न मे 'हम' की परिभाषा, तो यह परिभाषा राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था की साधारण धारणा के मरभं मे नहीं है बल्कि संबंधाधारण को सामाजिक परिवर्तन की देन के मंदभं मे है। इसलिए राष्ट्रवाद को समझने में यह नहीं देखना है कि इस शब्द मे क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं कि लोगों का विश्वास 'किस बात' मे है बल्कि यह कि इसमे 'किसका' विश्वास है। किमी एक राष्ट्रवाद द्वारा प्रतिपादित विचार, उस भावना पर आधारित कार्यक्रमों का संबद्ध रूप है, जो परिवर्तित सामाजिक, और इसलिए, मनोवैज्ञानिक वातावरण मे उपजती है। आधुनिक मत यह है कि राष्ट्रवाद स्वयं को आधुनिक बनाने की भावनात्मक प्रतिक्रिया है।

गैर पश्चिमी राष्ट्रवाद और पश्चिम

आधुनिकीकरण और राष्ट्रवाद के बीच का संबंध, गैर पश्चिमी क्षेत्रों में राष्ट्रवाद के अध्ययन मे कही ज्यादा रहा है। राष्ट्रवाद के पहले के अध्ययनों मे, गैर पश्चिमी राष्ट्रवाद को पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रवाद से निश्चित रूप से भिन्न माना गया और

इसमें एशिया और अफ्रीका के नए राष्ट्रोंकी तथाकथित 'कृत्रिमता' पर विशेष जोर दिया गया। लेकिन हाल के अध्ययनों में इस तरह के भेदभाव कम किए गए हैं। जहां गैर पश्चिमी राष्ट्रवाद को आमतौर पर इसके उद्गम के क्षेत्रों और संस्कृतियों के संदर्भ में, और इसके समकालीन स्वरूप के संदर्भ में देखा जाता है, वहां इसे मूलतः पश्चिमी राष्ट्रवाद जैसा ही माना गया है। जैसा कि रूपर्ट ऐमसन ने लिखा है :

राष्ट्रवाद जहां कहीं भी उभरता है वहां यह वास्तव में उन शक्तियों की प्रतिक्रिया का परिणाम है जिन्होंने हाल की शताब्दियों में पश्चिम में क्रांति पैदा की और विश्व के कोने कोने में एक के बाद एक लहर के रूप में पहुंच गई।⁹

ऐमसन ने जिस क्रांतिकारी शक्ति का उल्लेख किया है वह स्वयं आधुनिकीकरण ही है। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे 'पुरानी सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक मान्यताएं टूटती हैं' और उनकी जगह नई मान्यताएं जन्म लेती हैं।¹⁰ इस प्रकार किसी एक तरह के राष्ट्रवाद के विकास को इसी प्रक्रिया के अनुसार समझा जा सकता है। अफ्रीकी राष्ट्रवाद के बारे में लिखते हुए जेम्स एस० कौल-मेन ने 'राष्ट्रवाद का मनोविज्ञान' का उल्लेख किया है, जो 'अस्तित्व की चेतना या पूर्वस्थिति में विकल्पों की संभावना के साथ उपजता है। यह मानसिक स्थिति पश्चिमी शिक्षा की देन है।'¹¹ डेनियल लरनर ने मध्य पूर्व में राजनीतिक विकास के अध्ययन में 'एक गतिशील व्यक्तित्व' के उदय का उल्लेख किया है, जो बहुत तीव्र और व्यापक नगर विस्तार, साक्षरता और संचार से उपजा है, और जिसमें अपने आपको बदलते हुए वातावरण के अनुसार ढालने की क्षमता है।¹²

इस मूल तर्क पर हाल के वर्षों में काफी विस्तारपूर्वक लिखा गया है। आधुनिकीकरण के 'विशिष्ट लोकाचार' यानी राष्ट्रवाद को, बहुत से लोग अति आधुनिकतावादियों की विचारधारा मानते हैं। इन अति आधुनिकतावादियों में वे नए सामाजिक वर्ग आते हैं जो पश्चिमी प्रभाव का परिणाम हैं।¹³ राष्ट्रवाद को आधुनिकीकरण के और भयावह परिणामों के प्रति मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया भी कहा गया है। जैसा कि लुसियन पाई का कहना है :

यह (यह अवधि जिसमें आधुनिकीकरण अपना प्रभाव जमाना शुरू करता है) व्यक्तिगत असुरक्षा का समय है, क्योंकि करोड़ों लोगों को अपनी अपनी जीवन-पद्धति में भयंकर परिवर्तन करने पर बाध्य होना पड़ता है।... पुरानी और जानी पहचानी जीवनधारा में अलग हो जाने की पीड़ा और कष्ट झेलने

के साथ साथ उन्हें अत्यंत मूल मानवीय समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ये समस्याएं हैं व्यक्ति के अपना अलग अस्तित्व और व्यक्तिगत संपूर्णता बनाए रखने की। सबसे बड़ी बात यह है कि पुरानी व्यवस्था ऐसी है जिससे दोस्त और दुश्मन सभी, अपने स्व को अनूठा बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसी व्यवस्था का उपयोग उस 'हम' को जीवित रखने के लिए भी होता है जो मानव समाज की विशेषता का मूल है। दूसरी ओर दोस्त और दुश्मन दोनों ही, नवीन को विदेशी मूल की बात समझते हैं।¹⁴

राष्ट्रवाद, आधुनिकीकरण के तनावों की प्रतिक्रिया है, जो 'सामाजिक असंतुलन से उपजी भावनात्मक उलझनों को निकालने का प्रतीकात्मक द्वार है।'¹⁵

न केवल राष्ट्रवाद बल्कि राष्ट्रवादी आंदोलनों की भी आधुनिकीकरण के संदर्भ में देखा जा रहा है। जो ऐसे आंदोलनों में भाग लेते हैं वे परिभाषा के अनुसार लगभग आधुनिक बन चुके हैं और वे राष्ट्रवादी भावनाओं का जोर शोर से प्रचार करते हैं और आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप राष्ट्रवादी आंदोलनों में शामिल होते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास को, आधुनिकीकरण के प्रसार के साथ साथ बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, और राष्ट्रवादी आंदोलन आधुनिकता का पोषण स्थल बन जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे आंदोलनों में भाग लेने वाले सभी लोग पूरी तरह आधुनिक बन चुके हैं, या जैसाकि पश्चिमी देश समझते हैं, उसी अर्थ में निश्चित ही राष्ट्रवादी बन गए हैं। फिर भी आमतौर पर यह तर्क दिया जा रहा है कि राष्ट्रवादी आंदोलनों में भाग लेने वाले लोगों में, 'अपने ही 'राष्ट्रीय' माधियों और 'राष्ट्रीय' सरकारों के साथ घनिष्ठ संपर्क की बहुत अधिक चेतना है।'¹⁶ राष्ट्रवादी आंदोलन, आधुनिक समाज के धीरे धीरे उदय होने का परिणाम है। यह आंदोलन तब और विस्तृत होता चला जाता है जब इसमें आधुनिकता से प्रभावित ज्यादा में ज्यादा लोग शामिल होते जाते हैं। अन्य शब्दों में, आधुनिकीकरण, राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवादी आंदोलन एक दूसरे के समानार्थक हो गए हैं।

राष्ट्रवादी आंदोलन के आधुनिकीकरण के बढ़ते हुए प्रभाव के साथ जुड़ने की बात को, किमी एक राष्ट्रवादी आंदोलन या विभिन्न आंदोलनों के बीच कालांतर में आने वाले मंडांतिक मतभेदों के कारणों को स्पष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए आमूल परिवर्तन लाने वाले राष्ट्रवाद की नहर, या गुरत स्वाधीनता दिए जाने की उत्कट भावों के बारे में, अचरम इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है कि इन तरह के आंदोलनों में भाग लेने वाले अधिकांश लोग पश्चिम में कम प्रभावित होते हैं, और इनमें मध्यम वर्ग के

लोगों की संख्या कम होती है। ऐसी ही एक लहर भारत में 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर कई संगठनात्मक सुधारों के बाद आई थी जिनमें लगभग सभी वर्गों के लोगों ने काफी बड़े स्तर पर भाग लिया था।¹⁷ एक और आंदोलन गोल्ड कोस्ट (आजकल घाना) में हुआ था, जब मध्यम वर्गीय दल 'दि यूनाइटेड गोल्ड कोस्ट कन्वेंशन' पर, उग्रवादी कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी, हावी हो गई थी। इस पार्टी में अधिकांश ऐसे लोग थे जो 'प्रारंभिक स्कूलों को छोड़कर' भागे थे और पार्टी में इन्हीं का बोलबाला था। ऐसे व्यक्ति 'माध्यमिक शिक्षा की सीमित प्रणाली से होकर जैसे जैसे न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त कर सके थे।'¹⁸ मामूली तौर पर आधुनिक आर्थिक और सामाजिक प्रणाली से संबद्ध किए गए थे। परंपरा से कटकर अलग हो जाने और फिर भी आधुनिक समाज में कोई प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार न होने के कारण, प्रारंभिक स्कूलों से भागने वाले ये लोग अपने ही अन्य मध्यम वर्गीय साथियों की अपेक्षा, कहीं अधिक संख्या में राष्ट्रवाद के आंदोलनों में शामिल होने को बाध्य हुए।

राबर्ट निस्वेट ने राष्ट्रवाद पर टिप्पणी करते हुए लिखा है :

आधुनिक राष्ट्रवाद को मानव की आस्थाओं के परंपरागत ढांचे में पड़ी उन दरारों से अलग करके नहीं समझा जा सकता जो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने से पड़ी और जिनके कारण एक दूसरे से दूर हटने वाले जनसमूहों को एक तरह की मनोवैज्ञानिक रिक्तता का आभास होने लगा।¹⁹

राष्ट्रवादी आंदोलनों के बारे में किए गए अधिकांश अध्ययनों में बताया गया है कि इन आंदोलनों के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। इस तरह के आंदोलन आधुनिकीकरण के बराबर फैलते हुए प्रभाव, और राष्ट्रवाद के प्रसार के परिणाम माने जा रहे हैं। इसका मार यह है कि 'राष्ट्रवाद, आधुनिकीकरण का 'उन्माद' है और राष्ट्रवादी आंदोलन इसी उन्माद का व्यावहारिक रूप है।

गैर पश्चिमी राष्ट्रवाद : एक पुनर्मूल्यांकन

आजकल राष्ट्रवाद को आमतौर पर, और गैर पश्चिमी राष्ट्रवाद को विशेष रूप में, जिन तरह का समझा जाता है उसके अनुसार यह माधारण और प्रभावकारी, दोनों ही हैं। लेकिन कई समस्याएं उठ सकती हैं। एक तो यह कि राष्ट्रवाद के उदय का संबंध आधुनिकीकरण के प्रसार में जोड़ा गया है, और ऐसा लगता है कि इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर भी राष्ट्रवाद को आधुनिकीकरण के परिणामों

के साथ साथ उन्हें अत्यंत मूल मानवीय समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ये समस्याएं हैं व्यक्ति के अपना अलग अस्तित्व और व्यक्तिगत संपूर्णता बनाए रखने की। सबसे बड़ी बात यह है कि पुरानी व्यवस्था ऐसी है जिससे दोस्त और दुश्मन सभी, अपने स्व को अनूठा बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसी व्यवस्था का उपयोग उस 'हम' को जीवित रखने के लिए भी होता है जो मानव समाज की विशेषता का मूल है। दूसरी ओर दोस्त और दुश्मन दोनों ही, नवीन को विदेशी मूल की बात समझते हैं।¹⁴

राष्ट्रवाद, आधुनिकीकरण के तनावों की प्रतिक्रिया है, जो 'सामाजिक असंतुलन से उपजी भावनात्मक उलझनों को निकालने का प्रतीकात्मक द्वार है।'¹⁵

न केवल राष्ट्रवाद बल्कि राष्ट्रवादी आंदोलनों को भी आधुनिकीकरण के संदर्भ में देखा जा रहा है। जो ऐसे आंदोलनों में भाग लेते हैं वे परिभाषा के अनुसार लगभग आधुनिक बन चुके हैं और वे राष्ट्रवादी भावनाओं का जोर शोर से प्रचार करते हैं और आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप राष्ट्रवादी आंदोलनों में शामिल होते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास को, आधुनिकीकरण के प्रसार के साथ साथ बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, और राष्ट्रवादी आंदोलन आधुनिकता का पोषण स्थल बन जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे आंदोलनों में भाग लेने वाले सभी लोग पूरी तरह आधुनिक बन चुके हैं, या जैसाकि पश्चिमी देश समझते हैं, उसी अर्थ में निश्चित ही राष्ट्रवादी बन गए हैं। फिर भी आमतौर पर यह तर्क दिया जा रहा है कि राष्ट्रवादी आंदोलनों में भाग लेने वाले लोगों में, 'अपने ही 'राष्ट्रीय' साथियों और 'राष्ट्रीय' सरकारों के साथ घनिष्ठ संपर्क की बहुत अधिक चेतना है।'¹⁶ राष्ट्रवादी आंदोलन, आधुनिक समाज के धीरे धीरे उदय होने का परिणाम है। यह आंदोलन तब और विस्तृत होता चला जाता है जब इसमें आधुनिकता से प्रभावित ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होते जाते हैं। अन्य शब्दों में, आधुनिकीकरण, राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवादी आंदोलन एक दूसरे के समानार्थक हो गए हैं।

राष्ट्रवादी आंदोलन के आधुनिकीकरण के बढ़ते हुए प्रभाव के साथ जुड़ने की बात को, किसी एक राष्ट्रवादी आंदोलन या विभिन्न आंदोलनों के बीच कालांतर में आने वाले मैदातिक मतभेदों के कारणों को स्पष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए आमूल परिवर्तन लाने वाले राष्ट्रवाद की लहर, या तुरंत स्वाधीनता दिए जाने की उत्कट मांगों के बारे में, अक्सर इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है कि इस तरह के आंदोलनों में भाग लेने वाले अधिकांश लोग पश्चिम से कम प्रभावित होते हैं, और इनमें मध्यम वर्ग के

लोगों की संख्या कम होती है। ऐसी ही एक लहर भारत में 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर कई संगठनात्मक मुद्दों के बाद आई थी जिसमें लगभग सभी वर्गों के लोगों ने काफी बड़े स्तर पर भाग लिया था।¹⁷ एक और आंदोलन गोल्ड कोस्ट (आजकल घाना) में हुआ था, जब मध्यम वर्गीय दल 'दि यूनाइटेड गोल्ड कोस्ट कन्वेंशन' पर, उपवादी कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी, हावी हो गई थी। इस पार्टी में अधिकांश ऐसे लोग थे जो 'प्रारंभिक स्कूलों को छोड़कर' भागे थे और पार्टी में इन्हीं का बोलबाला था। ऐसे व्यक्ति 'माध्यमिक शिक्षा की सीमित प्रणाली से होकर जैसे जैसे न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त कर सके थे।'¹⁸ मामूली तौर पर आधुनिक आर्थिक और सामाजिक प्रणाली से संबद्ध किए गए थे। परंपरा से कटकर अलग हो जाने और फिर भी आधुनिक समाज में कोई प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार न होने के कारण, प्रारंभिक स्कूलों से भागने वाले ये लोग अपने ही अन्य मध्यम वर्गीय साथियों की अपेक्षा, कहीं अधिक मख्या में राष्ट्रवाद के आंदोलनों में शामिल होने को बाध्य हुए।

राबर्ट निस्वेट ने राष्ट्रवाद पर टिप्पणी करते हुए लिखा है :

आधुनिक राष्ट्रवाद को मानव की आस्थाओं के परंपरागत ढांचे में पड़ी उन दरारों से अलग करके नहीं समझा जा सकता जो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने में पड़ी और जिनके कारण एक दूसरे में दूर हटने वाले जनसमूहों को एक तरह की मनोवैज्ञानिक रिक्तता का आभास होने लगा।¹⁹

राष्ट्रवादी आंदोलनों के बारे में किए गए अधिकांश अध्ययनों में बताया गया है कि इन आंदोलनों के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। इस तरह के आंदोलन आधुनिकीकरण के बराबर फैलते हुए प्रभाव, और राष्ट्रवाद के प्रसार के परिणाम माने जा रहे हैं। इसका सार यह है कि राष्ट्रवाद, आधुनिकीकरण का 'उन्माद' है और राष्ट्रवादी आंदोलन इसी उन्माद का व्यावहारिक रूप है।

गैर पश्चिमी राष्ट्रवाद : एक पुनर्मूल्यांकन

आजकल राष्ट्रवाद को आमतौर पर, और गैर पश्चिमी राष्ट्रवाद को विशेष रूप से, जिस तरह का समझा जाता है उसके अनुसार यह साधारण और प्रभावकारी, दोनों ही है। लेकिन कई समस्याएं उठ सकती हैं। एक तो यह कि राष्ट्रवाद के उदय का संबंध आधुनिकीकरण के प्रसार में जोड़ा गया है, और ऐसा लगता है कि इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर भी राष्ट्रवाद को आधुनिकीकरण के परिणामों

की भावात्मक प्रतिश्रिया मात्र समझना, यानी यह प्रतिश्रिया नए सामाजिक वर्गों के उदय, व्यक्तिगत और सामाजिक असुरक्षा आदि के विरुद्ध है,—राष्ट्रवादी विशिष्ट वर्गों पर पश्चिमी विचारों के प्रभावों तथा इन विचारों के प्रति विशिष्ट वर्गों की प्रतिश्रियाओं की उपेक्षा करना है। जैसाकि वाद में तर्क दिया जाएगा, इस तरह की प्रतिश्रियाएं उन राष्ट्रवादी आंदोलनों से अलग नहीं की जा सकती जिन्हें राष्ट्रवादी विशिष्ट वर्ग चलाना चाहते हैं।

इससे भी बड़ी कठिनाई उस हालत में उत्पन्न होती है जब आधुनिकीकरण, राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी आंदोलनों को समरूपी मानने की प्रवृत्ति हो। यदि राष्ट्रवादी आंदोलन को आधुनिकीकरण के बढ़ते हुए प्रभाव के परिणामस्वरूप राष्ट्रवादी भावना की व्यापक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है तो स्वाधीनता के बाद अल्पविकसित राज्यों में राष्ट्रवादी भावना की कमी (जिसकी अक्सर निंदा की गई है) एक प्रकार का रहस्य बन जाती है।

यहां एक विरोधाभास उभरता है। एक ओर तो अल्पविकसित राज्यों में समकालीन राजनीति के विद्वान, क्षेत्रवाद और विशिष्टतावाद को स्वाधीनता के पश्चात के युग में इन राज्यों के प्रमुख लक्षण मानते हैं। उधर दूसरी ओर राष्ट्रवाद का विकास, जैसाकि राष्ट्रवादी आंदोलन में हुआ, स्वाधीनतापूर्व के युग के अध्ययनों में विशेष स्थान पाता है।

जैसा पहले अध्याय में कहा गया, आधुनिक समाजविज्ञानशास्त्रियों में सामाजिक परिवर्तन के बारे में बड़े आदर भाव की वृत्ति नजर आती है। यानी समाजों की केवल एक सामाजिक विशेषता मानी जाती है जिनसे इनका वर्गीकरण होता है ('परंपरावादी', या 'आधुनिक')। परिवर्तन को इस तरह की समाजव्यवस्था का परिणाम कहा जाता है। यह दोनों व्यवस्थाएं कभी कभी एक दूसरे के क्षेत्रों का उल्लंघन कर सकती हैं लेकिन अंततः एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था को अपने समक्ष नहीं पनपने दे सकती।

राष्ट्रवाद का आधुनिकतावादी सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के बारे में यही धारणा लेकर चलता है। यह बात विभिन्न दलीलों से स्पष्ट होती है। इनसे राष्ट्रवाद को, उसके विकास के विभिन्न चरणों में अच्छी तरह समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक विद्वान ने कांगो की राजनीति का अध्ययन करते हुए 'राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास के पांच चरण' बताए हैं :

1. प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलन

2. मसीही और संहितावादी संप्रदाय
3. नगर दंगे और हिंसा
4. पूर्व राजनीतिक आधुनिक संस्थाएं
5. राजनीतिक दल²⁰

व्यावहारिक दृष्टि से, इनमें से प्रत्येक चरण आधुनिकीकरण के बारे में समाज की प्रतिक्रिया और निश्चित प्रकार के सामाजिक ढांचों का प्रतीक है। प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलन, विदेशी शक्तियों की आक्रामक गतिविधियों के प्रति स्थाई पर-परागत प्रणाली की प्रतिक्रिया है। परंपरागत सामाजिक ढांचों के छिन्न भिन्न हो जाने से, किसान विद्रोह और धार्मिक तथा सांप्रदायिक समूहों के विद्रोह, नगर दंगे और हिंसा की घटनाओं के लिए आधार तैयार हो जाता है। धीरे धीरे समाज का नया केंद्र बनता है और उसका विस्तार होने लगता है। यह बात नजर आती है पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित विशिष्ट वर्ग की बढ़ती हुई संख्या, और नई 'राष्ट्रीय' सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं से—जिससे राष्ट्रवाद अंतिम चरण में पहुंच जाता है। यह अंतिम चरण है राजनीतिक संस्थाओं का गठन जो अंत में राष्ट्रवादी राजनीतिक दल बन जाती है। परंपरागत क्षेत्रवादी संस्थाएं धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं, और उनका स्थान राष्ट्रीय संस्थाएं ले लेती हैं।

राष्ट्रवाद के विकास के इस विवरण में, सामाजिक परिवर्तन के, आधुनिकीकरण लाने वाले परिणामों के बारे में न केवल बड़ा चढ़ाकर कहा गया है बल्कि सामाजिक परिवर्तन के अलग अलग अनुपात में पड़ने वाले उम्र प्रभाव, चाहे यह आधुनिकीकरण लाने वाला ही क्यों न हो, को भी अनदेखा किया गया है, जो किसी प्रदेश में रहने वाले लोगों के विभिन्न वर्गों पर पड़ता है। प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलन, धार्मिक संप्रदाय, शहरी दंगे और हिंसा, और पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, किसी एक प्रदेश में एक साथ, एक समय हो सकती हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन, एक राष्ट्रीय सामाजिक प्रणाली और राष्ट्रीय चेतना की लहर की शुरुआत शायद इतनी नहीं करते जितना कि शहरी, ग्रामीण, धार्मिक, जातीय, और राष्ट्रीय स्तर पर विरोध का मंचालन करते हैं।

राष्ट्रवादी आंदोलन के स्रोत

इस पुस्तक के अगले भागों में राष्ट्रवाद के स्रोतों के बारे में लिखा गया है। एक अर्थ में इन्हें 'स्रोत' नहीं कहा जा सकता। जैसा काफोर्डिंग ने कहा है, यह 'स्रोत' राष्ट्रवाद के प्रारंभिक चरण हैं। आधुनिकीकरण के प्रभाव में भिन्नता को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न विरोध आंदोलन लगभग एक ही समय हुए।

हा, यह हो सकता है किसी एक प्रकार का विरोध आंदोलन औपनिवेशिक युग के शुरू में हुआ हो (उदाहरण के लिए धार्मिक विरोध)। इन विरोध आंदोलनों को 'स्रोत' इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनमें भाग लेने वालों को अनिवार्यतः राष्ट्रीय दृष्टिकोण से मोचने पर बाध्य होना पड़ा। फिर भी एक तरह से इन्हें 'स्रोत' कहा जा सकता है क्योंकि इनसे राष्ट्रवादी विशिष्ट वर्ग को वह सामाजिक शक्ति प्राप्त होती है जिसका वे उपयोग कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रवादी आंदोलन, उतना मुसगठित जन आंदोलन नहीं है, जितना कि यह क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, और सामाजिक परिवर्तन के कारण विभक्त समाज में, अलग अलग आंदोलनों का मिलाजुला रूप है। राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू करने में राष्ट्रवादी विशिष्ट वर्ग ने एक तरह की काल्पनिक प्रवृत्ति का निर्माण किया है और इसके लिए उन्होंने स्थानीय तौर पर शुरू होने वाले विरोध आंदोलनों और दलों को राष्ट्रवादी उद्देश्यों के पीछे लगाकर अपने स्वार्थ सिद्ध करने के प्रयत्न किए हैं। जरूरी नहीं है कि यह राष्ट्रवादी उद्देश्य सभी लोगों को स्वीकार्य हों। ऐसा करते हुए राष्ट्रवादी विशिष्ट वर्ग ने स्वाधीनता की मांग, और स्वाधीनता संघर्ष के नेता का अपना दर्जा उचित बताने का प्रयत्न किया है।

शहरी राजनीति और विरोध

अफ्रीका और एशिया में राजनीतिक गतिविधि के प्रथम मूकण आमतौर पर नगरी और कस्बों में देखे गए। लगभग अनिवार्यतः इन गतिविधियों का संचालन और नेतृत्व पश्चिमी प्रभाव में आए स्थानीय विशिष्ट वर्ग, नव मध्यम वर्ग, ने किया। अधिकांश शहरी समस्याओं के साथ बहुत सारी संस्थाएं संपर्क में आ गईं क्योंकि इनके सदस्य, एक से अधिक समस्याओं के सदस्य थे।

अपने अपने वर्ग के हित की भावना ने अधिकांश संगठनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया। सरकारी नीतियों में जाने अज्ञाने, पश्चिमी प्रभाव वाले विशिष्ट वर्ग की संख्या और बढ़ा दी साथ ही उनके लिए नौकरी और प्रगति के अवसर भी कम कर दिए। पारंपरिक प्रभाव वाले ये विशिष्ट वर्ग धीरे धीरे आत्माभिमानों में बढ़ गए और केवल अपने ही वर्ग के हितों और स्वत्व पर ही ध्यान देने लगे।²¹ इनके परिणामस्वरूप अत्यंत भिन्न विचारों और उद्देश्यों वाले संगठन और संस्थाएं बन गईं जो अपने अपने हितों की ही बात करती थीं, व्यापारिक संस्थाएं, सरकारी कर्मचारियों के दल, बुद्धिजीवियों के क्लब, और राजनीतिक संस्थाएं, जैसे कलकत्ता की इंडियन एसोसिएशन, शुरू की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, टागोरिका की अफ्रीकी एसोसिएशन और यंग ट्यूनिशियंस।²² उनके विधिवत रूप से घोषित उद्देश्य कुछ भी रहे हों, इनमें से अधिकांश दलों ने कई कार्य किए, और कई बार तो वे बौद्धिक

विचार विमर्श वाले दलों के वजाय विरोध आंदोलन चलाने वाले दल बने और फिर दुबारा वीरदिक दल बन गए। इनके सदस्य आमतौर पर कई संस्थाओं के सदस्य रहते थे। उदाहरण के लिए टांगानिका के एक जिले में राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास के अध्ययन से पता चला कि स्थानीय टांगानिका अफ्रीकी एसोसिएशन के सक्रिय कार्यकर्ता, व्यापारियों की एक सहकारी संस्था और सामाजिक मांस्कृतिक क्लबों से भी घनिष्ठ रूप से संबद्ध थे।²³ ऐसे ही उदाहरण भारत, कांगो, मोरक्को, ट्यूनीशिया और अन्य स्थानों पर भी देखे जा सकते हैं।²⁴

ये मध्यम वर्गीय संस्थाएं कभी तो सक्रिय हो जाती थीं और कुछ समय के लिए विरोध आंदोलनों का मंचालन करती या अदालतों में याचिकाओं की भरमार कर देती थी, तो कभी बिलकुल निष्क्रिय होकर चुप बैठ जाती थी, जब तक कि कोई नए मामले नहीं उठ खड़े हुए (ये मामले ऐसे होते थे जिनमें बहुधा नए दल उभरकर आते थे)। व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक सुधार लाने के लिए कुछ प्रयत्न किए गए लेकिन आमतौर पर ये दल मुख्यतः अपने अपने वर्गों के हितों की रक्षा तक ही सीमित रहे। आधुनिक सुधारों के लिए अपनी मांग के बावजूद यह दल मूल रूप से अपने लिए ही गतिविधियां चलाते थे अर्थात् ये विशिष्टतावादी रहे, और केवल स्थानीय समस्याओं तक ही उनके क्रियाकलाप सीमित रहे। यदि भौगोलिक दृष्टि से अपने दायरे से बाहर निकलकर कोई बड़ी संस्था या आंदोलन चलाने के प्रयत्न हुए तो आमतौर पर ऐसे मामले पर ही ध्यान दिया जाता था जो नए मध्यम वर्ग से संबंध रखते हों जैसे कि सरकारी नौकरियों में और अधिक अवसरों की मांग। पश्चिमी प्रभाव वाले विशिष्ट वर्ग के वारे में एक आम गलत धारणा यह है कि इन्हे परंपरागत समाज से अलग थलग कर दिया गया, वैसे इस वर्ग की तो अपनी कोई नींव ही नहीं थी।²⁵ वास्तव में पश्चिमी प्रभाव वाले विशिष्ट वर्ग ने अपने अपने परंपरागत समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। इस पर टिप्पणी करते हुए उन्नीसवीं शताब्दी के भारत के इतिहास के संबंध में लिखने वाले एक इतिहासकार ने कहा है :

'एक शिक्षित व्यक्ति अपनी जाति और समाज का सदस्य बना ही रहता था और इसलिए वह दोनों तरह की संस्थाओं का सदस्य रहता था। एक संस्था रिस्ते और धर्म पर आधारित होती थी और दूसरी शिक्षा और राजनीतिक विचारधाराओं पर।'²⁶

पश्चिमी प्रभाववाले विशिष्ट वर्ग अपरिहृषा' तो थें ही लेकिन उनके परंपराओं के बंधनों की दृढ़ता और नई परिस्थितियों में उनकी मफलता, दोनों के कारण यह

वर्ग अपने अपने परंपरागत समाज में काफी प्रभावशाली ढंग में घुलमिल रहे।²⁷ नतीजा यह रहा कि इस विशिष्ट वर्ग ने मापदायिक बंधनों, जातीय संस्थाएं, कबीले के कल्याण की समस्याएं, धार्मिक मंगलन आदि, पर आधारित संस्थाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण योग दिया।²⁸

टांगानिका वाने पहले उदाहरण के अनुसार ही, टांगानिका अफ्रीकी एसोसिएशन की स्थानीय शाखा में सक्रिय कई विशिष्ट वर्ग वाने लोगों ने एक कबीले की एमोनिएशन मुकूमा यूनिन का मंगलन और मचालन किया। इन यूनिन का उद्देश्य 'मुकूमा जाति के लोगों को एक दूमरे का ध्यान रखने और जीवन की कठिनाइयों में एक दूमरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहन देना था।'²⁹

इन एमोनिएशनों का सदस्य बनने के लिए वहां का परंपरागत निवानी होना आवश्यक था, लेकिन ये संस्थाएं वास्तव में परंपरावादी नहीं थीं। यह जहरी नहीं था कि इन संस्थाओं के नेता वंश के आधार पर चुने जाते हों। इनका चुनाव शिक्षा और योग्यता के अनुसार होता था। ये दल कई तरह के काम करते थे, जैसे अने ही ममाज के अंदर सामाजिक मुद्धार लाना, या दो पक्षों के बीच झगड़ों में मध्यस्थता करना या नई शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था कराना। ये दल विरोध की गतिविधियों के केंद्रबिंदु के रूप में भी कार्य करते थे। भारत में छोटी जातियों के बीच बनाई गई संस्थाएं अक्सर धार्मिक और सरकारी भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन चलाती थीं।³⁰ सारे अफ्रीका में, विशेषकर पश्चिमी अफ्रीका में इन तरह के विरोध आंदोलन हुए। ऐसी जातीय संस्थाएं आमतौर पर पश्चिमी प्रभाव वाले विशिष्ट वर्गीय लोगों के दबाव में रहती थीं। लेकिन अक्सर ये संस्थाएं एक ही जाति के अलग अलग दलों को संगठित करने का काम भी करती थीं।

नगरी और कस्बों में सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों का उत्साह केवल नए मध्यम वर्ग तक ही सीमित नहीं था। कुछ स्थानों में बहुत कम वेतन और स्थानीय मजदूरों की दयनीय कार्य परिस्थितियों के कारण, मजदूर मंगलन की गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिला।³¹ ज्यादातर तो इस तरह की गतिविधि का प्रोत्साहन मजदूर वर्ग में बाहर के लोगों की ओर से मिला। यह प्रोत्साहन या तो स्थानीय राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों (विशेषकर अफ्रीका में) या यूरोपीय मजदूर मंगलनों की ओर से प्राप्त हुआ। यूरोपीय मजदूर, अफ्रीका में

इन यूनियनों पर ज्यादातर तो कानूनी अंकुश रहता था और मालिकों की ओर से इन्हें कोई मान्यता नहीं थी इसलिए अक्सर वे हड़तालें करती थीं। कुछ एक हड़तालें तो बहुत बड़े पैमाने पर करने के प्रयत्न हुए। इनमें उल्लेखनीय है भारत में 1920 और 1931 में असहयोग आंदोलन, सूडान में 1947 और घाना में 1950 की हड़ताल।

लेकिन आमतौर पर स्थानीय उद्देश्यों को लेकर स्थानीय हड़तालें ही मजदूर संगठन आंदोलन की विशेषता रही। जहां मजदूर संगठनों की गतिविधि कम से कम रही वहां भी अक्सर हड़तालें हुईं। रोजगार के अवसरों की अपेक्षा अप्रशिक्षित मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाने के कारण, एक ऐसी स्थिति जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के नगरों की ओर जाने के कारण और गंभीर बन गई, अक्सर हिंसात्मक विरोध आंदोलन होते थे और ये समाज में एक महामारी की तरह फैले। ये सभी जनसमूह, चाहे निश्चित वर्गों के हों या मजदूर वर्गों के, समय समय पर कभी कभी उभरते थे। इनका संगठनात्मक ढांचा नहीं था और इनकी प्रवृत्ति अकेले ही काम करने की थी। पश्चिमी प्रभाव वाले विशिष्ट वर्ग के लोगों ने विभिन्न सामाजिक समूहों में अमंतीप फैलाने की कोशिश की जबकि उन्हें नई मांगों पर ध्यान देना चाहिए था जिनके लिए जन समर्थन का आधार तैयार नहीं था।³² बहुत सारे सदस्य एक से अधिक दलों में शामिल थे लेकिन इन दलों को, यद्यत्कि शहरी वातावरण में भी, कभी एकता के सूत्र में बांधने की कोई कोशिश नहीं की गई। अलग अलग दलों के भिन्न भिन्न उद्देश्य थे और भिन्न समस्याओं तथा नीतियों के लिए उनकी अलग प्रतिक्रियाएं थीं।

ग्रामीण राजनीति और विरोध

राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जनता का समर्थन जुटाना केवल शहरी वातावरण की ही विशेषता नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी संगठनात्मक और विरोधात्मक गतिविधियां देखने को मिलीं। विभिन्न आंदोलनों, किसान आंदोलन, स्थानीय धार्मिक विरोध और सहकारिता आंदोलन, की शुरुआत के कारण, और इनका समर्थन करने वाली जनता अलग अलग तरह की थी। लगभग सभी आंदोलनों के उद्देश्य सीमित थे और उनका समर्थन करने वालों का दायरा भी छोटा था। अकेले कार्य करने की राजनीति, और विरोध आंदोलन, शहरो की अपेक्षा गांवों में ज्यादा रहे। पश्चिमी अर्थव्यवस्था और विचारों का प्रभाव अफ्रीकी और एशियाई समाज में कई तरह से महसूस किया गया। इन क्षेत्रों में पाश्चात्य आर्थिक गतिविधियों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास तो हुआ ही, साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था में उसने अपने पैर जमाने शुरू किए। इसके परिणाम काफी गंभीर हुए। ऐरिक वुल्फ ने

इसे 'उत्तर ऐटलाटिक पूंजीवाद' कहा है। इसने कृषक समाज की नींव पर ही आघात किया है।

जैसे जैसे गावों में नकद पैसा देकर लेनदेन करने की अर्थव्यवस्था आती गई वैसे वैसे पुरानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था फ़ूटने लगी और गांव की आत्मनिर्भरता का भी विनाश हो गया। किसान ने दैनिक उपयोग के काम आने वाले अनाज की खेती करने की बजाय नकद धन दिलाने वाली फसल उगानी शुरू कर दी। इसी प्रक्रिया में किसान ने अपनी मेहनत, अपनी जमीन का उपयोग, और अपना उत्पादन, उन्हीं चीजों के लिए किया जिसमें 'एक ऐसी मंडी की आवश्यकताएं पूरी होती थी, जिसका संबंध ग्रामीण जनता की जरूरतों में बहुत मामूली सा था।'²²

मंडी व्यवस्था के विकास ने कृषक समाज के परंपरागत बंधनों को भी काट दिया। पहले, किसान नुकसान के जोखिम कम करने और अपनी स्थिरता को दृढ़ करने के प्रयत्न में अपने अपने साधनों को समाज के साथ बांटता था। इसके अलावा वह, शक्तिशाली संरक्षकों जैसे जमींदारों के साथ अपने संबंधों पर भी निर्भर रहता था। पश्चिमी पूंजीवाद ने लोगों को समाज की मुख्यधारा से अलग कर दिया और उन्हें आर्थिक कार्यकर्ता बना दिया जो अपने सगे संबंधियों और पड़ोसियों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्वों से स्वयं को मुक्त समझते थे।²³ संरक्षक की भूमिका भी बदली। परंपरागत संरक्षक, जैसे कबीले का सरदार, जमींदार आदि का स्थान उद्योगपतियों ने ले लिया या उन लोगों ने अपने आपको नई अर्थव्यवस्था के अनुसार बदला। दोनों ही स्थितियों में किसान के साथ उनके परंपरागत संबंध टूटे। औपनिवेशिक शासन द्वारा अपने ही कानून लागू करने और इस शासन का समर्थन प्राप्त करने के कारण ये संरक्षक स्थानीय समाज के प्रति अपनी परंपरागत जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर सकते थे। ऐसा करते हुए यदि उसे वह सामाजिक प्रतिष्ठा, जो उसे या उससे पहले वाले संरक्षकों को मिली हुई थी, खोनी पड़ी तो भी उसे एक ऐसा बाहरी साथी मिला जिसके पास उसका स्थानीय दर्जा बनाए रखने की शक्ति थी।²⁴

ऋण लेने-देने की व्यवस्था में भी परिवर्तन आया। हालांकि साहूकार, परंपरागत ग्राम्य जीवन में एक कार्यकर्ता मात्र था फिर भी बड़ी-बड़ी दरों पर ब्याज लेने की उसकी क्षमता पर ग्रामीण अधिकारियों और स्थानीय रीति रिवाजों ने काफी अंकुश लगा रखा था। ज्यादातर जमीन संपत्ति हुआ करती थी और साहूकारों को ऋण वसूल करने के लिए बहुत कम कानूनी तरीके उपलब्ध थे। औपनिवेशिक प्रणाली ने इस स्थिति में आमूल परिवर्तन किया। निश्चित लोगों के नाम जमीन कर दी गई जिसे साहूकार के दावों को बल मिला। इन बातों से साहूकार के

पहले से बढ़ रही गतिविधियों में और तीव्रता आई। यहां तक कि जहां कानूनी तौर पर जमीन का हस्तांतरण बहुत कम था, गावों की व्यवस्था में पश्चिमी आर्थिक गतिविधियों के आ जाने से मुद्रा का आदान-प्रदान अधिक हुआ और इसका खराब असर गावों की वस्तु विनिमय प्रणाली पर पड़ा। साथ ही अधिकांश लोगों को उचित ऋण सुविधाएं भी प्राप्त न हो सकी।³⁶ अब किसान को बार बार साहूकार के पास दौड़ना पड़ा और उसे अत्यंत कठिन शर्तों पर ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक कमी न खत्म होने वाली शृंखला की शुरुआत हो गई जिसमें बहुत ऊंची च्याज दर पर ऋण लिया जाता था और ऋण से मुक्ति की कोई आशा नहीं रही, जमीन हाथ से निकल गई, कृषि के उत्पादन को मंडी में बेचने के लिए सौदेवाजी करने की क्षमता कम हो गई, और फिर से ऋण लेने की जरूरत पड़ गई। किसान सिर्फ एक पट्टेदार काश्तकार बन गया। जो पट्टे पर काश्तकारी करते थे वे मामूली मे कृषि मजदूर की स्थिति में पहुंच गए।

इस स्थिति के बारे में किसान की प्रतिक्रिया अक्सर हिंसा और विद्रोह का रूप लेती थी और उसकी बढ़ती हुई नाजुक स्थिति उमरकर सामने आती थी। ज्यादातर यही होता था कि इस तरह के विद्रोह किसानों की दुर्दशा के प्रतीक जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध होते थे न कि राज्य के खिलाफ। बर्मा में साया सान का विद्रोह, दक्षिण भारत में मोपला विद्रोह, फिलीपींस में तायुग घटना और सकदल विद्रोह, तथा ऐसी ही अन्य घटनाएं अस्थाई, हिंसात्मक और सीमित उद्देश्यों के साथ हुईं। जहां कहीं सैद्धांतिक प्रश्न उठे, वहां इस तरह की घटनाओं के पीछे राजनीतिक राष्ट्रवाद कम, और स्थाई रूप से आगे चलकर एक मुदर भविष्य के स्वप्न को साकार बनाने की प्रेरणा ज्यादा थी। जैसाकि ऐरिक आर० वुल्फ ने लिखा है :

किसान का अनुभव दो तरह का है। एक तो यह विचार कि विश्व को किस तरह से सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए, और दूसरा है वे कुछ वास्तविकताएं जिन्हें अव्यवस्था ने जन्म दिया है। किसान ने हमेशा ही यह स्वप्न देखा है कि कभी न कभी उसे इस अव्यवस्था से मुक्ति मिलेगी और कोई ऐसा मसीहा आएगा जो विश्व को अत्याचारों से छुड़ाएगा, कोई ऐसा पैगंबर आएगा जिसके पास ईश्वरीय शक्ति होगी... आधुनिक परिस्थितियों में वर्तमान अव्यवस्था को विश्व की उलटी व्यवस्था समझा गया है और इसलिए यह एक बुराई है... सच्ची सुव्यवस्था अभी आने वाली है, चाहे वह किसी दैवी शक्ति के माध्यम से आए चाहे किसी विद्रोह से, या दोनों के माध्यम से। किसानों की दुर्दशा, और कानून की अवहेलना, तथा विश्व के भविष्य का

स्वप्न, ये सभी किसान विद्रोह की आग भड़काने के लिए सैद्धांतिक तेल का काम करते हैं।³⁷

किसानों के विरोध आंदोलन हमेशा ही इतने अल्पकालिक नहीं थे। कभी कभी स्थानीय किसान संगठन बनते थे जो किसानों की स्थिति को राजनीतिक प्रयत्नों से सुधारने की कोशिश करते थे। भारत में बीसवीं शताब्दी में किसान सभाएं बनीं। इन किसान सभाओं ने भूमि की पट्टेदारी की बढ़ती हुई पेचीदगियों, पट्टे की अवधि की अनिश्चितता, और बिचौलियों द्वारा लगाए जाने वाले कई उपकरणों की बढ़ती हुई संख्या के प्रति विरोध आंदोलन चलाए और भारत के कुछ भागों में काफी हद तक सुसंगठित होकर इन्हें जारी रखा।³⁸ इस तरह के संगठन अपने किसान सदस्यों के लिए नाए संरक्षक बने जिन्होंने जमींदारों और सरकार के खिलाफ किसान सभाओं द्वारा समस्याएं हल कराने के प्रयत्न किए।

किसान चाहे कितने ही सुसंगठित हुए लेकिन उनके विरोध आंदोलन में भाग लेने वालों की संख्या और क्षेत्र की दृष्टि से काफी सीमित रहे। ग्रामीण असंतोष पैदा करने वाली परिस्थितियां व्यापक थीं, लेकिन यह असंतोष अपेक्षाकृत निश्चित जनसमूहों तक सीमित था।

किसान आंदोलनों का एक और महत्वपूर्ण पहलू या धर्म के साथ उनका संबंध। ज्यादातर तो ये आंदोलन धार्मिक ही होते थे जिनमें सामाजिक उद्देश्यों के लिए समर्पण जुटाने के काम में धार्मिक प्रतीकों और रीतियों का प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए बर्मा में माया मान आंदोलन का नेतृत्व एक पाखंडी धर्माचार्य ने किया था। इसी तरह का एक और उदाहरण है 1921 में दक्षिणी भारत में हुआ मोपला आंदोलन। मुस्लिम किसानों ने विद्रोह किया था और उन्होंने एक खलीफा के अधीन शासन की स्थापना की घोषणा की। पर उनका अधिकांश समय और शक्ति हिंदू साहूकारों के विरुद्ध कार्यवाहियों में ही लगे।

अधिकतर धार्मिक आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन के किसी निश्चित कार्यक्रम की वजह से आंदोलन में भाग लेने वालों की अपनी जरूरतों को लेकर हुए। ये आंदोलन गांधी में बड़ी संख्या का रूप लेकर शुरू होते थे। अफ्रीका में अधिकांश धार्मिक संप्रदाय ईसाइयों के मत और स्थानीय परंपरागत रीतियों को बने थे। इस तरह के दलों को बौद्ध, हिंदू आंदोलनों, ... में 'जिया-

क्रियाओं तथा उपासना से व्याधियां दूर करने पर बल दिया जाता था। लेकिन ये दल सुसंगठित नहीं थे।

दक्षिण एशिया में धार्मिक आंदोलनों की विशेषता, पुनर्जागरणवाद थी। यह चाहे हिंदू समाज में, उदाहरण के लिए उत्तर भारत में आर्य समाज, या मुसलमानों अथवा अन्य अल्पसंख्यक ममुदायो में हो, इसका मूल उद्देश्य एक ही था। उद्देश्य था अपने संप्रदाय को सुदृढ़ करना, जो अपवित्र रीतियों के कारण कमजोर हो गया था और औपनिवेशिक व्यवस्था में जिसका पतन हुआ था। प्रयत्न यही था कि संप्रदाय को वापस अपने स्वर्ण युग में लाया जाए।⁴⁰

हालाकि धार्मिक आंदोलनों ने व्यापक और विविध रूप अपनाए, फिर भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के आंदोलन बहुत प्रचलित हुए। धार्मिक आंदोलनों ने व्यापक मंचार संपर्क के लिए आधार दिया और जहां कहीं भी इन्हें दबाया गया वहां विशेष रूप से कई विरोध आंदोलन चलाए गए। इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि हालांकि कुछ विद्वान इन आंदोलनों को ऐसे युग में 'जब औपनिवेशिक स्थिति के कारण उत्पन्न निराशाओं का कोई धर्मनिरपेक्ष समाधान नजर नहीं आ रहा था'⁴¹ राष्ट्रवाद के विकास का एक चरण मानते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि धार्मिक आंदोलनों ने न केवल भाग लेने वालों के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए जो आंदोलन की समाप्ति के बाद भी अकमर बने रहे बल्कि अभिव्यक्ति के प्रतीकों का भी सृजन किया। यही प्रतीक उस समय और महत्वपूर्ण होने वाले थे, जब राष्ट्रवादी विशिष्ट व्यक्तियों ने गांवों वालों को अपने आंदोलनों में जुटाने के प्रयत्न शुरू किए।

विभिन्न संस्थाओं अथवा एसोसिएशनों के सभी ग्रामीण क्रियाकलाप विरोध आंदोलनों के लिए ही नहीं थे। कभी कभी किसान अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उत्पादकों की सहकारी समितियां बनाने की कोशिश करते थे जिनका उद्देश्य बिचौलियों को हटाकर अपने उत्पादनो के लिए मंडियों में बिक्री के काम में और अधिक सक्रिय भाग लेना था।⁴²

सहकारिताओं का विकास उतना ही पुराना प्रतीत होता है जितना उपनिवेशवाद। पूर्वी अफ्रीका में इस तरह की प्रथम सहकार समिति का गठन, वहां बसने वाले पाश्चात्य निवासियों ने 1908 में किया था। दक्षिण एशिया में इन सहकारिताओं का उदय इससे भी पहले हुआ। सहकारी समितियों को सरकार से भी कुछ प्रोत्साहन मिला हालांकि जरूरी नहीं कि प्रोत्साहन उन्हीं कारणों से दिया गया हो जिनपर इन समितियों का गठन करने वालों ने विशेष बल दिया था, (यानी उत्पादक के हितों की रक्षा

करना)। वास्तव में उपनिवेशों की सरकारें अक्सर यह महसूस करती थी कि स्थानीय उत्पादकों को नकदी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाने का सबसे कारगर और कुशल तरीका यही था कि सहकारी समितियां बनें।

सहकारिता के विकास पर विस्तृत रूप से ध्यान नहीं दिया गया लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मस्याओं के गठन के काम में सक्रिय मध्यमवर्गीय विशिष्ट व्यक्तियों ने ही अक्सर सहकारिता आंदोलनों की शुरुआत कराई। जांबिया में बरिष्ठ राष्ट्रवादी पा स्माल ने सहकारिता आंदोलन को मुख्य प्रेरणा दी।⁴³ मैग्वायर ने तंजानिया का जो अध्ययन किया है उससे पता चला है कि टांगानिका अफीकन एसोसिएशन (टी० ए० ए०) और कबीले की एसोसिएशन के नेता ने ही उत्पादक सहकारिताओं का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई। एक सहकारिता के संयोजक ने कुछ सहयोगियों के दल के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश किया, और धीरे धीरे गांवों के बड़े-बूढ़े और युवकों की समितियों के साथ अपना संपर्क बढ़ाया।⁴⁴

लेकिन आमतौर पर, सहकारी समितियों को बड़ी सीमित भी सफलता मिली। उपनिवेशिक सरकारें इन सहकारी समितियों की राजनीतिक भूमिकाओं की संभावित क्षमता के प्रति संदेहशील थीं और परंपरावादी विशिष्ट वर्ग तो अक्सर इनका विरोधी रहा। संभवतः इससे भी महत्व की बात यह है कि सहकारी समितियों के विकास के मार्ग में अड़चन अपर्याप्त पूंजी के कारण आईं। इसके अलावा ये समितियां उस स्तर तक नहीं पहुंच पाईं जहां तक पहुंचने की आवश्यकता थी। यानी ये समितियां पट्टे पर काम करने वाले उस किसान तक नहीं पहुंचीं जो कर्ज के बोझ से दबा हुआ था और जिसके पास न तो कर्ज के लिए कोई जमानत थी और न ही वह इतनी बचत कर सकता था कि जो थोड़ा बहुत ऋण वह ले सका हो उसे लौटा सके।

जहां कहीं सहकारी समितियां सफल हुईं वहां इन्होंने स्थानीय समाज को काफी हद तक संस्थात्मक व्यवस्था प्रदान की। मैग्वायर ने कहा है, 'आंकड़ों की दृष्टि' से ही, 1954 तक सहकारी समितियों में लगभग तीस हजार सदस्य थे। यह संख्या टांगानिका अफीकन एसोसिएशन या मुकूमा यूनियन की सदस्य संख्या के दस गुना के करीब थी (टी० ए० ए० या मुकूमा यूनियन की सदस्य संख्या लगभग तीन तीन हजार थी)।⁴⁵ सहकारिताओं ने ऐसे संपर्क स्थापित किए कि पश्चिमी प्रभाव वाले विशिष्ट वर्गों को गांवों तक सीधे पहुंचने का अवसर मिल गया।

परंपराओं की दृढ़ता

अफ्रीका और एशिया में अधिकांश सामाजिक गतिविधियों का आधार परंपरागत

सामाजिक व्यवस्था ही बनी रही। परंपरागत संस्थाएं खून के रिस्तों, सामाजिक दर्जों, पारस्परिक निर्भरता, और रीति रिवाजों का मिलाजुला स्वरूप थी। ज्यादातर यही होता था कि इन संस्थाओं में समाज के छोटे वर्ग से बड़े वर्ग तक के लोग होते थे। पुराने जमाने से जो वर्ग विशिष्ट माने जाते थे उनका संबंध सामाजिक दृष्टि से छोटे वर्गों के साथ संबंधों के प्रकार के आधार पर रहता था। यह संबंध बड़े वर्ग के प्रति छोटे वर्ग के आदर और आत्महित पर आधारित होते थे। यह ऐसी परस्पर निर्भरता थी जिसके बारे में आमतौर पर संरक्षक-संरक्षित संबंधों के दृष्टिकोण से विचार किया जाता है।⁴⁶ इस तरह के संबंध अत्यंत स्थानीय होते थे और इनमें शामिल लोगों के लिए इन्हीं संबंधों से उनके समाज का दायरा बनता था।

जहां पश्चिम का प्रभाव महसूस किया जाने लगा वहां भी अक्सर संरक्षक-संरक्षित संबंध बने ही रहे। औपनिवेशिक समाज की पेचीदा आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप पश्चिम के प्रभाव ने, संरक्षक और संरक्षित के बीच के संबंधों को संकीर्ण बनाना शुरू किया, और स्थानीय बड़े व्यक्ति के लिए बाहरी साधनों के महत्व को क्रांतिकारी ढंग से बढ़ा दिया (इससे स्थानीय संरक्षक, गांव और व्यापक प्रणाली के बीच एक बिचौलिया मात्र बन गया)। लेकिन कुछ स्थितियों में, पहले से चले आ रहे बड़े लोगों ने औपनिवेशिक समाज के नए साधनों का पूरा पूरा उपयोग किया और अपना महत्व बढ़ाया। उदाहरण के लिए, लैमरचंद ने बताया है :

नाइजीरिया के राष्ट्रीय संदर्भ में, 'पुराने जमाने से चले आ रहे उत्तरी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने', बिचौलियों की भूमिका निभाई; राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्कृतियों तथा समाज के वर्गों के बीच रहते हुए ये लोग, प्रथम और द्वितीय साधनों—यानी संरक्षक के पद, ऋण देने वाले, छात्रवृत्तियां और अनुबंध देने वाले तथा अनुबंधों के साथ साथ संपर्क बनाने वाले साधनों का समुचित उपयोग करने वाले बन गए। ऐसी ही भूमिकाएं, बुइंडी के गनवा लोगों ने, सैनेगल के शेख कहलाने वाले लोगों ने, मोरीटानिया में हसन और जव्या ने, बुगागा के कबीलों के सरदारों साजा ने, आइवरी कोस्ट, घाना, नाईजर और अपरवोल्टा के कुछ परंपरागत सरदारों ने थोड़ी बहुत सफलता के साथ निभाई।⁴⁷

जहां कहीं सामाजिक परिवर्तन के कारण ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की शक्ति में कमी आई, वहां भी इन व्यक्तियों की सामाजिक सत्ता और प्रतिष्ठा में हमेशा ही ह्रास नहीं हुआ। नए और अधिक प्रभावशाली संपर्कों वाले संरक्षकों के उदय से परंपरागत संरक्षकों का प्रभाव कम होने के बावजूद इन परंपरागत संरक्षकों के अनुयायियों की संख्या में कमी नहीं हुई। कुछ किसान या तो आदरभाव के कारण या इस गलत-

फहमी के कारण कि उनके परंपरागत संरक्षकों का वास्तव में कुछ प्रभाव है, अपने पुराने संरक्षकों के साथ संबंध बनाए रखना चाहते थे।

अन्य शब्दों में यही कहा जा सकता है कि पश्चिम के प्रभाव के कारण सभी पुरानी सामाजिक व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न नहीं हुईं। यहां तक कि जहां परंपरागत सत्ता का ह्रास हुआ, वहां भी समाज में उन लोगों ने अपना दर्जा बनाए रखा जिनके पास पहले सत्ता थी (लेकिन बाद में औपनिवेशिक शक्ति के सामने वे डमे खो बैठे थे)।

संपर्क-राजनीति : राष्ट्रवादी आंदोलन की उपलब्धि

एक व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास कुछ अंशों में राष्ट्रवादी विशिष्ट वर्ग के बीच होने वाले मूल संगठनात्मक परिवर्तनों का परिणाम है। ये परिवर्तन जैसे सामूहिक दल या किसी राष्ट्रीय दल का केंद्र, या जनमत जुटाने वाली राष्ट्रवादी पार्टियों का उदय, आमतौर पर राष्ट्रवादी विशिष्ट वर्ग के अंदर विभिन्न स्तरों पर (स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय) संबंधों को स्थापित कराते हैं और इन विशिष्ट वर्गों, और स्थानीय आंदोलनों तथा सामाजिक दलों के बीच संपर्क बनाने में सहायक होते हैं।

1919 और 1921 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आए परिवर्तन, इसी संपर्क प्रक्रिया के उदाहरण हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के प्रारंभिक वर्षों में (1885-1920) यह पार्टी वास्तव में भारत के प्रमुख नगरों के मध्यमवर्गीय विशिष्ट व्यक्तियों का मिलाजुला दल थी। इस सारी अवधि में कांग्रेस का विस्तार मुख्यतः भारत के नगरों में ही हुआ। स्थानीय और प्रांतीय संगठन जगजग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे और इनमें सदस्यों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम थी। राष्ट्रीय स्तर के कुछ ही नेता 'राष्ट्रीय' कांग्रेस के प्रतीक थे और इस पार्टी की अखिल भारतीय स्तर की सभाएं साल में सिर्फ एक बार होती थी। कांग्रेस में धीरे धीरे अंदरूनी संगठन की व्यवस्था का विकास हुआ क्योंकि उसने औपनिवेशिक शासन में सुधारों के लिए बातचीत में हिस्सा लेना शुरू किया, और कांग्रेस के विशिष्ट व्यक्तियों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के बढ़ते हुए क्षेत्र में कदम रखा।⁴⁹ इसी अवधि में कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में दो पक्ष उभरे। कुछ लोग नरम दल के थे तो कुछ गरम दल के। किमी मीमा तक इस अंदरूनी विभाजन ने संगठनात्मक विकास को गति प्रदान की क्योंकि एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में आने वाले इन दलों ने, कांग्रेस समर्थकों में अपने प्रभाव का विस्तार करने का प्रयत्न किया।⁴⁹

लेकिन 1920 के दशक के प्रारंभ में संगठनात्मक विकास नब तक अपनी पूर्ण

गति में नहीं आया जब तक मोहनदास करमचन्द गांधी ने नेतृत्व नहीं संभाला।⁵⁰ और तब लगभग तुरंत ही, कई संगठनात्मक परिवर्तन किए गए। दैनिक कार्यों को चलाने के लिए एक सक्रिय कार्यसमिति बनाई गई और इसी तरह, प्रांतीय और स्थानीय स्तरों पर भी कार्यकारिणियां स्थापित की गईं। वित्तीय साधनों का विस्तार किया गया, और पार्टी के संगठन का कार्य पूरे समय करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया गया। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 1920 के कांग्रेस संविधान में यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय कांग्रेस समितियों को अंगरेजों द्वारा की गई प्रशासनिक व्यवस्था का अनुकरण नहीं करना चाहिए (जैसा कि उस समय तक किया जा रहा था) बल्कि भारत के अंदर भापाई विभाजनों को आधार मानकर चलें। इसी के अनुसार वर्तमान प्रांतों का पुनर्गठन करके भापाओं के आधार पर 21 क्षेत्र बनाए गए।

इन सुधारों के परिणामस्वरूप कांग्रेस का औपचारिक गठन हुआ। नवविकसित पार्टीकेन्द्रों और पार्टी की शाखाओं के बीच स्याई संचार संपर्क स्थापित किए गए, और पार्टी के सभी स्तरों पर पूरे समय काम करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी। इसके साथ साथ, इन सुधारों ने कांग्रेस के विशिष्ट व्यक्तियों को स्थानीय राजनीति में प्रवेश करने की और अधिक क्षमता प्रदान की। कांग्रेस के सभी विचार विमर्श स्थानीय भापाओं में होने लगे। पार्टी के कार्यकर्ता स्थानीय दलों और विरोध आंदोलनों में और सक्रिय रूप से भाग ले सके।

भारत का उदाहरण अपने आप में कोई निराला नहीं था। आइवरी कोस्ट के बारे में लिखते हुए जोनबर्ग ने पार्टी डेमोक्रेटिक द-कोट-द-आइवायर (पी० डी० सी० आई०) के संगठनात्मक विकास की भी ऐसी ही पद्धति बताई है। 1947 में पी० डी० सी० आई० जैसे मिलेजुले दल को एक जनसंगठन का रूप देने का प्रयत्न किया गया।⁵¹ कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया, पार्टी संचालकों के प्रशिक्षण के लिए एक काडर स्कूल की स्थापना की गई और सिद्धांत रूप में इस पार्टी का पुनर्गठन करके ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें नीचे से ऊपर तक के पदों की व्यवस्था थी और यह एक जनसंगठन बन गई।⁵² पी० डी० सी० आई० और अन्य पार्टियों,⁵³ जनता का सामूहिक समर्थन प्राप्त करने के इच्छुक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों की संगठनात्मक गतिविधियों के कारण या तो बनी या समाप्त हो गईं। इन पार्टियों का गठन अथवा पुनर्गठन किया गया जिससे इनके बीच आपस में, और अन्य सामाजिक दलों के साथ, संपर्क बन सके। पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता जनसमर्थन प्राप्त करने के लिए बराबर प्रचार करते थे, और इसके लिए वे अक्सर स्थानीय विरोध अंदोलनों में भी शामिल होते थे। सामूहिक समर्थनप्राप्त राष्ट्रवादी पार्टियां अन्य पार्टियों के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में थी और काफी लोग उनके साथ थे फिर भी इन्हें आमतौर पर विशाल पार्टी

नहीं कहा जा सकता। आइवरी कोस्ट में 1952 के चुनावों में पी० डी० सी० आई० को मताधिकार प्राप्त कुल लोगों में से केवल लगभग 33 प्रतिशत वोट मिले थे। घाना में 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी (पी० पी० पी०) को मताधिकार प्राप्त नागरिकों में से लगभग तीस प्रतिशत का समर्थन मिला।⁵⁴ अन्य पार्टियाँ भी सामूहिक समर्थन प्राप्त करने को दिना में अपनी गतिविधियों के प्रारंभिक वर्षों में बहुत सफल नहीं हुई थी। उदाहरण के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की स्वाधीनता से कुछ ही वर्ष पहले सही मायने में जनता का सामूहिक समर्थन प्राप्त कर सकी उससे पहले नहीं।

इसके अलावा सामूहिक समर्थनप्राप्त राष्ट्रवादी संगठनों के उदय का अर्थ यह नहीं था कि वे अत्यंत सुसंगठित राष्ट्रवादी पार्टियाँ बन चुकी थी। पश्चिम अफ्रीका की सामूहिक समर्थनप्राप्त राष्ट्रवादी पार्टियों के एक अध्ययन ने यह स्पष्ट हुआ है कि संगठन की दृष्टि से वे प्रारंभिक चरणों में थीं।⁵⁵

नई लहर (राष्ट्रवादियों की) ने बहुत ही मामूली साधनों में अपने प्रारंभिक उद्देश्य प्राप्त किए। उन्होंने साइकिलों, कुछ ट्रकों और कभी कभी एक आध मोटरगाड़ियों का इस्तेमाल किया। उनके पास कभी कुछ निजी धन होता था, लेकिन वे मुख्यतः मुट्ठीभर निष्ठावान लोगों पर निर्भर थे। उन्होंने जिन संगठनों की स्थापना की, वे शुरू में तो बहुत ही सीमित थे : महर्मस्थापकों की एक मिलीजुली कार्यकारिणी, संवाददाताओं का एक बड़ा दल जिसके संपर्क विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं (विशेषकर राजधानी की और ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ प्रमुख कस्बों की) तथा विभिन्न जातियों के साथ होते थे। इन संगठनों का केंद्र राजधानी में था और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ शाखाएं थीं।⁵⁶

वास्तव में जो बात सामने आई उसे राजनीतिक घटना तो कहा जा सकता था, लेकिन यह एक सुसंगठित पार्टी से बिल्कुल भिन्न थी। यह अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ आंदोलन था जिनके बीच की कड़ी राष्ट्रवादी विशिष्ट व्यक्ति और राष्ट्रवादी पार्टी संगठन थे। सैनेगल की पहली जनता की पार्टी ब्लाक डेमोक्रेटिक सैनेगालेज, का गठन सिद्धांत रूप में फ्रांस की सोशलिस्ट पार्टी (एस० एफ० आई० ओ०) को आदर्श मानकर किया गया था, लेकिन वास्तव में यह पार्टी बहुत सारे हिस्सों में बंटी हुई थी।

पार्टी की शाखाओं में अमतौर पर स्थानीय बड़े लोगों का बोलबाला था और इसी कारण यह पार्टी जातीय दलों और राजनीतिक घुपों, जिन्हें कबीले कहा जाता था,

का एक अव्यवस्थित रूप बनकर उभरी। जोलबर्ग ने पी० डी० मी० आई० की एक शहरी शाखा (सैद्धांतिक तौर पर इसे कम्युनिस्ट पार्टी के ढंग का बनाया गया) के बारे में लिखा है कि इसके बीस हजार सदस्य सौ से ज्यादा जातीय उपसमितियों में बंटे हुए थे।⁵⁷

इस तरह की संस्था के उभरने की बात शायद तभी अच्छी तरह समझी जा सकती है जब प्रारंभिक संगठनात्मक परिवर्तनों और राष्ट्रवादी विशिष्ट व्यक्तियों के बीच संबंधों पर नजर डाली जाए। इस तरह के परिवर्तन किसी पार्टी के संगठनात्मक बनने की वास्तविक शुरुआत होते हैं।⁵⁸ ऐसी हालत में संगठन अपनी भूमिकाओं का निर्धारण करने लगता है।⁵⁹ वह अपने विशिष्ट व्यक्तियों के चुनाव की प्रक्रिया (उनकी संगठनात्मक कार्यकुशलता के आधार पर और पार्टी की विचारधारा को प्रसारित करने के काम में सफलता, और पार्टी के पदों पर वे कितने समय तक रहे, इसके आधार पर उन्हें विशिष्ट व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है), अपने निर्णय लेने और इसके निराले आंतरिक गुटों (आमतौर पर ये गुट व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सैद्धांतिक मतभेदों पर आधारित होते हैं) के निर्माण का काम शुरू कर देता है। कम से कम कागज पर तो यह पार्टी अत्यंत अनुशासनबद्ध और स्वायत्त सत्ता होती है।

लेकिन जैसा अभी कहा गया, ये परिवर्तन संस्थात्मकता की शुरुआत मात्र होते हैं और पार्टी को सिद्धांत रूप में जितनी स्वायत्तता दी जाती है उतनी वास्तव में नहीं होती।⁶⁰ यह बात पार्टी की भूमिकाओं के संदर्भ में विशेष रूप से सामने आती है। विशिष्टता का दर्जा, पार्टी, इतना नहीं देती (उदाहरण के लिए पार्टी के पद) जितना कि वह उस दर्जे की पुष्टि करती है। व्यक्ति अन्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दलों में अपने वर्तमान विशिष्ट दर्जे के कारण, इस नवगठित या पुनर्गठित पार्टी के विभिन्न स्तरों पर प्रमुखता का स्थान पाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अन्य दलों के साथ उसके जो संबंध हैं, उसका फायदा पार्टी को मिल सकता है। उधर पार्टी में उसका विशिष्ट दर्जा होने के कारण, अन्य दलों में भी उसका दर्जा ऊंचा होता है।

विशिष्टतावादियों के संपर्क की यह प्रक्रिया लगभग सभी राष्ट्रवादी आंदोलनों में नजर आती है। इसका एक उदाहरण कांगों के राष्ट्रवादी नेता पैट्रिस लुमुबा हैं। 1951 में स्टैनलेवील पहुंचने के कुछ ही समय बाद लुमुबा ने वहां के प्रमुख बुद्धिजीवी क्लब एसोसिएशन देज इवाल्बज दि स्टैनलेवील की सदस्यता ग्रहण की। उसी साल उन्हें एसोसिएशन देज पोस्टीयर्स दि ला प्राविस ओरियेंटल का महासचिव नियुक्त किया गया। 1953 तक पैट्रिस लुमुबा कम से कम सात एसोसिएशनों

के पूर्ण सदस्य बन चुके थे। 1955 तक वे एमोसिएशन देज इवाल्ज, और एमो-सिएशन दू पयनिल इडिजीन दि ना कालोती आफ स्टैनलेवील, दोनों के ही अध्यक्ष बन चुके थे। यह दूसरी एमोसिएशन, अफ्रीकी मरकारो सेवाओं की स्थानीय थ्रमिक मस्या थी। 1956 में उन्होंने एमीकैल लिबरेल दि स्टैनलेवील की स्थापना की। दो साल के बाद वे मूवमेंट नेशनल कांगोलेज के संस्थापकों में से एक थे। यह, सारे कांगो का पहला राष्ट्रवादी संगठन बना।⁶¹ अधिकांश प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं की जीवनिया भी ऐसी ही हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पार्टी के विशिष्ट व्यक्तियों में अधिकांश निचले स्तर के लोगों का जीवन भी ऐसा ही देखने को मिलता है। मंगवायर ने सुकूमा क्षेत्र के संबंध में जो लिखा है, उसमें एक सक्रिय कार्यकर्ता पाल बोमानी का जीवन भी कई तरह से इसी ढंग का रहा है। बोमानी, म्वाजा अफ्रीकन ट्रेडर्स कोआपरेटिव सोसायटी के नेता थे, इस क्षेत्र के उत्पादक सहकारी समितियों के संगठनकर्ता थे और प्रांतीय सहकारिता आंदोलन के नेता भी थे।⁶² 1951 में बोमानी, सुकूमा आदिवासी एमोसिएशन सुकूमा यूनियन के अध्यक्ष बने, और 1952 में उन्हें लोक प्राविंस टंगानिकन अफ्रीकन एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया।⁶³ स्थानीय राजनीति के विशिष्ट व्यक्तियों के विस्तृत अध्ययन से उनके जीवन का यही ढंग नजर आता है।⁶⁴

राष्ट्रवादी पार्टिया, स्थानीय एमोसिएशनों और आंदोलनों को इतना दबाती नहीं हैं जितना कि उनमें राष्ट्रवादी विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम में संपर्क बनाती हैं। इसके परिणामस्वरूप 'राष्ट्रीय' राष्ट्रवादी व्यक्तियों की अपनी महत्वाकांक्षा, और एक व्यापक आंदोलन चलायें की उनकी इच्छा, दोनों का एक दूसरे में विलय होता है और छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए, लेकिन स्थानीय विरोध आंदोलनों और दलों के आपसी संपर्क के कारण जुड़े हुए 'राष्ट्रवादी आंदोलन' का उदय होता है।

टांगानिका में टी० ए० ए० (1954 में जिसका पुनर्गठन करके नया नाम टंगानि-कन अफ्रीकन नेशनल यूनियन टी० ए० एन० यू० (तानू) रखा गया था) संगठन सारे प्रदेश में स्थानीय विरोध आंदोलनों में सक्रिय था। इन आंदोलनों में कहीं हड़ताल तो कहीं सहकारी समितियों पर सरकारी प्रतिबंधों पर विरोध प्रदर्शन, और कहीं भूमि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन आदि शामिल थे। मंगवायर ने जिम क्षेत्र का अध्ययन किया उसमें इस तरह के लगभग सभी विरोध आंदोलन अंत में मिल्कर एक हुए और 1958 में मविनय अबजा आंदोलन के रूप में लगातार चले।⁶⁵ बहुत सारे इनके में तानू संगठन विरोध आंदोलनों और अपनी भागों के बीच संपर्क स्थापित करने में सफल हो गया। तानू संगठन

के राष्ट्रीय नेता जूलियस न्येरेरे ने इस संगठन के लिए मददस्य बनाने के उद्देश्य से, इस प्रदेश का सफल दौरा किया और एक स्थानीय तानू नेता, प्रतीकात्मक नेता के रूप में उभरा और अंत में विरोध आंदोलनों से नाम कमाया। अन्य स्थानों पर भी तानू ने अन्य दलों तथा विरोध आंदोलनों का मीमित संचालन किया। उदाहरण के लिए, वैंस्टलैक प्रांत में राष्ट्रवादी आंदोलन, आदिवासी दलों और काफी उत्पादकों की सहकारिताओं के बीच आपसी संपर्क से चला।⁶⁶

गिनी में पार्टी डेमोक्रेटिक दि गिनी (पी० डी० जी०) ने जिस राष्ट्रवादी आंदोलन को चलाया उसके लिए जनसहयोग और नेता औद्योगिक श्रमिक वर्ग में प्राप्त हुए। पी० डी० जी० नेता सेकुतूरे ने, जो मजदूर संगठन का नेतृत्व करके प्रसिद्ध हुए थे, एक उग्र मजदूर संगठन के आधार के साथ राष्ट्रवादी आंदोलन को जोड़ा। सूडान में (आजकल माली) यूनियन सूडानेज संगठन विभिन्न मजदूर संघों, नाईजर नदी पर व्यापार करने वाले वर्ग, और उसके विशिष्ट व्यक्तियों, तथा टिबकटू के शासक परिवार हैदारा जैसे परंपरावादी विशिष्ट वर्ग के आपसी संपर्कों में बना।⁶⁷ अल्जीरिया में फ्रंट दि लिबरेशन नेशनल ने शहरी श्रमिक आंदोलनों, किसान विद्रोहों और सुधारवादी इस्लाम की विभिन्न शाखाओं के बीच संपर्क स्थापित किया।⁶⁸

आमतौर पर राष्ट्रवादी विशिष्ट वर्ग ही किसी आंदोलन में एकता का सूत्र बनते थे और अपने सामाजिक संपर्कों के कारण अलग अलग विरोध आंदोलनों, और विभिन्न दलों को, एक मंच पर लाते थे। जैसा उदाहरणों से स्पष्ट होता है, विभिन्न आंदोलनों में जिन परस्पर संपर्क वाले दलों और विरोध प्रदर्शनों को शामिल किया गया, वे भी भिन्न भिन्न प्रकार के थे। यही बात सामान्यतः किसी एक आंदोलन के बारे में भी लागू होती है, जैसा टांगानिका के उदाहरण से स्पष्ट है।

किसी भी राष्ट्रवादी आंदोलन का स्वरूप किसी देश के अलग अलग भागों में बहुत ही भिन्न हो सकता है। भारत में 1920-1921 में गांधीजी के पहले अमहयोग आंदोलन के दौरान पंजाब का आंदोलन एक इस्लामी और एक मिस्त्र, दो धार्मिक सुधारवादी आंदोलनों का संयुक्त रूप था। इनके साथ मिलने वाला राष्ट्रवादी शहरी विरोध दल तो वास्तव में बहुत ही छोटा था।⁶⁹ इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन में, शहरी राष्ट्रवादी विरोध दल और स्थानीय किसान आंदोलनों की मिलीजुली शक्ति थी।

इस संपर्क प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी एक क्षेत्र के अंदर अलग अलग जन-

समाहित राष्ट्रवादी संगठनों ने अलग अलग स्वरूप के राष्ट्रवादी आंदोलनों को जन्म दिया। सियेरा लियोने में विभिन्न पार्टियों ने न केवल अलग अलग जातीय दलों को, बल्कि विभिन्न सामाजिक दलों को भी अपने साथ शामिल किया। सियेरा लियोने पीपुल्स पार्टी का बहुत सी नवपरंपरावादी आदिवासी एसोसिएशनों के साथ घनिष्ठ संपर्क था।⁷⁰ अत्यंत क्रांतिकारी राष्ट्रवादी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी और पीपुल्स नेशनल पार्टी, दोनों ने मिलकर कई आर्थिक और राजनीतिक विरोध आंदोलनों को तीव्र बनाया। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी के अधिकांश सदस्य 1955-56 में कर के मामले को लेकर हुए दंगों के दौरान बने। उन दिनों पार्टी के नेता ने कर के विरोध में दंगे करने वाले हजारों व्यक्तियों को अपनी कानूनी सेवाएं मुफ्त दी।⁷¹

राष्ट्रवाद एक राजनीतिक विचार : टिप्पणी

राष्ट्रवादी आंदोलनों के अलग अलग स्वरूप को देखते हुए यह सवाल उठता है कि आखिरकार इस अंतर का मूल कारण क्या है। न तो राष्ट्रवादी विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलन चलाने का फैसला, और न ही आंदोलन में भाग लेने वालों की संख्या, कोई ऐतिहासिक अनिवार्यताएं हैं। केवल श्रीलंका ही एक ऐसा उदाहरण है जहां राष्ट्रवादी आंदोलन में विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति ही ज्यादा थे।⁷² आमतौर पर राष्ट्रवादी आंदोलनों के बीच अंतर इस बात को दर्शाता है कि राष्ट्रवादी विशिष्ट व्यक्तियों ने सोच समझकर एक तो यह फैसला किया है कि उनकी मांगें केवल तुरंत पूर्ण स्वाधीनता दिए जाने से ही मुलज्ज सकती हैं, और दूसरे यह कि स्वाधीनताप्राप्ति के इस प्रयत्न के लिए कुछ एक साथी ही उचित हैं।

जैसाकि पहले कहा जा चुका है, राष्ट्रवाद के बारे में आधुनिक मत यह है कि राष्ट्रवाद कुछ तरह के सामाजिक परिवर्तन से उपजी कुछ मान्यताओं का रूप है। इसीलिए राष्ट्रवाद का अध्ययन करने वालों ने राष्ट्रवाद कही जाने वाली भावना का मूल कारण पता लगाने के प्रयत्न किए हैं। यह मूल कारण अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए हैं। एक प्रमुख विद्वान ने कहा है, किसी एक राष्ट्रवाद के कार्यक्रम, 'सहपर-स्थितिया' हैं क्योंकि ऐसे कार्यक्रम इतिहास की कुछ निश्चित परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं।

इसके विपरीत, यदि यह तर्क दिया जाए, जो कि दिया जाता है, कि राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवादी आंदोलन समानार्थक नहीं हैं, और राष्ट्रवादी आंदोलन वास्तव में राष्ट्रवादी विशिष्ट वर्ग द्वारा सोच समझकर चलाए गए अभियान हैं, तो यह तर्क भी दिया जा सकता है कि ऐसे आंदोलन, इनको चलाने वालों के इरादों और लक्ष्यों,

जो सबकी सहमति और असहमति दोनों से तय हो सकते हैं, को दशति है। चूँकि राष्ट्रवादी आंदोलन का अर्थ राष्ट्रवाद की भावना को उभारा जाना ही नहीं है, इसलिए उस जन समुदाय की भावनाओं और प्रकृति तथा आचार विचार को समझना जरूरी है, जिसमें राष्ट्रवादी विशिष्ट वर्ग अपना आंदोलन चलाना चाहते हैं। कुछ अंश तक तो जन समाज के सवाल का जवाब, इतिहास, और समाजविज्ञान देता है। प्रश्न, 'हम कौन हैं?' का उत्तर आंशिक रूप से मिलता है इतिहास के अनुभवों और समानजातीय बंधनों के संदर्भ में। लेकिन 'हम कौन हैं' का जवाब राजनीतिक संदर्भों में भी मिल सकता है, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए क्या क्या नीतियां आदि ठीक होंगी। राष्ट्रवादी नेता सिर्फ आधुनिक युग की आवश्यकताओं को जोर शोर से नहीं बताते बल्कि वे यह आवाज भी बुलंद करते हैं, कि समुचित राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो। इसी के आधार पर वे अपने लक्ष्यों तथा कार्यों का चुनाव करते हैं।

इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रवादी विशिष्ट व्यक्ति, कोई दार्शनिक है, या कुछ निश्चित विचारधाराएं सारे राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए समान रूप से उचित हैं। इसके बजाय यह कहा जा रहा है कि कुछ एक विशिष्ट व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं, उनका कारण चाहे जो भी रहा हो, राष्ट्रवादी आंदोलन के निर्माण के लिए आधार बनी हैं, और इस आंदोलन को वैध नीतियों तथा ध्येयों और उचित साधियों के संदर्भ में देखा जाता है।⁷⁴ ये महत्वाकांक्षाएं हैं समाजीकरण, मंडातिक विचारधारा, तनाव, आर्थिक हित, और सुरक्षा। यही बातें, राष्ट्रवादी विशिष्ट वर्गों के बीच मतभेदों को समझने में सहायक होती हैं।

निष्कर्ष

इस अध्याय के प्रारंभ में एक विरोधाभास की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था। यह था अल्पविकसित राज्यों की समकालीन राजनीति का अध्ययन करने वालों, और राष्ट्रवादी युग का अध्ययन करने वालों के मतों की भिन्नता। पहले वर्ग के विद्वानों का जोर क्षेत्रवाद बने रहने के बारे में है, और राष्ट्रवादी युग का अध्ययन करने वालों का विचार है कि प्रमुख विशेषता यही है कि संकीर्ण क्षेत्रवाद का अंत इसी युग में हुआ। इस नए मत के मामले पहले मत को समझ पाना लगभग असंभव हो गया है। इस विरोधाभास से पार पाने का एक प्रयत्न यह रहा है कि हाल तक राष्ट्रवादी मंगठनों की जिस कमजोरी पर ध्यान नहीं दिया गया था अब उसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यह कमजोरी, स्वाधीनता के बाद भी बनी हुई है, और तब तक रहेगी जब तक कि आधुनिकीकरण की शक्तियां काबू में बाहर नहीं हो जानी। समाज में आधुनिकीकरण लाने वाले

तत्वों के बह जाने से जो रिक्तता आती है उसमें स्थिरता टूट जाती है और परंपरावाद फिर उभरता है।

इस बात में सचाई तो है लेकिन साथ ही राष्ट्रवादी आंदोलन के स्वरूप पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। राष्ट्रवादी आंदोलन राष्ट्रवाद और विशिष्टतावाद के परस्पर विरोधी दलों का संगठित रूप है जिसमें विरोध के लिए एक कच्ची पक्की एकता ही नजर आती है। स्वाधीनता के बाद, परंपरावाद का उभरना इतनी बड़ी समस्या नहीं है, जितनी एकता के नए स्रोत खोजने के कार्य में राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों की अस्तमर्षता।

संदर्भ

1. देखिए विशेष रूप से, कार्ल्टन हेज . नेशनलिज्म ए रेलिजन (न्यूयार्क: मैकमिलन, 1960) और हैन्स कोहन . दि एज आफ नेशनलिज्म . दि फस्ट इरा आफ ग्लोबल हिस्ट्री (न्यूयार्क: हापर एंड सो, 1962)
2. इसका अर्थ यह नहीं है कि भावनात्मक पक्ष पर बल नहीं दिया गया. उदाहरण के लिए हैन्स कोहन ने लिखा है कि राष्ट्रवाद 'किसी अन्य बात से अधिक एक मानसिक स्थिति है।' देखिए कोहन : नेशनलिज्म : इट्स भीनिंग ऐंड हिस्ट्री (प्रिस्टन . वान नोस्ट्राद, 1965), पृ० 9.
3. कार्ल डब्ल्यू० डायश : नेशनलिज्म ऐंड सोशल कम्प्यूनिकेशन (न्यूयार्क: एंड कैब्रिज : एम० आई० टी० ऐंड जान वाईली ऐंड सन, 1953), पृ० 16
4. यह मन सबसे अधिक कार्ल डायश के लेखों में है.
5. वही, पृ० 97.
6. वही, अध्याय 4.
7. वही, अध्याय 8.
8. देखिए, उदाहरण के लिए कोहन : नेशनलिज्म, पृ० 10.
9. राट्टे एमसन : फ्रान एगामर टु नेशन (बोस्टन : बेकन प्रेस, 1960), पृ० 188.
10. कार्ल डब्ल्यू डायश . 'सोशल मोबिलाइजेशन ऐंड पालिटिकल डेवलपमेंट, अमरीकन पालिटिकल सायन रिब्यू, LV, 3 (1961), 494.
11. जैम्स एम० कोलमैन : 'नेशनलिज्म इन ट्रांसिजल अफ्रीका', अमरीकन पालिटिकल सायन रिब्यू, XLVIII, 2 (1954), 404-426
12. डेनियल सनर : दि पार्सिप आफ ट्रेडीशनल सोसायटी (न्यूयार्क : फ्री प्रेस, 1958), विशेषकर पृ० 43-75.
13. मार्टिन विन्सन, जूनियर : 'नेशनलिज्म ऐंड सोशल क्लासेज इन ट्रिटिश वेस्ट अफ्रीका', जर्नेल आफ पालिटिक्स, XX, 2 (1958), 368-409.
14. मूनियन पाई : 'पालिटिक्स, परमैनेन्टिटी ऐंड नेशन विन्डिंग' (न्यू हैवन : येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1962) पृ० 4.

15. बिलफर्ड गोल्स : 'आइडियालाजी ऐज ए कल्चरल सिस्टम', डेविड ई० ऐंटर (संपादित) : आइडियालाजी ऐंड डिस्कटेंट (न्यूयार्क : फ्री प्रेस, 1964), पृ० 54
16. कोलमन, पृ० 404.
17. गोपाल कृष्ण : 'दि डेवलपमेंट आफ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐज ए मास अगंताइजेशन', जर्नल आफ एशियन स्टडीज, XXV, 3 (1966), 413-430, में इन सुधारों और उनके प्रभाव के बारे में काफी विस्तार में लिखा गया है
18. डेनिम आस्टिन : पालिटिक्स इन घाना, 1946-1960 (लंदन आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1970), पृ० 13-14.
19. राबर्ट निम्बेट : कम्युनिटी ऐंड पावर (न्यूयार्क आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1962) पृ० 164.
20. ब्राफोर्ड यंग : पालिटिक्स इन कांगो (प्रिन्स्टन : प्रिन्स्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1965), पृ० 281.
21. किल्सन : पृ० 385 औपनिवेशिक सरकार की ओर में नीति संबंधी विरोधाभास का उत्तम अध्ययन मिलेगा, ब्रिटन मार्टिन जूनियर : न्यू इंडिया, 1885 (बर्कले ऐंड लाम एजिल्स यूनिवर्सिटी आफ कैलीफोर्निया प्रेस, 1969) में
22. अफ्रीका में एसोसिएशनो की गतिविधियों के बारे में श्रेष्ठ परिचय के लिए देखिए, टामस हाजकिन : नेशनलिज्म इन कालोनियल अफ्रीका, (न्यूयार्क न्यूयार्क यूनिवर्सिटी प्रेस, 1957) पृ० 84-92
23. जी० ऐंड्रू मैग्वायर : टुवांड 'उडुरु' इन तंजानिया (कैम्ब्रिज, इंग्लैंड : कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 1969), पृ० 63-75
24. देखिए विभिन्न देशों के अध्ययन के बारे में, इसी अध्याय में.
25. यह आधार है, इस तर्क का कि राष्ट्रवाद अमरता की भावना की प्रतिबिम्ब है, इसे पहने बताया जा चुका है.
26. अनिल सियाल : दि इमर्जेंस आफ इंडियन नेशनलिज्म, (कैम्ब्रिज इंग्लैंड : कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1968), पृ० 15-16.
27. ज्याजिस बैलैंडियर : दि सोशयोलोजी आफ ब्लैक अफ्रीका (न्यूयार्क : फ्री प्रेस, 1970), पृ० 388.
28. विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों द्वारा भारत में जातियों पर आधारित संस्थाएं बनाने के बारे में अध्ययन के लिए देखिए, लायड आई० रुडोल्फ और मूसन होवर रुडोल्फ : दि माडर्निटी आफ ट्रेडीशन (शिकागो : यूनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस, 1967), भाग 1, इन संस्थाओं के बारे में मसूमन्विच टिप्पणी, पृ० 62-63 के नीचे देखी जा सकती है.
29. मैग्वायर, पृ० 75-76.
30. रुडोल्फ ऐंड रुडोल्फ, पृ० 36-64.
31. उदाहरण के लिए देखिए, डब्ल्यू० एम० बारेन : 'अर्देन ग्विल सेजेज ऐंड दि नाइजीरियन ट्रेड यूनिनन मूवमेंट, 1939-1960', इकानामिक डेवलपमेंट ऐंड मन्चरल चेंज, 15 (1966), पृ० 21-36
32. रिचर्ड मिमन : दि कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान, (बर्कले ऐंड लाम एजिल्स यूनिवर्सिटी आफ कैलीफोर्निया प्रेस, 1972), पृ० 48

33. एरिक आर० बुल्फ. 'आन पेजेंट रिदेतिंग्स', इंटरनेशनल सोशल सायंस जर्नल, XXI, 2 (1969), पृ० 287.
34. एरिक आर० बुल्फ. पेजेंट वास आफ दि ट्वेंटीथ सेंचुरी, (न्यूयार्क: हार्पर एंड सो, 1969), पृ० 279.
35. जेम्स सी० स्काट - पैट्रन - बलायट पालिटिक्स ऐंड पालिटिकल चेंज इन साउथ ईस्ट एशिया, अमरीकन पालिटिकल सायंस रिव्यू, LXXVI, 1 (1972), 108.
36. एरिक एव० जैकोबी एग्सेरियन अनरेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया, (न्यूयार्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1949), पृ० 21.
37. बुल्फ. पेजेंट वास, पृ० 295
38. देखिए, वाटर हाजर. एग्सेरियन मूवमेंट्स इन इंडिया (पुस्तक आ रही है) इन संगठनों को बहुत सी गतिविधियों का स्पष्ट संवेक्षण
39. बंगल सडक्वेर. बाटू प्राफेक्ट्स इन साऊथ अफ्रीका, दूसरा संस्करण, (न्यूयार्क, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1961). कुछ निश्चित आंदोलनों के अध्ययन के लिए देखिए, राबर्ट सी० मिचेल, 'रिलिजियस प्रोटेस्ट ऐंड सोशल चेंज: दि ओरिजिनस आफ अलाइड मूवमेंट इन वेस्टर्न नाट-जोरिया', राबर्ट आर्न रोडबर्ग एंड अली ए० मजार्ई, (संपादित): प्रोटेस्ट ऐंड पावर इन ब्लैक अफ्रीका (न्यूयार्क: आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1970); जेम्स डब्ल्यू० फ्लडिंग: 'दि एफ-मैगन आफ थियम पास्ट अलार् आयोर्ग ऐंड थ्योरी ऐंड मूवमेंट्स आफ प्रोटेस्ट इन सेंट्रल ऐंड नाईन बेंबाव', टामस हाजकिन: नेशनलिज्म ऐंड कालोनियल अफ्रीका, (संजन: आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1956); जार्ज शेपसन: 'ईथियोपियनिज्म ऐंड अफ्रीकन नेशनलिज्म', फाइलान, (14, मार्च 1953), 9-19 और 'दि पालिटिक्स आफ अफ्रीकन चर्च सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इन ब्रिटिश सेंट्रल अफ्रीका, 1892-1916', अफ्रीका, XXIV (जुलाई 1954), 233-237; और माइकेल बैटन: 'अफ्रीकन प्राफेक्ट्स', रेस, V, 2 (अक्टूबर 1963) 42-55
40. आर्य समाज संबंधी अध्ययन के लिए देखिए, केन्थेड जॉन: 'दि आर्य समाज इन पंजाब, 1880-1902', (पी-एच० डी० की थीसिस, यूनिवर्सिटी आफ कैंटीफोनिया, बर्कले, 1965); दलित एशिया में मुस्लिम पुनरुत्थान संबंधी सामग्री के लिए देखिए, अजीज अहमद: इस्लामिक माडर्निज्म इन इंडिया ऐंड पाकिस्तान (संजन: आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1967).
41. पृ० 254.
42. मद्रास समितियों का अध्ययन करने के बाद एक पुस्तक ऐसी लिखी गई है जिसके शीर्षक में अधिक व्यापक, सैदानिक बातें हमके अंदर हैं. देखिए आर्यर डारविन: दि रोस आफ एग्सेरियन कोआपरेटिव्स इन दि डेवेलपमेंट आफ कीनिया, स्टडीज इन कोपरेटिव इंटरनेशनल डेवेलपमेंट, V, 1969-70 नंबर-6
43. एम० ए० एन० न्याय: 'प्राक्नेस आफ गवियन कोआपरेटिव्स' (एम० ए० की थीसिस, यूनिवर्सिटी आफ बर्नोनिया, 1971), पृ० 14-26.
44. गेवायर, पृ० 109-110.
45. वही, पृ० 109
46. मरदाक-सर्गाथन मध्य को दो ऐसे व्यक्तियों के बीच द्विपक्षीय आधार पर दोस्ती का विरोध, उदाहरण कहा या मचना है जिसमें सामाजिक आर्थिक दृष्टि से ऊंचे दर्जे का व्यक्ति (मरदाक),

अपने प्रभाव और साधनों से, एक अन्य निचले दर्जे के व्यक्ति (संरक्षित) को सुरक्षा या लाभ, या दोनों ही प्रदान करता है जिनके बदले में निचले दर्जे वाला व्यक्ति अपने संरक्षक को सामान्य समर्थन, सहायता, और व्यक्तिगत सेवाएं देता है ऐसे संबंधों के बारे में विशेष रूप से देखिए, जार्ज एम० फोस्टर : 'डायेटिक कार्टूकट इन त्सिसुंस्तान · पैट्रन-क्लायट रिनेशनशिप' अमरीकन एथोपोलाजिस्ट, LXV (1963), 1280-1294; एरिक वुफ : 'किनशिप, फीडशिप एंड पैट्रन-क्लायट रिनेशन', माइकेल वैंटन (संपादित) : दि सोशल एथोपोलाजी आफ कान्पेक्स सोमायटीज, एसोमिएशन आफ ऐप्लाइड सोशल एथोपोलाजी मोनोग्राफ 4 (लंदन टैविस्टाक पब्लिकेशन, 1966) पृ० 1-22 : जान डकन पावेल · 'पेजेंट सोसायटी एंड क्लायंटेलिस्ट पालिटिक्स', अमरीकन पोलिटिकल सायम रिव्यू, LXIV, 2 (1970), 411-425; रैने सैमरचंद : 'पालिटिकल क्लायंटलिज्म एंड एथनिमिटी इन ट्रापिकल अफ्रीका : कपीटिंग सोलो-डेरिटीज इन नेशन बिल्डिंग', अमरीकन पालिटिकल सायम रिव्यू LXVI, 1 (1972), 68-90; और स्काट.

47. सैमरचंद, पृ० 80.
48. कांग्रेस के विशिष्ट व्यक्तियों की ओर से उनके कार्यों के विस्तार के श्रेष्ठ अध्ययन के लिए देखिए [चार्ल्स हार्डिसाथ : इंडियन नेशनलिज्म एंड हिंदू सोशल रिफार्म (प्रिस्टन : यूनिवर्सिटी प्रेस, 1964)].
49. इन विभाजनों के बारे में देखिए डेनियल आरगोव : माइरेट्स एंड एक्स्ट्रीमिस्ट्स इन दि नेशनलिस्ट मुवमेंट (बंबई : एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1967).
50. यह अधिकांश भाग कृप्य से उद्धृत किया गया है.
51. ऐरिस्टिड जोलबर्ग : वन पार्टी गवर्नमेंट इन दि आइवरी कोस्ट (प्रिस्टन : प्रिस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1964) पृ० 113.
52. वही, पृष्ठ 116.
53. अन्य जनसमर्थन वाली पार्टियों के बारे में मामूरी के लिए, देखिए उदाहरणार्थ टेविड ई० ऐप्टर : घाना इन ट्रांजिशन (न्यूयार्क : ऐथेनियम, 1963); लास रूडवैक : पार्टी एंड पीपुल : ए स्टडी आफ पालिटिकल चेंज इन टर्निसिया (न्यूयार्क . फ्रेडरिक ए प्रेंजर, 1968); रिचर्ड एल० स्कलार, नाइजीरियन पालिटिकल पार्टीज (प्रिस्टन : प्रिस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1963); और जॉन कैंडी : ए हिस्ट्री आफ माइने बर्मा (ईथाका : कारनेल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1958).
54. ऐरिस्टिड जोलबर्ग : क्विंटिंग पालिटिकल आर्डर : दि पार्टी स्टेट्स आफ वेस्ट अफ्रीका (शिवागो रीच. मॅकनेली एंड कंपनी, 1966), पृ० 15
55. वही, पृ० 19-36.
56. वही, पृ० 13.
57. जोलबर्ग : वन पार्टी गवर्नमेंट इन दि आइवरी कोस्ट, पृ० 116
58. संगठनात्मक स्वरूप के सिद्धान्त के बारे में देखिए प्रथम अध्याय का संदर्भ सध्या 2.
59. 'भूमिका' की परिभाषा इन शब्दों में दी जा सकती है : किसी एक प्रणाली में निश्चित पदों पर आसक्त व्यक्तियों का अपेक्षित आचरण.
60. संगठनात्मक 'स्वायत्तता' की परिभाषा इन प्रकार हो सकती है : किसी एक संगठन की अपनी भूमिकाएँ, मानदंड, मूल्य और उद्देश्य किसी अन्य इन अपवा सम्पा की अवस्था बिना भिन्न हैं. इन संबंध में देखिए हटिंगटन, पृ० 20-22.

61. 'दो मैमरचद 'पेट्रिम मुमुबा', इन्फ्यू. ए. ई. ग्युनिक (मगादिन) : अरोहन पानिटिवन माट मुमुबा, एन्नुमा, एंड नूर; प्रेरणाट म्बुन भाक इटरेनेशनल स्टडीज, मोनोग्राफ, खड (पाच, नवर मॉन और चार, 1967-68 (ईनवर, कांपरिया : युनिवर्सिटी आफ ईनवर 1968)
62. मैवापर पृष्ठ 83, 86-88
63. बही, पृ. 136
64. उदाहरण के लिए 'देशिए, पान ब्राग पैंगनन पानोटिवम इन ऐन इंडियन स्टेट (बॉन्डे ऐंड नाम एजिलम युनिवर्सिटी आफ कॅनोकोनिया प्रेम, 1965); होनाट भी रोमेनयान : दि निमिटेड एनीट (जिवापो युनिवर्सिटी आफ जिवापो प्रेम, 1970); और भार. विविध निहल एथनीमिटी, पार्टी ऐंड नेशनल इटीपेगन ऐन इंडोनेशियन बेग स्टडी (न्यू हेवन : येन युनिवर्सिटी प्रेम, 1970)
65. मैवापर, पृ. 196-212
66. गोरल हार्डइन पानिटिवन रेकनरमेट इन करन मजानिया (नैरोबी : ईस्ट अरीरा पानिगम हाउस, 1969), पृ. 125-140
67. बही पृ. 31, और ऐन्टिरीड जोनबगं. 'पानिटिवन रिवाइवन इन मात्री', अकीरा रिपॉर्ट, 10, 7 (1965), 18.
68. अन्जीरिया के मरुध में देशिए विविधम बी क्वाट्ट : रिवायुगन ऐंड पानिटिकल सांडरगिा : अन्जीरिया, 1954-1968 (कॅब्रिज, मैगायुमेट्म . एम. आई. टी. प्रेम, 1969).
69. देशिए जैरुड ए. डीगर 'दि पानिटिवम आफ इटीपेगन : कम्प्युटी, पार्टी ऐंड इटीपेगन इन पंजाब' (पॅग-एच. डी. पीगिंग, युनिवर्सिटी आफ जिवापो, 1971), पृ. 16-19.
70. माटिन विनमन पानिटिकल चेंज इन ए वेस्ट अरीरन स्टेट (कॅब्रिज, मैगायुमेट्म : हार्वर्ड युनिवर्सिटी प्रेम, 1966), पृ. 219-265.
71. बही, पृ. 237
72. देशिए इन्फ्यू. हार्वर्ड रिगिम मिलोन. हावनेमात्र आफ ए न्यू नेशन (मिस्टन, मिस्टन युनिवर्सिटी प्रेम, 1960); और कालविन ए. ब्रुवर्ड 'दि घोष आफ दि पार्टी मिस्टम इन मिलोन (प्रोवोइंस. ब्राउन युनिवर्सिटी प्रेम, 1969).
73. नियोनाडे बिडर. दि आइडियोलॉजीकल रिवायुगन इन दि मिडिल ईस्ट (न्यूयार्क : जान वार्डनो ऐंड सन, 1964), पृ. 109.
74. हम तर्क के लिए कि आर्थिक द्विज ही राष्ट्रवाद का आधार है, देशिए विनमन : 'नेशनलिज्म ऐंड सोशल क्लेमिंग'. 'तनाव' और 'अगुरुता' की भूमिका के बारे में तर्क के लिए देशिए गोर्नर्स; पाई, और चार्ल्स एफ. गेंडरेल : 'दि पानिटिकल पाट आफ मेगनूरे', स्तुरनिक (मगादिन), पृ. 129-136

राजनीतिक स्थिरता की खोज

स्वाधीनता मिलने पर राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं के लिए प्रबंध का सफ़ट उठ खड़ा होता है। उन्हें न केवल अपने और नवोदित राज्य के लिए नए ध्येय तैयार करने होते हैं बल्कि उन्हें प्राप्त करने के लिए साधन भी जुटाने होते हैं। अब चूंकि हर एक की अलग अलग पसंद-नापसंद होती है इसलिए विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को आपस में ही, और अन्य वर्गों के साथ, कुछ हद तक राजनीतिक समेकन (कंसालिडेशन) उत्पन्न करना होता है। राजनीतिक दृढ़ता अथवा एकता की तीन प्रमुख आवश्यकताएं हैं : विभिन्न राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों के बीच एकता, विशिष्ट व्यक्तियों की समान पसंद को जनता की मान्यता, और चूंकि विक्रम के ध्येय प्राप्त करने के लिए जनता की मान्यता ही काफी नहीं है इसलिए जनसमर्थन भी होना चाहिए।

जिस समय स्वाधीनता प्राप्त होती है उस समय ये तीन मूल आवश्यकताएं विद्यमान नहीं होती। उस समय तो राष्ट्रवादी युग के समय की तीव्र राजनीतिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप विभिन्न मतों वाले विशिष्ट व्यक्तियों और उनके अनुयायियों के बीच एक प्रकार का मतैक्य ही होता है। जिन अर्थों में समाज के केंद्र और परिधि की बात की जाती है उस तरह का केंद्र, राष्ट्रवादी आंदोलन में लगभग अस्तित्वविहीन होता है।¹ आंदोलन के लिए बनाए गए ध्येय और प्रतीक उतने ही भिन्न होते हैं जितना कि स्वयं आंदोलन।

राजनीतिक दृढ़ता लाने की समस्या का सबसे पहले अध्ययन करने वाले राजनीतिशास्त्रियों को लगभग स्वाभाविक रूप में ही मौंडांतिक विचारधारा, करिश्मा अथवा

चमत्कार, और राजनीतिक पार्टियों को, दृढ़ता प्राप्त का माध्यम मानना पड़ा। हम 'लगभग स्वाभाविक रूप से' शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो केवल इसलिए नहीं कि इन राज्यों के नेता स्वयं भी सैद्धांतिक विचारधारा, राजनीतिक पार्टियों और अपने व्यक्तिगत गुणों पर बल देते थे, बल्कि इसलिए भी कि एक मायने में ये सभी बातें पश्चिमी देशों की नजर में सबसे ज्यादा थीं। तभी तो चमत्कारी नेतृत्व को बहुत से जनसमूहों का साक्षात् केंद्रबिंदु समझा गया, जबकि प्रारंभिक रूप में इन अलग अलग समूहों अथवा दलों के बीच कोई आपसी संबंध नजर नहीं आता था। एन्क्रूमा, सुकानों, नेहरू, और हुफूए-बीइनी ने वास्तव में राज्य को दृढ़ता प्रदान की।

अपने अनुयायियों के लिए मानदंडों के स्रोत बनकर, समाज के अलग अलग वर्गों के बीच समानता की भावना पैदा करने में सहायक प्रतीक बनकर, नए संस्थात्मक ढांचे में सत्ता का प्रमुख व्यक्ति होने के नाते राजनीतिक एकता का केंद्रबिंदु बनकर और नए क्षेत्र के समुदाय का ऐसा जीवित प्रतीक बनकर जो व्यक्तियों को अपने अपने परंपरागत जातीय दलों के प्रति आस्थाओं से ऊपर उठने का प्रोत्साहन देता था।²

सैद्धांतिक विचारधारा, विशिष्ट व्यक्तियों और साधारण जन के लिए सिद्धांतों की एक समान रूपरेखा प्रस्तुत करती थी।³ पार्टियों की शाखाओं, राजनीतिक पार्टियों, विशेषकर चमत्कारी और प्रभावशाली व्यक्तित्वों वाले नेताओं, और काफी विकसित सैद्धांतिक विचारधाराओं वाली पार्टियों के रूप में एकता के नए दलों की स्थापना से आम जनता की सहमति और समर्थन प्राप्त करने के माध्यम तैयार हुए।

हाल की घटनाओं से यह स्पष्ट हुआ है कि ये सभी सैद्धांतिक धारणाएं राजनीतिक एकता तथा दृढ़ता की प्राप्ति से संबद्ध समस्याओं को जन साधारण तक पहुंचाने की सीमित क्षमता रखती हैं। चमत्कारी प्रभाव जहां कहीं था अल्पकालिक सिद्ध हुआ और जैसा डेविड ऐस्टर ने घाना संबंधी अपने संशोधित अध्ययन में कहा है, एकता लाने की दिशा में यह तनिक भी प्रभावशाली हो सकता है इस विषय में संदेह है।⁴ सैद्धांतिक विचारधारा भी इसी तरह अपनी सीमाओं में बंधी है। जैसा हैनरी बिएनन ने कहा है :

मह मान लेना गलत है कि निश्चित सैद्धांतिक विचारधाराएं सामान्य रूप से उचित हैं; इन्हें कुछ चुने हुए लोग ही अपना सकते हैं जिन्हें पार्टी के अंदर ही सत्ता के केंद्र से भी हटाया जा सकता है। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की यह महत्वाकांक्षा कि वे किसी एक पार्टी के माध्यम से अपने अपने समाज में परिवर्तन

ला सकते हैं महत्वपूर्ण हो भी सकती है और नहीं भी। उनका विचार है कि यह एक ऐसी पार्टी हो जो समाज के सभी वर्गों और सामाजिक पहलुओं तक फैली हो और समाज के साधनों को जुटा सकती हो।⁶

इसके अलावा अल्पविकसित समाजों में राजनीतिक पार्टियों के अध्ययन से राजनीतिक संगठन और दृढ़ता की प्रक्रिया को स्पष्ट करने में सफलता नहीं मिली है। पहले किए गए अध्ययनों में अक्सर यह गलत धारणा व्यक्त की गई है कि राजनीतिक विशिष्ट वर्ग की संगठनात्मक महत्वाकांक्षाएं वास्तव में एक सत्य हैं और इनसे एक ऐसी एकता पैदा होने की बात कही गई जो 'अमल में बहा थी ही नहीं।⁷ बाद के अध्ययनों में हालांकि वास्तविकता को ज्यादा ध्यान में रखा गया फिर भी दृढ़ीकरण की प्रक्रिया में पार्टी की भूमिका पर विशेष बल दिया जाना जारी रहा।

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि नेताओं का चमत्कारिक व्यक्तित्व अथवा करिश्मा, सैद्धांतिक विचारधारा और राजनीतिक पार्टियां, पूरी तरह राजनीतिक एकता लाने की समस्या के हल के लिए काफी नहीं हैं। एक तो, राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों के बीच आपसी गुटबंदी के कारण अल्पविकसित राज्यों में बहुत जल्दी जल्दी अस्थिरता आने लगी जिसपर बहुत टिप्पणियां भी हुईं। दूसरे, इस गुटबंदी का सैद्धांतिक विचारधारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अधिकांश विद्वलेपणकर्ताओं ने विशिष्ट वर्गों और उनकी संभावित क्षमताओं की भिन्नता पर ज्यादा जोर दिया।

राजनीतिक दृढ़ीकरण को, अधिक से अधिक विशिष्ट वर्ग और साधारण जन के बीच एकता की प्रमुख समस्या ही समझा गया। यहाँ भी जो विचार व्यक्त किए गए वे साधारण थे। विशिष्ट वर्ग और साधारण जन के बीच एकता को केन्द्र और बाह्य परिधि के बीच एकमात्र सफल संपर्क के संदर्भ में देखा गया, यानी नेताओं का करिश्मा और पार्टी आदि। इसी बात को यदि दूसरी तरह से कहा जाए तो जहाँ कहीं भी इस तरह के संपर्क विद्यमान थे वहाँ जिस तरह के संबंध स्थापित हुए, उन्हें वास्तविकता से कहीं अधिक औचित्य प्रदान किया गया। इन संपर्कों के वास्तव में एक से अधिक होने, और उनके संभावित परस्पर विरोध को या तो देखा नहीं गया, या वे नजर ही नहीं आए। हाल में तथाकथित एकस्तंभीय राजनीतिक पार्टियों के संशोधनवादो अध्ययनों को इस आलोचना से मुक्ति नहीं दी जा सकती। एक ओर तो इन अध्ययनों में केन्द्र और बाह्य परिधि के बीच एकता की काफी कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, दूसरी ओर, एक ही व्यवस्था, इस मामले में एक राजनीतिक पार्टी व्यवस्था, के विकास के संपर्क में राजनीतिक एकता पर विशेष ध्यान दिया गया है।⁸

यह महत्त्वपूर्ण दिया जाएगा कि नई राजनीतिक प्रणालियों के अलग अलग खंडों में विभाजित होने के कारण किसी भी शासन की—चाहे वह किसी भी प्रकार का हो या मताधारी विशिष्ट व्यक्तियों के किसी एक गुट की कोई भी महत्वाकांक्षा क्यों न हो—की उम राजनीतिक प्रणाली को सुदृढ़ करने की क्षमता सीमित हो जाती है। जैसा पहले कहा गया है, विकसित राज्यों में राजनीतिक प्रक्रिया, विशिष्ट वर्गों के एक दूसरे के साथ सहमत होने के प्रयत्नों पर आधारित होती है जिसमें राजनीतिक केंद्र में राष्ट्रीय संस्थाएं बन सकें और इनके लिए मजाल का समर्थन जुटाया जा सके। इस प्रक्रिया में जो संस्थाएं उभरती हैं उनकी विशेषता यह है कि अधःस्वायत्त विशिष्ट वर्गों और स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों के दलों के बीच गठबंधन रहते हैं।

राजनीतिक स्वाधीनता के आने से राजनीति के संचालन का संदर्भ ही आमूल रूप से परिवर्तित हो जाता है। स्वाधीनता के साथ, कम से कम सिद्धांत रूप में तो, केंद्र सरकार और राजनीतिक मन्त्रियों के एक राजनीतिक केंद्र की व्यवस्था होनी है, यह औपनिवेशिक युग के दौरान स्थापित राजनीतिक संगठनों की देन और नए नेताओं के सतत प्रयत्नों से होता है। इन संस्थाओं के बीच नीतियों पर आधारित राजनीतिक भूमिकाएं और उन्हें निभाने के नियम निर्धारित किए जाते हैं।

इस संदर्भ में राष्ट्रवादी आंदोलन की खंडों में विभाजित होने की वृत्ति बदल जाती है। ये विभिन्न खंड विन्तुलन सम्पाप्त तो नहीं हो जाते, पर नई प्रणाली में, नए राजनीतिक केंद्र के भीतर विभिन्न नीतियों पर आधारित राजनीतिक भूमिकाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए राजनीतिक खींचताती शुरू हो जाती है। नई नीतियों पर आधारित राजनीतिक भूमिकाओं तक पहुंचने और उनपर नियंत्रण प्राप्त करने से नीति निर्धारण के काम में हिस्सेदार बनने का मौका मिलता है, और शायद इससे भी ज्यादा महत्व की बात यह है कि सरकार को होने वाले प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभों के वितरण में भी भागीदारी मिलती है। वरिष्ठ सरकारी और राजनीतिक पदों पर नियंत्रण होने में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की व्यवस्था पर भी नियंत्रण हो जाता है; जैसे अनुपलब्ध साधनों के बंटवारे का काम, उदाहरण के लिए व्यापारिक साईंस, सरकारी ऋण और नोटियां। इसके अलावा इस बात पर भी नियंत्रण हो जाता है कि सरकार किमी निश्चिन्त दल और उनकी मांगों को कहां तक पूरा करेगी। 'विरोध आंदोलनों के संचालक' में बदलकर राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रीय शक्ति में नई भूमिकाओं में उभरते हैं जिनमें विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति और अन्य दल प्रभुत्व पाने के लिए एक दूसरे में होंड़ लगाते हैं और फिर इसी प्रभुत्व के माध्यम में, सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं।

अल्पविकसित समाजों में सरकार और उसकी शक्ति ही, राजनीतिक संगठनों के मूल और उन्हें बनाए रखने का मूल स्रोत है। यानी एक बार सरकार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है तो जनशक्ति का प्रयोग वास्तव में व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। सत्तारूढ़ विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मिलन का विस्तार प्रतिस्पर्धा में उनके अन्य दलों के मूल्य पर होता है। अल्पविकसित प्रणालियों में राजनीतिक संस्थाएं वास्तव में संस्थाएं नहीं हैं जितनी कि क्षणिक गठबंधनों के लिए एक मुछौटा। सरकारी सत्ता और साधनों पर नियंत्रण में चाहे वे सीमित हों, वे माध्यम प्राप्त हो जाते हैं जिनसे ये संस्थाएं विकसित हो सकती हैं। डराने-धमकाने, फायदा पहुंचाने, संरक्षण प्रदान करने जैसे तरीकों के प्रयोग और सरकार की सीमित वैधता के प्रयोग में ये संस्थाएं (जैसे कि राजनीतिक पार्टियाँ) और इनपर नियंत्रण रखने वाले गठबंधनों का निर्माण तथा विस्तार किया जाता है और अन्य दलों तथा विशिष्ट व्यक्तियों का समर्थन व सहयोग प्राप्त किया जाता है।

सरकार और राजनीतिक पार्टियों जैसे अन्य संस्थाओं के इस आपसी गठबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विद्वानों की वर्तमान धारणाओं के अनुसार राजनीतिक पार्टियाँ सरकारी संस्थाएं होने के अलावा विशेष और अलग वृत्ति वाले संगठन भी हैं।⁸ इस प्रकार की धारणाओं में अल्पविकसित राज्यों की राजनीतिक संस्थाओं की संगठनात्मक कामजोगियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बहुत कम संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनके पास अपने सुचारु संचालन के समुचित साधन हों। जो संगठन एक संस्था प्रतीत होता है वह वास्तव में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के छोटे मोटे गठबंधन में अधिक कुछ नहीं होता, जैसे कोई विपक्षी राजनीतिक पार्टी होनी है। इसके विपरीत, आमतौर पर सरकारी पार्टियाँ ठीक वही होती हैं, जिनका गठन सरकारी सत्ता और व्यवस्था के माध्यम से होता है। यदि ऐसी पार्टियों के हाथ में यह सत्ता और व्यवस्था चली जाए तो वह भी विशिष्ट व्यक्तियों का एक छोटा मोटा दल ही बनकर रह जाएगी।

पार्टियों वाले और बिना पार्टियों वाले राज्यों के बीच तथा राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा शासित और सैनिक या अधिकारीतंत्र के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा शासित राज्यों के बीच, लगभग परंपरागत विभेदों को बढ़ाचढ़ाकर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सत्ता में आने के बाद विशिष्ट वर्ग आपसी गठबंधन में जिम प्रकार के संगठनों का निर्माण करते हैं, उसके संदर्भ में, विभिन्न प्रकार के शासन में भिन्नता हो सकती है। उदाहरण के लिए पार्टी सरकारें अपनी तम परंपरा में ही इस तरह के गठबंधन वाली व्यवस्था पर ध्यान दे सकती हैं; अधिकारी तंत्र की सरकारें यही कार्य नौकरियों की धरोहर में कर सकती हैं आदि।⁹ फिर भी

समाप्त करने की क्षमता प्राप्त हुई। विशिष्ट व्यक्तियों के ऐसे गठबंधन किसी एक पार्टी को श्रेणियों में ही नजर नहीं आते। मोमालिया में तीन राजनीतिक दलों के गठबंधन का प्रभाव सरकार पर था। प्रत्येक दल अलग अलग कबीलों का प्रतिनिधि था। धाईलैंड में सरकारों का गठन राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों के निश्चित गुटों द्वारा किया गया।

संभवतः विभिन्न दलों के सम्मिलन का और अधिक व्यापक आधार एक तरह का पितृवाद (पैट्रिमोनियलिज्म) है जिसमें विशिष्ट वर्गों के लोग एक पुस्तैनी (पैट्रिमोनियल) नेता के आमपाम संगठित हो जाते हैं और उस नेता के व्यक्तिगत गुणों में आस्थाओं, और उसके साथ अपने संबंधों से मिलने वाले भौतिक लाभों के कारण आकृष्ट होते हैं।¹⁴ लाभ यही है कि यह पुस्तैनी नेता विशेष पदों पर अपने चुने हुए अनुयायियों को नियुक्त कर सकता है। जैसा मैक्स वेबर का कहना है :

जिस व्यक्ति का अनुसरण किया जाता है और आज्ञा मानी जाती है उसके अंदर कुछ व्यक्तिगत प्रभाव और सत्ता होती है जो उसे अपने परंपरागत दर्जे से पैतृक निधि के रूप में मिली होती है। जो संगठित दल सत्ता का संचालन करता है वह मूलतः अपने उन व्यक्तिगत आस्थाओं के संबंधों पर आधारित होता है जो शिक्षा की समान प्रक्रिया के माध्यम से बनी होती हैं। जिस व्यक्ति के अंदर सत्ता निहित है वह कोई 'अति श्रेष्ठ' व्यक्ति नहीं है बल्कि अपने अनुयायियों का व्यक्तिगत 'नायक' है। उसके अधीन कार्य करने वाले प्रशासनिक कर्मचारी मुख्य रूप से अधिकारीगण नहीं होते बल्कि उसके परम कृपापात्र व्यक्ति होते हैं। जिन्हें सत्ता के अधिकार दिए जाते हैं वे 'किसी एसोसिएशन के सदस्य' नहीं होते बल्कि या तो उसके पुराने 'साथी' या उससे 'प्रभावित अनुयायी' होते हैं।

अपने नेता या सरदार के साथ उसके प्रशासनिक कर्मचारियों के संबंध, पदों के कर्तव्यों के कारण नहीं, बल्कि उसके प्रति कर्मचारियों की व्यक्तिगत आस्था से बनते हैं।¹⁵

पुस्तैनी विशिष्ट वर्ग के बीच आपसी समन्वय और एकता मोरक्को में स्पष्ट नजर आती है जहाँ की राजनीतिक प्रणाली कई तरह के प्राचीन संबंधों तथा आपसी हितों वाले गुटों में बंटी हुई है और प्रत्येक गुट का अपना ही विशिष्ट व्यक्ति है। मोरक्को के शाह हसन द्वितीय ने विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के साथ कई तरह के समझौतों के माध्यम से राजनीतिक प्रणाली पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न किया है। उन्होंने

दृढ़ता और स्थिरता लाने के लिए सभी सरकारों को गठबंधन की प्रक्रिया का ही सहारा लेना पड़ता है।

राजनीतिक केंद्र का गठन करना

राजनीतिक स्थिति को दृढ़ करने के काम के लिए विशिष्ट व्यक्तियों के बीच काफी आपसी सहमति की जरूरत होती है ताकि सरकार का गठन हो सके। विशिष्ट व्यक्तियों का इस तरह का गठबंधन अत्यंत अस्थायी होता है। हालांकि विभिन्न विशिष्ट व्यक्ति और उनके अनुयायी प्रभावशाली राजनीतिक इकाइयों की स्थापना के लिए आपस में गठबंधन करते हैं, फिर भी वे नई व्यवस्था के अंदर अपना कुछ अलग अस्तित्व बनाए रखने पर जोर देते हैं।

इस तरह की आपसी सहमति और परस्पर समर्थन, अल्पकालिक भौतिक लाभ के लिए विशिष्ट व्यक्ति की लालसा का ही परिणाम हो सकता है। नए राजनीतिक केंद्र में जो सरकारी व्यवस्था स्थापित होती है और जो औपनिवेशिक युग की देन तथा स्वाधीनता से पैदा होती है, वास्तव में विभिन्न स्वीकृतियां प्रदान करने का केंद्र बन जाती है, जैसे नई नौकरियों, ऋणों, आर्थिक सहायता, अनुकूल प्रशासनिक कानून आदि की स्वीकृति। ये सभी काम करने की सामर्थ्य के आकर्षण के कारण ही अलग अलग विशिष्ट वर्गों को एक दूसरे से मिलने की प्रेरणा मिल सकती है।

इस प्रकार के गठबंधन, श्रीलंका और सीयेरा लियोने में नजर आए। श्रीलंका में प्रथम शासक दल, यूनाइटेड नेशनलिस्ट पार्टी का गठन, सिलोन नेशनल कांग्रेस, सिंहला महासभा (सिंहलियों का एक सांप्रदायिक दल), आल सिलोन मुस्लिम लीग, मूमं एसोसिएशन और कई तमिल नेताओं, जैसे अलग अलग संगठनों के विशिष्ट व्यक्ति के गठबंधन से बनी।¹⁰ पार्टी के संविधान में इस बात की अनुमति थी कि शामिल होने वाले अलग अलग दल अपने पृथक संगठन बनाए रख सकते हैं और उन्होंने ऐसा किया भी।¹¹ इस मिलीजुली व्यवस्था को दृढ़ता मिली इस भावना में कि सरकार पर अपना प्रभुत्व जमाया जाए। पार्टी ने 'समर्थन जुटाने और अपने नेताओं तथा विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक वर्गों के बीच एकता स्थापित करने' के लिए सरकारी पदों से प्राप्त सत्ता का उपयोग किया।¹² पार्टी की कार्यसमिति में उन एसोसिएशनों के नेता थे जिन्होंने मिलकर पार्टी की स्थापना की थी। इसी प्रकार सीयेरा लियोने पीपुल्स पार्टी, प्रोटेक्टोरेट के राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों की दो एसोसिएशनों (एक की स्थापना कबीलों के सरदारों ने की थी और दूसरी राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों की थी) से मिलकर बनी थी जिससे प्रोटेक्टोरेट के मददगारों को सीयेरा लियोने की राजनीति पर त्रिव्योद लोगों का प्रभुत्व

समाप्त करने की क्षमता प्राप्त हुई। विशिष्ट व्यक्तियों के ऐसे गठबंधन किसी एक पार्टी की श्रेणियों में ही नजर नहीं आते। सोमालिया में तीन राजनीतिक दलों के गठबंधन का प्रभाव सरकार पर था। प्रत्येक दल अलग अलग कबीलों का प्रतिनिधि था। थाईलैंड में सरकारों का गठन राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों के निश्चित गुटों द्वारा किया गया।

संभवतः विभिन्न दलों के सम्मिलन का और अधिक व्यापक आधार एक तरह का पितृवाद (पैट्रिमोनियलिज्म) है जिसमें विशिष्ट वर्गों के लोग एक पुस्तनी (पैट्रिमोनियल) नेता के आमपाम संगठित हो जाते हैं और उस नेता के व्यक्तिगत गुणों में आस्थाओं, और उसके साथ अपने संबंधों में मिलने वाले भौतिक लाभों के कारण आकृष्ट होते हैं।¹⁴ लाभ यही है कि यह पुस्तनी नेता विशेष पदों पर अपने चुने हुए अनुयायियों को नियुक्त कर सकता है। जैसा मैक्स वेबर का कहना है :

जिस व्यक्ति का अनुसरण किया जाता है और आज्ञा मानी जाती है उसके अंदर कुछ व्यक्तिगत प्रभाव और सत्ता होती है जो उसे अपने परंपरागत दर्जे से पैतृक निधि के रूप में मिली होती है। जो संगठित दल सत्ता का संचालन करता है वह मूलतः अपने उन व्यक्तिगत आस्थाओं के संबंधों पर आधारित होता है जो शिक्षा की समान प्रक्रिया के माध्यम से बनी होती हैं। जिस व्यक्ति के अंदर सत्ता निहित है वह कोई 'अति श्रेष्ठ' व्यक्ति नहीं है बल्कि अपने अनुयायियों का व्यक्तिगत 'नायक' है। उसके अधीन कार्य करने वाले प्रशासनिक कर्मचारी मुख्य रूप से अधिकारीगण नहीं होते बल्कि उसके परम कृपापात्र व्यक्ति होते हैं। जिन्हें सत्ता के अधिकार दिए जाते हैं वे 'किसी एसोसिएशन के सदस्य' नहीं होते बल्कि या तो उसके पुराने 'साथी' या उससे 'प्रभावित अनुयायी' होते हैं।

अपने नेता या सरदार के साथ उसके प्रशासनिक कर्मचारियों के संबंध, पदों के कर्तव्यों के कारण नहीं, बल्कि उसके प्रति कर्मचारियों की व्यक्तिगत आस्था से बनते हैं।¹⁵

पुस्तनी विशिष्ट वर्ग के बीच आपसी समन्वय और एकता मोरक्को में स्पष्ट नजर आती है जहाँ की राजनीतिक प्रणाली कई तरह के प्राचीन संबंधों तथा आपसी हितों वाले गुटों में बंटी हुई है और प्रत्येक गुट का अपना ही विशिष्ट व्यक्ति है। मोरक्को के शाह हसन द्वितीय ने विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के साथ कई तरह के समझौतों के माध्यम से राजनीतिक प्रणाली पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न किया है। उन्होंने

दृढ़ता और स्थिरता ताने के लिए सभी सरकारों को गठबंधन सहारा लेना पड़ता है।

राजनीतिक केंद्र का गठन करना

राजनीतिक स्थिति को दृढ़ करने के काम के लिए विशिष्ट व्यक्ति आपसी सहमति की जरूरत होती है ताकि सरकार का गठन व्यक्तियों का इस तरह का गठबंधन अत्यंत अस्थायी होता विशिष्ट व्यक्ति और उनके अनुयायी प्रभावशाली राजनीतिक लिए आपस में गठबंधन करते हैं, फिर भी वे नई व्यवस्था के अस्तित्व बनाए रखने पर जोर देते हैं।

इस तरह की आपसी सहमति और परस्पर समर्थन, अलग-अलग लिए विशिष्ट व्यक्ति की लालसा का ही परिणाम हो सकता है जो सरकारी व्यवस्था स्थापित होती है और जो आपसी स्वाधीनता में पैदा होती है, वास्तव में विभिन्न स्वीकृतियाँ आती हैं, जैसे नई नौकरियों, ऋणों, आर्थिक सहायता आदि की स्वीकृतियाँ। ये सभी काम करने की सामर्थ्य अलग अलग विशिष्ट वर्गों को एक दूसरे में मिलने की प्रेरणा

इस प्रकार के गठबंधन, श्रीलंका और मीयेरा लियो प्रथम शासक दल, यूनाइटेड नेशनलिस्ट पार्टी का मिहला महामभा (मिहलियों का एक सांप्रदायिक मीग, मूर्म एगोमिगेशन और कई तमिल नेताओं विशिष्ट व्यक्ति के गठबंधन से बनी।¹⁰ पार्टी के भी कि शामिल होने वाले अलग अलग दल अपने और उन्होंने ऐसा किया भी।¹¹ इन मिलीजुली भावना में कि सरकार पर अपना प्रभुत्व जमाया और अपने नेताओं तथा विभिन्न सामाजिक तथा स्थापित करने के लिए सरकारी पदों में प्राप्त मत्ता व इतर संस्थाओं के नेता से जिन्होंने की थी। इसी प्रकार मीयेरा लियोने पीपुल्स पार्टी, विशिष्ट व्यक्तियों की दो एगोमिगेशनों (एक की स्थापना कर थी और दूसरी राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों की भी) में मिल प्रोटेक्टोरेट के सदस्यों को मीयेरा लियोने की राजनीति पर नियंत्रण

पाकिस्तान में अधिकारीतंत्र के राजनीतिज्ञों ने जिन पुस्तकें गुटों का निर्माण किया या उन्होंने ही अंत में 1956 में गण्ट्वादी पार्टी मुस्लिम लीग को विभिन्न खंडों में विभाजित किया।²¹

पितृवाद और सरकार में आने की समान इच्छा के साथ ही, विशिष्ट व्यक्तियों के बीच आपसी एकता के सभावित स्रोत समाप्त नहीं हो जाते। सिद्धांतों के आधार पर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बीच संपर्क बन सकता है। इसी तरह किसी एक पार्टी के मदस्य होने के कारण भी यह संपर्क हो सकता है या फिर दबाव डालकर भी ऐसा हो सकता है। एन्क्रूमा के शासनकाल के अंतिम वर्षों में घाना में दबाव डालकर एकता स्थापित करने का तरीका ही ज्यादा से ज्यादा अपनाया गया। केंद्रीय राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों को अन्य तरीकों से मगठित न कर पाने के कारण एन्क्रूमा ने राजनीतिक प्रणाली में उन बड़े लोगों को जबरदस्ती निकाल बाहर करने का प्रयत्न किया जो उनके साथ या तो सहयोग नहीं कर सकते थे या नहीं करते थे। इस तरह के दमन में बाकी बचे कई विशिष्ट व्यक्तियों का सहयोग और समर्थन उन्हें प्राप्त हो गया। :

जहां कहीं राजनीतिक विशिष्ट व्यक्ति 'शासक वर्ग' की श्रेणी में हैं उनके बीच की आपसी सहमति और एकता काफी नाजुक संबंधों पर टिकी होती है। जहां इस तरह की एकता है उसका आधार अक्सर व्यक्तिगत आस्थाएँ होती हैं, सर्वोच्च नेता और उनके अभिन्न अनुयायियों और केंद्रीय विशिष्ट व्यक्तियों के बीच। विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के बीच एक दूसरे को संतुष्ट रखने के आधार पर स्थापित संबंधों के ज़रिए भी एकता लाई जाती है।²² केन्द्र को समर्थन देने के बदले में इन विशिष्ट व्यक्तियों को एक दर्जा और कई भौतिक लाभ (राजनीतिक पद), और अपने अनुयायियों को बनाए रखने के साधन (एक संरक्षक के रूप में धन बांटकर) मिलते हैं। राजनीतिक केन्द्र में अत्यंत व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर स्थापित व्यवस्था की जटिलताएं उन राजनीतिक प्रणालियों में और बढ़ जाती हैं जहां सत्तारूढ़ राजनीतिक विशिष्ट व्यक्ति सरकारी दायरे का विस्तार करके समाज पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए, सिद्धांतिक रूप से बचनबद्ध हैं। यह बात विशेष रूप से पश्चिम अफ्रीका जैसे एक पार्टी वाले राज्यों पर लागू होती है।²³ वास्तव में ऐसे विशिष्ट व्यक्ति, प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं, जैसे मजदूर मगठनों, सहकार समितियों, और महिला एसोसिएशनों को पार्टी की शाखाएं बनाकर अपना नियंत्रण स्थापित करने के प्रयत्न करते हैं। इसके परिणामस्वरूप इन एसोसिएशनों में नेताओं के पद, राजनीतिक केन्द्र में महत्वपूर्ण भूमिकाओं वाले पद हो जाते हैं। अक्सर यही होता है कि जब विभिन्न एसोसिएशनों को पार्टी की शाखाओं में बदल दिया जाता

ये समझते करते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग किया है और सरकार के लगभग प्रत्येक वरिष्ठ पद पर इन विशिष्ट व्यक्तियों की नियुक्तियों की है।¹⁶ उनका महत्त्व, लाभों के बंटवारे और संरक्षण प्राप्ति का अंतिम केंद्र बन गया है और संरक्षक तक पहुंचने की क्षमता किसी विशिष्ट व्यक्ति में होना आवश्यक भी है क्योंकि उसे अपने अनुयायियों को अथवा गुट को सतुष्ट करना है और नेतृत्व का अपना दर्जा भी बनाए रखना है।¹⁷ विशिष्ट व्यक्तियों के बीच एकता, विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों और पुस्तनी नेता के बीच बहुमुखी संबंधों द्वारा स्थापित होती है।

पुस्तनी विशिष्ट वर्ग की एकता केवल परंपरागत राजनीतिक प्रणालियों की ही विशेषता नहीं है, नए राज्यों में चमत्कारी प्रभाव वाले नेता पर जो विशेष बल दिया जाता है वह वास्तव में किसी पुस्तनी नेता का चुनाव ही होता है।¹⁸ एन्क्रूमा, मंगोर, तूरे, बुर्गीवा और हुफूए बोइनी जैसे नेताओं द्वारा अपने खास समर्थकों (पुस्तनी कृपापात्रों) को महत्वपूर्ण सरकारी और राजनीतिक पदों पर नियुक्त करके अपने शासन को दृढ़ बनाने जैसे प्रयत्न अब अधिकांश नए राज्यों में भी होते नजर आते हैं।¹⁹

पुस्तनी संबंध बिल्कुल भिन्न संस्थात्मक परिस्थितियों में भी स्थापित हो सकते हैं, जैसे किसी एक संस्था के बीच वर्गीकृत प्रणाली (उदाहरण के लिए आइवरी कोस्ट में पी० डी० सी० आई० या घाना में सी० पी० पी०), या संस्थाओं के बीच (उदाहरण के लिए पार्टी के नेता का संबंध स्वयंसेवी संस्थाओं के नेताओं में स्थापित करना), या महत्त्व के परंपरागत अथवा नवपरंपरागत अधिकारीतंत्र (बुरुंडी 1967, इथियोपिया, मोजम्बिक, और नेपाल), या आधुनिक अधिकारीतंत्र (जैसे 1958 में पहले पाकिस्तान और थाईलैंड)। थाईलैंड में प्रभुत्व वाले मम्मिलन वास्तव में कुछ पुस्तनी गुटों में मिलकर बने थे जो सत्ता में आने की समान महत्वाकांक्षा से प्रेरित हुए थे।

एडगर शोर के अनुसार .

व्यक्तिगत अनुग्रह की सामंतवादी प्रणाली पर आधारित व्यक्तिगत गुटों ने ही अधिकारीतंत्र की आस्थाओं और विशिष्टताओं को मूल आधार दिया है। परंपरागत सामाजिक प्रणाली के संरक्षक-संरक्षित दलों के अर्धन एक दूसरे को संतुष्ट रखने के लिए जिम प्रकार के संबंध स्थापित हुए थे उन्हीं के अनुसार कई अप्रतिम्य व्यक्तियों और प्रशासनिक नेताओं के बीच लगभग अनौपचारिक गुणना के संबंध बनते हैं।²⁰

पाकिस्तान में अधिकारीतंत्र के राजनीतिज्ञों ने जिन पुस्तकें गुटों का निर्माण किया था उन्होंने ही अंत में 1956 में राष्ट्रवादी पार्टी मुस्लिम लीग को विभिन्न खंडों में विभाजित किया।²¹

पितृवाद और सरकार में आने की ममान इच्छा के साथ ही, विशिष्ट व्यक्तियों के बीच आपसी एकता कि संभावित स्रोत समाप्त नहीं हो जाते। मिद्धातों के आधार पर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बीच मपक बन सकता है। इसी तरह किसी एक पार्टी के मदस्य होने के कारण भी यह मपक हो सकता है या फिर दबाव डालकर भी ऐसा हो सकता है। एन्क्रूमा के शासनकाल के अंतिम वर्षों में घाना में दबाव डालकर एकता स्थापित करने का तरीका ही ज्यादा से ज्यादा अपनाया गया। केंद्रीय राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों को अन्य तरीकों से मगठित न कर पाने के कारण एन्क्रूमा ने राजनीतिक प्रणाली में उन बड़े लोगों को जबरदस्ती निकाल बाहर करने का प्रयत्न किया जो उनके साथ या तो सहयोग नहीं कर सकते थे या नहीं करते थे। इस तरह के दमन में बाकी बचे कई विशिष्ट व्यक्तियों का सहयोग और ममथन उन्हें प्राप्त हो गया।

जहां कहीं राजनीतिक विशिष्ट व्यक्ति 'शासक वर्ग' की श्रेणी में हैं उनके बीच की आपसी सहमति और एकता काफी नाजुक संबंधों पर टिकी होती है। जहां इस तरह की एकता है उसका आधार अक्सर व्यक्तिगत आस्थाए होती हैं, सर्वोच्च नेता और उसके अभिन्न अनुयायियों और केंद्रीय विशिष्ट व्यक्तियों के बीच। विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के बीच एक दूसरे को मनुष्ट रखने के आधार पर स्थापित संबंधों के जरिए भी एकता लाई जाती है।²² केंद्र को ममथन देने के बदले में इन विशिष्ट व्यक्तियों को एक दर्जा और कई भौतिक लाभ (राजनीतिक पद), और अपने अनुयायियों को बनाए रखने के साधन (एक संरक्षक के रूप में धन बांटकर) मिलते हैं। राजनीतिक केंद्र में अत्यंत व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर स्थापित व्यवस्था की जटिलताएं उन राजनीतिक प्रणालियों में और बढ़ जाती हैं जहां मत्तारूढ़ राजनीतिक विशिष्ट व्यक्ति सरकारी दायरे का विस्तार करके समाज पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए, सैद्धांतिक रूप से वचनबद्ध हैं। यह बात विशेष रूप से पश्चिम अफ्रीका जैसे एक पार्टी वाले राज्यों पर लागू होती है।²³ वास्तव में ऐसे विशिष्ट व्यक्ति, प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं, जैसे मजदूर मंगठनों, महकार, ममितियों, और महिला एसोसिएशनों को पार्टी की शाखाएं बनाकर अपना नियंत्रण स्थापित करने के प्रयत्न करते हैं। इसके परिणामस्वरूप इन एसोसिएशनो में नेताओं के पद, राजनीतिक केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिकाओं वाले पद हो जाते हैं। अक्सर यही होता है कि जब विभिन्न एसोसिएशनो को पार्टी की शाखाओं में बदल दिया जाता

ये समझौते करते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग किया है और सरकार के लगभग प्रत्येक वरिष्ठ पद पर इन विशिष्ट व्यक्तियों की नियुक्तियाँ की हैं।¹⁶ उनका महत्त्व, लाभों के बंटवारों और संरक्षण प्राप्ति का अंतिम केंद्र बन गया है और संरक्षक तक पहुँचने की क्षमता किसी विशिष्ट व्यक्ति में होना आवश्यक भी है क्योंकि उसे अपने अनुयायियों को अथवा गुट को संतुष्ट करना है और नेतृत्व का अपना दर्जा भी बनाए रखना है।¹⁷ विशिष्ट व्यक्तियों के बीच एकता, विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों और पुस्तनी नेता के बीच बहुमुखी संबंधों द्वारा स्थापित होती है।

पुस्तनी विशिष्ट वर्ग की एकता केवल परंपरागत राजनीतिक प्रणालियों की ही विशेषता नहीं है, नए राज्यों में चमत्कारी प्रभाव वाले नेता पर जो विशेष बल दिया जाता है वह वास्तव में किसी पुस्तनी नेता का चुनाव ही होता है।¹⁸ एन्कूमा, मेघोर, तूरे, बुर्गीबा और हुफूए बोइनी जैसे नेताओं द्वारा अपने खास ममयंकों (पुस्तनी श्रुपापात्रों) को महत्वपूर्ण मरकारी और राजनीतिक पदों पर नियुक्त करके अपने शासन को दृढ़ बनाने जैसे प्रयत्न अब अधिकांश नए राज्यों में भी होते नजर आते हैं।¹⁹

पुस्तनी संबंध विल्कुल भिन्न सस्थायक परिस्थितियों में भी स्थापित हो सकते हैं, जैसे किमी एक मस्या के बीच वर्गीकृत प्रणाली (उदाहरण के लिए आइवरी कोस्ट में पी० डी० मी० आई० या घाना में मी० पी० पी०), या संस्थाओं के बीच (उदाहरण के लिए पार्टी के नेता का संबंध स्वयंसेवी संस्थाओं के नेताओं से स्थापित करना), या महल के परंपरागत अथवा नवपरंपरागत अधिकारीतंत्र (बुहंडी 1967, इथियोपिया, मोंगको, और नेपाल), या आधुनिक अधिकारीतंत्र (जैसे 1958 में पहले पाकिस्तान और थाईलैंड)। थाईलैंड में प्रभुत्व वाले सम्मिलन वास्तव में कुछ पुस्तनी गुटों में मिलकर बने थे जो सत्ता में आने की समान महत्वाकांक्षा से प्रेरित हुए थे।

एडगर शोर के अनुसार .

व्यक्तिगत अनुग्रह की सामनवादी प्रणाली पर आधारित व्यक्तिगत गुटों ने ही अधिकारीतंत्र की आस्थाओं और विशिष्टताओं को मूल आधार दिया है। परंपरागत सामाजिक प्रणाली के संरक्षक-संरक्षित ढांचे के अंदर एक दूसरे को संतुष्ट रखने के लिए जिम प्रकार के संबंध स्थापित हुए थे उन्हीं के अनुसार कई अधीनस्थ व्यक्तियों और प्रशासनिक नेताओं के बीच लगभग अनौपचारिक एकता के संबंध बनते हैं।²⁰

पाकिस्तान में अधिकारीतंत्र के राजनीतिज्ञों ने जिन पुश्तैनी गुटों का निर्माण किया था उन्होंने ही अंत में 1956 में गण्टवादी पार्टी मुस्लिम लीग को विभिन्न खंडों में विभाजित किया।²¹

पितृवाद और सरकार में आने की समान इच्छा के साथ ही, विशिष्ट व्यक्तियों के बीच आपसी एकता कि मभावित स्रोत समाप्त नहीं हो जाते। सिद्धांतों के आधार पर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बीच संपर्क बन सकता है। इसी तरह किसी एक पार्टी के मदस्य होने के कारण भी यह संपर्क हो सकता है या फिर दबाव डालकर भी ऐसा हो सकता है। एन्क्रूमा के शासनकाल के अंतिम वर्षों में घाना में दबाव डालकर एकता स्थापित करने का तरीका ही ज्यादा से ज्यादा अपनाया गया। केंद्रीय राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों को अन्य तरीकों से मगठित न कर पाने के कारण एन्क्रूमा ने राजनीतिक प्रणाली में उन बड़े लोगों को जबरदस्ती निकाल बाहर करने का प्रयत्न किया जो उनके साथ या तो सहयोग नहीं कर सकते थे या नहीं करते थे। इस तरह के दमन में बाकी बचे कई विशिष्ट व्यक्तियों का सहयोग और समर्थन उन्हें प्राप्त हो गया।

जहां कहीं राजनीतिक विशिष्ट व्यक्ति 'शासक वर्ग' की श्रेणी में हैं उनके बीच की आपसी महमति और एकता काफी नाजुक संबंधों पर टिकी होती है। जहां इस तरह की एकता है उसका आधार अक्सर व्यक्तिगत आस्थाएं होती हैं, सर्वोच्च नेता और उसके अभिन्न अनुयायियों और केंद्रीय विशिष्ट व्यक्तियों के बीच। विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के बीच एक दूसरे को सतुष्ट रखने के आधार पर स्थापित संबंधों के जरिए भी एकता लाई जाती है।²² केंद्र को समर्थन देने के बदले में इन विशिष्ट व्यक्तियों को एक दर्जा और कई भौतिक लाभ (राजनीतिक पद), और अपने अनुयायियों को बनाए रखने के साधन (एक संरक्षक के रूप में धन बाटकर) मिलते हैं। राजनीतिक केंद्र में अत्यंत व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर स्थापित व्यवस्था की जटिलताएं उन राजनीतिक प्रणालियों में और बढ़ जाती हैं जहां सत्तारूढ़ राजनीतिक विशिष्ट व्यक्ति सरकारी दायरे का विस्तार करके समाज पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए, सैद्धांतिक रूप में वचनबद्ध हैं। यह बात विशेष रूप से पश्चिम अफ्रीका जैसे एक पार्टी वाले राज्यों पर लागू होती है।²³ वास्तव में ऐसे विशिष्ट व्यक्ति, प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं, जैसे मजदूर संगठनों, सहकार समितियों, और महिला एसोसिएशनों को पार्टी की शाखाएं बनाकर अपना नियंत्रण स्थापित करने के प्रयत्न करते हैं। इसके परिणामस्वरूप इन एसोसिएशनों में नेताओं के पद, राजनीतिक केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिकाओं वाले पद हो जाते हैं। अक्सर यही होता है कि जब विभिन्न एसोसिएशनों को पार्टी की शाखाओं में बदल दिया जाता

है तो उसके बाद पुस्तैनी नेता प्रत्येक पद पर अपने खास खास लोगों को नियुक्त करने की कोशिश में रहता है। उदाहरण के लिए आइवरी कोस्ट में 1959 के बाद पी० डी० मी० आर्दी० के महासचिव जो पार्टी की नवनिमित्त युवा शाखा के नेता थे, और हुफूए बोईनी के बीच टकराव हुआ और महासचिव को पद से हटना पड़ा और उनकी जगह हुफूए बोईनी के एक खास आदमी को रखा गया।

राजनीतिक केंद्र पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए राजनीतिक विशिष्ट व्यक्ति आपस में सम्मिलन का आधार तैयार करने के जो प्रयत्न करते हैं उन्हीं से एक राजनीतिक प्रक्रिया का दायरा बनता है जो उस केंद्र का क्षेत्र होता है। राजनीतिक नेता राजनीतिक केंद्र के अंदर विभिन्न दलों और संस्थाओं को अपने व्यक्तिगत संबंधों और संरक्षितों के माध्यम से एकता के सूत्र में बांधकर, केंद्र सरकार पर अपने नियंत्रण को दृढ़ करने का प्रयत्न करते हैं। साथ ही, विशिष्ट व्यक्ति अपने पदों के कारण प्राप्त सत्ता का उपयोग करके अपनी व्यक्तिगत सत्ता और अनुयायियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया मध्य युग के यूरोप की पैतृक प्रणालियों जैसी है, जिसकी विशेषता यह थी कि 'राजा अपने पुस्तैनी कृपापात्रों को संगठित करके, केंद्र की सत्ता मजबूत करने का प्रयत्न करते थे और अधीनस्थ अधिकारी स्थानीय जमींदार बनकर केंद्र की सत्ता को कमजोर करने का प्रयत्न करते थे।'²⁴

राजनीतिक केंद्र द्वारा अपने आपको मजबूत बनाने के प्रयत्नों का मुकाबला विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों की इस प्रवृत्ति से होता है कि वे स्थानीय सत्ता में पुस्तैनी जमींदार के रूप में बने रहना चाहते हैं।

राईनहार्ड बेडिक्स ने कहा है :

पुस्तैनी शासन के विस्तार और विकेंद्रीकरण से व्यक्तिगत आश्रितों के कार्य और बढ़ सकते हैं क्योंकि अपने स्वामी के नियंत्रण से उन्हें वास्तविक स्वतंत्रता में और छूट मिलती है। 'यह स्पष्ट है कि पुस्तैनी शासन के विस्तार में अधीनस्थ राजनीतिक आश्रित व्यक्ति अपने शासक के सीधे नियंत्रण से दूर हो जाता है।'²⁵

'पुस्तैनी शासन के संबंध में व्यक्त किए गए इस मत की तुलना बेनबेल्वा के शासन-काल में अल्जीरिया की स्थिति के साथ की जा सकती है :

तात्कालिक हित माधने वाले दल आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों से उपजते हैं,

जो या तो सरकार अथवा अधिकारीतंत्र में उच्च स्थानों पर है या वहाँ तक पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं... इस बात की प्रवृत्ति हो सकती है कि विभिन्न मंत्रालय अपनी अपनी नीतियों को कार्यरूप देने के लिए अपने अपने दल गठित करें और इन नीतियों का अन्य मंत्रालयों में भी प्रचार करें... उदाहरण के लिए युद्ध के पुराने सैनिकों की एसोसिएशन, वयोवृद्ध सैनिक तथा सामाजिक कार्य मंत्रालय की एक शाखा है।... प्रत्येक (एसोसिएशन) कोई संस्था या एसोसिएशन उतनी नहीं है जितनी कि प्रशासनिक इकाइयों का मोहरा।²⁶

पहले कहा जा चुका है, विशिष्ट व्यक्तियों का गठबंधन, राजनीतिक प्रक्रिया के कारण काफी अस्थायी और विभाजनीय बन जाता है। इस संबंध में अगले अध्याय में आगे लिखा जाएगा। राजनीतिक केंद्र की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि विशिष्ट व्यक्ति कहा तक यह समझते हैं कि उनके सम्मिलन से उन्हें और उनके अनुयायियों को कितना फायदा हो रहा है। पुस्तक सत्ता की अनिश्चितता और अपने अनुयायियों को संरक्षण तथा भौतिक लाभ दिलाने की सामर्थ्य की अपेक्षाकृत कमी के कारण स्थिरता एक समस्या ही बनी रहती है।

राजनीतिक बाह्य परिधि का गठन करना

किसी शासन का अस्तित्व में बने रहना, विभिन्न आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रमों को लागू करना तो बात ही अलग है, उसकी इस क्षमता पर निर्भर करता है कि वह केंद्र से बाहर कहा तक अपनी सत्ता का विस्तार कर सकता है और बाह्य परिधि पर अपने नियंत्रण को कितना दृढ़ कर पाया है। इस तरह की दृढ़ता लाने के काम में काफी हद तक इस बात से मदद मिलती है कि स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति केंद्र नियंत्रित साधनों पर निर्भर रहते हैं। केंद्रीय विशिष्ट व्यक्ति भिन्न भिन्न परिमाण में यह निर्धारित करते हैं कि बाह्य परिधि वाले क्षेत्रों को कितने साधन दिए जाएं। इस निर्धारण में वे केंद्रीय नियंत्रणों और सरकारी राजस्व तथा संरक्षण क्षमता पर अपने नियंत्रण का उपयोग करते हैं। साधनों को नियंत्रण में रखने की क्षमता, चाहे किसी जगह ये साधन सीमित ही क्यों न हों, न केवल केंद्र और परिधि क्षेत्रों के संबंधों का निर्धारण करती है बल्कि, क्योंकि कुछ एक स्थानीय विशिष्ट व्यक्तियों के गुट को किसी अन्य गुट से अधिक प्राथमिकता दी जा सकती है स्थानीय सत्ता के संबंधों को भी दिशा प्रदान करती है।

स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति और दल भी सौदेबाजी की क्षमता से हीन नहीं हैं। वे स्थानीय राजनीतिक प्रणाली में अपने निजी वित्तीय साधनों और अपने परंपरागत

संबंधियों व अनुयायियों की शक्ति का प्रयोग करके राजनीतिक दृढ़ीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान कर सकते हैं या उममें रूकावट डाल सकते हैं। इसके अलावा जहाँ स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति, अपने दर्जे को बनाए रखने के लिए आमतौर पर केंद्र द्वारा नियंत्रित साधनों पर निर्भर रहते हैं, वहाँ उन्हीं साधनों का इस्तेमाल दृढ़ता लाने के लिए करना भी स्थानीय विशिष्ट व्यक्तियों की महमति और क्षमताओं पर निर्भर करता है।

तो इस प्रकार बाह्य परिधि का सुनियोजित मगठन करने के लिए केंद्रीय और स्थानीय राजनीतिक प्रक्रियाओं के बीच बड़े नाजुक तरीके इस्तेमाल करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि केंद्रीय और स्थानीय विशिष्ट व्यक्तियों ने जिस प्रकार के अनुमान और दावपेच मोच रखे हों वे आपस में मेल न खाते हों, बल्कि हो सकता है इसमें टकराव की स्थिति पैदा हो जाए। केंद्र के अंदर या स्थानीय राजनीतिक प्रणाली के अंदर पारस्परिक विरोधों में इन दोनों का एक दूसरे पर निर्भरता में कुछ परिवर्तन हो सकता है।

केंद्र के आपसी मतभेदों के कारण केंद्रीय विशिष्ट वर्ग संभवतः स्थानीय आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने में कोई रुचि न ले, उधर परिधि वाले क्षेत्रों में आपसी मतभेदों के कारण शक्ति और सत्ता के ऐसे संबंध उत्पन्न हो सकते हैं जिन्हें केंद्रीय विशिष्ट व्यक्ति मान्यता नहीं देते।

केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली और स्थानीय उपप्रणालियों के बीच संबंधों को ठीक से समझना, राजनीतिशास्त्र के वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही कठिन रहा है। पहली बात तो यह है जिसे मार्टिन किलमन ने 'सीमा समस्या' कहा है, 'राजनीतिक चयन और कार्य के निरपेक्ष और पवित्र मानदंडों की व्यावहारिकता को समझने के काम में राजनीतिक अभिनेताओं की असमर्थता'।²⁷ केंद्रीय विशिष्ट वर्ग अक्सर स्थानीय विशिष्ट वर्ग की मांगों को स्वीकार करने से हिचकिचाता है क्योंकि इस तरह की मांगों को वह परंपरावाद और संकीर्ण क्षेत्रवाद से प्रेरित और इभीलिए राष्ट्र विरोधी मानता है और उसे इस बात की आशंका होती है कि यदि यह मांगें स्वीकार कर ली गईं तो इसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को स्वीकार कर लिया जाना समझा जाएगा।²⁸ लेकिन सीमा समस्या स्वयं इन राजनीतिक अभिनेताओं तक ही सीमित नहीं है। समाजविज्ञान के विद्वान विशेषकर राजनीतिविज्ञान के विशेषज्ञ भी अक्सर यही मानते हैं कि परंपरावाद और संकीर्ण क्षेत्रवाद, राष्ट्र निर्माण के कार्य में बाधक है। ऐसा माना जाता है कि ये शक्तियां संपूर्ण राष्ट्र को वजाय उससे कम के लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं और यही वास्तविक राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणाली के रास्ते में बाधक होती हैं।²⁹ इस प्रकार केंद्र और बाह्य परिधि के बीच

राजनीतिक तथा आर्थिक तनाव, जिसका एक कारण संकीर्ण क्षेत्रवाद हो भी सकता है और नहीं भी, बहुधा राष्ट्रवाद बनाम संकीर्ण क्षेत्रवाद, या राष्ट्रवादी बनाम संकीर्णतावादी माना जाता है।

‘परिधि’ शब्द का जिस अर्थ में यहाँ प्रयोग किया जा रहा है वह राष्ट्रवाद बनाम उपराष्ट्रवाद के सवाल से बिल्कुल भिन्न विश्लेषण करने का एक प्रयत्न है।³⁰ कोई ‘राष्ट्रीय’ राजनीतिक प्रणाली चाहे जितनी मजबूत हो, फिर भी केंद्रीय सत्ता की सस्थाओं में दूर एक राजनीतिक परिधि विद्यमान रहती है जिसे स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं और स्थानीय संघर्षों से आकार मिलता है।

हाल में ऐसे प्रयत्न किए गए हैं कि केंद्र और परिधि क्षेत्रों के संबंधों के बारे में एक या अधिक संकटपूर्ण घटनाओं के सदृश में सिद्धांत बनाए जाएं। इस तरह की घटनाएं राजनीतिक विकास की प्रक्रिया के इतिहास में हुई हैं।³¹ इस तरह के विशेषकर पृथक अस्तित्व, वैधता, क्रियाकलापों में भाग लेने और अपने विस्तार में संबद्ध, संकटों के विवरण में कई तरह से उस अंतर का पता चलता है जो केंद्र और परिधि के बीच है और वे कठिनाइयाँ दर्शाई गई हैं जो इस अंतर को पूरा करने के काम में सामने आती हैं। संकट योजना राजनीतिक विकास के अध्ययन के लिए सुझाई गई रूप-रेखा है हालांकि कौन सा संकट किसके बाद आएगा और इनके बीच के संबंध कैसे हैं यह अस्पष्ट है इस बात को योजना बनाने वालों ने भी स्वीकार किया है।³² फिर भी संकट योजना, केंद्र और परिधि के बीच के अंतर को पाटने और इन दोनों के बीच विद्यमान विभिन्न संपर्कों को सुचारु बनाने का एक प्रयत्न है। राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों की प्रमुख समस्या आधुनिक संस्थाओं को निर्जीव जनसमूह के अंदर ‘प्रविष्ट’ कराना और फिर इस जनसमूह को अपने उद्देश्यों के लिए जुटाना, इतनी नहीं है जितनी कि एक ऐसे उच्च आचार संहिता वाले समाज (या समाजों) के अस्तित्व को मानना जो विभिन्न तरीकों से आपसी संपर्क में हैं। और फिर इन राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों को इन पेचीदा संपर्कों को किसी न किसी प्रकार का समन्वित रूप प्रदान करने की समस्या भी हल करनी होती है।

केंद्र और परिधि के बीच एकता लाने के स्रोत

राष्ट्रवादी आंदोलन से बढ़ते हुए आगे चलकर स्वाधीन सरकार के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया के साथ साथ एक प्रक्रिया अनिवार्यतः चलती है। यह है केंद्रीय विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अपने प्रभाव का विस्तार करने और परिधि क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के प्रयत्न। स्वाधीनता के बाद ‘राष्ट्रवादी आंदोलन’ कई छंदों में विभाजित होने के कारण एकता (यदि ऐसी कोई एकता वास्तव में रही हो) को

कमजोर करता है और इसीलिए विभिन्न खंडों के बीच एकता लाने के सभी तरीकों की खोज करना आवश्यक हो जाता है।

इस सन्नमण का अध्ययन करते हुए विद्वानों ने सैद्धांतिक विचारधारा और चमत्कार पर विशेष बल दिया है। वास्तव में दोनों ही बातें राष्ट्रवादी आंदोलन वाली एकता को पुनः स्थापित करने की अद्भुत विधिधा है। सैद्धांतिक विचारधारा और चमत्कार या करिश्मे को दिए जानेवाले इस महत्त्व में ही यह तर्क निहित है कि विशिष्ट व्यक्तियों और अन्य लोगों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर इतना ज्यादा है कि इसे केवल अभूतपूर्व तरीको से ही दूर किया जा सकता है। फिर भी, जैसाकि राष्ट्रवादी आंदोलनों के विश्लेषण से पता चलता है, विशिष्ट व्यक्तियों और अन्य लोगों के बीच आपसी संबंध बने ही रहते हैं। इस प्रकार राष्ट्रवादी विशिष्ट व्यक्ति, जैसेकि तजानिया में पाल बोमानी, सरकार और राजनीतिक क्षेत्र के वरिष्ठ पदों पर आसीन होते हैं और अपने अनुयायियों तथा केंद्र के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा वे पार्टों और अधिकारीतंत्र के साथ कामकाज के सिलमिले में अपने अनुयायियों के हितों के संरक्षक होते हैं। वे नए राजनीतिक ध्येयों और आदर्शों को प्रसारित करते हैं और कभी कभी स्थानीय राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। श्रीलंका में पहले आम चुनाव में जो विशिष्ट व्यक्ति यूनाइटेड नेशनल पार्टी के उम्मीदवारों के रूप में खड़े हुए थे और जो पार्टी और सरकार के केंद्र के रूप में उभरे वे स्थानीय प्रभावशाली संपर्कों से संबद्ध थे।³³

ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के व्यक्तिगत संपर्क अल्पविकसित राज्यों में सभी जगह व्याप्त हैं। हाल के शोधकार्यों में हालांकि संरक्षक-संरक्षित संबंधों को आम संपर्क का रूप माना गया है फिर भी अन्य प्रकार के द्विपक्षीय संबंधों की बात भी कही गई है, जैसे समान स्तर के दो व्यक्तियों के बीच गठबंधन, एक ऐसी मंत्री या संधि सिद्ध होते हैं जिनमें एक दूसरे के लिए काम करने का क्षेत्र बहुत सीमित रहता है। इसके अलावा पारिवारिक संबंधों और जातीय संबंधों आदि की बात भी कही गई है।³⁴ केन्द्रीय विशिष्ट व्यक्तियों के पास जब वित्तीय साधन और संरक्षण प्रदान करने की क्षमता होती है तो वे अपने संपर्कों का इस्तेमाल बाह्य परिधि क्षेत्रों में बस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने के उपयोग में लाते हैं। इसके अलावा वे इन्हीं संपर्कों का इस्तेमाल स्थाई व्यक्तिगत अनुयायियों (संरक्षित) को हाथ में रखने के लिए भी करते हैं। इन बातों से, एक दूसरे के हित के लिए काम करने जैसे संबंधों का विकास होता है। संरक्षण और विशेष सुविधाएं दिए जाने के बदले संरक्षित वर्ग, विशिष्ट व्यक्ति को एक दर्जा प्रदान करता है और जब कभी आवश्यकता होती है उसे चुनावों के समय समर्थन भी देता है।³⁵

इन संपर्कों में निहित पारस्परिकता या आपसदारी की भावना के कारण अल्प-विकसित राज्यों के राजनीतिक दलों को ऐसे संगठन समझा गया है जो अमरीकी राजनीतिक पार्टियों के बारे में व्यापक रूप से लिखे गए साहित्य में उल्लिखित राजनीतिक व्यवस्थाओं की तरह हैं।³⁶ इस प्रकार की पार्टी व्यवस्थाएं पारस्परिकता और कार्यों के आधार पर बनती हैं लेकिन इनका उद्देश्य नीतियों का निर्धारण करना या सदस्यों को अनुशासन में लाना नहीं बल्कि चुनाव जीतना है और इसी के परिणाम-स्वरूप पार्टी के सदस्यों को नौकरियां देना भी है।

इस प्रकार भारत में :

कांग्रेस पार्टी के नेता, राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्यतः इसी बात को सोचते हैं कि वातावरण के अनुसार पार्टी को बदलने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएं . . . कांग्रेस पार्टी का मूल प्रयत्न सदस्यों को भर्ती करना और उनका समर्थन प्राप्त करना है। वह लोगों को इकट्ठा करके उनका संचालन नहीं करती बल्कि उन्हें समूहीकृत रूप देती है जिसका उद्देश्य केवल बड़ी संख्या में लोगों को अपने सदस्य बनाना है। पार्टी कोई नए प्रयोग नहीं करना चाहती बल्कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना चाहती है। हालांकि कुछ कांग्रेसजन ग्रामीण क्षेत्रों का स्वरूप ही बदल देने का स्वप्न देखते हैं, लेकिन वास्तविक व्यवहार में अधिकांश कांग्रेसजन केवल चुनाव जीतने में ही रुचि रखते हैं। . . . एक ओर तो भारत की राष्ट्रीय सरकार और अधिकारीतंत्र विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर, स्थानीय राजनीतिज्ञ सिर्फ लाभ उठाने में ही दिलचस्पी रखते हैं। कांग्रेस की सैद्धांतिक विचारधारा है समाजवाद लाना जिसमें सभी लोग सामाजिक और विशेषकर आर्थिक दृष्टि से समान होंगे। इसी विचारधारा के सदर्भ में लाभों के वितरण की राजनीति वैध मानी जा सकती है। संरक्षण प्रदान करने वाली पार्टी और सिद्धांत प्रतिपादित करने वाली पार्टी के बीच भेद करना स्वाभाविक है लेकिन यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि कौन सी विचारधारा, इस मामले में समता की अपील, संरक्षण के समर्थन के लिए किस सीमा तक उपयोग में लाई जाती है।³⁷

उत्तरी नाइजीरिया का भी एक उदाहरण है :

एन० पी० सी० (नार्दन पीपुल्स कांग्रेस) का स्वरूप कम से कम दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से पारंपरिक संबंधों की व्यवस्था में बिल्कुल सही बैठता है। एक

पहलू यह है कि सरकारी नियंत्रण हाथ में होने से उसे जो सत्ता मिली हुई है उसके कारण यह पार्टी विशिष्ट पदों पर अपने लोगों को लाने, ऋण, छात्र-वृत्तियाँ, ठेके और अन्य सुअवसर प्रदान करने का प्रमुख माध्यम बनी। ये सभी काम या तो सीधे और विधिवत रूप से या परोक्ष रूप में पार्टी अथवा पार्टी के ऐसे भूतपूर्व सदस्यों के माध्यम से किए जा सकते हैं जो सरकारी मंडलों, निगमों या आयोगों में महत्वपूर्ण पदों पर थे।

दूसरा पहलू (और यह जनसमर्थन प्राप्त करने की दृष्टि से अधिक महत्व का है) यह है कि स्थानीय प्रशासक के निदेशालय और पार्टी के व्यक्तियों के बीच अटूट संपर्क के कारण साधारण व्यक्ति को परंपरागत विशिष्ट व्यक्ति के साथ हर हालत में मिलकर चलने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि यह विशिष्ट व्यक्ति पार्टी का सदस्य था। परंपरागत समाज में जो संबंध संरक्षक-संरक्षित के बीच था और जिसके कारण निर्भरता की भावना उपजी थी, वही संबंध अब पार्टी और जन साधारण के बीच हो गया।³⁸

अन्य स्थानों पर भी ये पार्टियाँ राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय विशिष्ट व्यक्तियों के समूह ही हैं जो आपस में कई तरह के व्यक्तिगत संबंधों से जुड़े हैं। इस तरह के संबंध विशेष मुविधाएं और लाभ वितरित करने के माध्यम बनते हैं। इस व्यवस्था में जनसमर्थन प्राप्त होता है क्योंकि लोगों को भौतिक लाभ उन्हीं से मिलते हैं। व्यावहारिक रूप में यह व्यवस्था अक्सर ऐसी होती है जिसमें ऊपर में एक व्यक्ति का समर्थन कुछ एक व्यक्ति करते हैं और इसी प्रकार नीचे आते आते व्यक्तिगत अनुयायियों का एक समूह सा बन जाता है। यानी यह एक प्रकार की पिरामिड व्यवस्था है।

विशिष्ट व्यक्तियों और आम जनता के बीच वर्तमान व्यक्तिगत संपर्कों वाली पार्टियों और परंपरा से चले आ रहे आदरभाव पर आधारित पार्टियों (आदरभाव पर आधारित पार्टियों का उदाहरण है, नाइजीरिया की नार्दन पीपुल्स कांग्रेस और कुछ हद तक सियेरा लियोने पीपुल्स पार्टी) और रूढ़िवादी व्यवस्था जिसमें ऊपर में नीचे तक के संबंध भौतिक प्रोत्साहनों पर ही आधारित होते हैं (जैसे आइवरी कोस्ट की पी० डी० सी० आई०), के बीच भेद करने के कुछ प्रयत्न किए गए हैं।³⁹ लेकिन वास्तव में इस तरह के विभेद करना कठिन प्रतीत होता है। कभी कभी रूढ़िवादी व्यवस्था में ऐसे संपर्क भी आते हैं जो केवल भौतिक लाभों पर ही आधारित नहीं होते (उदाहरण के लिए किसी एक नेता को किसी जातीय दल का समर्थन) और वास्तव में ऐसा लगता है कि दोनों प्रकार के संपर्कों के आधार पर भी पार्टियों का गठन हो सकता है। 1950 के दशक में एंटी फ़ासिस्ट पीपुल्स फ्रीडम लीग (जिसे हमेशा

ए० एफ० पी० एफ० एल० कहा जाता रहा है) गांवों में तत्कालीन संरक्षक-संरक्षित संबंधों पर आधारित थी, और कस्बों में यह भौतिक लाभों से उत्पन्न सीमित एकता पर निर्भर थी।⁴⁰

राजनीतिक व्यवस्था के बारे में विस्तारपूर्वक लिखा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक पार्टियों तक ही सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है।⁴¹ मोरक्को में शासक को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करने का जो व्यक्तिगत अधिकार है वह वरिष्ठ सरकारी पदों के दायरे से भी आगे तक के क्षेत्र के लिए है जिसमें 'आपसी समझौतों की व्यापक प्रणाली भी शामिल है और इसके अंतर्गत मध्यमवर्गीय और छोटे मोटे अधिकारी भी बड़ी संख्या में, सामान्य सरकारी सेवा के नियमों से कहीं ज्यादा अपना वेतन बढ़वा सकते हैं और पदोन्नति करा सकते हैं।'⁴² इसके परिणामस्वरूप मोरक्को के शाह की अपनी ही व्यक्तिगत व्यवस्था है। कुछ खाम खास लोगों को अपने माधनों से सहायता पहुंचाकर शाह हसन ने अपने लिए समर्थन जुटाया है और उसके माध्यम से परिधि क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाया है।

इसके अलावा कभी कभी पार्टियाँ व्यवस्था, व्यक्तिगत व्यवस्था के लिए एक पर्दा बन जाती हैं या उसके साथ साथ चलती हैं। किसी राजनीतिक पार्टी का गठन करने के प्रयत्नों में पुरतनी संबंधों का भी विशेष महत्व हो सकता है। केन्द्रीय विशिष्ट व्यक्ति अपनी पार्टी और पार्टी व्यवस्था पर अपने निजी नियंत्रण को दृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण पदों का उपयोग कर सकते हैं। आइवरी कोस्ट में हुफूए बोइनी के व्यक्तिगत प्रतिनिधि ऐसे लोगों को चुनते थे जिनके बारे में उन्हें पूर्ण विश्वास था। इन लोगों को पार्टी की माध्यमिक शाखाओं के महासचिव बनाया जाता था।⁴³ जो लोग इस प्रकार नियुक्त किए जाते थे वे फिर अपने स्तर पर पार्टी के पदों के लिए व्यक्तियों का चुनाव करते थे।⁴⁴ इन सब बातों से अंत में हुफूए बोइनी और पार्टी संगठन के व्यक्तिगत संपर्कों का एक जाल बिछ गया।

अधिकारीतंत्र के विशिष्ट व्यक्ति भी इस तरह की व्यवस्थाओं का गठन कर सकते हैं जिसमें वे इस तंत्र के प्रमुख व्यक्तियों और निचले स्तर के व्यक्तियों तथा सरकार की सामान्य जनता के बीच व्यक्तिगत संपर्कों का विकास कर सकते हैं। थाईलैंड में वरिष्ठ अधिकारी कुछ मध्यम वर्गीय अधिकारियों के संरक्षक बन जाते हैं और फिर ये मध्यम वर्गीय अधिकारी निचले स्तर के अधिकारियों के संरक्षक बनते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अधिकारी स्थानीय जनसाधारण के संपर्क सूत्र में बंध जाता है, और स्थानीय जनसाधारण इन अधिकारियों का संरक्षण चाहते हैं।

दूसरी बात यह है कि राजनीतिक व्यवस्था के विचार में केंद्र और परिधि के बीच विभिन्न व्यक्तिगत संपर्कों के मामलस्य को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। यहां तक कि जहां अपेक्षाकृत सुमंगलित पार्टी व्यवस्था प्रचलमान है जैसे कि भारत की कांग्रेस पार्टी या आइवरी कोस्ट की पी० डी० सी० आई०, यहां भी स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति और उनके पीछे चलने वाले लोग, पार्टी को श्रेणीगत व्यवस्था में पदों पर नहीं बने रहते। इसकी वजाय, आवश्यक साधनों पर निर्भर करते हुए वे अन्य संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जैसे अन्य राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों के साथ जो पार्टी पदों के साधारण स्तर से भी दूर हैं या पार्टी से बाहर हैं, अथवा अधिकारीतंत्र के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ, या आर्थिक क्षेत्र के बड़े लोगों के साथ। व्यवस्थाएं, चाहे वे व्यक्तिगत, दलीय या अधिकारीतंत्र की हों—साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती हैं। फिलीपींस में दलीय राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कालं लैंडे ने निघा है :

राजनीतिक नेता अपने अपने अनुयायियों को लेकर पार्टियों में शामिल होते हैं या उनसे बाहर निकल जाते हैं और ऐसा करते हुए उन्हें किसी तरह के उत्तरदायित्व की भावना नहीं मताती और क्योंकि उनपर किसी तरह का कोई वास्तविक दबाव नहीं होता इसलिए वे अपनी पार्टी के अन्य माधियों का समर्थन करने के लिए भी अपने आपको बाध्य नहीं मानते। पार्टी की सदस्यता, किसी श्रेणी में शामिल होने का मामला नहीं बल्कि उस वर्ग में उच्च पद तक पहुंचने का मामला है।

यदि कोई यह जानना चाहता है कि चुनाव अभियानों का वास्तविक ढांचा क्या है तो उसे राजनीतिक पार्टियों से हटकर, अलग अलग उम्मीदवारों और नेता-अनुयायी संबंधों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऊपरी तौर पर तो ये व्यक्ति एक ही जैसे नजर आते हैं क्योंकि वे एक ही पार्टी के उम्मीदवार हैं लेकिन नेता-अनुयायी संबंधों को वास्तव में अलग मानना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे बहुत सारी सताएं दो बड़े लेकिन खोखले पेड़ों के बीच एक दूसरे के साथ जकड़ी हुई आगे-पीछे झूल रही हों या इन पेड़ों से (राजनीतिक पार्टियों) लिपटी हुई हों।⁴⁵

यदि हम इस उपमा में कुछ और 'लताएं' शामिल कर ले जो अधिकारीतंत्र के विशिष्ट व्यक्तियों के कभी कभार के समर्थकों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि ये विभिन्न लताएं एक दूसरे के साथ लिपटती हैं, तो केंद्र-परिधि संपर्कों तथा व्यवस्थाओं की पेचीदगिया स्पष्ट होने लगती हैं।

यह उलझाव जो पहले ही काफी अधिक होता है, उस स्थिति में और भी बढ़ने लगता है जब कोई सरकार परिधि के केंद्र से बाहर की ओर केंद्रीय पार्टी और सरकार को फँसाकर परिधि पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने की कोशिश करती है, उदाहरण के लिए केंद्र से बाहर के क्षेत्रों में राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर पार्टी और अधिकारियों को केंद्र द्वारा नियुक्त करना।⁴⁶ सिद्धांत रूप में यह विकेंद्रीकरण, जिसके अंतर्गत केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों के अधिकारों में वृद्धि करना और पार्टी की स्थानीय शाखाओं तथा सरकारों की सत्ता को कमजोर करना शामिल है, कई ऐसी सेवाओं का विस्तार करता है जिसके लिए स्थानीय जनता को केंद्र के प्रतिनिधि का मुंह देखना पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप, 'उन स्थानों पर केंद्र के नियंत्रण की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।'⁴⁷

विकेंद्रीकरण नए राज्यों की राजनीतिक प्रक्रिया की विशेषता बन गया है।⁴⁸ विशेषकर जिन राज्यों में जनसमर्थन जुटाकर कोई पार्टी सत्ता में आई है वहाँ केंद्रीय विशिष्ट व्यक्तियों ने ऐसे नियुक्त अधिकारियों की श्रेणियों का क्रम स्थापित करने के प्रयत्न किए हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के प्रति उत्तरदायी होंगे और जिन्हें जिला तथा स्थानीय संगठनों की सदिच्छा पर निर्भर नहीं रहना होगा।⁴⁹ घाना में सी० पी० पी० ने जब एकमात्र पार्टी के राज्य को सुदृढ़ किया, तो साथ ही यह भी कोशिश की गई कि सी० पी० पी० की स्थानीय शाखाओं को और दृढ़ नियंत्रण के अधीन रखा जाए। पार्टी के स्थानीय संगठन को भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर जिला तथा क्षेत्रीय पार्टी शाखाएं बनाई गईं जिनका मंचालन केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए जिला तथा क्षेत्रीय आयुक्तों द्वारा किया जाने लगा।⁵⁰

कभी कभी एक प्रशासनिक या तकनीकी क्षेत्र के एजेंट के रूप में केंद्र सभी जगह हावी हो जाता है। बर्मा के एक गांव नानद्विन पर सरकार और प्रशासन ने जिन 'असंख्य तरीकों' से प्रभाव डाला उसके बारे में टिप्पणी करते हुए मैनिंग नैश ने लिखा है :

गांवों, और सरकार के अन्य स्तरों के बीच बहुत सारे तथा विविध प्रकार के संबंध हैं। अत्यंत स्पष्ट संबंध हैं करों, पुलिस और न्यायालयों की एजेंसियों के माध्यम से। कर अधिकारी, पुलिस कर्मचारी और सैनिक, अपने सामान्य कार्यकलापों के सिलसिले में गांव में आकर विभिन्न ग्रामीणों के साथ अलग अलग या ग्राम प्रधान अथवा ग्राम बड़ों की परिपद के माध्यम से काम करते हैं। ... सड़क, वन और कृषि विभाग अपनी अपनी ओर से ममुचित सेवाएं प्रदान करते हैं ... गांववालों को कुछ निश्चित आकार के पेड़ काटने के लिए अनुमति लेनी होती है और उन्हें कभी कभी कृषि विभाग की एजेंसी से बीज खरीदने के लिए

पैसा या ऋण मिलता है . . . सरकार कुछ चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान करती हैं जिनका फायदा लोग अक्सर उठाते हैं . . . गांव के युवा वर्ग को शिक्षित करने का काम भी अब मुख्यतः सरकारी एजेंसी के हाथ में है।⁵¹

विकेन्द्रीकरण के कारण ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है जिनके पाम साधनों तक पहुंचने की सामर्थ्य होती है। इसलिए विकेन्द्रीकरण से जनता में मर्मर्थकों की संख्या में भी विस्तार होता है और केन्द्र और परिधि के बीच इनके द्वारा ही संपर्क बनता है। केन्द्र सरकार के साथ अपने संपर्कों के कारण स्थानीय प्रशासनिक प्रतिनिधि एक प्रकार के अर्धसंरक्षक बन जाते हैं। इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि पार्टियों के विशिष्ट व्यक्ति, तत्कालीन संरक्षक-संरक्षित संबंधों से दूर होने के कारण अक्सर स्वयं संरक्षक और विचौलिये बन जाते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सरकारी व्यवस्था के विस्तार के बारे में कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया के संबंध में मायरन चीनर ने कहा है :

पार्टी ने प्रशासनिक गतिविधियों के विस्तार के लिए कार्य को गति देने वाले कार्यकर्ताओं के एक वर्ग का सृजन किया है जो प्रशासकों और जनता के बीच माध्यम का काम करते हैं। 'सृजन' शब्द में यह निहित है कि सोच समझकर कोई निर्णय और कार्यक्रम बनाया गया है, इसलिए यह काफी भ्रामक शब्द है। इसके अलावा यह मान लेना भी एक भ्रांति है कि यह कोई नई भूमिका है। इसके विपरीत, ब्रिटिश शासन के अधीन ऐसे व्यक्तियों का एक वर्ग था जिनकी पहुंच स्थानीय प्रशासन तक थी और वे इसका उपयोग अपने या अपने दल के हितों की अभिवृद्धि के लिए करते थे। लेकिन 1937 से पहले (जब कांग्रेस ने कई राज्य सरकारों पर अपना अधिकार जमाया और राज्यस्तर पर वास्तव में राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त किया) बहुत कम कांग्रेसजन यह काम करते थे। जब पार्टी ने मत्ता संभाली तो जो लोग काम को गति देते थे वे कांग्रेस में शामिल हो गए⁵²...

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि केन्द्र और परिधि के बीच के संपर्कों के अतर्गत विविध प्रकार के व्यक्तिगत संबंध आते हैं। इस तरह के संपर्क, सरकारी साधनों और सेवाओं की स्वीकृतियां प्रदान करने के काम पर केंद्रीय विशिष्ट व्यक्तियों के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। कम से कम सिद्धांत रूप में तो परिधि क्षेत्र के लिए साधनों और सेवाओं की स्वीकृति इस प्रकार की जाती है कि सरकार को अधिक से अधिक समर्थन मिल सके। व्यावहारिक रूप में देखा जाए तो इस तरह का समर्थन अक्सर अस्थायी सा होता है।

केंद्र-परिधि सघर्ष के स्रोत

केंद्र और परिधि के बीच संपर्कों के महत्व को काफी कम करके बताया जाता है और इसी प्रकार केंद्र और परिधि के बीच सघर्ष को भी काफी गलत समझा जाता है, हालांकि यह भ्रांति भिन्न प्रकार की होती है। जैसा पहले कहा गया है, समाज-विज्ञानशास्त्रियों ने सकीर्ण क्षेत्रवाद को अक्सर परंपरावाद ही माना है। अन्य शब्दों में, केंद्र और परिधि के बीच का सघर्ष अधिकतर राष्ट्रवाद बनाम उपराष्ट्रवाद (जैसे कबीलावाद, जातिवाद आदि), या विश्व स्तर पर, आधुनिकतावाद बनाम परंपरावाद बनकर रह जाता है। इसलिए परिधि को मंगठित करने की समस्या मुख्यतः, पारंपरिक सत्ताओं, राजनीतिक आंदोलनों और नए राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर के दलों की स्वायत्ता को कम करने की है।⁵³ हालांकि परंपरा और आधुनिकता के बीच विभेद को इस तरह के विश्लेषणों में कुछ बढ़ा चढ़ाकर ही प्रस्तुत किया जाता है फिर भी इस प्रकार के सघर्षों या टकरावों के महत्व से इकार नहीं किया जा सकता। घाना में सी० पी० पी० और विभिन्न जातीय राजनीतिक दलों (विशेषकर नार्देन पीपुल्स पार्टी और नेशनल लिबरेशन मूवमेंट) के बीच आपसी होड़ इस तरह के सघर्ष का एक उदाहरण है।⁵⁴ फिर भी, केंद्र और परिधि के बीच संपर्क की समस्या, एकता के संकट से कुछ अधिक है।

जहां कहीं इस तरह के संपर्क विद्यमान हैं और केंद्र की सत्ता को स्वीकार किया जाता है वहां भी हो सकता है कि केंद्र बाह्य परिधि पर अपने नियंत्रण को सुदृढ़ न बना सके। केंद्र और परिधि के बीच सघर्ष, राष्ट्रवाद के विरुद्ध एक प्रकार के पृथकतावाद का सवाल इतना नहीं हो सकता जितना कि बहुत अधिक विभाजित राजनीतिक प्रणाली को संचालित करने का।

संचालन समस्या का प्रमुख कारण केंद्र और परिधि के बीच संपर्कों की जटिलता है जो अक्सर इस बात के कारण और भी गहरी हो जाती है कि केंद्रीय विशिष्ट व्यक्ति परिधि क्षेत्र पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के प्रयत्न करते हैं। बहुत कम शासन हैं जो केंद्र और परिधि के विभिन्न संबंधों में आपसी संपर्क में आए हुए तकनीकी, अधिकारीतंत्र और राजनीतिक क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों के बीच कोई समुचित श्रेणीगत व्यवस्था बना सके हों। ऐसा बहुत कम होता है कि विकेंद्रीकरण के साथ साथ इस तरह के निश्चित निर्णय किए गए हों कि कौन किससे बड़ा है। दर्जा, सत्ता और अपने अनुयायियों को विशेष सुविधाएं प्रदान कराने की क्षमता को लेकर उत्पन्न होने वाले सघर्ष, राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। इस प्रकार के सघर्ष, नियुक्त किए गए अधिकारियों के बीच, या इन अधिकारियों और निर्वाचित अधिकारियों

के बीच, या स्थानीय राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों और स्थानीय अधिकारियों तथा तकनीकी क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों आदि के बीच होने लगते हैं।

यह समस्या केन्द्रीय विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा, परिधि क्षेत्र में विभिन्न दर्जोवाली श्रेणीगत व्यवस्था की स्थापना करने में विफल होने की समस्या नहीं है। वास्तव में बहुत कम शासनो के पास इस तरह की श्रेणीगत व्यवस्था स्थापित करने के मनमाने साधन हैं। अब चूँकि आर्थिक क्षमता बहुत कम है और इसका विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है इसलिए अपने समर्थकों अथवा अनुयायियों को संतुष्ट रखने के लिए विज्ञापन मुविधाओं आदि के बटवारे को अपने साधन बनाना केंद्रीय सत्तारूढ़ व्यक्तियों के लिए कठिन हो जाता है।⁵⁵ यह अनमर्थता न केवल राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों, बल्कि अधिकारी तंत्र के विशिष्ट व्यक्तियों की भी है। आइवरी कोस्ट में स्थानीय अधिकारियों के बारे में टिप्पणी करते हुए एक विद्वान ने कहा है कि 'हाल के वर्षों में (स्थानीय सरकारी अधिकारियों के छोटे-बड़े पदों) के प्रसार से ऐसे ऐसे व्यक्ति नियुक्त हो गए हैं जिनकी आवश्यकता लगभग न के बराबर है और जिनके पास कोई साधन ही नहीं है। प्रमुख कस्बों से बाहर तो प्रशासकीय व्यवस्था ऐसी होती है कि बड़ी मुश्किल से शायद कार्यालय में कोई एक आध क्लर्क ही और अक्सर एक टाइपराइटर भी नहीं होता'⁵⁶... राजनीतिक व्यवस्थाएं चाहे व्यक्तिगत हों या पार्टी अथवा नौकरशाही की हों, सभी, जैसाकि विएनन ने कहा है, 'अल्प विकास (सीमित संसाधन और कमजोर संगठन) के सीमित संसाधनों के दुष्प्रकार में फस सकती हैं।'⁵⁷

परिधि क्षेत्र में, अधिकारी तंत्र की मत्ता कहां समाप्त होती है और श्रेणीगत व्यवस्था कहां आरंभ होती है इसकी निश्चित सीमाएं नहीं हैं। नियुक्त किए गए अधिकारी, सिद्धांत रूप में, केंद्र के प्रतिनिधि हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे स्थानीय सहयोग पर बहुत निर्भर हैं, तभी वे कोई निश्चित ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप ये अधिकारी अपने ही स्थानीय समर्थक या अनुयायी (पुस्तैनी निष्ठाओं के आधार पर) बनाने लगते हैं, जो सरकारी साधन उनके पास हैं उनका दुरुपयोग करके आमदनी अपनी जेब में डालते हैं और स्वयं एक व्यवस्था के निर्माण के लिए नियमों का दुरुपयोग करते हैं।⁵⁸ जब इस तरह की बातें होती हैं तो केंद्र और परिधि के बीच के संपर्क लगभग टूट सकते हैं।

मत्ता और संपर्क के जटिल ढांचे अनिश्चित होने का एक और परिणाम है जिसकी वजह से ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। चूँकि स्थानीय स्तर पर मत्ता का इतना विकेंद्रीकरण है कि केंद्र तक अपनी पहुंच बनाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति बहुधा वर्तमान व्यक्तिगत, अधिकारी तंत्र और राजनीतिक व्यवस्थाओं की अपेक्षा करके आगे बढ़ने

का प्रयत्न करते हैं और केंद्रीय विशिष्ट व्यक्तियों के साथ आपसदारी के आधार पर अपने अपने काम कराते हैं। अन्य शब्दों में, वर्तमान व्यवस्थाएं विफल हो जाती हैं। जो भी विशेष सुविधाएं और धनराशि आदि उपलब्ध हैं वे अक्सर व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जबकि यह संबंध नए और अस्थायी होते हैं। इस प्रकार पुराने स्थापित संबंधों के माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता। केंद्र और परिधि के संपर्कों की जटिलता उस हालत में और भी बढ़ जाती है जब विशेष सुविधाएं प्राप्त करने वाले लोग नए संरक्षकों की खोज करने लगते हैं।

इस प्रकार घाना में :

विभिन्न स्थानीय दलों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक व्यापक व्यवस्था स्थापित की गई लेकिन इसे बिना इस्तेमाल किए, सीधे मुख्यालय अर्थात् क्षेत्रीय आयुक्त या स्वयं एन्क्रूमा से अपील करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक थी। कुछ लोग जो एन्क्रूमा तक पहुंचने की क्षमता रखते थे, यह मानकर चलते थे कि वे अन्य लोगों से अधिक 'पवित्र' हैं। ऐसे लोग साधारण रास्तों की बराबर उपेक्षा करते थे, और पार्टी के समाचारपत्र ने उन्हें बार बार यह चेतावनी दी कि 'राष्ट्रीय सचिवालय को केवल ऐसे ही मामले सीधे पहुंचाए जाएं जो बहुत गंभीर, जटिल और कठिन हों, और जिनका असर मुख्य नीति पर पड़ता हो। अगर कोई भी छोटा मोटा मामला अक्करा स्थित राष्ट्रीय सचिवालय के पास भेजा गया तो यह इस बात का संकेत होगा कि कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है या पार्टी का कोई सदस्य नियमित विधि का उल्लंघन कर रहा है।'⁵⁹

केंद्र और परिधि के बीच मतभेदों के सभी कारण परिधि में ही नहीं हैं। उदाहरण के लिए केंद्रीय विशिष्ट व्यक्ति असंगत नीतियां अपना सकते हैं, या अपेक्षाकृत बहुत ही थोड़े थोड़े समय बाद नीतियों में परिवर्तन कर सकते हैं। सैनेगल में पार्टी के गठन के कुछ ही समय बाद सैचोर शासन ने कई सुधार लागू किए जिनसे वास्तव में, परिधि क्षेत्र में अधिकारियों की स्थिति दृढ़ करने का प्रयत्न हुआ और काफी बड़े प्रभाव वाली पार्टी, यूनियन प्रोग्रेसिस्ट सैनेगालेज का प्रभुत्व कम हो गया।⁶⁰ स्थानीय पार्टी के विशिष्ट व्यक्तियों के मुकाबले अधिकारियों को और ज्यादा सत्ता मिली और पार्टी के स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति अपने अनुयायियों को विशेष लाभ पहुंचाने की शक्ति से वंचित कर दिए गए। परिणाम यह हुआ कि यू० पी० एस० पार्टी की शाखाएं, सैनेगल के विकास संबंधी जटिलताओं की प्राप्ति के लिए सरकार कि प्रयत्नों को संगठित करने की प्रक्रिया में कमजोर हो गईं।⁶¹

केंद्रीय विशिष्ट व्यक्तियों के बीच आपसी संपर्कों से ही केंद्र और परिधि क्षेत्र के बीच विभिन्न संपर्क कमजोर पड़ सकते हैं। घाना में इस प्रकार के संपर्कों के बारे में मार्टिन किलसन का कहना है कि उच्च दर्जे के विश्वविद्यालयीय विशिष्ट व्यक्तियों, जिनकी आवश्यकता सरकार चलाने के लिए थी और दूसरे वर्ग सी० पी० पी० के पदाधिकारियों के बीच प्रतिस्पर्धा और तनाव के कारण केंद्रीय नेताओं ने स्वयंसेवी संस्थाओं (मजदूर मंगठन आदि) को पार्टियों की शाखाओं में बदल दिया और इस प्रकार सी० पी० पी० के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पार्टियों के पदों पर नियुक्त किया।⁶² स्वयंसेवी संस्थाओं को पार्टियों की शाखाओं में बदलने के काम से लक्ष्य तो प्राप्त हो गया (और साथ ही काफी गुटबंदी भी हुई) लेकिन अंततः केंद्र और परिधि के संबंधों की दृष्टि से यह हानिकर था। एक तो स्वयंसेवी संस्थाओं को अर्धसरकारी संगठनों में बदलने से उनका प्रभाव कम हो गया क्योंकि वे अपने सदस्यों के हितों का ध्यान उतना नहीं रख सके जितना कि पहले रखते थे,⁶³ दूसरी बात यह हुई कि इस परिवर्तन से संस्थात्मक और व्यक्तिगत संपर्कों की एक नई स्थिति पैदा हो गई, जबकि स्थिति पहले ही बहुत उलझी हुई थी। उदाहरण के लिए युनाइटेड घाना फार्मर्स कौंसिल कोआपरेटिव्स ने राजनीतिक दृष्टि से बाछनीय कार्यकर्ताओं, जैसे क्षेत्रीय अधिकारियों, जिला अधिकारियों, क्रय-विक्रय अधिकारियों, भंडार अधिकारियों और ऐसे ही अन्य तीन हजार से ज्यादा व्यक्तियों को नौकरिया दीं।⁶⁴

एक अन्य उदाहरण के अनुसार भारत में 1966 के बाद कार्पेस हार्डिकमान के अंदर आपसी संपर्कों के कारण राज्यों की राजनीति पर केंद्रीय विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अपना प्रभाव जमाने की क्षमता में बहुत कमी आ गई। इसमें पहले कांग्रेस हार्डिकमान, निचले स्तरों पर बराबर होने वाली गुटबंदी को पार्टियों में फूट डालने में रोकने में सफल हुई (और विभिन्न गुटों को एक दूसरे की बातें मानने आदि के लिए बाध्य किया), लेकिन विशेषकर 1967 के बाद, हार्डिकमान में आपस में ही झगड़े हो गए, और राज्यों तथा जिला पार्टियों में एकता के लिए समझौते कराने का उसका प्रभाव बहुत कम हो गया। परिणाम यह हुआ कि व्यक्तिगत संपर्क (गुट) तेजी से बढ़े, जो कांग्रेस से अलग हो गए। परिधि क्षेत्र की स्थिति पहले की अपेक्षा अत्यंत अव्यवस्थित हो गई।

अंतिम विश्लेषण में, अल्पविकसित राज्यों में केंद्र और परिधि के बीच आपसी संबंध लगभग परस्पर विरोधाभास वाले हैं। एक ओर तो केंद्र और परिधि के बीच अमध्य संपर्क विद्यमान हैं, और इन दोनों के बीच संपर्कों का यह विशाल जाल बराबर बदलता रहता है, दूसरी ओर, अधिक सुसंगठित मंस्याएँ जैसे टागानिकन, अफ्रीकन नेशनल यूनियन, 'क्षेत्रीय, जिला और उपजिला मंस्याओं का एक समूह है, जो एक

दूसरे के साथ संपर्क रखती हैं और दारेमलाम स्थित मुख्यालय के साथ भी कभी कभी संपर्क में आती हैं।⁶⁵

यह संपर्क व्यवस्था अत्यंत निजी है और केंद्र तथा परिधि के बीच अलक्षित सत्ता संबंधों, और संरक्षण पर निर्भर है।

अलग अलग अभिनेताओं, सरकारी मस्थाओं, राजनीतिक पार्टियों स्वहित वाले दलों, के संदर्भ में राजनीति पर विचार करने की आदत बड़ी मुश्किल से जाती है। और फिर भी यह आदत बहुधा ऐसी वृत्ति को जन्म देती है, कि अल्पविकसित राज्यों की राजनीति के मुख्य मुख्य भेदों की उपेक्षा कर दी जाती है। ये मुख्य भेद हैं इन अल्पसंख्यक राज्यों का अस्पष्ट, अनाकार और अनियमित होना। बाह्य रूप से जो संस्थाएं नजर आती हैं, वे आंतरिक दृष्टि में वास्तव में विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मिलन हैं और बाहरी तौर पर ये, व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित समूह हैं। ये सभी केवल सरकार और उससे प्राप्त होने वाले विशेष अधिकारों तक अपनी अपनी पहुंच के कारण उत्पन्न अस्थाई एकता के सूत्र में बंधे हैं। संस्थाओं के निर्माण का हमेशा ही यह परिणाम नहीं हुआ है कि कोई स्थाई विधियां और आचार-नियम बन पाए हो। सैमुअल हंटिंगटन ने इस प्रक्रिया की विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार किया है : 'संस्थाएं, स्थिर, श्रद्धेय और बार बार अपनाए जाने वाले आचार-व्यवहार की प्रारूप हैं।'⁶⁶ इस बात की संभावना अधिक है कि संस्थाएं, केंद्रीय विशिष्ट व्यक्तियों की आपसी क्रिया-प्रतिक्रिया और डम वर्ग तथा परिधि क्षेत्र के बीच की क्रिया-प्रतिक्रिया के अस्थाई और अक्सर वनन-टूटने वाले संबंधों का सुखीटा हों। अल्पविकसित राजनीतिक प्रणालियों में जिस प्रकार का व्यक्तिगतवाद सभी जगह व्याप्त है, वह कभी कभी एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया का मूजन करता हुआ प्रतीत होता है जो न केवल संस्थात्मकता में परे है बल्कि वास्तव में इसका विरोधी है।

संदर्भ

1. ये विचार एडवर्ड शिन्स के हैं। उन्होंने केंद्र की परिभाषा इस प्रकार दी है : 'समाज का संचालन करने वाले प्रतीक, मूल्य और आस्थाओं का केंद्र - यह सम्पाओं के अंदर भूमिकाओं और व्यक्तियों की गतिविधियों का ढांचा है - केंद्रीय सम्पायक प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचने से ही शासक वर्ग को सत्ता प्राप्त होती है। एडवर्ड शिन्स : 'मिटर ऐंड वेरीकरी', दि लाजिक ऑफ पर्सनल गानेज : एमेज प्रेजेंटेंड टू मारकन पोपान्सी (सदन : एटनेज ऐंड बेगनपात, 1961), पृ० 117, 125.
2. ऐरिस्टिड जोनवर्ग - दन पार्टी गवर्नमेंट इन दि आइवरी कोस्ट (प्रिन्टन - प्रिन्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1964), पृ० 323-324

3. उदाहरण के लिए देखिए, डेविड ऐस्टर . दि पालिटिकल आफ माडर्नाइजेशन, (शिकागो : यूनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस, 1967), विशेषकर पृ० 313-356.
4. डेविड ऐस्टर घाना इन ट्रांजीशन, (न्यूयार्क : एथेनियम, 1963).
5. हैनगे विएनन . तंजानिया : पार्टी ट्रांसफार्मेशन ऐंड इकोनामिक डेवलपमेंट (प्रिस्टन : प्रिस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1970), पृ० 5.
6. ऐंरिस्टिड जोलबर्ग : त्रिएंटिग पालिटिकल आर्डर दि पार्टी स्टेट्स आफ वेस्ट अफ्रीका, (शिकागो : रैंड-मैकनेली ऐंड कंपनी, 1966), पृ० 138.
7. ऐसे अध्ययनों के लिए देखिए, विशेषकर, जोलबर्ग त्रिएंटिग पालिटिकल आर्डर, और विएनन : तंजानिया ।
8. रजनी कोठारी पालिटिकल इन इंडिया, (बोस्टन : लिटिल ब्राऊन ऐंड कंपनी, 1970), पृ० 159
9. सैनिक शासनो का विश्लेषण इस पुस्तक में अलग से किया जाएगा क्योंकि इस प्रकार की घटनाएँ हाल में होनी शुरू हुई हैं और इनमें वृद्धि होती जा रही है, और क्योंकि सम्मिलन की इस प्रक्रिया के सबंध में अधिकांश सैनिक विशिष्ट व्यक्तियों के विचार बिल्कुल भिन्न हैं फिर भी कुछ सबंध चुननाएँ यहाँ की गई हैं. देखिए अध्याय 5.
10. श्रीलंका की पार्टी प्रणाली के लिए देखिए, काल्विन वुडवर्ड : दि ग्रोय आफ ए पार्टी सिस्टम इन सिंगल, (प्रावीडेंस ब्राउन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1969).
11. यूनाइटेड नेशनलिस्ट पार्टी : मैनीफेस्टो ऐंड कास्टीच्यूशन (1947), अनुच्छेद 3 और 9.
12. वुडवर्ड, पृ० 73.
13. सिएरा लियोने के बारे में देखिए, मार्टिन किलसन : पालिटिकल चेंज इन ए वेस्ट अफ्रीकन स्टेट (कैम्ब्रिज, मैसाच्युसेट्स : हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1966) और जान आर० कार्टराईट : पालिटिकल इन सिएरा लियोने 1947-1967 (टोरंटो : यूनिवर्सिटी आफ टोरंटो प्रेस, 1970)-
14. पुश्तैनी सत्ता के सबंध में मैक्स वैबर ने दि थ्योरी आफ सोशल ऐंड इकोनामिक आर्गनाइजेशन में लिखा है. अनुवाद : टालकोट पार्संस द्वारा, (न्यूयार्क : फ्री प्रेस, 1957). वैबर ने कहा है कि पितृवाद वहाँ विद्यमान है 'जहाँ सत्ता मूल रूप से परंपराओं से मिलती है लेकिन व्यावहारिक रूप में इसका प्रयोग व्यक्तिगत सत्ता के अधिकार से होता है.' पृ० 347.
15. वही, पृ० 341
16. जान वाटर्बर्गे . कमांडर आफ दि फेंग्युल (न्यूयार्क : कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1970), पृ० 270
17. वही.
18. प्रारंभ में जिन्हें एक स्तंभीय पार्टियाँ कहा गया था उनके अंदर सपनों का अच्छा विश्लेषण करने के लिए, पितृवाद को एक सैद्धांतिक विचार के रूप में सबसे पहले जोलबर्ग ने प्रस्तुत किया था; त्रिएंटिग पालिटिकल आर्डर, पृ० 141-142; और विशेष रूप से स्वेयर राय : 'पर्मनन इस्तरगिप, पैट्रीमोनियोलिग्य, ऐंड एंपायर बिल्डिंग इन दि न्यू स्टेट्स', बर्लैंड पालिटिकल XX, 2 (1968), 194-203. जोलबर्ग, पितृवाद को ऐसी स्थितियों तक ही सीमित रखना चाहते हैं जहाँ करिष्मा एक 'दैनिक' बात बन चुका है जे० सी० विलियम ने, पैट्रीमोनियोलिग्य,

एंड पालिटिकल चेंज इन दि कागो (स्टैन्फोर्ड : स्टैन्फोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1972) में इस विचार का प्रयोग करने का प्रयत्न किया है। लेकिन विलियम ने 'पिनूचाद के युग' को कागो में उसी अवधि में ही रखा है जब निजी सेनाएं एक दूसरे से लड़ती थीं (1960-1965)

19. इन नेताओं और उनके राज्यों के बारे में पहले बताया गए अध्ययन देखिए : एच० एन० ब्रेटन की दि राइज ऐंड फाल आफ क्वाय्म एन्क्रूमा (लंदन प्रेंजर, 1967) में एन्क्रूमा के व्यक्तिगत प्रभावों से शासन चलाने के बारे में काफी बड़ा चर्चाकर कहा गया है, फिर भी इस पुस्तक में काफी सूचना मिलती है.
20. एडगर शोर : दि थाई ब्यूरोक्रेसी, ऐडमिनिस्ट्रेटिव सायम क्वाटंरली, V, (जून 1960), 70 थाईलैंड के विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए, डेविड ए० विल्सन पानिटिकम इन थाईलैंड, (इयाका : कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1962)
21. इस तर्क के विस्तार के लिए देखिए, जेराल्ड ए० होगर 'ब्यूरोक्रेसी, पालिटिकल पार्टीज ऐंड पालिटिकल डेवलपमेंट', वर्ल्ड पालिटिकम, XXV, 4, (जुलाई 1973), 600-607
22. पारस्परिकता का सिद्धांत सबसे पहले किलसन ने रखा था . पालिटिकल चेंज इन ए वेस्ट जफोकन स्टेट (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस : हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1966), विशेष रूप से देखिए, पृ० 252-280
23. एक पार्टी विचारधारा पर काफी टिप्पणी हुई है विशेषकर देखिए, चार्ल्स एंट्रेन . डिमोक्रेसी ऐंड सोशलिज्म, आइडियोलॉजीज आफ अफ्रीकन लीडर्स, डेविड ई० एंफ्टर (संपादित) : आइडियोलॉजी ऐंड डिमोक्रेसी, (न्यूयार्क . फ्री प्रेस, 1964), 157-169, जोनबर्ग . वि-ए-टिंग पालिटिकल आर्डर पृ० 37-65; जेम्स हीफ्री : दि आर्गनाइजेशन आफ ईजिप्ट इन डि-केसीज आफ ए नान पालिटिकल माडल फार नेशन बिनिडिंग, 'वर्ल्ड पालिटिकम, XVIII', 2 (1966), 177-183 और देखिए, बर्नार्ड निक : इन डिफेंस आफ पालिटिकम (शिकागो : यूनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस, 1972).
24. सायड फानस और आर्टो रिचर्ड्स (संपादित) दि फिन्स मेन, (लंदन : आक्सफोर्ड यूनि-वर्सिटी प्रेस, 1964), पृ० 99
25. राइनहार्ड बैडिकम . मैक्स वैबर : ऐन इटैलेबचुअप पोर्ट्रेट, (गार्डन सिटी, न्यूयार्क डबल डे ऐंड कंपनी, 1962), पृ० 336.
26. क्लोमेंट एच० मूर . पालिटिकम इन नाथ अफ्रीका (बोस्टन : लिटिल, ब्राउन ऐंड कंपनी, 1970), पृ० 204
27. मार्टिन किल्सन : 'दि ग्रासस्ट्रस इन घानयन पालिटिकम', फिलिप फोस्टर और ऐरिस्टिड जोन-बर्ग (संपादित) : घाना ऐंड दि आइवरी कोस्ट (शिकागो : यूनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस, 1971), पृ० 116
28. इस सीमा समस्या से बनने वाली नीतियों के बारे में विचारों के लिए देखिए, मैथ्रिकम मैरियट : 'बल्चरल पालिमीज इन दि न्यू स्टेट्स', क्लिफर्ड गोल्ड (संपादित) : ओन्ट मॉगायटीज ऐंड न्यू स्टेट्स, (न्यूयार्क : फ्री प्रेस, 1963).
29. विशेष रूप से देखिए, क्लिफर्ड गोल्ड : 'दि इटिप्रेटिव रिबोन्सूशन : प्रिमोर्डियल सेंटीमेंट्स ऐंड निविक पालिटिकम इन दि न्यू स्टेट्स', 3 प्रॉब्लम में, पृ० 105-157

30. परिधि (या उसका कुछ भाग) वास्तव में कब और किन परिस्थितियों में उपराष्ट्रीय बनती है, ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें यदि एक ही जैसा मान लिया जाए तो उनका महत्व ही नहीं रहेगा, इस विषय पर, और इसके सबद्ध विषयों पर चौथे अध्याय में लिखा गया है.
31. मकड़ उत्पन्न होने के कारणों और परिस्थितियों आदि के बारे में लियोनार्ड बिडर और अन्य लेखकों ने बताया है. थॉमस एंड सोकवेंसिज इन पालिटिकल डेवलपमेंट, (प्रिन्स्टन : प्रिन्स्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1971) और देखिए रेमंड ग्रियू, 'राइसिस आफ पालिटिकल डेवलपमेंट', वॉशिंगटन डी० सी० में अमरीकन पालिटिकल सायंस एसोसिएशन की 1972 में हुई वार्षिक बैठक में पढ़ा गया निबंध.
32. मिटनी बर्बा 'सीकवेंनेज एंड डेवलपमेंट', बिडर और अन्य, पृ० 286-316 पर
33. बुडवर्द, पृ० 178
34. उदाहरण के लिए देखिए, वालें एच० लैंडे 'नेटवर्क एंड ग्रुप इन साऊथ ईस्ट एशिया : मम आउटग्रेशन इन दि ग्रुप थ्योरी आफ पालिटिक्स', अमरीकन सायंस रिव्यू, LXVII, (1973), 103-127
35. इन सबद्ध में लैमरचंद का कहना है : 'राजनीतिक दक्षता का सागरत्व है आर्थिक साम पहुंचाकर. अपने समर्थकों को अपने अनुयायी बनाए रखने की क्षमता'. रेने लैमरचंद 'पालिटिकल क्वायटेरिज्म एंड एथनोसिटी इन ट्रापिकल अफ्रीका : कापीटल सालिडेरिटीज इन नेशन बिल्डिंग' अमरीकन पालिटिकल सायंस रिव्यू, LXVI, 1, (1972), 79.
36. अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखिए, सी० डी० मेरियम और एच० एफ० गोस्नेल : दि अमरीकन पार्टी सिस्टम (न्यूयार्क : मैकमिलन एंड कंपनी, 1949); और एडवर्ड बैनफोल्ड पालिटिकल इन्फ्लूएंस (न्यूयार्क की प्रेस, 1961). अफ्रीकी राजनीतिक पार्टियों के मामले में व्यवस्था के आदर्शों को लागू करने के हैनरी बिएनत सबसे अधिक समर्थक रहे हैं देखिए उनकी पुस्तक, तत्रानिमा, पृ० 3-15, उनकी, 'पालिटिकल मॉडल इन अफ्रीका' माइकेल नापची (संपादित) : दि स्टेट आफ नेशन कस्टुम्स थान डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट अफ्रीका (बर्कले एंड लास ऐंजिल्स यूनिवर्सिटी आफ कैलीफोर्निया प्रेस, 1971); और उनकी 'वन पार्टी सिस्टम इन अफ्रीका' सीमुअल पी० इटिंगटन और ब्लीमेंट एच० मूर (संपादित) : अपार्टिटेरियन पालिटिक्स इन माउंटेन सोसायटी (न्यूयार्क वेस्लिक बुक्स, 1970), पृ० 99-127.
37. मायरल बीनर पार्टी बिल्डिंग इन ए न्यू नेशन (लिकायो : यूनिवर्सिटी आफ लिकायो प्रेस, 1967), पृ० 14-15, 473.
38. सी० एम० व्हिट्टेकर : दि पालिटिक्स आफ ट्रेडींग (प्रिन्स्टन प्रिन्स्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1970), पृ० 375.
39. लैमरचंद, पृ० 86
40. ए० एफ० पी० एफ० एन और बर्मा के बारे में देखिए, फ्रैंक एन० ट्रेजर : बर्मा : फ्राम डिग्रेडम टु रिपब्लिक, (न्यूयार्क : डब्ल्यू ए० प्रेजर, 1966), पृ० 166-214 और रिचर्ड बर्टन : ऊ नू आफ बर्मा, (स्टेन्फोर्ड : स्टेन्फोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1966) पृ० 146-171.
41. ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों को एक ही मानने की कृति इस तथ्य से उपजी कि अमरीकी व्यवस्थाएँ लगभग हमेशा ही राजनीतिक पार्टियाँ थीं. इन प्रकार, बैनफोल्ड ने इन व्यवस्थाओं को परिभाषा दी, 'वे पार्टियाँ जो राजनीतिक सिद्धान्तों में निष्ठा के बजाय भौतिक लाभों के प्राथम्य पर अधिक निर्भर करती हैं' (पृ० 237).

42. घाटखरी, पृ० 269 इथियोपिया, ईरान और बुर्डी में 1962 से 1968 के बीच, राजमहलों में ऐसी ही व्यवस्थाएँ थी
43. रिचर्ड ई० स्ट्राइकर : 'पालिटिकल ऐंड ऐडमिनिस्ट्रेटिव लिंकेज इन दि आइवरी कोस्ट', फोसटर और जोलवर्ग में, पृ० 86-87
44. वहाँ, पृ० 87.
45. लंडे, पृ० 116
46. परंपरा से ही, 'विकेंद्रीकरण' केवल प्रशासनिक और तकनीकी वर्गों का ही किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए देखिए, एम० जे० कैंपबेल और अन्य दि स्ट्रक्चर आफ लोकल गवर्नमेंट इन वेस्ट अफ्रीका (दि हेग : एम० निशाफ, 1965) हम चूँकि यह कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर पार्टी के व्यक्तियों की नियुक्ति किया जाना, अक्सर इसलिए होता है कि स्थानीय शाखाओं के बढ़ते केंद्रीय पार्टी की शक्ति बढ़े, इसलिए 'विकेंद्रीकरण' शब्द, राजनीतिक पार्टियों पर भी समान रूप से लागू प्रतीत होता है
47. जोलवर्ग : त्रिएटिंग पालिटिकल आर्डर, पृ० 115
48. तीन राज्यों में इस प्रकार के श्रेष्ठ तुलनात्मक अध्ययन के लिए देखिए, डगलस ऐशफोर्ड नेशनल डेवलपमेंट ऐंड लोकल रिफार्म (प्रिस्टन प्रिस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1967)
49. उदाहरण के लिए देखिए, विएनन तजानिया, विशेषकर, पृ० 112-157
50. डेनिस एल० कोहन : 'दि कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी आफ घाना - रिप्रिजेंटेशनल आर सालिटेरिटी पार्टी', कनेडियन जर्नल आफ अफीकन स्टडीज, VI, 2 (1970), 177
51. मैनिंग नैश : दि गोलडन रोड टु माडर्निटी, (न्यूयार्क जान बाईली ऐंड सम, 1965) पृ० 93-94 यह ठीक है कि सभी गावों में इस प्रकार की गतिविधियाँ नहीं होती, लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है कि नैश एक ऐसे युग के बारे में लिख रहा है जबकि राजनीतिक केंद्र में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी, और लगभग सैनिक विद्रोह की स्थिति थी
52. मायरन बीनर : 'रोल परफार्मेंस ऐंड दि डेवलपमेंट आफ माडर्न पालिटिकल पार्टीज : दि इथियन केस जर्नल आफ पालिटिक्स, XXVI, 4, (नवंबर 1964), 835
53. इन मतों का विश्लेषण किया गया है, लायड आई० हडोल्फ और सूसन होबर हडोल्फ की पुस्तक, दि माडर्निटी आफ ट्रेडीशन, (शिकागो : यूनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस, 1967) में
54. देखिए, डेनिस आस्टिन : पालिटिक्स इन घाना, 1946-1960 (सदन : आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1970) पृ० 250-315. यहाँ इन सघर्षों के बारे में लिखा गया है.
55. विएनन : 'पालिटिकल मशीस इन अफ्रीका', पृ० 204.
56. स्ट्राइकर, पृ० 93.
57. विएनन : तजानिया, पृ० 412.
58. समाज में झूठाचार के प्रभावों का विषय बड़ा जटिल है. इसपर विचारों के लिए देखिए, जेम्स सी० स्काट : 'दि एनालिसिस आफ करप्शन इन सोमायटी ऐंड हिस्ट्री, XI, 3 (जून 1969), 315-341; और उनकी पुस्तक, कंफेरेटिव पालिटिक्स करप्शन (एंगलवुड क्लिफ्स, एन० जे० प्रेंटिस हॉल, 1972).

59. मैल्विन रियास . 'दि घ्योरी ऐंड प्रैक्टिस आफ अफ्रीकन वन पार्टीइज्म : दि सी० पी० पी० रिइज्जामिड, कनेडियन जर्नल आफ अफ्रीकन स्टडीज, IV, 2 (1970), 157; पार्टी क्रानिकल, XXXVI के (जून 1964) का हवाला देते हुए.
60. बनीमोंट कार्टिधम . 'पालिटिकल कसालीउेशन ऐंड सेंटरलोकल रिलेशस इन सेनेगल', कनेडियन जर्नल आफ अफ्रीकन स्टडीज, IV, 1 (1970), 103
61. वही.
62. किल्सन . 'दि ग्रामरूट्स इन घानयन पालिटिक्स', पृ० 119
63. 'पार्टी राज्य' के साथ किसी कार्यकारी दल के संबंधों के अध्ययन के लिए देखिए, विलियम टार-डाफ : 'ट्रिंड यूनिवर्सिटी इन तंजानिया', 'जर्नल आफ डेवलपमेंट स्टडीज, II, 4 (1966), 408-430.
64. किल्सन, पृ० 120
65. बिण्टन . तंजानिया, पृ० 413.
66. सैमुअल हटिंगटन पालिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसायटीज, (न्यू हेवन : येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1968) पृ० 12

अस्थिरता की राजनीति

हाल के वर्षों में लगभग प्रत्येक अल्पविकसित देश को किसी न किसी रूप में राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा है : सैनिक क्रातिया और विद्रोह, विप्लव, राजनीतिक हत्याएं, दंगे, अस्तव्यस्त गुटों के नेताओं में आपसी संघर्ष आदि। शिकायत की गई है कि इस प्रकार की अस्थिरता की घटनाएं, समाजविज्ञान के विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार नहीं हुईं क्योंकि 'संघर्षों और अव्यवस्था की घटनाओं का कोई संबंध, परिवर्तनीय स्थितियों, जैसे उपनिवेशवाद, आकार, पार्टियों की संख्या, और आर्थिक तथा सामाजिक विकास' के साथ नजर नहीं आया।¹

इस अस्थिरता के स्रोत और कारण क्या हैं? पिछले डेढ़ दशक के दौरान इन प्रश्नों के जो उत्तर मिले हैं, वे सभी एकरूपता लिए हुए हैं। अल्पविकसित राज्य इसलिए अस्थिर हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक संस्थाएं सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के परिणामों का संचालन करने की क्षमता नहीं रखती। इस तर्क को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1. अल्प विकसित राज्यों पर आधुनिकीकरण का प्रभाव बहुत असंतुलित है।

हालांकि नई राजनीतिक इकाइयों ने एक ऐसा क्षेत्रीय ढांचा प्रस्तुत किया जिसके अंदर औपनिवेशिक सत्ता के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, हमें इस बात की बराबर चेतना हो रही है कि यद्यपि ये प्रक्रियाएं आपस में संबद्ध हैं फिर भी उनमें भिन्नता अनिवार्यतः बहुत 'तालबद्ध' नहीं है अर्थात् ऐसा नहीं है कि यह एक ही गति से हुई हों' . . .।²

संभवतः आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता यह है कि यह अभूतपूर्व रही है। विशेषकर परिवर्तन की प्रक्रिया, और 'केंद्रीय' और 'स्थानीय' स्तरों के बीच संक्रमण की प्रक्रिया के संबंधों की दृष्टि से।¹

2 आधुनिकीकरण का अर्थ है मागों में तेज वृद्धि, विशेषकर उन आधुनिक दलों की ओर से, जिनपर नई राजनीतिक प्रणाली सबसे अधिक निर्भर करती है।

सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन राजनीतिक मांगों को बढ़ाते हैं, और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने वालों की संख्या में वृद्धि करते हैं। इन परिवर्तनों में राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक समस्याओं के परंपरागत स्रोतों का प्रभाव कम हो जाता है, ये परिवर्तन राजनीतिक एमोसिएशनों के नए आधार और नई राजनीतिक समस्याओं की स्थापना की समस्याओं को अत्यंत जटिल बना देते हैं।²

जिस किसी भी देश में जनसाधारण को साथ लेकर चलने की प्रक्रिया शुरू होती है वहां इसके साथ साथ राजनीतिक विचारों में प्रभावित लोगों की संख्या में भी वृद्धि होती है। जब लोग भौतिक और बौद्धिक दृष्टि से अपने सीमित स्थानीय दायरे तथा अपनी पुरानी आदतों और परंपराओं की सीमाओं से उछाड़े जाते हैं, तो वे अपनी आवश्यकताओं में भी बहुत बड़े परिवर्तन का अनुभव करते हैं। हो सकता है कि अब उन्हें मकान और नौकरी, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, और समय समय पर होने वाली बेरोजगारी के खतरे से सुरक्षा, अपने और अपने बच्चों के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधा की आवश्यकता महसूस होने लगे। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उन्हें बहुत बड़े परिमाण में विभिन्न प्रकार की नई सरकारी सेवाओं की आवश्यकता होने लगती है।³

(अ) व्यक्तियों के तीन निर्णायक वर्ग हैं जिनकी ओर से चुनौती मिल सकती है। ये वर्ग हैं सरकारी के अतिरिक्त कर्मचारी, मैनिक कर्मचारी और युवा वर्ग। राजनीतिज्ञों के बाद समाज में सरकारी कर्मचारियों का ही वर्ग ऐसा है जो आय और प्रतिष्ठा की दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट वर्ग है। अपने कार्य और प्रशिक्षण के कारण, सरकारी कर्मचारियों ने अपने यूरोपीय पूर्ववर्तियों जैसी जीवन पद्धति अपना ली है। वे सोचते हैं कि अन्य देशवासियों की अपेक्षा वे क्षमता और प्रशिक्षण की दृष्टि से इस योग्य हैं कि शासन का संचालन करें, न कि, केवल नीतियों को कार्यात्मक देने के माध्यम मात्र रहें। जल्दी जल्दी

पदोन्नतियों के कारण जिन्हें पदोन्नति मिली है वे और जिनको पदोन्नतियां नहीं हो पाई हैं वे भी महत्वाकांक्षी हो जाते हैं । . . . मैनिक कर्मचारी भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति व्यवहार करने लगते हैं । . . .

. . . लगभग प्रत्येक संस्था के क्षेत्र में पीढ़ियों के बीच अंतर देखा जा सकता है . . . । (ऐसा) संघर्ष, युवा वर्ग के असंतोष के कारण और तीव्र हो जाता है । यह असंतोष इस बात से झलकता है कि युवा वर्ग पुराने स्थापित नियमों और मानदंडों का उल्लंघन करने लगता है । साथ ही यह असंतोष समान आयु के लोगों के आंदोलनों और मंगठनों के उभरने में भी व्यक्त होता है । ये आंदोलन और मंगठन औद्योगिक दृष्टि से विकसित समाज के युवक दलों का व्यावहारिक रूप हैं, जो अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र होकर काम करना चाहते हैं ।⁶

3. मांगों में वृद्धि और अनुपलब्ध साधनों के लिए विभिन्न संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण संप्रदायों का राजनीतिक विभाजन हुआ है और इनके आपसी तनावों में भी वृद्धि हुई है ।

अफ्रीका में विभिन्न दलों के बीच पहले से विद्यमान भेदभावों में कुछ अन्य दलों ने वृद्धि की जो यूरोपजन्य परिवर्तन के असंतुलित प्रभाव से उपजे थे . . . साधारणतया, दो समूहों के बीच प्रायः कोई भी भेद या अंतर, राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकता है ।⁷ . . . सामाजिक संघटन और प्रतिस्पर्धित आधुनिक क्षेत्र की इस पृष्ठभूमि में ही, बहुत सी संस्कृतियों वाले समाज में सांप्रदायिक संघर्ष को समझने की जरूरत है . . . बहुसांस्कृतिक समाज के सदस्यों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे प्रतिस्पर्धा से भरे इस विश्व को सांप्रदायिक नजरिए से देखते हैं और सांप्रदायिक भावनाओं के लिए की गई अपील के प्रभाव में आ जाते हैं । इसलिए सांप्रदायिकता एक प्रकार का अवसरवाद बन जाती है । इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि किसी एक प्रतिस्पर्धा के परिणाम के लिए सांप्रदायिक मानदंडों की कोई आवश्यकता नहीं है । महत्व की बात यह है कि आमतौर पर यह विश्वास किया जाता है कि व्यक्तियों का भाग्य उनके संप्रदाय और संपर्कों पर निर्भर करता है ।⁸

4. आधुनिक राजनीतिक संस्थाएं अभी इतनी नई हैं कि उनमें बड़ी हुई मांगों को पूरा करने की क्षमता नहीं है ।

राजनीतिक संस्थानीकरण के संदर्भ में देश का राजनीतिक पिछड़ापन सरकार

के लिए विभिन्न मांगों को विशेषकर उन मांगों को जिन्हें वैध तरीकों से व्यक्त किया जाता है और जिनको राजनीतिक प्रणाली के अंदर साधारण एकीकृत रूप में रखना होता है, पूरा करना असंभव नहीं तो कम से कम कठिन अवश्य बना देता है। इसीलिए राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सख्या बहुत बढ़ जाती है जिससे राजनीतिक अस्थिरता की आशंका उत्पन्न हो जाती है।⁹

इस सामान्य तर्क के साथ बहुधा एक और बात कही जाती है। अक्सर यह कहा जाता है कि अस्थिरता ऐसे नेताओं के कारण आती है जो 'सुयोग्य' नहीं होते, इस अर्थ में कि उनमें 'आधुनिकीकरण की वृत्ति और सरकार चलाने का औपचारिक कौशल बहुत कम होता है।'¹⁰

यहां उदाहरण के साथ दिया गया तर्क साकेतिक है और एक ऐसे भाजुक राजनीतिक केंद्र का चित्र प्रस्तुत करता है जिसपर परिधि का परंपरावाद हावी है। लेकिन इस तर्क और इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए चित्र, दोनों को लेकर कुछ कठिनाइयां हैं।

पहली बात तो यह है कि संस्थानीकरण (इंस्टिट्यूशनलाइजेशन) और संस्थात्मक क्षमता को जो विशेष महत्व दिया गया है वह वंसा ही पक्षपातपूर्ण है जैसाकि इस पुस्तक के प्रारंभ में बताया गया है। पक्षपातपूर्ण इस संदर्भ में है कि परिवर्तन तो अनिवार्य है और आवश्यकता केवल इसके समुचित संचालन की है। अस्थिरता को इस अर्थ में अनिवार्य माना जाता है कि यह अस्पष्ट विचारों वाले या भ्रष्ट नेताओं, गलत ढंग से नियोजित आर्थिक कार्यों, अपर्याप्त रूप से नियंत्रित जनसहयोग आदि की चरम परिणति है। इसके साथ ही यह इन अर्थों में अनिवार्य नहीं है कि ये सभी विकार दूर किए जा सकते हैं या इनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। नए नेता चुनकर, और अच्छी योजनाएं बनाकर और अधिक अनुशासन लागू करके इस तरह का परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन इस बात का प्रमाण बहुत कम है कि विकारों को दूर करने से संबंधित कथन सत्य है। अनुभव से यही सिद्ध हो रहा है कि अस्थिरता भयंकर रूप में है। कभी ऐसा नजर नहीं आता कि नेता बहुत अच्छे स्तर के हों, या योजनाएं काफी प्रगतिशील हो। अब सवाल यह उठता है कि अल्पविकसित राज्यों में, चाहे किसी राज्य का शासन चलाने वाले कितने ही बुद्धिमान क्यों न हों, राजनीतिक अस्थिरता किस सीमा तक अनिवार्य है। अल्पविकसित राज्यों की राजनीतिक प्रक्रिया में अस्थिरता अंतर्निहित है। राजनीतिक केंद्र में राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों के बीच आपसी सामंजस्य का उतना सुदृढ़ न होना, उनके गठबंधन अल्पकालिक होना और उनके आपसी झगड़ों के कारण इनकी संधियों के टूटने का खतरा सदा बने रहना,

ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे लगभग अनिवार्यतः कोई भी राजनीतिक सस्था दुर्बल और खोखली हो जाती है।

दूसरी बात है मांगों में वृद्धि की। सिद्धांत रूप में तो यह बात बड़ी प्रभावशाली लगती है लेकिन वास्तव में यह कुछ अस्पष्ट सी है। कितनी वृद्धि को अत्यधिक माना जाए? हमें इसका पता कैसे लगे? क्या हमें इन बातों का पता तभी लग सकता है जबकि कोई प्रणाली ढह गई हो और अपने पीछे अपर्याप्त जानकारी छोड़ गई हो जिससे कोई दूसरे कारण खोजे जा सकें? बहुधा ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिकीकरण के कारण, मांग और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने वालों की संख्या में वृद्धि का बोझ केंद्र पर उतना नहीं पड़ता जितना कि उसे व्यक्तिवाद और गुटबंदी से खतरा होता है।

इस कथन और वर्तमान तर्क के बीच अंतर बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण है। यह कहने के बजाय कि अस्थिरता का खोत राजनीतिक गतिविधियों में लोगों का अधिक संख्या में शामिल होना ही है, यह कहा जा रहा है कि स्वयं राजनीतिक विशिष्ट व्यक्ति ही अस्थिरता के प्रमुख कारण हैं। उनकी आपसी एकता का कमजोर होना, और राजनीतिक प्रणाली में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति, ये दोनों ऐसी बातें हैं जिनमें केंद्र अस्थिर हो जाता है। सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों की संख्या में वृद्धि ने यह समस्या बढ़ती ही है क्योंकि राजनीतिक केंद्र में सत्ता के महत्वपूर्ण पदों की संख्या भी बढ़ती है।

विशिष्ट व्यक्तियों के आपसी संघर्ष के कारण अल्पविकसित राज्यों में पृथक समूहीकरण होने लगता है। पुराने जमाने में ही इस समूहीकरण को पृथक्तावादी प्रणालियों के साथ संबद्ध किया जाता रहा है। किमी झगड़े से संबद्ध विशिष्ट व्यक्ति के संपर्क वाले दल और अन्य विशिष्ट लोग भी उस विवाद में उलझ जाते हैं और धीरे धीरे कई बड़े बड़े गुट उभर आते हैं।¹¹ इस तरह के संघर्ष से एक तरह की गुटबंदी की प्रक्रिया शुरू होती है क्योंकि संघर्षरत विशिष्ट व्यक्ति, व्यक्तिगत समर्थन के लिए अपने समर्थकों का दायरा विस्तृत करने का प्रयत्न करते हैं। इसी तरह अन्य विरोधी विशिष्ट व्यक्ति भी अपने अपने अनुयायियों को जुटाने लगते हैं।

इस तरह की गुटबंदी या दल विरासत निर्माण (पैट्रिमनी बिल्डिंग) की वृत्ति अलग अलग तरीकों से उभरती है। राजनीतिक विशिष्ट व्यक्ति अपने समर्थकों को अपने पीछे लगाए रखने के लिए परंपरागत संबंधों की दुहाई दे सकते हैं या सैद्धांतिक मामलों को उठाकर अपील कर सकते हैं। या फिर वे अधिकारीतंत्र और सेना के विशिष्ट

व्यक्तियों को शामिल करने के लिए व्यक्तिगत आधार पर गठजोड़ कर सकते हैं। अन्य शब्दों में, विशिष्ट व्यक्तियों के बीच संघर्ष और गुटबंदी अक्सर सांप्रदायिकता और मौनिक हस्तक्षेप की घटनाओं का रूप ले लेते हैं।

गुटबंदी और विरासत निर्माण

इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि अल्पविकसित राज्यों के राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों के बीच गुटबंदी की प्रवृत्ति क्षेत्रीय है। लेकिन, गुटों की इस प्रकार से परिभाषित करने की प्रवृत्ति भी है, कि विभाजनो में, लगभग अनिवार्य और कभी न दूर होने वाले मतभेद प्रतिबिंबित होते हैं। इसका एक उदाहरण है विशिष्ट व्यक्तियों के आपसी संघर्ष का सैद्धांतिक दृष्टि से विश्लेषण। उदाहरण के लिए जान कार्टस्की ने राष्ट्रवादी विशिष्ट व्यक्तियों (जिन्हें वे 'आधुनिक रूप देने वाले' कहते हैं) के बीच स्वाधीनता के बाद उपजे संघर्षों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सबसे पहले सैद्धांतिक मतभेदों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।¹² अन्य तथाकथित अनिवार्य मतभेदों जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर ही अलग अलग पीढ़ियों के लोगों के बीच संघर्ष और विभिन्न जातीय पृष्ठभूमियों वाले विशिष्ट व्यक्तियों के बीच के संघर्ष की ओर भी विशेष रूप से ध्यान दिलाया गया है।

इस प्रकार के सामान्यीकरण से समस्या यह नहीं उठती कि विशिष्ट व्यक्तियों के बीच आपसी मतभेद वास्तविक और लाभकारी नहीं हैं, बहुधा ये वास्तविक और लाभकारी होते हैं, बल्कि समस्या उठती है कि उनके ये विभाजन अनिवार्य या पूर्वनिश्चित नहीं हैं।¹³ आधुनिकीकरण से सामाजिक अस्मिता विशेषकर, और साथ ही राष्ट्रीय अस्मिता की संभावनाएं बढ़ती हैं। अल्पविकसित राज्यों में सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से पृथक अस्तित्वों की संख्या बहुत अधिक है और ज्यादातर यह पृथकता अपरिपक्व होती है परिणामस्वरूप अव्यवस्थित भी। असली सवाल यह नहीं है कि सामाजिक विभेद उभरकर सामने आएंगे या नहीं बल्कि प्रश्न यह है कि मुख्य राजनीतिक मतभेद इस विभेद का कौन सा रूप ग्रहण करेंगे। राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों के बीच संघर्ष को समझने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुरुआत उनके सामाजिक, आर्थिक और सैद्धांतिक मतभेदों से नहीं बल्कि उनकी इस तरह की फूट को राजनीतिक दृष्टि से अपने लिए महत्वपूर्ण और लाभकारी बनाने के प्रयत्नों से की जाए।

जैसा पहले कहा गया है, अल्पविकसित राज्यों के राजनीतिक केंद्रों में विवैक्रीकरण की बहुत तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। किसी भी केंद्रीय सम्मेलन अथवा गठबंधन की स्थिरता विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के इस दृष्टिकोण पर निर्भर करती है कि इस

सम्मिलन में भाग लेने से कुछ लाभ हो रहे हैं। यह स्थिरता इस बात पर भी निर्भर करती है कि ये विशिष्ट व्यक्ति अपने अपने अनुयायियों पर नियंत्रण बनाए रखने में कहा तक सक्षम हैं। इसके अलावा स्थिरता इस बात पर भी निर्भर है कि जहाँ पितृवाद के अंकुर विद्यमान हैं वहाँ ये पुश्तैनी नेता अपने व्यक्तिगत अनुयायियों को अपने अपने राजनीतिक प्रभावक्षेत्र बनाने से रोकने में किम सीमा तक सफल होते हैं।¹⁴ इन सभी बातों को पूरा करने के मार्ग में आने वाली स्पष्ट कठिनाइयों से ही विभिन्न गुटों के उस मघर्ष को समझा जा सकता है जो अक्सर अल्पविकसित राज्यों में पैदा होता है।

विकेंद्रीकरण विशेष रूप से उत्तरी नाईजीरिया, मिएरा लियोने और श्रीलंका जैसे इलाकों में नजर आता है जहाँ परंपरागत विशिष्ट व्यक्तियों ने राजनीतिक केंद्र के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तरी नाईजीरिया में नार्दन पीपुल्स कांग्रेस ने 'अर्ध प्रभुसत्ता मंत्र 'स्वायत्तशासी' राज्यों के रूप में अमीरों के परंपरागत अस्तित्व को प्रतिबिंबित किया और मान्यता दी।'¹⁵ एन० पी० सी० की कार्यकारिणियों ने स्वयं को उच्च अधिकारों वाली ऐसी संस्थाओं के रूप में स्थापित करने के बजाय जिनके निर्णयों को विभिन्न अमीरों को स्वीकार करना ही होता था, समान हित के मामलों तक ही अपने आपको मघद्ध रखा।¹⁶ विकेंद्रीकरण के दबाव तंजानिया जैसे देशों में भी उपस्थित थे जहाँ के नेता अधिक आधुनिकतावादी थे। सरकार के मंत्रालय और व्यक्तिगत अनुयायी भी निजी विरामत का आधार बन सकते हैं।

सरकारी नेता स्वयं टी० ए० एन० यू० सगठन के नेता हैं जो कुछ हद तक स्वाधीनता आंदोलन के नेता होने के कारण सत्ता में हैं लेकिन साथ ही इसलिए भी उनकी सत्ता है कि उन्होंने इसे औपनिवेशिक शासकों से उत्तराधिकार में प्राप्त किया। वे सरकारी तंत्र का नियंत्रण करने वाले पदों पर पहुँचे हैं, अपनी स्थिति के अनुकूल वेतन लेते हैं और सत्ता के प्रतीकों, राजभवन, बड़ी बड़ी मोटरगाड़ियों, और उपाधियों, पर अपना एकाधिकार रखते हैं। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सत्ता के क्षेत्र में वे प्रथम उत्तराधिकारी हैं। चूँकि नए नेता स्वदेशी शासन चलाने वाले पहले व्यक्ति हैं इसलिए उन्हें प्रतीकों पर एकाधिकार बनाए रखने के अधिक अवसर हैं और अपनी ही परिकल्पना के अनुसार नई संस्थाओं का सृजन करने की अधिक स्वतंत्रता है।¹⁷

उत्तरी नाईजीरिया और तंजानिया दोनों में एक दृढ़ केन्द्रीय पार्टी कर्मचारी सगठन का विकास करके केन्द्रीयकरण को प्रोत्साहन देने के प्रयत्नों को, स्वयं निर्वाचित राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों ने ही निरुत्साहित किया।¹⁸

विकेंद्रीकरण की यह लगभग स्वाभाविक प्रक्रिया कई तरह से तीव्र होती है। एक तो यह कि केंद्रीय नेता अक्सर सरकार के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करके केंद्र और परिधि पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न करते हैं। यह विस्तार विकास एजेंसियों का गठन करके और स्वयंसेवी संस्थाओं को सीधा सरकार में मिलाकर किया जाता है। विशिष्ट व्यक्तियों को विरासत के नए स्रोत देकर ये नई एजेंसियां गठबंधनों अथवा सम्मिलनों की जटिलता और विशिष्ट व्यक्तियों के बीच पारस्परिक स्पर्धा की संभावनाएं बढ़ा देती हैं।

विकेंद्रीकरण का यह नमूना घाना में 1960 के बाद विशेष रूप से स्पष्ट दिखाई दिया। अपनी लोकप्रियता में कमी, दूसरे और तीसरे वर्ग के सक्रिय व्यक्तियों (जिन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं का नेतृत्व किया) के बीच बढ़ते हुए अंततोग, और पार्टी में आम बेचैनी को देखते हुए, एन्क्रूमा और सी० पी० पी० के महासचिव तवाया एडमा-फियो ने मारी पार्टी का पुनर्गठन किया। पार्टी से संबद्ध स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड घाना फार्मर्स काउंसिल, नेशनल काउंसिल आफ घाना विमेन, घाना यंग पायोनियर्स और दि कोआपरेटिव मूवमेंट को सी० पी० पी० की शाखाओं में बदल दिया गया (और इसीलिए ये अर्धसरकारी एजेंसियां हो गईं)। विभिन्न एसोसिएशनो के नेताओं की पार्टी के पदों पर नियुक्त किए जाने की मांगें पूरी की गईं और सिद्धांत रूप में पार्टी के संगठनात्मक और सैद्धांतिक विचारधारा के प्रभावक्षेत्र का विस्तार किया गया।¹⁹ पार्टी का एक नया हराबल तैयार किया गया जिसका केंद्र, नेशनल एसोशिएशन आफ सोशलिस्ट स्टूडेंट्स आर्गनाइजेशन (एन० ए० एम० एस० ओ०) और क्वामे एन्क्रूमा आईडियोलॉजीकल इंस्टीच्यूट थे। जल्दी ही इन सभी दलों ने सी० पी० पी० में, और घाना की राजनीतिक प्रणाली में अपना अपना प्रभाव जमाने के प्रयत्न शुरू कर दिए। इससे भी पहले, कोको परचेजिंग कंपनी लिमिटेड जैमी एजेंसिया न केवल सी० पी० पी० के लिए बल्कि इनका संचालन करने वाले खाम खाम विशिष्ट लोगों के लिए वित्तीय संरक्षण प्रदान करने का माध्यम बन गई थी।²⁰

सरकारी उद्यमों अथवा प्रतिष्ठानों ने थार्नहैड में भी स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिकांश सरकारी उद्यमों और विकास एजेंसियों पर कुछ खास लोगों के किमी न किसी गुट का नियंत्रण रहा है और इनका उपयोग विभिन्न गुटों के समर्थन और विस्तार के लिए किया गया है।²¹ टी० एच० मिलकोक के अनुसार, विरासत निर्माण के काम में बैको का व्यापक उपयोग किया गया, और अलग अलग बैंकों पर अलग अलग गुटों का नियंत्रण था। वे इनका इस्तेमाल अपने गुट के मददगारों को ऋण, नौकरियां और व्यवसाय दिमाने के लिए करते थे।²²

दूसरी बात यह है कि विकेंद्रीकरण को राजनीतिक नेताओं ने भी गति प्रदान की है। ये नेता अधिकतर योग्यता के स्तर से नीचे ही हैं। अल्पविकसित राज्यों के कई शासकों को, विचारधारा की हठधर्मी और सीमित समझबूझ के कारण, 'अपनी प्रारंभिक राजनीतिक वैधता का अधिकार, लाभों के वितरण की क्षमता, और प्रभाव को अनावश्यक कामों में लगाकर' व्यर्थ गंवाना पड़ा है।²³ इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी पुश्तैनी नेता को अपनी स्वायत्ता और सत्ता बनाए रखने के लिए जो प्रयत्न करने पड़े हैं वे आत्मविफलता ही लाए हैं। एन्क्रूमा ने विभिन्न गुटों को एक दूसरे से लड़ाने के जो प्रयत्न किए उनसे इन गुटों के समक्ष उनकी साख कम हो गई और वे 'दिनों दिन एक डरे हुए, सबसे कटे हुए नेता बनते चले गए जो एक जड़ राजनीतिक ढांचे के शिखर पर बैठे थे।' ²⁴ 1963 तक 'एन्क्रूमा ने अपने सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया था लेकिन स्पष्ट है कि उनके दोस्त गिने-चुने ही रह गए।' ²⁵

इस प्रकार के अयोग्यतापूर्ण नेतृत्व और तेजी से बढ़ती हुई सरकारी गतिविधि के परिणामस्वरूप अक्सर गुटों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ जाता है। अनुयायियों को अपने पीछे लगाए रखने के लिए उत्सुक लेकिन केंद्र में सीमित साधनों की समस्या में उलझे विशिष्ट व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित साधने के लिए कई तरह के स्रोतों का उपयोग करते हैं। विशिष्ट व्यक्ति एक दूसरे को पारस्परिक आधार पर संतुष्ट रखने की जिस भावना को लेकर चलते हैं वह टूट जाती है और प्रत्येक विशिष्ट व्यक्ति मिलेजुले सत्तारूढ़ सम्मिलन या पुश्तैनी नेता के लिए साधन जुटाने के बजाय अपने लिए ही कार्य करने लगता है। इस प्रकार राष्ट्रनिर्माण की जगह गुटनिर्माण होने लगता है।

कभी कभी गुटों में मूलतः विचारधारा संबंधी संघर्ष भी हो सकता है। 1958 में सत्तारूढ़ सिंघरा लियोने पीपुल्स पार्टी में मिल्टन मारगाई और अल्बर्ट मारगाई के बीच जो झगड़ा हुआ था उसका मुख्य कारण अल्बर्ट मारगाई और उनके समर्थकों की तीव्र सामाजिक सुधार लाने की इच्छा थी।²⁶ इस झगड़े का नतीजा यह हुआ कि बाद में अल्बर्ट मारगाई ने एक विपक्षी दल बना लिया। इसी प्रकार सिंगापुर में पीपुल्स ऐक्शन पार्टी भी सैद्धांतिक मतभेदों को लेकर कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट गुटों में बंट गई।²⁷ 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उच्च कमान के विघटन का कारण भी विचारधारा संबंधी मतभेद ही थे।

लेकिन आम तौर पर यह देखा गया है कि गुटों के संघर्ष विशिष्ट व्यक्तियों के आपसी झगड़ों से पैदा होते हैं। ये विशिष्ट व्यक्ति अपने व्यक्तिगत समर्थन को सुदृढ़ करने के प्रयत्नों के कारण ही आपस में झगड़ बैठते हैं। गुट निर्माण केंद्रित होता है व्यक्तिगत

व्यवस्थाओं के विकास पर जिनके माध्यम से कोई नेता अपने लिए समर्थकों को आकृष्ट कर सकता है। ज्यादातर ये व्यवस्थाएँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि नेता की पहुंच सरकारी लाभों और संरक्षण प्रदान करने वाले पदों तक बनी रहे। अब चूकि गुटों के नेताओं को इस पहुंच की आवश्यकता होती है इसलिए वे सरकार में ही बने रहना चाहते हैं। हां वे संभवतः यह इच्छा उस हालत में छोड़ सकते हैं जबकि उन्हें काफी बड़ा पारंपरिक दर्जा मिला हुआ हो या अपने अनुयायियों को अपने साथ रखने के लिए उनके पास समुचित निजी संपत्ति हो, या जब वे यह स्पष्ट रूप से जान लें कि विपक्ष के विशिष्ट व्यक्ति, सचमुच ही सरकार का नियंत्रण (और संरक्षण) अपने हाथ में ले सकते हैं।²⁸

आम तौर पर गुटों का संघर्ष शासन के दायरे में ही सीमित रहता है। संपर्क विशिष्ट व्यक्ति मंत्रालयों और पार्टी के विभिन्न अंगों पर अपने नियंत्रण का उपयोग, अपने वर्तमान समर्थकों को विशेष लाभ पहुंचाने और नए समर्थकों को आकृष्ट करने के लिए करते हैं। उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। विशिष्ट व्यक्ति अपने तथा अपने समर्थकों के लाभ के लिए राजस्व की हेराफेरी करते हैं।²⁹

व्यक्तिगत व्यवस्था के निर्माण में ऊपरी तौर पर तो सांप्रदायिक और फ्रांटिकारी बातों को लेकर अपील की जाती है जबकि वास्तव में यह व्यक्तियों का संघर्ष होता है। इन तरह की अपीलों में संपर्क विशिष्ट व्यक्तियों को समर्थक आकृष्ट करने और अपने लिए समर्थन सुदृढ़ करने का एक और साधन मिल जाता है। श्रीलंका में यह गुटवाद सबसे पहले उस समय सामने आया जब एम० डब्ल्यू० आर० डी० भंडारनायके और जेप यूनाइटेड नेशनलिस्ट पार्टी के बीच नीति संबंधी झगड़े हुए और शायद इससे भी महत्वपूर्ण घटना थी प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत होने के भंडारनायके के विफल प्रयास। अंततः वे यू० एन० पी० से अलग हो गए और विपक्ष से जा मिले। इस विभटन से पहले ही भंडारनायके ने व्यक्तिगत संपर्कों, स्थानीय सामाजिक व्यवस्थाओं, और जनसमर्थन को एक गुट का रूप देना आरंभ कर दिया था। इस काम में उन्होंने अपनी निजी संपत्ति, आल मिलोन विलेज कमेटी कान्फेस के अध्यक्ष पद पर अपनी सत्ता और सांप्रदायिक मिदल महासभा के नेता पद का उपयोग किया और सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भाषायी पुनर्गठन की अपीलें की।³⁰

केंद्र के विस्तार की प्रक्रिया और गुट निर्माण के बीच बड़ा अनिश्चित सा अंतर है। वास्तव में वे दोनों एक ही हैं। जैसा पहले हम देख चुके हैं, केंद्र और परिधि के संपर्कों का विस्तार परीक्षा है जो किमी एक विशिष्ट व्यक्ति और उसके अनुयायियों के बीच व्यक्ति-

गनसंपर्कों पर निर्भर करता है। इस तरह के संपर्क, केंद्र (गता का औपचारिक स्थल) के लिए समर्थन जुटाते हैं या किसी एक नेता के लिए (एक गुट), यह इस बात पर निर्भर करता है कि पुरानी नेता में अपने परम अनुयायियों पर प्रभाव बनाए रखने की क्षमता कितनी है (जबकि इन अनुयायियों के अपने ही और अनुयायी होते हैं), और केंद्र में विशिष्ट व्यक्तियों और उनके अनुयायियों को भौतिक लाभ पहुंचाने की कितनी सामर्थ्य है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गुटवाद, अलग अलग खंडों में विभाजन का परिणाम इतना नहीं है (खंड तो पहने में विद्यमान हैं) जितना कि यह विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के बीच एकरा के संबंधों के टूट जाने का परिणाम है।

विशिष्ट व्यक्तियों के आगामी संपर्क का परिणाम श्रेय राजनीतिक प्रणाली के लिए क्या हो सकता है, इस संबंध में आशंका में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। केंद्र और परिधि के बीच, और स्वयं परिधि के अंदर ही बनने-बिगड़ने वाले इन संबंधों से राजनीतिक गतिविधियों का अभिन्न अलग राजनीतिक अखाड़ों में बना रहता है, संपर्क का प्रत्येक क्षेत्र अलग अलग समस्याओं और व्यक्तियों के कारण अपनी विशिष्टता लिए हुए रहता है। किसी एक स्तर पर होने वाला गुटवाद, किसी दूसरे स्तर पर प्रभाव डाल भी सकता है और नहीं भी। भारत में केंद्र के विशिष्ट व्यक्तियों के आगामी संपर्क का प्रभाव, संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली पर बहुत मामूली सा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए न चुने जाने पर 1951 में आचार्य कृपलानी द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़ देने का अमर पार्टी में अन्य कहीं भी वास्तव में नहीं पड़ा। यहां तक कि आचार्य कृपलानी की विचारधारा के दृढ़ समर्थकों पर भी इस घटना का कोई अंतर नहीं हुआ।

कभी कभी राजनीतिक अखाड़ों, और गुटों, के बीच व्यक्तित्वों के कारण संपर्क बने रहते हैं। उदाहरण के लिए कीनिया में ओगिंगा ओडिंगा और टाम एंबोया के बीच व्यक्तिगत मतभेदों का प्रभाव पार्टी के निचले स्तरों पर केवल उन्हीं जिलों में पड़ा जहां ओडिंगा के सक्रिय व्यक्तिगत अनुयायी थे। इन मतभेदों के कारण 1966 में ओडिंगा ने कानू (के० ए० एन० यू०) पार्टी छोड़ दी थी। मेट्टल न्यांजा जिले में, जो ओडिंगा का अपना क्षेत्र था, के० ए० एन० यू० की शाखा पर ओडिंगा और उनके समर्थकों का बोलबाला था और ओडिंगा द्वारा पार्टी में अलग हो जाने के बाद सेट्टल न्यांजा जिले की मारी शाखा ही नई पार्टी में बदल गई।³¹ 1969 में भारत में कांग्रेस पार्टी के विघटन से भी ऐसे ही संपर्क का स्वरूप नजर आता है। केंद्र में सिडीकेट ग्रुप (संगठन कांग्रेस) मुख्यतः मिसूर और गुजरात राज्य में कांग्रेस सरकारों पर अपना प्रभाव और नियंत्रण जमाए हुए था क्योंकि इन राज्यों में सिडीकेट के कई सदस्यों का व्यक्तिगत प्रभाव था। कीनिया और भारत में अन्य स्थानों पर भी विभिन्न स्तरों पर

परस्पर विरोधी गुटों के बीच जो षोड़ा बहुत संपर्क था, वह अपने अपने हितों की दृष्टि में बना हुआ था।

निचले स्तर के गुटों ने अपने आपको किमी केंद्रीय गुट के साथ इतना संबद्ध इसलिए नहीं किया कि वे ओडिगा या सिडीकेट का व्यक्तिगत या सैद्धांतिक समर्थन करते थे बल्कि इसलिए किया कि उनके स्थानीय विरोधी गुट ने अपने आपको केंद्र के अंदर किसी अन्य गुट से संबद्ध कर लिया था। इसके परिणामस्वरूप गुटों की ये शृंखलाएं अक्सर असमान तत्वों की कड़ियों से जुड़ी होती हैं जो अपेक्षाकृत अस्थिर रहती हैं। इसके अलावा ये गुट किसी निश्चित प्रक्रिया के कारण नहीं बनते, बल्कि किमी एक क्षण में ये एक दूसरे का साथ देने लगते हैं। गुटों की शृंखला की कड़ियां जोड़ने वाले तत्व तो पहले से ही विद्यमान रहते हैं।³²

गुटों के बीच विभिन्न स्तरों पर, सैद्धांतिक संपर्क भी बन सकते हैं। घाना में एन० ए० एस० एस० ओ० यानी नेशनलिस्ट एसोसिएशन आफ सोशलिस्ट स्टूडेंट्स आर्गनाइजेशन, ऐसे ही सैद्धांतिक संपर्कों वाले गुट का उदाहरण है। यह गुट पार्टी के विभिन्न स्तरों पर अस्तित्व में आ गया है। आइवरी कोस्ट के अध्ययन में मार्टिन स्टेनोलेड ने कहा है कि एक 'विकासोन्मुख गुट' अस्तित्व में है, जिसके सदस्यों को 'उनके इस दावे के आधार पर पृथक रूप में देखा जा सकता है कि वे जिन आधुनिक 'तर्कसंगत' मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं वे विकास के वास्तविक हित में हैं और इसीलिए वे (अपनी शिखा और प्रशासन चलाने की योग्यता के आधार पर) राजनीति में भाग लेने 'विशेषकर बीच के स्तरों पर (सरकार और पार्टी के अंतरवर्ती स्तर) भाग लेने के अधिकारी हैं। कभी कभी केंद्रीय विशिष्ट व्यक्ति जिनके बीच का मतभेद आंशिक रूप से सैद्धांतिक होता है ऐसे दलों को अपने समर्थन में जुटा सकते हैं। लेकिन इस तरह के गुट अल्पकालिक होते हैं। जैसा स्टेनोलेड ने कहा है: 'संभवतः इस वर्ग को गुट नहीं अपितु मनोवैज्ञानिक जुटाव, दल नहीं अपितु कुछ व्यक्तियों को एक ही स्थान पर उपस्थिति कहा जाना चाहिए।'³³

विपक्ष गुटबंदी की इस प्रक्रिया का एक अविभाज्य अंग है। यह सरकारी दल के अंदर ही आपसी गठबंधनों और वितय आदि की स्थितियों पर निर्भर है। विपक्षी पार्टियां बहुधा विशिष्ट वर्ग के गुटवाद से बनती हैं। यह बात कोनिया के उदाहरण से स्पष्ट है। भारत के बारे में रजनी कोठारी ने लिखा है:

इस प्रकार राजनीतिक मतभेद, समाज के राजनीतिक केंद्र में विभाजन की प्रक्रिया का परिणाम है न कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में अपने अपने हितों

के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने की वृत्ति का परिणाम। विरोधात्मक गतिविधियों को समाजिक हितों की विभिन्नता से नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के विभाजन में बल मिला।

असहमति की प्रक्रिया पर कही गई इस बात से भारत की राजनीति की एक और विशेषता स्पष्ट होती है। यह विशेषता है सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर असंतुष्ट गुटों, विपक्षी पार्टियों और उनके अंदर के विपक्षी गुटों के बीच अस्पष्ट, परस्परव्यापी विभेदों का होना।³⁴

इस प्रकार का वेतुकापन भारत में ही नहीं है।

आज के विद्वान जिस तरह से राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण करते हैं उसी प्रकार वे राजनीतिक विरोध, विशेषकर विपक्षी पार्टी के स्वरूप, को भी मूर्त रूप देना चाहते हैं। राजनीतिक पार्टियों को सामान्यतया 'सरकारी संस्थाओं से भिन्न अलग संगठनों के रूप में देखा जाता है जो जोर-शोर से व्यक्त किए गए 'समर्थनों' और 'पृथक अस्तित्वों' के आधार पर कार्य करते हैं। इन्हें 'संसदीय सरकार की प्रातिनिधिक प्रणाली का हिस्सा मात्र माना जाता है जो चुनाव लड़ते हैं, समाज के अंदर विद्यमान विभाजनों या खंडों को अपने साथ मिलाते हैं और इसे आधुनिक राजनीति की गतिविधियों को चलाने की पूजा का अंश समझते हैं।'³⁵ इस दृष्टि से विपक्षी पार्टियाँ लगभग पूरी तरह उन सामाजिक वर्गों और व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ नहीं हैं। दूसरे शब्दों में इस तरह से देखने पर विपक्षी पार्टियों और सरकारी पार्टियों के ढाँचे में कोई वास्तविक सरचनात्मक अंतर नहीं है। दोनों ही पृथक मंगठन हैं जिनका मुख्य उद्देश्य निश्चित सामाजिक हितों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है।

लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन विघटनों से विपक्ष का जन्म होता है वे अक्सर विशिष्ट वर्ग के आपसी झगड़ों से पैदा होते हैं। विपक्षी पार्टियों को सरकारी पार्टियों की तरह संरक्षण प्रदान करने या अन्य सरकारी साधन जुटाने का मौका नहीं होता इसलिए वे संरचनात्मक रूप से बहुधा सरकारी पार्टियों की अपेक्षा कम सुसंगठित होती हैं। जैसा हम कह चुके हैं, विशिष्ट व्यक्तियों और दलों का कामचलाऊ गठबंधन, सरकार पर नियंत्रण और उस तक पहुँच से बनता है।

इसका मतलब यह नहीं है कि विपक्षी दलों का कोई सामाजिक (जातीय, वर्गीय आदि) आधार नहीं है। विपक्षी दल उभरते हैं सामाजिक दलों जैसे क्षेत्रीय, जातीय,

भापायी और वर्गीय दलों से, जो शासक विशिष्ट वर्ग की सत्ता को चुनौती देते हैं। घाना की एन० एल० एम० पार्टी और श्रीलंका की तमिल पाटिया ऐमी ही विपक्षी पार्टी का बढ़िया उदाहरण है। कुछ विपक्षी पाटिया भिन्न प्रकार की सैद्धांतिक परंपरा का आश्रय लेती हैं और इस प्रकार एक तरह से वे सदा ही विरोधात्मक रही हैं।³⁶ जहां कोई विपक्षी पार्टी किसी विशिष्ट वर्ग के गुटों के आपसी झगड़ों में घनी है वहां भी असंतुष्ट नेताओं की अपीलों के परिणामस्वरूप यह पार्टी समाज के अलग वर्गों का समर्थन प्राप्त कर सकती है। एजिला वंजर ने भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की विपक्षी पाटियों के अध्ययन में कहा है कि अतः ये पाटिया सामाजिक गुटों का समर्थन प्राप्त करने की ओर तब प्रवृत्त हुई थी जब उनका गठबंधन सरकारी दल के साथ हो गया था।³⁷ सिएरा लियोने में विपक्षी दल पी० एन० पी० का गठन अल्बर्ट मारगाई ने किया और इसका नेतृत्व विशिष्ट व्यक्तियों के ऐसे वर्ग ने किया जो शासक दल से भिन्न नहीं थे और यह विपक्षी दल अपने लिए काफी बड़ा जनसमर्थन जुटाने में सफल हुआ।

विशिष्ट व्यक्तियों के आपसी झगड़े और सामाजिक मतभेद, व्यावहारिक दृष्टि से एक दूसरे से लाभ उठा सकते हैं। 1958 में मोरक्को में जो ग्रामीण उपद्रव हुआ वह किसी सीमा तक रिफ कबीले के लोगों की इस भावना का परिणाम था कि उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में जो योगदान किया था उसका सरकार की ओर से समुचित इनाम नहीं मिला। किसी हद तक यह उपद्रव, इस्तिकलाल विशिष्ट वर्ग के साथ, राजतंत्र के झगड़ों का नतीजा भी था।³⁸ इस्तिकलाल के प्रतिसतुलन के लिए राजतंत्र ने उस क्षेत्र के प्रभावशाली राजनीतिक नेता अहरदेन को इस्तिकलाल के मुकाबले अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का प्रोत्साहन दिया। विद्रोह का एक कारण इस पार्टी की यह मांग थी कि इस्तिकलाल सरकार उसे विधिवत मान्यता दे।³⁹

दूररे शब्दों में, विपक्षी दल अक्सर केन्द्र में असंतुष्ट विशिष्ट व्यक्तियों, उनके निकटतम अनुयायियों और, उनके अंतोप, या असंतुष्ट विशिष्ट व्यक्तियों की अपीलों के कारण परिधि क्षेत्र के भिन्न भिन्न विशिष्ट व्यक्तियों तथा दलों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं कि ऐसी दलबंदियां प्रायः कमजोर तथा अल्पकालिक होती हैं। जो सामाजिक वर्ग अपेक्षाकृत कुछ चिंतन से किसी दल के साथ जुड़े हैं वे एक दूसरे से अलग थलग पड़ जाते हैं और इन सबके बीच एक ही समानता होती है कि उन्हें शासक दल तक पहुंचने का अवसर नहीं मिलता। सरकारी पार्टी में रह गए विशिष्ट व्यक्तियों और असहमत विशिष्ट व्यक्तियों के बीच नीति संबंधी या विचारधारा संबंधी जितने मतभेद होते हैं उससे कहीं अधिक मतभेद विपक्षी पार्टी के विभिन्न तत्वों के बीच हो सकते हैं। असंतुष्ट विशिष्ट व्यक्ति मूल भावनाओं को

उभारने वाली अपीलों के जरिये जनसमर्थन जुटाने का जो प्रयत्न करते हैं वह अंततः विघटनकारी सिद्ध हो सकता है। जबकि विपक्षी दल इन्हीं पारंपरिक संपर्कों पर आधारित दलों का सम्मिश्रण होते हैं। अंतिम बात यह है कि अलग अलग खंडों को एकता के सूत्र में बांधने के साधनों के अभाव के कारण विपक्षी पार्टियों में सत्तारूढ़ विशिष्ट व्यक्तियों के प्रभाव के प्रवेश पा जाने की आशंका हो जाती है। अल्पविकसित राज्यों की राजनीतिक प्रक्रिया के विभाजित स्वरूप से ही यह निश्चित होता है कि विपक्ष और सत्तारूढ़ दल का स्वरूप क्या होगा।

सांप्रदायिकता की राजनीति

अल्पविकसित राज्यों की राजनीति में जातीयता की भूमिका पर विशेष बल दिया जाता है, यह देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विभिन्न जातीय इकाइयों के स्वरूप और सीमाएं अक्सर अपेक्षाकृत सुनिश्चित समझी जाती हैं और इन्हें 'प्रदत्त' माना जाता है जिनके आधार पर इन राज्यों में राजनीतिक क्रियाकलापों का विक्षेपण शुरू किया जा सकता है।⁴⁰ रिश्तेदारी, भाषा, जाति और धर्म के आधार पर विभाजित वर्गों के बीच अंतर को पाटना होगा। यह काम बहुत बड़ा है क्योंकि ये सामाजिक विभाजन, अटूट परंपराओं के परिणाम हैं। इस दृष्टि से, अल्पविकसित राज्यों की राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणालियां अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणालियों जैसी बन जाती हैं जिनमें काफी हद तक सुनिश्चित अभिनेता होते हैं। जैसाकि डोनाल्ड रायचार्डल्ड ने कहा है :

चूंकि नए राज्यों के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक विभाजनों का स्वरूप इतना आधारभूत होता है, इसलिए इन खंडों के आपसी संबंध वैसे ही होते हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलते हैं।⁴¹

इस मंडातिक दृष्टिकोण से यह पता नहीं चलता कि समाज का एक खास वर्ग किनी अन्य वर्ग में अधिक राजनीतिक महत्व का क्यों है। इसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिकता और राष्ट्रीय एकता की बड़ी समस्या का विक्षेपण किनी एक राज्य में सभी संभव सामाजिक विभेदों की पड़ताल सूचियों के द्वारा ही किया जा सकता है।⁴² इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मत में किनी एक सामाजिक संपर्क, और संपर्कत दलों को एक ऐतिहासिक अनिवार्यता मान लिया जाना है जो संभवतः उचित न हो।

अल्पविकसित राज्यों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बढ़ने हुए सामाजिक प्रतिमानों ने उन विधियों को बहुत बढ़ान दिया है जिनमें व्यक्ति स्वयं को और अपने दलों को पृथक अस्तित्व में रखते हैं। भारत में जहां परंपरा में ही ऐसा होना आया है

कि जाति का उद्गम स्थल गाव, या ग्राम समूह रहा है, जाति ने एक विस्तृत भौगोलिक अर्थ ग्रहण किया है।⁴³ संचार के सुधरे हुए साधनों, पश्चिमी शिक्षा और नए आर्थिक अवसरों ने स्थानीय जातियों (या उपजातियों जिन्हें आमतौर पर गोत्र कहा जाता है) को भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत संपर्कों में आने की सामर्थ्य प्रदान की।⁴⁴ नगरों में जातीय अतन्त्रता या तो और दृढ़ हो जाती है, या बदल सकती है। किसी एक ही स्थान, प्रदेश या गाव में आने वाले लोग नगर के एक ही हिस्से में इकट्ठे रह सकते हैं और एक प्रकार की समान पहचान की भावना का विकास कर सकते हैं, जो पहले के किमी भी ग्रामीण जातीय समूह की भावना से कहीं अधिक होती है।⁴⁵ अन्य स्थानों में, नए शहरी वातावरण के अनुसार पृथक जातीयता की भावना बदल सकती है। कोई व्यक्ति जब शहर में रहने के लिए आता है तो उसे जो नई शहरी कबीलाई पहचान (अर्बन ट्राइबल आइडेंटिटी) मिलती है, उसके संदर्भ में या तो वह अपनी जाति के बंधनों से निकल सकता है या और अधिक उसकी जकड़ में आ जाता है।⁴⁶ आर्नलड एपस्टोन ने उत्तरी रोडेेशिया के तावा क्षेत्र के शहरों में रहने वाले समूहों के अध्ययन में बताया है कि न्यामालैंड (मलावी) से आए विभिन्न जातीय समूह के लोगों को 'न्यामालैंडवासी' कहा जाता था और स्वयं उन्होंने भी अपना यही नाम स्वीकार किया।⁴⁷

प्रशासनिक विधियों, जैसे जनगणना से भी व्यक्ति समूहों की, पृथक जातीयता पर प्रभाव पड़ सकता है। अंग्रेजों ने हिंदुओं के प्राचीन वर्णभेद — ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, का अपने प्रशासन में जो उपयोग किया उससे कई जातीय एसोसिएशनों के गठन को प्रोत्साहन मिला।⁴⁸

जब किसी जाति के पढ़े-लिखे विशिष्ट व्यक्तियों ने अपनी जातियों और उपजातियों के लिए ऊंचा दर्जा प्राप्त करने के प्रयत्न शुरू किए तो उन्होंने जल्दी ही यह अनुभव किया कि जातीय दावों में एकरूपता लाने के लिए क्षेत्रीय उपजातियों को संगठित करने की आवश्यकता है।⁴⁹

जब यह मान लिया जाता है कि आधुनिकीकरण और प्रशासनिक निर्णयों से पृथक जातीयता में परिवर्तन लाया जा सकता है या इसका नया सृजन किया जा सकता है तो भी मूल समस्या बनी ही रहती है। वह समस्या यह है कि कोई एक जातीय समूह या बहुत सारे जातीय समूह किसी एक निश्चित समय पर राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कैसे बन जाते हैं। भारत में जातीयता की भावना से कई राजनीतिक अभिनेताओं का उदय हुआ है : जैसे जातीय संगठन जो भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग जगह पड़े हुए समान उपजातियों के सदस्यों को संपर्क में लाते हैं या जातीय

भारत में कांग्रेस के असंतुष्ट विशिष्ट व्यक्तियों ने अपने लिए राजनीतिक समर्थन के नए आधार बनाने के प्रयत्न में अक्सर जाति, वंश, क्षेत्र और भाषा का सहारा लेकर अपील की है और अपने इन प्रयत्नों में उन्होंने बहुधा जाति, भाषा और सांस्कृतिक संस्थाओं को सगठनात्मक आधार बनाया है।⁵³ सिएरा लियोने में पी० एन० पी० का एक संगठनकर्ता जो एस० एल० पी० पी० का भूतपूर्व नेता था कुछ व्यक्तिगत कारणों को लेकर इन दोनों पार्टियों के सम्मिलन से अलग हो गया और उसने एक और पार्टी बना ली। उसने नई पार्टी के लिए जिस प्रकार की अपील की उनके कारण नई पार्टी सांप्रदायिकता की भावनाओं से भरी हुई थी।⁵⁴

सांप्रदायिक राजनीतिक गतिविधि का बहुभागीय क्रम सचय (मल्टिपल पर्प्युटेशंस) करना संभव है लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों का संघर्ष किस प्रकार का है, किसी एक समुदाय या संप्रदाय में कितना विकास हुआ है, या कोई संप्रदाय अन्य जातीय समूहों से किस सीमा तक अलग चल रहा है और वर्तमान नेता-अनुयायी संपर्क, विभिन्न जातीय दलों में फैले होने के वजाय किसी एक जातीय समूह में कहां तक समाए हुए हैं।

जिन समाजों में विशिष्ट व्यक्ति और उनके अनुयायी एक ही संप्रदाय में सीमित होते हैं वहां सांप्रदायिक भावनाओं पर आधारित अपील तो वर्तमान व्यक्तिगत, विरादरी, और संरक्षक-संरक्षित संबंधों को केवल और दृढ़ करने के लिए ही होती है। वर्तमान सामाजिक ढांचों के साथ साथ सांप्रदायिक भावनाओं की अपीलों के सम्मिश्रण से किसी एक संप्रदाय के अंदर एकता लाई जा सकती है, लेकिन साथ ही यह सम्मिश्रण विभिन्न संप्रदायों के बीच अंतरआकर्षण पैदा करने, या राष्ट्रीय एकता लाने के काम में अड़चन भी डाल सकती है। मलयेशिया, बर्मा और लाओस के बारे में लिखते हुए स्काट ने कहा है :

किसी राजनीतिक ढांचे के शिखर को छोड़कर जहां किसी एक नेता के साथ अनुयायियों के रूप में छोटे छोटे सांप्रदायिक दलों के नेता हो सकते हैं, अधिकांश संरक्षकों या बड़े नेताओं के अनुयायी वे होते हैं जो केवल उनके अपने ही संप्रदायों में हैं। विभिन्न संप्रदायों के बीच एकता किसी राजनीतिक ढांचे के शिखर के पास जाकर ही आती है। प्रत्येक सांप्रदायिक समूह का आधार मुख्यतः अलग अलग रहता है।⁵⁵

विशिष्ट व्यक्तियों के इस प्रकार के अंतर्सांप्रदायिक संपर्क वैसे ही हैं जिनका विवरण आरेंड निजफार्टे ने पश्चिमी यूरोप के 'सहयोगी नोकतंत्रों' (कमैशनर्स डिमांकेसी)

संबंध टूट सकते हैं। इस प्रकार संरक्षक और संरक्षित के बीच जितने अधिक सांस्कृतिक मतभेद होंगे, और इन दोनों के बीच सामाजिक दूरी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही अधिक उप्रता के साथ जातीय संघर्ष, नौत्र सामाजिक समूहीकरण की परिस्थितियों में होने की सम्भावनाएं हैं।⁶⁰

मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुजातीय समाज में सांप्रदायिक संघर्ष अनिवार्य नहीं है। यदि इस बात को मान लिया जाए कि समाज में विभिन्न दलों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू होने से जो सामाजिक समूहीकरण होता है उसके कारण यह प्रतिस्पर्धा सांप्रदायिक रूप ले लेती है और इस आधार पर जो समूहीकरण होता है उससे समाज में दलीय विभेद बढ़ जाते हैं और फूट बढ़ती चली जाती है,⁶¹ यह बात भी माननी होगी कि सांप्रदायिक फूट भी प्रायः किसी वर्गीय या क्षेत्रीय फूट में अलग, स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की जा सकती।

परंपरागत अस्मिता (ट्रेडिशनल आइडेंटिटी), स्थानीय संबंधों के मद्दे में सुनिश्चित होती है। इस भावने में सांप्रदायिक अस्मिता को परंपरागत नहीं कहा जा सकता और इसमें समावेशन की दृष्टि से काफी परिवर्तनों की सम्भावना होती है।

इसके परिणामस्वरूप संप्रदायवाद एक निश्चित राजनीतिक रंग लिए हुए होता है जो एक निश्चित संदर्भ में खास मामलों और व्यक्तियों को लेकर बनता है।⁶² जैसा एक अध्ययन में कहा गया है: 'राजनीतिक समुदाय में प्रत्येक अभिनेता चाहे वह कितना ही महत्वहीन क्यों न हो, सामाजिक संघटन का केंद्रबिंदु बनने की बहुमुखी क्षमता रखता है। उसकी भूमिका क्या होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्थिति कैसी है। या यह कहा जा सकता है कि भूमिका का निर्धारण इस बात पर निर्भर करेगा कि अभिनेता किसी स्थिति को किस तरह लेता है।'⁶³ लेकिन इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि 'अभिनेता द्वारा स्थिति का मूल्यांकन' संयोग की बात नहीं है। बहुधा यही होता है कि यह मूल्यांकन राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों की अभीलों के आधार पर किया जाता है। नाईजीरिया में एक 'वर्ग' द्वारा 1964 में लागोस, इबादान और अन्य महत्वपूर्ण नगरों में आम हड़ताल में सफलता प्राप्त करने के बावजूद कई महीने बाद जो संसदीय चुनाव हुए, उनमें इन्हीं मजदूर संगठन कार्यकर्ताओं ने मजदूर संगठन नेताओं को राजनीतिक उम्मीदवारों के रूप में अस्वीकार कर दिया, और सांप्रदायिक दल के उम्मीदवारों को वोट दिया।⁶⁴ लेकिन अलग अलग राजनीतिक दायरे अपने आप नहीं बने, बल्कि प्रतिस्पर्धायुक्त राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों ने इनका स्वरूप फिर से बनाया, और जातीय समूहों के संगठनों और व्यक्तिगत व्यवस्था के राजनीतिक महत्व को फिर सक्रिय किया।⁶⁵

के सम्मिश्रण वाले देशों में सैनिक क्रांतियों की जो बाढ़ आई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह की क्रांतियां, कहीं भी और किसी भी कारण अथवा कारणों से हो सकती हैं, और इनका संबंध ऊपर बताई गई परिवर्तनशील बातों से होना अनिवार्य नहीं है।⁷³ दूसरी बात यह है कि क्रांतियों के संबंध में जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं अथवा कारण बताए गए हैं उनसे अल्पविकसित राज्यों में सेना का स्वरूप विकृत प्रतीत होता है। सैनिक हस्तक्षेप के संबंध में साधारण तौर पर जो विश्लेषण किया गया है वह प्रभुता वाली राष्ट्रवादी पार्टियों के उदय से संबद्ध उस विश्लेषण जैसा ही है जो दूसरे अध्याय में किया गया। जिस प्रकार पहले यह कहा गया था कि इस तरह की पार्टियां अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले संगठनात्मक श्रेष्ठता की द्योतक हैं उसी प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि संगठनात्मक दृष्टि से सेना अन्य सामाजिक, और राजनीतिक संगठनों में श्रेष्ठ है। यह कहा जाता है कि सेना एक 'वजनदार' (heavy) संस्था है और इमीलिए वह अधिक प्रभुता वाली है। लेकिन कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोड़ दें तो यह बात सही नहीं है। विशेषकर अफ्रीका में आम तौर पर सेना बहुत छोटी है और उसका प्रशिक्षण बड़े निम्न स्तर का है। सेना, 'एक आदर्श श्रेणीगत संगठन' और अपनी संगठनात्मकता के आधार पर प्रभुतासंपन्न होने की क्षमता रखने के बजाय, 'कुछ ऐसे मशरूफ़ व्यक्तियों का समूह मात्र होती है जो अपने अधिकारियों के आदेशों का पालन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते।'⁷⁴

और अंतिम बात यह है कि इन सभी स्पष्टीकरणों में हालांकि सेना द्वारा राजनीतिक गतिविधि के प्रति पश्चिम की नफरत पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई तथापि सेना को एक ऐसा अभिनेता समझा गया है जिसकी भूमिका आम तौर पर राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर है। सैनिक हस्तक्षेप, सेना की कुछ आंतरिक बातों (जैसे व्यावसायिक वृत्ति का होना या उसका अभाव) अथवा बाह्य बातों (जैसे आर्थिक जड़ता और राजनीतिक गतिविधि का ह्रास) का परिणाम है या नहीं, लेकिन परिस्थितियां यह बात सिद्ध करती हैं कि जो वास्तव में होना चाहिए वह नहीं हुआ है। अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि विकृत परिस्थितियां ही सैनिक क्रांति का मानदंड हैं। फिर भी विचारधारा का झुकाव बना हुआ है और बहुत हद तक इसका प्रभाव स्थिति के विश्लेषण पर पड़ता है।

अनिवार्यतः, सैनिक क्रांतियों का स्पष्टीकरण किसी असामान्य घटना या घटनाक्रम के संदर्भ में किया जाता है।

इस प्रकार के स्पष्टीकरणों में नए राज्यों की सस्थात्मक स्थिरता और एकता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है। राजनीतिक केंद्र, चाहे किसी पुरानी

वे सफल हों या न हों, सेना की भूमिका काफी व्यापक हो जाती है। जैसा एक विद्वान का मत है :

जब अधिकार के उपयोग का स्थान बलप्रयोग ले लेता है तो इसके साथ साथ तत्कालीन व्यवस्था के सपेक्ष 'बाजार भाव' में भी परिवर्तन आता है। नए अफ्रीकी राज्यों में, राजनीतिक पार्टियों और नागरिक प्रशासन के मूल्य में एक प्रकार का ह्रास हुआ है जबकि पुलिस और सेना का मूल्य बहुत बढ़ गया है।⁷⁹

राबर्ट सी नार्थ द्वारा सुझाए गए शब्दों का प्रयोग करें तो यही कहा जाएगा कि 'हिंसा के विशेषज्ञ', 'प्रतीको के विशेषज्ञों' से अधिक महत्व प्राप्त कर लेते हैं।⁸⁰ यह बात अजर बोल्टा, सोमालिया, वर्मा और तुर्की जैसे स्थानों के लिए भी सही सिद्ध हुई है जहां सेना को एक हथियार के रूप में खुल्लमखुल्ला इस्तेमाल करने का प्रयत्न नहीं किया गया है लेकिन जहां सशस्त्र संघर्ष, दंगे, हड़ताले और विद्रोह, (ये सभी विशिष्ट व्यक्तियों के आपसी संघर्षों के कारण हुए) सभी तरफ फैल गए हैं।⁸¹ इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक प्रणाली की व्यक्तिगत गुटबंदी सेना को भी गुटों के गठन की प्रक्रिया में उलझा लेती है या गुट निर्माण के कारण तेज होने वाले संघर्षों में भी सेना को उलझना पड़ता है।

अल्पविकसित राज्यों की राजनीतिक प्रक्रिया में सेना के शामिल होने को, किसी चाहे सगठन द्वारा राजनीतिक प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता बल्कि गुटों के संघर्ष का विस्तार होने के कारण सेना के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा इन प्रक्रिया में उलझना कहा जा सकता है। किसी राजनीतिक प्रणाली में उलझने (विशेषकर ऐसी प्रणाली में जिसमें सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया हो) से सेना के विशिष्ट व्यक्तियों के हावी हो जाने की संभावना पैदा हो जाती है, क्योंकि उनमें डराने-धमकाने और दबाव डालने की क्षमता होती है। 30 सितंबर 1965 को इंडोनेशिया में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में सेना के विरुद्ध जो क्रांति हुई थी और जिसमें सेना के छः बड़े अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी उसे जनरल मुहार्तो, नसूतियों और अन्य वरिष्ठ मैनिक कमांडरों ने जवाबी हमला करके बड़ी तेजी से कुचल दिया था। अंतिम विश्लेषण में यही कहा जा सकता है कि शासन बर्ही करेगा जिसके पास सामरिक महत्व का दबाव डालने की क्षमता है।

लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि दबाव डालने की क्षमता बहुत अधिक होना जरूरी नहीं है। राजनीतिक केंद्र में विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मिश्रण बड़े नाजुक

बंधनो पर आधारित होते हैं और केंद्र तथा परिधि क्षेत्र के बीच संपर्क अस्थिर होते हैं जिसके कारण राजनीतिक केंद्र में दबाव डालने की क्षमता बहुत सीमित होती है। जोलबर्ग का कहना है कि अफ्रीका की दो लघुतम सेनाओं ने अपने हस्तक्षेप के समय बड़ी सरलता से सफलता प्राप्त कर ली थी। इनमें से एक मे टोंगो के डाई सौ सैनिक थे जिन्होंने 1963 में हस्तक्षेप किया और दूसरी थी मध्य अफ्रीकी गणराज्य की छः सौ व्यक्तियों की सेना जिसने 1966 में सफलता प्राप्त की थी।⁸² दक्षिण कोरिया में क्रांति करने वाले सैनिकों की संख्या तो बहुत कम थी (अनुमानतः साढ़े तीन हजार सैनिक) और सेना के बाकी लोग शुरू में या तो क्रांति के विरोधी थे या तटस्थ रहे। राजधानी सिओल पर शीघ्र नियंत्रण कर लेने के कारण क्रांति को जो सफलता मिली उससे शेष सैनिक भी क्रांति के नेताओं के साथ आ मिले। इसी प्रकार यदि किसी सरकार का नियंत्रण सेना की सामरिक महत्व की यूनिट पर है तो वह क्रांति को रोक सकती है चाहे उन परिस्थितियों में गुटों के संघर्ष रहे हों या अव्यवस्था फैली हुई हो। सेनेगल में सेघोर ने वायुसेना की एक बटालियन पर अपने नियंत्रण के माध्यम से ममदू दिया के समर्थक सैनिकों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर लिया।⁸³

क्रांति की स्थिति अगणित कारणों से पैदा हो सकती है। इनमें कुछ कारण, सेना और राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों के बीच मतभेद, सेना के अंदर राष्ट्रवाद का बढ़ती हुई भावना, सेना में व्यापारिक क्षेत्र के प्रति रुचि का उदय होना और सेना के अंदर जातीय दलों के बीच संघर्ष से उत्पन्न विभाजन, हो सकते हैं। सारांश यह है कि हाल के अनुभवों से यह पता चलता है कि अल्पविकसित राजनीतिक प्रणाली में संघर्ष को लगभग किसी भी स्थिति में क्रांति हो सकती है।

किसी देश की विशेष परिस्थितियों से ही यह तय होता है कि क्रांति किन मांगों को लेकर, किस समय होगी और इसके अभिनेता कौन होंगे। अल्पविकसित राज्यों के बीच एक ही समानता है कि उनके अंदर गुटों के संघर्ष हैं जो अक्सर बड़ा रूप ले लेते हैं। इस बात का पूर्वानुमान लगाना कठिन है कि किस संघर्ष में कौन से सैनिक विशिष्ट व्यक्ति उल्लंघन करेंगे। इसमें संदेह नहीं कि अंततः संघर्ष में सेना के विशिष्ट व्यक्तियों के उल्लंघन की पूरी संभावना रहती है, और संघर्ष की उग्रता में वृद्धि होने से ये विशिष्ट व्यक्ति लगभग स्वाभाविक रूप से ही हावी हो जाते हैं।

अल्पविकसित राज्यों की राजनीतिक प्रक्रिया बड़ी विरोधाभासी है। इन राज्यों में दृढ़ीकरण का आधार है पुस्तनी और भौतिक लाभ, जिनसे विकेंद्रीकरण के साधन उपलब्ध होते हैं। पुस्तनी सत्ता का सीमित स्थायित्व, और भौतिक लाभों के साधनों का अभाव बने रहना, ऐसी बातें हैं जो गुटवाद और विघटन की प्रवृत्ति को लगभग

अनिवार्य बना देती है। पिछले अध्याय के अंत में यह कहा गया था कि राजनीतिक प्रक्रिया संस्थात्मकता लाने की प्रक्रिया के प्रतिकूल है।

न केवल केंद्र और परिधि के विशिष्ट लोगों के व्यक्तिगत मपकं बनते बिगड़ते रहते हैं बल्कि अपने अरने प्रभावक्षेत्र बनाने के राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों के प्रयत्नों (व्यक्तिगत गुटों, पार्टी की शाखाओं पर प्रभुत्व स्थापित करके या मंत्रालयों पर अपना नियंत्रण जमाकर) से उन स्थापित विधियों और संस्थाओं के काम में भी अड़चनें पड़ती हैं जिनके माध्यम से दृढीकरण किया जा सकता है। ऐसे वातावरण में गुटों, संप्रदायों, विपक्ष और सेना के संघर्ष, एक विकृति नहीं बल्कि नियमित घटना बन जाते हैं। अस्थिरता की राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था के छिन्न भिन्न हो जाने या राजनीतिक हास का परिणाम नहीं बल्कि यह विघटित राजनीतिक प्रक्रिया में ही अंतर्निहित है।

संदर्भ

1. एरिस्टिड जोलवर्थ 'दि स्ट्रक्चर आफ पालिटिकल कान्फ्लिक्ट इन दि न्यू स्टेट्स आफ ट्रापिकल अफ्रीका', अमरीकन पालिटिकल सायंस रिव्यू LXII; 1 (1968), 70.
2. वही, पृ० 71
3. एम० एन० ईसेंस्टाट : 'सोशल चेंज ऐंड माडर्नाइजेशन इन अफ्रीकन सोसायटीज माऊव जाफ दि सहारा', काहियमं दि एट्यूड्स, अफ्रीकन V, 3 (1965), 453-471.
4. सेमुअल हार्टिंगटन - पालिटिकल आर्डर इन चीजिंग सोसायटीज, (न्यू हैवन : येल् यूनिवर्सिटी प्रेस, 1968), पृ० 5
5. कार्ल डब्ल्यू० डायस : 'सोशल मोबिलाइजेशन ऐंड पालिटिकल डेवलपमेंट', अमरीकन पालिटिकल रिव्यू, LV, 3 (1961), पृ० 498
6. जोलवर्थ, पृ० 76
7. वही, पृ० 73-74
8. राबर्ट मेलमन और हार्वे बोल्स 'माडर्नाइजेशन ऐंड दि पालिटिकल आफ कम्यूनलिज्म : ए थ्योरीटिकल एम्पेरिस्टिक', अमरीकन पालिटिकल रिव्यू, LXIV, 4 (1970) 1115.
9. हार्टिंगटन, पृ० 55.
10. जेम्स ओ'कोनेन. 'दि इनएक्टिविलिटी आफ स्टेटिलिटी' दि जर्नल आफ अफ्रीकन स्टडीज, 5, 2 (1971), 188
11. खडगुरन समाज में संघर्ष के संबंध में लिखा गया है सायड फालसे की इस पुस्तक में: 'पालिटिकल मोबायलायटी ऐंड दि एथोपोलिटिकल स्टडी आफ अफ्रीकन पालिटिकल', आर्काइव्स युरो-पियनज दि सोस्योलॉजी, IV, 2 (1963) 311-329.
12. जान वाट्सकी. दि पालिटिकल कामीकवेंसेज आफ माडर्नाइजेशन (न्यूयार्क : जान वार्ल्डी ऐंड सम, 1972) पृ० 139-142.

- 13 इन विपटनों के दो श्रेष्ठ अग्रयनों के लिए देखिए विक्टर टी० नेवाइन पानिटिकल सीडर-शिप इन अफ्रीका : पोस्ट इंडिपेंडेंट जेनरेशनल कानफिन्सट इन अपर, बोल्टा, सेनेगल, नार्डजर, दाहोमी, दि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक (स्टैनफोर्ड . हूवर इंस्टीच्यूशन ऑन वार, रिबोन्सुशन ऐंड पीस, 1967), और विनियम बी० क्वाट, रिबोन्सुशन ऐंड पालिटिकल सीडरशिप अल्जीरिया, 1954-1968, (कैब्रिज, मैगाच्यूमेटम : एम० आई० टी० प्रेस, 1969).
14. पुस्तकें नेताओं के लिए इन प्राप्ति करना कितना कठिन है, इसके उदाहरणों के लिए देखिए, हैनरी बिंनन : तजानिया : पार्टी ट्रामफारमेशन ऐंड इकानामिक डेवलपमेंट (प्रिन्स्टन : प्रिन्स्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1970), पृ० 158-167, 185-195; और एच० एल० ब्रेटन . दि राईज ऐंड फाल आफ क्वामे एन्गूमा (मदन प्रेजर, 1967).
15. सी० एस० व्हिटेकर दि पानिटिवम आफ ट्रेडीशन (प्रिन्स्टन . प्रिन्स्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1970), पृ० 365.
- 16 बही.
17. बिंनन, पृ० 195
- 18 बही, पृ० 196-197; व्हिटेकर, पृ० 366
19. डेनिस एन० कोहन . 'दि कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी आफ घाना', रिप्रजेंटेशनल आर मालिडैरिटी (पार्टी), कनेडियन जर्नल आफ अपीकल स्टडीज, IV, 2 (1970), 178-179.
20. गवर्नमेंट आफ घाना रिपोर्ट आफ दि कमीशन आफ इन्क्वायरी इन टू दि अफेयर्स आफ दि कोको पर्चॉजिंग कंपनी, लिमिटेड (अकरा . गवर्नमेंट प्रिंटर्स, 1956).
21. फ्रेड रिम्स : घाईनैड . दि माइनाइजेशन आफ ए म्यूरोक्रेटिक पोलिटी (होनोलूलू ईस्ट वेस्ट सेंटर प्रेस, 1966), पृ० 242-310.
22. टी० एच० मिलकाक : 'मनी ऐंड बैंकिंग', टी० एच० मिलकाक (संपादित) : घाईनैड : सोशल ऐंड इकानामिक स्टडीज इन डेवलपमेंट (दरहम, एन० सी० इयूक यूनिवर्सिटी प्रेस, 1967), पृ० 183-185
23. जोनबर्ग, पृ० 72.
24. बारबरा कैलवे और एमिली काई : 'पानिटिकल कस्ट्रेंट्स आन इकानामिक डेवलपमेंट इन घाना', भाइकिल साफयाई (संपादित) : दि स्टेट आफ दि नेर्गम : कस्ट्रेंट्स आन डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट अफ्रीका, (वर्कले ऐंड साम एजिलम . यूनिवर्सिटी आफ केनीफोर्निया प्रेस, 1971), पृ० 73.
25. डेविड एक्टर : 'एन्गूमा, कैरिस्मा, ऐंड दि कू', डेडालस, XGVII, 3 (1968), 784.
26. जान आर० क्वार्टरमाईट : पालिटिक्स इन मिएरा लियोने 1947-1967; (टोरॉन्टो : यूनिवर्सिटी आफ टोरॉन्टो प्रेस, 1970), पृ० 109, किंतु यहा भी गुटवाद के कुछ और पहलू थे. उदाहरण के तौर पर, यहा का अमनुष्ट दल कुछ कम आयु के लोगों का था और ज्यादा पढ़ा-लिखा था.
27. यामस जे० बेल्सॉज : दि पीपुल्स ऐक्शन पार्टी आफ सिगापुर : इमर्जेंस आफ ए डामोनेट पार्टी मिस्टम, मोनोग्राफ मिरीज न० 14, (न्यू हैवन : येन यूनिवर्सिटी साइजोगट एशिया स्टडीज, 1970), पृ० 35-44.

- 28 यह अंतिम बात, 1967 के बाद भारत में कांग्रेस पार्टी छोड़कर दल बदलने के मामलों में बड़ी महत्वपूर्ण रही
- 29 जैम्स सी० स्काट का कहना है कि ऐसे भ्रष्टाचार के साम भी हैं, क्योंकि समर्थकों को आकृष्ट करने की प्रतिस्पर्धा में आम लोगों को भ्रष्टाचार का फायदा मिलता है देखिए, जेम्स स्काट द्वारा लिखित, 'ऐन एस्से आन दि पालिटिक्स फवरास आफ करप्शन', एशियन स्टडीज, V, 3 (1967), 501-523.
30. देखिए, काल्विन वुडवर्ड . दि प्रोथआफ ए पार्टी सिस्टम इन सिलोन (प्रोवीडेंस . ब्राउन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1969), पृ० 76-79, और राबर्ट एन० केमनी . कम्युनिज्म ऐंड लैंग्वेज इन दि पालिटिक्स आफ मिलोन, (दरहम एन० सी० . ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस, 1967), पृ० 63-67.
31. कीनिया और 1966 के चुनावों के लिए देखिए, चैरी गर्जेल . दि पालिटिक्स आफ इंडिपेंडेंट कीनिया, 1963-1968 (इवास्टन, इलीनाय . नार्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी प्रेस, 1970).
32. भारत में गुटों के सघर्ष पर लिखी गई सामग्री में, भारतीय राजनीति का लगभग सपूर्ण अध्ययन सम्मिलित है विशेषकर देखिए, पाल ब्रास . फंकशनल पालिटिक्स इन ऐन इंडियन स्टेट (बर्कले ऐंड लास एंजिल्स . यूनिवर्सिटी आफ कैलीफोर्निया प्रेस, 1969), रिचर्ड सिमन . दि काय्रेस पार्टी इन राजस्थान (बर्कले ऐंड लास एंजिल्स : यूनिवर्सिटी आफ कैलीफोर्निया प्रेस, 1972); माधवल बीनर . स्टेट पालिटिक्स इन इंडिया (प्रिस्टन . प्रिस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1968) : और इक्वान नारायण . स्टेट पालिटिक्स इन इंडिया, (मेरट, भारत . मोनाक्षी प्रकाशन, 1957).
33. मार्टिन-स्टानोलेड . 'मिगल-पार्टी रेजिम्स ऐंड पालिटिकल चेंज दि पी० डी० सी० आई० ऐंड आइवरी कोस्ट पालिटिक्स', कोलिन लीज संपादित पालिटिक्स ऐंड चेंज इन डेवलपिंग कंट्रीज (कैम्ब्रिज, इंग्लैंड . कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1969) में पृ० 173 पर.
34. रजनी कोठारी . पालिटिक्स इन इंडिया, (बोस्टन . लिटिल, ब्राउन ऐंड कंपनी, 1970), पृ० 161
35. वही, पृ० 159
36. उदाहरण के लिए देखिए, गैरल्ड ए० हीगर : 'डिसिप्लिन वसिंग मोबिलाइजेशन . पार्टी विल्डिंग ऐंड दि पत्राव जनसघर्ष', एशियन सर्वे, XII, 10 (1972), 864-878
37. एजिता वर्जर . अपोजीशन इन ए डामोनेट-पार्टी सिस्टम, (बर्कले ऐंड लास एंजिल्स : यूनिवर्सिटी आफ कैलीफोर्निया प्रेस, 1969).
38. मोरक्को में ग्रामीण विद्रोहों और विशिष्ट व्यक्तियों के पारस्परिक सघर्षों के साथ इनके सबध के बारे में देखिए, अर्नेस्ट गेलनर : 'पेटर्स आफ हरत रिबेलियन इन मोरक्को . ऐन माइनिरिटीज' आब दिव्या यूरोपियन दे सोशपोलाजी III, 2 (1962), 297-311; अर्नेस्ट गेलनर : 'ट्राइबलिज्म ऐंड सोशल चेंज इन नार्थ अफ्रीका', इत्यु० एच० नेविम (संग्रहित) : फ्रेंच स्पीरिडिंग-अफ्रीका : 'दि सर्व फार आईडेंटिटी (न्यूयार्क) : वाकर, 1965), पृ० 107-108; और इत्यु० एच० सेविस : 'फ्यूटिंग ऐंड सोशल चेंज इन मोरक्को', जर्नल आफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, (1961), 43-54.
39. गेलनर, पृ० 116.

40. उदाहरण के लिए देखिए, गोल्ड, पृ० 105-157. गोल्ड ने राष्ट्रीय एकता की परिभाषा इस प्रकार दी है, 'स्वाधीन अस्तित्व वाले, निश्चित पारंपरिक तथा प्राचीन जनमूहों का आपस में मिलकर बड़े और व्यापक दृष्टिकोण वाले मूहों में परिवर्तित होना, जो केवल स्थानीय हितों को ही नहीं, बल्कि 'राष्ट्र' के हितों को देखते हैं' (पृ० 163), गोल्ड का कहना है, प्राचीनता की भावना का मतलब है ऐसी भावना जो 'प्रदत्त' में उपजती है या यह कहा जाए कि क्योंकि ऐसे मामलों में अनिवार्यतः संस्कृति का सबंध रहता है इसलिए यह सामाजिक अस्तित्व के 'प्रदत्त' माने जाते हैं, (पृ० 109).
41. डोनाल्ड रायचार्ड्स : 'एथनिसिटी ऐंड कान्फ्लिक्ट रेवोल्यूशन', बरंड पब्लिशिंग, XXII, 4, (1970), 597
42. गोल्ड, पृ० 112-113 : एमसन फ्राम एपायर टू नेशन, अध्याय 6, 7, 8. विकसित राष्ट्रों के सबंध में ऐसी ही जांच सूचियों के लिए देखिए, सेमोर मार्टिन लिपसेट और स्टीन रोसन (संपादन) . पार्टी सिस्टम्स ऐंड बोटर एनाइजमेंट्स (न्यूयार्क . फ्री प्रेस, 1967) : और रिचर्ड रोस तथा डेरेक डविन, 'सोशल कोहज़न, पालिटिकल पार्टीज ऐंड स्टैंस इन रेज़ीम्स', कपरेटिव पालिटिक्स V, 1 (1969), 7-67.
43. लायड आई० रुडोल्फ और सुनन होवर रुडोल्फ दि मार्टिनी आफ ट्रेडिशन (शिकागो : यूनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस, 1967), पृ० 30
44. वही, पृ० 31.
45. इस सबंध में देखिए, मे एंडेल 'अफ्रीकन टाइडलिग्म . मम रिप्रेजेंटेशन अल युगाडा', पालिटिकल सायंस क्वार्टर्ली, LXXX, 3 (1965), 357-72
46. डैन्युअल वानस्टीन : 'एथनिसिटी ऐंड नेशनल इटीयेशन इन वेस्ट अफ्रीका', कॉन्टिनेंट दि एट्यूड्स अफ्रीकन, I, 3 (1960), 131
47. आर्नल्ड एन० एफ्टोन पालिटिक्स इन ऐन अवेन अफ्रीकन कम्युनिटी, (मैनचेस्टर, टंग्लैंड . मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस, 1958), पृ० 236
48. एम० एन० श्रीनिवास : कास्ट इन मार्टिन इंडिया ऐंड अदर एस्तेज (बंबई' एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1962), पृ० 18. रुडोल्फ ऐंड रडोल्फ ने भी पृ० 116-117 पर, भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने के काम में 1901 में हुई जनगणना की भूमिका बताई है
49. कुछ ऐसी ही बात युगाडा और कांगो में भी हुई प्रगतिशिल सौर पर यह निश्चित किया गया कि कौन से लोग कितने कबीले के हैं। इन्हीं विभाजनों के आधार पर जातीय समूहों का निर्धारण हुआ। देखिए, थ्रोफोर्ड थग पालिटिक्स इन दि कांगो (प्रिस्टन न्यू जर्सी : प्रिस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1965) पृ० 245-246; और नेल्सन कास्किर, 'कल्चरल सबनेशनलिज्म इन युगाडा', वी० ए० ओलोस्तेमोला (संपादन) . दि पालिटिक्स आफ कल्चरल सबनेशनलिज्म, (गार्डन सिटी, न्यूयार्क : डबल डे ऐंड कंपनी, 1972), पृ० 61
50. जाति और भारत की राजनीति में जाति के बारे में बहुत सामग्री है. भारत में जाति के आधार पर समर्थन जुटाने के राजनीतिक परिणामों के सबंध में वैज्ञानिक विचारों के लिए देखिए, रुडोल्फ ऐंड रुडोल्फ पृ० 15-154
51. सामाजिक समर्थन जुटाने और संप्रदायवाद के बीच सबंध के बारे में विन्मून तर्कों के लिए देखिए, मैक्सन और बोल्डे.

52. रिचर्ड स्वत्तार 'पालिटिकल मायस एंड नेशनल इटीपेगन—ए ईडोकल अग्रोब' दि जर्नल आफ माइने अमीजन स्टडीज, V, 1, (1967), 7
53. ऐमे ही एक मामले के लिए देगिए, मेरलड ए० हीगर: 'पालिटिकल आफ इटीपेगन: इन्सुनिटी पार्टी एंड इटीपेगन इन पत्राब', (पी-एच० डी० के लिए थीसिस, यूनिवर्सिटी आफ मिचिगन, 1971) और देगिए ग्योनीड दाग गुल, सैम्बेज, कान्फ्लिक्ट एंड नेशनल डेवलापमेंट, (बर्नले एंड साग एजिनम: यूनिवर्सिटी आफ कैलीफोर्निया प्रेस, 1970), विशेषकर अध्याय 7 और 8
54. मार्टिन विल्सन 'पालिटिकल चेंज इन ए बेस्ट अमीजन स्टेट (कैलिफ, मैसाचुसेट्स: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1966) पृ० 271-272
55. जेम्स सी० स्काट 'पीटून-कलावंत पालिटिकल एंड पालिटिकल चेंज इन साउथ ईस्ट एशिया', अमीजन पालिटिकल सायस रिव्यू, LXVI, 1, (1973), 105.
56. आरेंड निरुफार्ट: 'कामोसिएशनल डिमोक्रसी', बर्ले पालिटिकल, XXI, 2, (1969), 207-226 और देगिए, आरेंड निरुफार्ट: दि पालिटिकल आफ एक्मोडेगन: प्लुरलिज्म एंड डिमोक्रसी इन दि नीदरलैंड्स (बर्नले एंड साग एजिनम: यूनिवर्सिटी आफ कैलीफोर्निया प्रेस, 1968).
57. गिबिया एच० एन्तो 'एथनिक कान्फ्लिक्ट एंड पालिटिकल डेवलापमेंट, (बोस्टन: मिडिल हाउस ऐंड कपनी, 1973) पृ० 169-170 में भी ऐमा ही लर्क है.
58. यह घटना जारोसन पुस्तक के पृ० 175-178 पर संशेष में दी गई है; और देगिए, गिबिया एच० एन्तो 'मल्टी-एथनिक पालिटिकल: दि बेस आफ मजबूतिया (बर्नले: सेंटर फार साउथ एंड माइडईस्ट एशिया स्टडीज, 1970), और के० जे० रजम और आर० एम० मिन्ने: 'दि 1969 पालिपारमेंटरी इमेचगन इन बेस्ट मातयेगिया', पैगिनिव अकेपन, XLIII, 2, (1970), 203-226
59. हीगर 'दि पालिटिकल आरु इटीपेगन', विशेषकर पृ० 264-331.
60. रेने सैमरबद, 'पालिटिकल क्वासेंटिज्म एंड एक्नीगिटी इन ट्रापीकल अडीश: कान्फ्लिक्ट सॉल्वेरीटी इन नेशन-डिन्चिग', अमीजन पालिटिकल मायस रिव्यू, LXVI, 1, (1972), पृ० 84
61. देवगत एंड बोन्ने, पृ० 1114.
62. यह कथन उर्गी को दोहराया है जो मेग्गल और बोन्ने का है (पृ० 1126) और इनमें वीग म्बुईन के लेख से कुछ लिया गया है। ट्राइबलिज्म इन माइने इंडिया गेटिंग अडीश', वेस्टर्न दि एस्टर्न अडीश, 1 (1960), 55-70, ए० एम० एण्टोन 'पालिटिकल इन ऐन अरेंड अमीजन इन्सुनिटी (कैलिफोर्निया, एण्ड ईन ईनपेगन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1958); तथा क्वासेंटिज्म दि कौन्सिल डाल (कैलिफोर्निया, एण्ड ईन ईनपेगन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1956) सभी का यह कथन है कि गिबिया के पुस्तक अध्याय का निर्धारण हुआ है अर्थात् सामाजिक संघर्ष में, वीग विचार के लिए वीग अध्याय वही अर्थात् आदि के नाम में, मत का अध्यायिक कथन हुआ क्योंकि। उदाहरण, अध्याय सामग्री में, विशेषकर उदाहरण के लिए गिबिया के अध्यायों के साथ क्वासेंटिज्म और सामग्री में, कर्तव्य रूप से दोहराया अध्याय हो सकता है.
63. कर्तव्य अध्याय, मेरलड एंड आर० वान देर वेगन, और पत्राब 89. एण्ड आरु पालिटिकल डेवलापमेंट (नैशनल डेवलापमेंट यूनिवर्सिटी: ईशिया एंड इंडोनेशिया 1967), पृ० 60

64. राबर्ट मेलसन : 'आईडियालाजी ऐंड इनकसिटीसो : दि ग्राम प्रेशर्ड नाईजीरियन वक्कर', अमरीकन पालिटिकल सायन रिव्यू, LXV, 1, (1971) 161-171
65. पूर्वी नाईजीरिया में इस व्यवस्था के सबध में देखिए, आडी भी० स्मोक . डबो पालिटिकस : दि रोल आफ एथनिक यूनियंस इन ईस्टर्न नाईजीरिया (कैब्रिज, मैगाच्यूसेट्स हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1971).
66. मैनकर ओलसन : 'रैपिड ग्रोथ ऐज ए डिस्टर्बिन्सिंग फोर्म', जर्नल आफ डेवलोपिंग हिस्ट्री, XXIII, (1963), 529-532, राबर्ट डी० पुटनम . 'टुवर्ड एक्सप्लेनिंग मिलिट्री इन्वैशन एन सैटिन अमरीका', अमरीकन पालिटिकल सायन रिव्यू LX, (1966), 616-626.
67. अधिकतर यही माना जाता है कि यह मत समुअल हंटिंगटन का है, पृ० 142-263, और इसके कई रूप हैं. स्वयं सेना को, अन्य संस्थाओं की तुलना में उसके 'वजन' और उसकी आधुनिकता को दृष्टि से महत्व दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, गाए पाकेर : 'साऊथ ईस्ट एशिया ऐज ए प्राब्लम एरिया इन दि नेक्स्ट डिकेड', वर्ल्ड पालिटिकस, XI, 3, (1959)' 325-345; लूसियन डब्ल्यू० पाई आर्मांज इन दि प्रोसेस आफ पालिटिकल माडर्नाइजेशन'; जान जे० जानसन (संपादित). दि रोल आफ दि मिलिट्री इन अडर डेवलपिंग कंट्रीज (प्रिस्टन : प्रिस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1962), मारिस जैनाविटज . दि मिलिट्री इन दि पालिटिकल डेवलपमेंट आफ न्यू नेशंस (शिकागो यूनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस, 1964), मैरियन जे० नेवी जूनियर : माडर्नाइजेशन ऐंड दि स्ट्रक्चर आफ सोसायटीज द्वितीय खंड, (प्रिस्टन : प्रिस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1966), पृ० 571-605, और हेनरी विएनन 'दि बैंकप्राउड टु दि कार्टेपररी स्टडी आफ मिलिट्रीज ऐंड माडर्नाइजेशन, (शिकागो : एलडाईस - एथेंट, 1971), पृ० 1-34; अर्सेनिक संस्थाओं के सुचारु रूप से कार्य न करने के परिणाम-स्वरूप सेना की भूमिका के विस्तार के सदर्भ में देखिए, मोशे लिताक 'माडर्नाइजेशन ऐंड दि रोल एक्सपैशन आफ दि मिलिट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज', कपेरेटिव स्टडीज इन सोसायटी ऐंड हिस्ट्री, IX, 3(1967), 233-255 जिस वातावरण में यह 'वजनदार' संस्था होती है, उसको विशेष महत्व दिया जा सकता है, उदाहरणार्थ मैनिक शामनाथेन समाज, जहा समाज की सभी शक्तियां राजनीति-प्रवृत्त होती हैं।' देखिए हंटिंगटन और एमास पलंगटन : 'प्रेटोरियन स्टेट ऐंड दि प्रेटोरियन आर्मी : टुवर्ड्स ए थ्योरी आफ सिविल-मिलिट्री रिलेशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज', कपेरेटिव पालिटिकस, I, 3 (1969), 382-404
68. विशेषकर देखिए, समुअल फिनर : दि मैन आन हासबैंक (न्यूयार्क फ्रीड्रिक ए० प्रेजर, 1962); और मर्ल क्लिंग : 'वायलेंस ऐंड पालिटिकस इन सैटिन अमरीका', पी० हालमोस (संपादित) : सैटिन अमरीकन सोशयोलोजीकल स्टडीज (सोशयोलोजीकल रिव्यू मोनाग्राफ II, 1967), पृ० 119-131.
69. फ्रीड धोन देर मेहूदेन और जी० डब्ल्यू० ऐंडर्सन . 'पालिटिकल ऐक्शन बाइ दि मिलिट्री इन डेवलपिंग एरियाज', सोशल रिमर्च, XXVIII, 4 (1961), 459-480, कार्ल हार्पाकिम 'सिविल-मिलिट्री रिलेशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज', ब्रिटिश जर्नल आफ सोशयोलोजी, XVII, 2 (1966), 165-182; एम० डी० फेन्ड . 'प्रोफेशनलिज्म, नेशनलिज्म ऐंड दि एलियनेशन आफ दि मिलिट्री', जेम्स वान डूनै (संपादित) आर्म्ड फोर्स ऐंड सोसायटी (दि हेग माऊटोन ऐंड कंपनी, 1966), पृ० 55-70 इन्हीं से सबद्ध है, राबर्ट एम० प्रार्डिस . 'ए थ्योरी-टिकल अपरोच टु मिलिट्री क्ल इन दि न्यू स्टेट्स : रेफरेंस ग्रुप थ्योरी ऐंड दि पानयन केम', वर्ल्ड पालिटिकस, XXIII, 3 (1971), 399-430 नेकिन प्राइम का कहना है कि घाला

की सेना में व्यावसायिकता की भावना के कारण सेना के विशिष्ट व्यक्ति स्वयं को ब्रिटिश सेना के समरूप मानने लगे और जब एन्ग्राम ने ब्रिटिश पद्धति को चुनौती दी और कम्युनिस्ट राष्ट्रों के साथ संपर्क स्थापित करने के प्रयत्न किए तो सेना ने हस्तक्षेप किया। इस मामले में हस्तक्षेप, राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर नहीं बल्कि अधिराष्ट्रीय स्वार्थपरता के कारण किया गया था।

70. मैमुअल हंटिंगटन 'दि सोलजर ऐंड दि स्टेट, (न्यूयार्क - रैंडमहाऊस, 1957). जिन परिस्थितियों में सेना वा एक सस्था या व्यावसायिक स्वरूप बनता अथवा टूटता है, उनके बारे में हाल के वर्षों में काफी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं विशेषकर देखिए, ए० स्टीवान, दि मिनिट्री इन पालिटिक्स चेंजिंग पैटर्न्स आफ मिविलियन मिनिट्री रिलेशनशिप्स इन ब्राजील (प्रिस्टन: प्रिस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1971), रेने लैमरचद. 'मिविलियन-मिनिट्री रिलेशंस इन बेंजियन अफ्रीका दि मिनिट्री ऐंड ए कोटेक्स्पुअल एलीट', थॉशिंगटन डी० सी० ने, 1972 में अमरीकन पालिटिकल सायंस एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में पढ़ा गया निबंध, और राबिन लकहेम. दि नाईजोरियन मिनिट्री - ए सोशयोलोजिकल एनालिसिस आफ अकार्टी ऐंड रिबोल्ट, 1960-1967 (कैंब्रिज, इंग्लैंड कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1971).
71. क्लाड वैल्व 'दि स्टूम ऐंड इन्फ्लिकेयस आफ मिनिट्री इटरवेंशन', क्लाड वैल्व जूनियर (संपादित) सोलजर ऐंड स्टेट इन अफ्रीका (इवास्टन इलीनाय नाथंबेस्टर्न यूनिवर्सिटी प्रेस 1970), पृ० 26-27 पर
72. राबर्ट डाऊज 'दि मिनिट्री ऐंड पालिटिकल डेवलपमेंट', सी द्वारा संपादित पृ० 213-214, यहा उद्धृत वाक्य लिमाक से है, (देखिए, सदभं 67).
73. जोनवर्ग 'दि स्ट्रक्चर आफ पालिटिकल कान्फ्लिक्ट', पृ० 78
74. वही, पृ० 72
75. जान थ्राम 'पालिटिकल चेंज कान्फ्लिक्ट ऐंड डेवलपमेंट इन घाना', फिनिप फॉस्टर और एरिस्टिड आर० ओलवर्ग (संपादित) घाना ऐंड दि आइवरी कोस्ट (शिकागो यूनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस, 1971) पृ० 59-60
76. इस प्रयत्न के बारे में देखिए, मुहम्मद अय्यूब खान फौडम, नाट माग्टस ए पालिटिकल आटोबायोग्राफी (लंदन आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1967)
77. वही
78. डब्ल्यू० ए० ई० स्त्रुनिक 'दि मिनिट्री ऐंड पालिटिक्स दाहोमी ऐंड अपर वोल्टा', वैल्व में पृ० 68-79
79. एरिस्टिड जोनवर्ग 'मिनिट्री इटरवेंशन इन दि न्यू स्टेट्स आफ ट्रापिकल अफ्रीका', हेनरो विणन (संपादित) दि मिनिट्री इटरवोम (न्यूयार्क रमल सेज फाउंडेशन, 1968), पृ० 80
80. राबर्ट सी० नार्थ. 'बाईनीज कम्युनिस्ट ऐंड कुओमिनारी एलीट्स', हैरल्ड सामवेल और डैनियल लॉरर (संपादित). वुड रिबोल्यूशनरी एलीट्स (कैंब्रिज, मैसाचूसेट्स: एम० आर्डी० टी० प्रेस, 1965), पृ० 319-455, 455
81. सोमालिया के बारे में देखिए, आर्डी० एम० सेविम 'दि पालिटिक्स आफ दि 1969 सोमाली क्रू', दि जर्नल आफ भाइरन अफ्रीकन स्टडीज, X, 3 (1972), 383-408
82. जोनवर्ग 'दि स्ट्रक्चर आफ पालिटिकल कान्फ्लिक्ट', पृ० 79
83. वही.

सेना सत्ता में

सत्ता हथियाने के बाद सेना के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा बनाई गई सरकारें विद्वान लोगों के लिए एक पहली सिद्ध हुई है। ऐसे शासनों की स्थापना के समय प्रभावोत्पादक ढंग से राष्ट्र पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय एकता, और जिन राजनीतिज्ञों में सैनिक नेताओं ने सत्ता हथियाई होती है उनके विरुद्ध अभियोग लगाने की मांग की जाती है। जैसा जोसफ मोबुतू ने घोषणा की थी।

सैनिक उच्च कमान क्या कर सकती थी? केवल वही, जो उसने किया : राजनीतिज्ञों को सत्ता से निकाल बाहर करना . . . उन्हें (राजनीतिज्ञों को) सत्ता, और सत्ता में आने से वे अपने लिए क्या कुछ कर सकते हैं इसके सिवाय और किसी बात से मतलब नहीं था . . . '। अपनी अपनी जैवें भरना, कांगो, और उसके निवासियों का शोषण करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य प्रतीत होता था।¹

यह शब्दाडंबर नए शासकों की क्षमता का संकेत कहा तक है? क्लाड वैंल्व ने सवाल उठाया था : 'क्या सेना पर आधारित सरकार उन कठिनाइयों को अधिक सफलतापूर्वक निपटा सकती है जो असैनिक सरकार के सामने थी? क्या इनमें से कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो सत्ताधारी सैनिक परिपद के अनुकूल तरीके से ही सुलझाई जा सकती थी, और क्या ये तरीके असैनिक सरकारों के वश की बात नहीं है?'²

सैनिक सरकारों के संबंध में व्यापक आकड़ों के अभाव में विद्वान लोग ऐसे शासकों के

वारे में अपने सैद्धांतिक विचारों की हवा में इधर उधर डोलते रहे हैं। 1950 के दशक के अंतिम वर्षों में, और 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में कुछ 'दृढ़ मत वाले' उदारतावादियों के ये तर्क-वितर्क चलते रहे कि सेना एक 'औद्योगिक ढंग' के सामाजिक संगठन के रूप में, विशेष रूप से अल्पविकसित समाजों को आधुनिक बनाने के लिए पूरी तरह उपयुक्त है।³ लेकिन हाल में एक अलग दृष्टिकोण सामने आया है। इसमें आधुनिकीकरण के लक्ष्य प्राप्त करने में सेना की क्षमता में सदेह प्रकट किया गया है। इस मत के अनुसार, सेना का अपने ही ढंग का संगठन आधुनिकीकरण का साधन नहीं, बल्कि उसके मार्ग में अड़चन है।

सेना के हराबल दस्ते, कंधे से कंधा मिलाकर, मार्च करते हुए सैनिक, मोर्चे बांधना, आक्रमण करना, महान लक्ष्य : यह परिकल्पना, पैदल सेना के आक्रमण की भांति जानी पहचानी है। आदेश और अनुशासन, निर्देश और गति हर बात के लिए महत्व रखते हैं...निश्चित यदि राष्ट्र की मुद्रिकले और बीमारियाँ इतनी सरलता से दूर की जा सकती तो सैनिक क्रांति का कभी मौका ही न आता। राजनीतिक क्षेत्र कोई संकीर्ण सीमित घाटी नहीं है। असैनिक सरकारी कर्मचारी पवित्रबद्ध होकर मार्च करते हुए कानूनी व्यवस्था नहीं चला सकते। अधिक योजनाएँ तैयार करने वाले विशेषज्ञ, मोर्चों पर आक्रमण करके उत्पादन नहीं बढ़ा सकते...और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति के लक्ष्यों पर मदा ही सदेह किया जाता है। सैनिक अधिकारियों की जो प्रशासक परिपद पवित्र लेकिन अनिर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने की अपेक्षा करती है, और समझती है कि वह कुछ ही घंटों या सप्ताहों में इसे प्राप्त कर लेगी, ऐसी परिपद को मोहभंग के लिए तैयार रहना चाहिए...⁴

जैमा ऐन रथ विलर ने कहा है, हाल का इतिहास न केवल इन व्यापक सर्वसामान्य सिद्धांतों की अनिश्चितता को बल्कि वर्धमान असमान घटनाओं, जिन्हें एक साथ आम तौर पर 'सैनिक शासन' कह दिया जाता है, की अनिश्चितता भी दर्शाता है।⁵ फिर भी क्लाड वैल्च द्वारा उठाए गए प्रश्न बने ही रहते हैं, बल्कि वास्तव में ये उस हालत में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब सैनिक शासन अपने आप को अफ्रीका और एशिया में एक अपवाद के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श प्रतिमान के रूप में स्थापित कर लेते हैं। अल्पविकसित राज्यों में सैनिक शासन हाल ही में स्थापित हुए हैं इसके बावजूद, और ऐसे शासनों के बारे में जानकारी का अभाव होते हुए भी, इन प्रश्नों के कुछ कामचलाऊ उत्तर खोजने की कोशिश तो होनी ही चाहिए।

सैनिक शासनों का विस्लेषण इस बात में प्रारंभ किया जा सकता है कि आम तौर

पर यह माना गया है कि सारी सशस्त्र सेना, शासन नहीं करती। सैनिक शासन एक ऐसी सरकार है जिसमें सेना के कुछ खास विशिष्ट व्यक्ति ही शासन चलाते हैं। इन व्यक्तियों को शोप सशस्त्र सेना का समर्थन प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी। वास्तव में सत्तासूद्ध सैनिक विशिष्ट व्यक्ति बराबर इसी प्रयत्न में लगे रहते हैं कि वे शोप सेना का समर्थन प्राप्त करें और उसे बनाए रखें। तो इसी संदर्भ में यह तर्क कि सेना जिस निश्चित ढंग के सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व कर रही है वह राजनीतिक विराम का प्रभावशाली माध्यम है या नहीं, एक ऐसी बात के बारे में तर्क है जिसका बहुधा, अस्तित्व ही नहीं होता। अल्पविकसित राज्यों में सशस्त्र सेनाएँ, कभी कभी बिल्कुल अनुशासनविहीन और अक्सर जातिगत भावनाओं को लेकर विघटित, अधिकारियों और सैनिकों के बीच वैमनस्य और स्वयं अधिकारी वर्ग के बीच आपसी झगड़ों के कारण—कुछ अपवादों को छोड़ आम तौर पर सुसंगठित नहीं रही हैं। इसके अलावा सेना के अंदर की फूट सत्ता हथिया लिए जाने के बाद और बढ़ जाती है और यह दरार उस हालत में बढ़ती चली जाती है जब कुछ सैनिक अधिकारी मरकारी पदों पर आ जाते हैं, और कुछ को इन पदों से वंचित रहना पड़ता है।

अपने पूर्ववर्ती असैनिक शासकों की तरह सैनिक विशिष्ट व्यक्तियों को भी ऐसी खंडित राजनीतिक प्रणालियों का सामना करना पड़ता है जिनपर वे एक अत्यधिक अनुशासनबद्ध नेता के रूप में, अथवा एक स्तंभीय संगठन के रूप में नहीं, बल्कि प्रमुखता की खोज में लगे विशिष्ट व्यक्तियों के रूप में शासन चलाना चाहते हैं। (वैसे यह प्रमुखता या प्राधान्य अनिवार्यतः एक अस्थायी बात ही होती है)। राजनीतिक दृष्टीकरण, सेना द्वारा समाज पर शासन चलाने से उत्पन्न एक निश्चित तथ्य बनने के बजाय, एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में ही रहता है चाहे वह अप्राप्त ही हो।

लेकिन अपने पूर्ववर्ती असैनिक अधिकारियों के विपरीत, सैनिक शासक राजनीतिक दृष्टीकरण के बारे में समान मत रखते हैं जो राजनीति विरोधी है। सैनिक शासक खुले तौर पर राजनीतिज्ञों के विरोधी होते हैं और जनसहयोग के प्रति संदेहात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और वास्तव में सामान्य राजनीति में भी उनका कोई विश्वास नहीं है। ऐसे सैनिक शासकों ने, 'एक अराजनीतिक शांति जो गुप्त संस्थाओं के अनिश्चित आंदोलनों से भंग नहीं होती', स्थापित करने की कोशिश की है...⁶। उनके प्रयत्न विफल रहे हैं। फिर भी हाल की घटनाओं से पता चलता है कि राजनीति में विश्वास न रहने के कारण, सैनिक शासन एक परस्पर विरोधी शासन की संभावनाओं से भरा पड़ा है। यह ऐसा शासन है जिसमें हालांकि सैनिक विशिष्ट व्यक्ति मारी सत्ता को एक ही जगह केन्द्रित करना चाहता है, फिर भी विकेंद्रीकरण की 'शक्तियाँ' पहले से कहीं अधिक तीव्र होती हैं।

राजनीति विरोधी

सैनिक शासक जिस प्रकार अपने सामने आने वाली समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोणों को व्यक्त करते हैं उन तरीकों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। सत्तारूढ़ सैनिक विशिष्ट व्यक्ति सामान्य रूप में सामाजिक संघर्षों के प्रति और हर ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति गहरा अविश्वास रखते हैं जो इस तरह के संघर्ष को वैध मानती है। जैसा जोलबर्ग ने कहा है :

वे राष्ट्रीय एकता को 'समरूपता' मानते हैं, और इसमें वे क्षेत्रवाद, स्थानीय परंपरावाद जैसे जातीय या धार्मिक संबंधों से उपजने वाले सामाजिक संघर्ष के अभाव को देखते हैं। सभी राष्ट्रो में 'जातीय पृथक्तावाद' की निंदा की गई है, और इसे स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उभरने नहीं दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उद्देश्य यह है कि राजनीतिक अधिकार के माध्यम से समरूपता लाई जाए मानो शासक वास्तव में यही मानते हों कि संघर्ष का अभाव किसी न किसी प्रकार से राष्ट्रीय एकता पैदा करता है।⁷

इन मतों को अबसर 'गैर राजनीतिक' कहा गया है और तर्क दिया गया है कि इन्हें एक पार्टी वाले अफ्रीकी राज्यों के कई नेता मानते हैं।⁸ लेकिन सैनिक विशिष्ट व्यक्तियों और असैनिक नेताओं के विचारों में महत्वपूर्ण भिन्नता है। सैनिक विशिष्ट व्यक्ति खुल्लमखुला इतने राजनीति-विरोधी नहीं हैं, जितने कि अराजनीतिक। एक पार्टी वाले राज्यों के नेताओं जैसे एन्कूमा और तूरे, के लिए सर्वसम्मति प्राप्त करने का माध्यम, जनसहयोग को बढ़ावा देना था। जब तक जनसमर्थन जुटाने की प्रक्रिया पर विशिष्ट व्यक्तियों के एक ही गुट का नियंत्रण था, तब तक जनसमर्थन जुटाना और जनसहयोग प्राप्त करना, नए सद्यों और नई राजनीतिक शब्दावली के प्रसार के प्रमुख माध्यम थे। समर्थन और सहयोग के आह्वान ने लोगों को अपने सकीर्ण क्षेत्रवाद के दायरे से बाहर निकाला। इसके विपरीत, सैनिक शासक न केवल अनेक व्यक्तियों की हिस्सेदारी के प्रति संदेह रखते थे, बल्कि उन्हें स्वभावतः हिस्सेदारी में भी कोई विश्वास नहीं था। उनका विचार है कि सहयोग अनिवार्यतः एक से अधिक लोगों के बीच होता है और इसलिए यह अनिवार्यतः विघटनकारी है। राजनीतिज्ञों द्वारा जनता में जोड़-तोड़ करने और उनके क्रियाकौशल से माधारण जन मर्दव ही 'कबीलावाद, गुटबंदी और पारिवारिक पृष्ठभूमि की चेतना' के शिकार होते रहते हैं।⁹

कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सैनिक शासकों ने आम तौर पर राजनीतिक

गतिविधियों पर कड़ा अंकुश लगाया है। उन्होंने अक्सर सभी राजनीतिक पार्टियों पर यहां तक कि उन पार्टियों पर भी प्रतिबंध लगाया है जो सेना द्वारा सत्ता से हटाए गए शासकों का विरोध करती थीं। पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया में बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिज्ञों को मार्क्सवादी गतिविधियों में भाग लेने की मनाही हो गई।¹⁰ नाईजीरिया में तो मौनिक शासन ने स्थानीय राजनीतिज्ञों के स्तर तक सभी निर्वाचित अधिकारियों को गैरवा मुक्त कर दिया।¹¹ यह देखने पर कि ये लोग पूंजनावाद को उकसा रहे हैं, बहुधा क्षेत्रीय गीमाओं में भी परिवर्तन किया गया। कांगो में जनरल मोबूतु ने 22 प्रांतों को मिलाकर 12 प्रांत बनाए। नाईजीरिया में जनवरी 1966 की सैनिक क्रांति के बाद जनरल इरोंसी ने नाईजीरिया को एकात्मक राज्य घोषित कर दिया। दूसरे शब्दों में राजकार्य में जनता को शामिल होने से रोका गया, और इसके लिए उन सामाजिक भेदभावों को बलपूर्वक समाप्त किया गया जो कुछ एक व्यक्तियों की स्वार्थपूर्ति कर सकते थे। इसके अलावा जनता को ऐसे व्यक्तियों से दूर किया गया जो अपने स्वार्थों के लिए जनता में जोड़-तोड़ कर सकते थे। ये व्यक्ति थे अमैनिक राजनीतिज्ञ।

जहां जनसहयोग की अनुमति दी गई वहां श्मे काफी मोहित रखा गया। पाकिस्तान में जनरल अयूब खां के सत्ता में आने के एक साल बाद जो मूल लोकनैत्रीय प्रणाली (बेसिक डेमोक्रेसी) गठित की गई उसमें पंचस्तरीय पद्धति के सबसे निचले स्तर पर ही सामान्य मताधिकार की अनुमति दी है।¹² इंडोनेशिया में सरकार ने निर्दलीय विधायकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन लाने की कोशिश की।¹³ घाना में यह सुझाव दिया गया कि केवल पढ़े-लिखे लोग ही मतदान करें। शासन ने जो थोड़े बहुत उदार सांविधानिक प्रस्ताव रखे थे वे भी जनहित के काफी प्रतिकूल थे।¹⁴ हर हालत में लोगों को राजनीतिज्ञों के चंगुल में दूर रखा गया। पाकिस्तानी शासन के एक समर्थक की दलील है:

यदि एकदलीय प्रणाली को उसके अनोक्तान्त्रिक खतरों के साथ स्वीकार नहीं किया जाना है तो सबसे उपयुक्त प्रणाली राष्ट्रपति के शासन की ही है। क्योंकि जहां यह प्रणाली लोगों को अत्यंत संगठित राजनीतिक पार्टियों के साथ नहीं बाधती और वे, पार्टी के प्रति अपने कर्तव्यों तथा निष्ठा की मजबूरी से स्वतंत्र रह सकते हैं, वहां लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने और अपनी पसंद की सरकार चुनने का मौका भी मिलता है।¹⁵

राजनीतिज्ञों और खुल्लमखुल्ला राजनीतिक गतिविधियों पर कई अस्थाई प्रतिबंध लगाने से ज्यादा, 'राजनीति विरोधी' रवैया, जैसा इस शब्द से ही स्पष्ट है, हर प्रकार के

राजनीतिक आदान-प्रदान पर एक तरह का आक्रमण है। सैनिक शासनों ने आम तौर पर व्यावसायिक वर्गों की आर्थिक सौदेबाजी को रोका है, और मजदूर संगठनों जैसे संगठनात्मक दलों पर कड़ा अंकुश लगाया है। कोई आश्चर्य नहीं है कि राजनीति पर अंकुश के साथ साथ, प्रशासनिक ढांचे का भी अक्सर तीव्र विस्तार हुआ है। राजनीतिक भूमिकाओं को प्रशासनिक भूमिकाओं में बदल दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक दृढ़ीकरण को, प्रशासनिक ढांचे के प्रभावशाली पुनर्गठन का अनिवार्य परिणाम समझा जाने लगा है, न कि केंद्र के अंदर, और परिधि तथा केंद्र के बीच के पारस्परिक संबंधों की देन। मिश्र के बारे में जेम्स हीफी ने इस राजनीति विरोधी मत के संबंध में जो बात कही है वह अन्य सैनिक शासनों पर भी उतनी ही लागू होती है।

यह कल्पना (विकास की) एकरूपता चाहती है न कि मतभेद या व्यक्ति के लिए अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की क्षमता। मिश्र के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अपनी कल्पना में राजनीति को प्रतिष्ठापित करना मूल्यों का विरोधाभास होगा क्योंकि इन व्यक्तियों ने एक ऐसी मुचारे व्यवस्था की कल्पना की है जो तीव्र आर्थिक विकास की सुनियोजित आवश्यकताओं को तर्कसंगत ढंग से पूरा करेगी। राजनीति के अप्रिय और अनिश्चित पहलुओं को सम्मिलित करके एक राजनीतिक आदर्श बनाना, एक अवांछनीय लक्ष्य होगा।¹⁶

क्वामे एन्क्रूमा के कथन को अगर उलटकर कहा जाए तो, 'राजनीतिक साम्राज्य' को यदि कभी प्राप्त करना है तो यह प्रयत्न सबसे अंत में होना चाहिए।

राजनीतिक केंद्र में एकता और संघर्ष

सत्ता हथियाने के बाद सेना के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा संगठित प्रारंभिक शासन संरचना प्रायः अस्थिर सी रहती है जिससे उनकी उभयभावी बंधता, उनका जल्दबाजी में बनाया जाना तथा उनमें भाग लेने वाले सैनिक विशिष्ट व्यक्तियों के बीच अपेक्षतया नए गठजोड़ आदि बातें प्रतिबिंबित होती हैं। अधिकांश मामलों में शुरू में तो शासन व्यवस्था एक संकटकालीन रूप में होती है जिसमें अपनी तरह की एक क्रांतिकारी परिपद होती है जिसके सदस्य वे लोग होते हैं, जिन्होंने क्रांति में प्रमुख भाग लिया हो। मिश्र में रिवाल्भूशनरी कमांड कौंसिल, घाना में राष्ट्रीय मुक्ति परिपद (नेशनल लिबरेशन कौंसिल) और सिएरा लियोने में राष्ट्रीय मुद्धार परिपद (नेशनल रिफार्मेशन कौंसिल) इस प्रकार की सरकारों के कुछ उदाहरण हैं। इस तरह की परिपदों में सत्ता का केंद्र अनिश्चित सा रहता है। वास्तव में बहुत कम क्रांतियों का कोई एक नेता रहा है। इनमें से अनेक सरकारों के बनते ही इनमें शामिल विभिन्न

व्यक्तियों के बीच सत्ता, नीति निर्धारण अथवा शासनकार्य में सेना की भावी भूमिका के बारे में मतभेद उठ खड़े होते हैं। इस तरह के कुछ उदाहरण हैं इराक में कामिम और आरिफ, और मिस्र में नासिर तथा नगीव के बीच, या तुर्की में सैनिक शासन चलते रहने के समर्थक सक्रियतावादियों और इसके विरोधी रूढ़ीवादियों के बीच के संघर्ष।

अनिश्चितता और अस्थिरता, न केवल सैनिक प्रशासक परिपद में ही होती है, बल्कि यह राजनीतिक केंद्र में अन्य अभिनेताओं और सैनिक परिपद के बीच भी रहती है। सैनिक परिपद के विशिष्ट व्यक्तियों और सेना के शेष विशिष्ट व्यक्तियों के बीच संपर्क लगभग होता ही नहीं है, विशेषकर उस स्थिति में जबकि सैनिक क्रांति करने वाले लोगों की संख्या, सैनिक विशिष्ट व्यक्तियों के मुकाबले बहुत कम हो। अक्सर क्रांति में मुख्यतः छोटे अधिकारी ही होते हैं। उदाहरण के लिए, तुर्की में मई 1960 में जो क्रांति हुई थी उसमें विभिन्न पदों वाले 38 अधिकारियों का एक पड़्यत्रकारी दल था, और सेना के शेष लोग इस सैनिक परिपद को बड़ी मंद्देह की दृष्टि से देखते थे। हालांकि क्रांति के बाद नए बरिष्ठ सैनिक कमांडर नियुक्त किए गए थे, जिसका ऊपरी तौर पर उद्देश्य यह था कि सैनिक परिपद और शेष सेना के बीच संबंध अच्छे बने, फिर भी ऐसा लगता था कि ये जनरल खास तौर पर यह चाहते थे कि सेना को राजनीति से अलग रखा जाए। उनकी यह चिंता उस समय और भी बढ़ी, जब सैनिक परिपद के अंदर ही गुटबंदी शुरू हो गई और विभिन्न गुटों ने अन्य सैनिक अधिकारियों को अपने साथ मिलाना शुरू किया। उच्च कमान ने, सक्रियतावादी गुट के निर्वासन के मुझाव का समर्थन किया और सैनिक परिपद के सभी मदस्यों की छानबीन करके उन्हें सेना में निकाल दिया और दोबारा सेना में आने की अनुमति नहीं दी।¹⁷ दक्षिण कोरिया में छोटे और बड़े सैनिक अधिकारियों के बीच आपसी झगड़ों के कारण ही क्रांति हुई जिसका नेतृत्व छोटे अधिकारियों ने किया था और दोनों पक्षों के संबंधों में तनाव रहा। जहां सत्ता में आने वाले सैनिक विशिष्ट व्यक्ति बड़े पदों वाले हों, और जहां सैनिक क्रांति में सारी सेना शामिल हुई हो, वहां भी फूट पैदा हुई है। डंकवार्ट रस्टो का कहना है :

सैनिक परिपद को अपने पड़्यत्र की सफलता के कारण ही राजधानी और उसके आसपास के महत्वपूर्ण पद उन अधिकारियों को देने होंगे, जिनकी महायत्ना में यह परिपद सत्ता में आई। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में अर्थ मंत्रालय और टैकों की बटालियन का निर्देशन नहीं कर सकता। अपनी प्रमुख चाल चलने के बाद सैनिक शासकों को दूसरे लोगों को भी अवसर देना होगा और हो सकता है उनके मामले भी ऐसी ही चालों की चुनौतियां आएँ।¹⁸

घाना में एक युवा लेफ्टीनेट और उसकी स्ववाङ्मन ने बड़ी धीमी गति से पदोन्नतियाँ किए जाने पर असंतुष्ट होकर 1967 में सैनिक शासन का तख्ता लगभग पलट ही दिया था। दाहोमी में सेना के सत्ता में आने के दो वर्षों बाद दिसंबर 1967 में छोटे सैनिक अधिकारियों ने सफलतापूर्वक क्रांति की। उन्होंने इसे उचित बताया और कहा कि जो सैनिक अधिकारी सत्ता में आए थे उन्होंने छोटे अधिकारियों के साथ कभी कोई परामर्श नहीं किया और इन बड़े अधिकारियों ने असैनिक नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने के प्रयत्न किए।

मत्तारूढ़ सैनिक विशिष्ट व्यक्ति आम तौर पर सत्ता में आने के बाद नागरिक सेवा के अधिकारियों पर बहुत निर्भर रहते हैं। यह एक ऐसी बात है जो अधिकांश सैनिक विशिष्ट व्यक्तियों के राजनीति विरोधी विचारों को देखते हुए, आश्चर्यजनक नहीं है। अगर हम यह भी मान लें कि सैनिक परिपद और शेष सेना के बीच घनिष्ठ संबंध है, फिर भी ऐसे सैनिक नेता बहुत कम रहे हैं जिनके पास प्रशासन पर सीधा नियंत्रण चलाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति रहे हों। बहुत से नेताओं ने भी इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि यदि इस तरह के व्यक्ति सैनिक परिपद के पास होते तो स्वयं सेना की क्या स्थिति रहती? उदाहरण के लिए अयूब खान ने घोषणा की :

यह अत्यंत आवश्यक था कि सेना को पीछे ही रखा जाए क्योंकि देश के सामान्य जीवन में उसका वही स्थान है। यदि वह नागरिक प्रशासन में सीधे तौर पर उलझ जाती, तो इसका असर यह होता कि मनोबल और कम हो जाता, और नागरिक मत्ता छिन्न भिन्न हो जाती। इसके अलावा, सेना को बाद में नागरिक जीवन में हटाकर अपने सामान्य कार्यक्षेत्र में काम करने के लिए वापस लाना और कठिन हो जाता। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यदि सेना को नागरिक प्रशासन चलाने या आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में बहुत अधिक उलझा लिया जाता, तो वह खत्म हो जाती।¹⁹

इसके परिणामस्वरूप सैनिक नेताओं ने स्वयं को औपनिवेशिक युग के गवर्नर और उपगवर्नर जैसा बनाना बेहतर समझा है, और विभिन्न प्रशासनिक विभागों के लिए केवल अस्थायी सैनिक निरीक्षक नियुक्त करने तक ही स्वयं को सीमित रखा। प्रशासन के विभिन्न विभाग, मुख्यतः असैनिक कर्मचारियों के हाथ में ही रहे हैं।²⁰ उदाहरण के लिए घाना में सैनिक परिपद के सदस्यों ने प्रारंभ में अपने हाथ में सेना और पुलिस की कमान रखी, जिससे वे नियंत्रण के अधिकार को पूरी तरह उपयोग में नहीं ला सके। उधर असैनिक व्यक्तियों को मंत्रालयों के अध्यक्ष, या क्षेत्रीय आयुक्त बना दिया गया और बहुत सी समितियों में पूरी तरह असैनिक नागरिक ही

रखे गए²¹, जिनका काम विभिन्न मामलों पर सैनिक परिपद को परामर्श देना था। नौकरशाही के साथ यह प्रारंभिक गठबंधन तनावरहित नहीं था। जब मेना अपने हाथ में सत्ता लेती है तो इस तरह की योजनाओं की घोषणा की जाती है कि नौकरशाही में भ्रष्टाचार होने और पुराने अमैनिक शासन के साथ उनका मवघ होने के कारण अधिकारियों को पदों से हटाया जाएगा और प्रशासन में सुधार लाया जाएगा। कुछ राज्यों में तो इस तरह की कार्यवाही वास्तव में की गई। पाकिस्तान में अयूब खान ने विभिन्न सेवाओं की जांच पडताल के लिए एक जांच समिति नियुक्त की थी। जिनकी जांच पडताल होनी थी उनमें अधिकांश व्यक्ति अधिकारीतंत्र के मध्य स्तर के थे। 526 असैनिक कर्मचारियों को या तो रिटायर होने के लिए बाध्य किया गया या नौकरी में निकाल दिया गया।²² सैनिक शासक अक्सर नागरिक सेवाओं के खराब संचालन की निंदा करते रहते हैं और घाना तथा नाईजीरिया में तो उन्होंने यहां तक कार्यवाही की कि जो नागरिक कर्मचारी ठीक समय पर काम पर नहीं आए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

बहुत से राज्यों में सेना ने सरकार का प्रशासन चलाने के काम में वास्तव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बर्मा और इंडोनेशिया जैसे राज्यों में, जहां सेना काफी असें से विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक कार्य चलाती रही है, वहां उसकी भूमिका का विस्तार ही हुआ। इंडोनेशिया में मंत्रिमंडलीय और विभागीय स्तरों पर सक्रिय बहुत से नागरिक कर्मचारियों को वास्तव में सेना के सत्ता में आने के बाद सशस्त्र सेनाओं में लिया गया था।²³

सैनिक क्रांति के बाद की इस प्रारंभिक अवधि के दौरान शासन द्वारा की गई सभी कार्यवाहिया राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं रही हैं। वास्तव में बहुत कम राजनीतिज्ञों को जेल में डाला गया। जिन लोगों को कारावास की सजा हुई उनमें से बहुत कम व्यक्तियों को लंबी अवधि के लिए बंदी रखा गया। राजनीतिक गतिविधि पर लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों को भी आम तौर पर इन्के रूप में ही लागू किया गया। कुछ मामलों में राजनीतिक समितियों, सलाहकार समितियों आदि के जरिए राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों को, शासक वर्ग के साथ संबद्ध किए जाने के प्रयत्न किए गए हैं। इस तरह की बात विशेष रूप से घाना जैसे देशों में हुई जहां सारी राजनीतिक प्रणाली के खिलाफ नहीं, बल्कि राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों के एक खाम दल के खिलाफ क्रांति की गई थी।

सैनिक परिपद की आंतरिक अस्थिरता और क्रांति के तुरंत बाद की अवधि में राजनीतिक केंद्र में सत्ता संबंधों की अनिश्चिता के कारण, अंत में सैनिक शासकों

घाना में एक युवा लेफ्टीनेंट और उसको स्ववाङ्मन ने बड़ी धीमी गति से पदोन्नतियाँ किए जाने पर असंतुष्ट होकर 1967 में सैनिक शासन का तख्ता लगभग पलट ही दिया था। दाहोमी में सेना के सत्ता में आने के दो वर्ष बाद दिसंबर 1967 में छोटे सैनिक अधिकारियों ने सफलतापूर्वक क्रांति की। उन्होंने इसे उचित बताया और कहा कि जो सैनिक अधिकारी सत्ता में आए थे उन्होंने छोटे अधिकारियों के साथ कभी कोई परामर्श नहीं किया और इन बड़े अधिकारियों ने असैनिक नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने के प्रयत्न किए।

सत्ताह्वित सैनिक विशिष्ट व्यक्ति आम तौर पर सत्ता में आने के बाद नागरिक सेवा के अधिकारियों पर बहुत निर्भर रहते हैं। यह एक ऐसी बात है जो अधिकांश सैनिक विशिष्ट व्यक्तियों के राजनीति विरोधी विचारों को देखते हुए, आश्चर्यजनक नहीं है। अगर हम यह भी मान लें कि सैनिक परिपद और शीप सेना के बीच घनिष्ठ संबंध हैं, फिर भी ऐसे सैनिक नेता बहुत कम रहे हैं जिनके पास प्रशासन पर सीधा नियंत्रण चलाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति रहे हों। बहुत से नेताओं ने भी इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि यदि हम तरह के व्यक्ति सैनिक परिपद के पास होते तो स्वयं सेना की क्या स्थिति रहती? उदाहरण के लिए अयूब खान ने घोषणा की :

यह अत्यंत आवश्यक था कि सेना को पीछे ही रखा जाए क्योंकि देश के सामान्य जीवन में उसका वही स्थान है। यदि वह नागरिक प्रशासन में सीधे तौर पर उलझ जाती, तो इसका अमर यह होता कि मनोबल और कम हो जाता, और नागरिक सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती। इसके अलावा, सेना को बाद में नागरिक जीवन में हटाकर अपने सासान्य कार्यक्षेत्र में काम करने के लिए वापस लाना और कठिन हो जाता। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यदि सेना को नागरिक प्रशासन चलाने या आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में बहुत अधिक उलझा लिया जाता, तो वह खत्म हो जाती।¹⁹

इसके परिणामस्वरूप सैनिक नेताओं ने स्वयं को औपनिवेशिक युग के गवर्नर और उपगवर्नर जैसा बनाना बेहतर समझा है, और विभिन्न प्रशासनिक विभागों के लिए केवल अस्थायी सैनिक निरीक्षक नियुक्त करने तक ही स्वयं को सीमित रखा। प्रशासन के विभिन्न विभाग, मुख्यतः अमैनिंक कर्मचारियों के हाथ में ही रहे हैं।²⁰ उदाहरण के लिए घाना में सैनिक परिपद के मदत्यों ने प्रारंभ में अपने हाथ में सेना और पुलिस को कमान रखी, जिससे वे नियंत्रण के अधिकार को पूरी तरह उपयोग में नहीं ला सके। उधर असैनिक व्यक्तियों को मंत्रालयों के अध्यक्ष, या क्षेत्रीय आयुक्त बना दिया गया और बहुत सी समितियों में पूरी तरह अमैनिंक नागरिक ही

खे गए²¹, जिनका काम विभिन्न मामलों पर सैनिक परिपद को परामर्श देना था। नौकरशाही के साथ यह प्रारंभिक गठबंधन तनावरहित नहीं था। जब मेना अपने हाथ में सत्ता लेती है तो इस तरह की योजनाओं की घोषणाएँ की जाती हैं कि नौकरशाही में भ्रष्टाचार होने और पुराने असैनिक शासन के साथ उनका मवध होने के कारण अधिकारियों को पदों से हटाया जाएगा और प्रशासन में सुधार लाया जाएगा। कुछ राज्यों में तो इस तरह की कार्यवाही वास्तव में की गई। पाकिस्तान में अयूब खान ने विभिन्न सेवाओं की जांच पड़ताल के लिए एक जांच समिति नियुक्त की थी। जिनकी जांच पड़ताल होनी थी उनमें अधिकांश व्यक्ति अधिकारीतंत्र के मध्य स्तर के थे। 526 असैनिक कर्मचारियों को या तो रिटायर होने के लिए बाध्य किया गया या नौकरी से निकाल दिया गया।²² सैनिक शासक अन्सर नागरिक सेवाओं के खराब संचालन की निंदा करते रहते हैं और घाना तथा नाईजीरिया में तो उन्होंने यहां तक कार्यवाही की कि जो नागरिक कर्मचारी ठीक समय पर काम पर नहीं आए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

बहुत से राज्यों में सेना ने सरकार का प्रशासन चलाने के काम में वास्तव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वर्मा और इंडोनेशिया जैसे राज्यों में, जहां सेना काफी अर्थ से विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक कार्य चलाती रही है, वहां उसकी भूमिका का विस्तार ही हुआ। इंडोनेशिया में मंत्रिमंडलीय और विभागीय स्तरों पर सक्रिय बहुत से नागरिक कर्मचारियों को वास्तव में सेना के सत्ता में आने के बाद सशस्त्र सेनाओं में लिया गया था।²³

सैनिक क्रांति के बाद की इस प्रारंभिक अवधि के दौरान शासन द्वारा की गई सभी कार्यवाहियां राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं रही हैं। वास्तव में बहुत कम राजनीतिज्ञों को जेल में डाला गया। जिन लोगों को कारावास की सजा हुई उनमें से बहुत कम व्यक्तियों को लंबी अवधि के लिए बंदी रखा गया। राजनीतिक गतिविधि पर लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों को भी आम तौर पर इल्के रूप में ही लागू किया गया। कुछ मामलों में राजनीतिक समितियों, मलाहकार समितियों आदि के जरिए राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों को, शासक वर्ग के साथ संबद्ध किए जाने के प्रयत्न किए गए हैं। इस तरह की बात विशेष रूप से घाना जैसे देशों में हुई जहां सारी राजनीतिक प्रणाली के खिलाफ नहीं, बल्कि राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों के एक खास दल के खिलाफ क्रांति की गई थी।

सैनिक परिपद की आंतरिक अस्थिरता और क्रांति के सुरंत बाद की अवधि में राजनीतिक केंद्र में सत्ता संबंधों की अनिश्चिता के कारण, अंत में सैनिक शासकों

के लिए एक संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। यह बराबर स्पष्ट होता चला जाता है कि घोषणाओं में राजनीतिक शक्तियों को बिल्कुल समाप्त, या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जिन राज्यों में इन शक्तियों पर कोई स्पष्ट और कारगर प्रति-वध नहीं लगा है, वहाँ उन्होंने अक्सर यह माग की है कि शासन चलाने में उनका और अधिक सहयोग लिया जाए, या फिर से नागरिक शासन स्थापित हो। राजनीतिक व्यक्तियों के निरीक्षण में मुक्त अधिकारीतंत्र, धीरे धीरे स्वायत्त होता जाता है। ग्रैंड सेना लगातार एक खतरा बनी रहती है, विशेषकर उस समय जब असैनिक व्यक्तियों को भी अपने साथ मिलाने के सत्तारूढ़ सैनिक विशिष्ट व्यक्तियों के प्रयत्नों को लेकर अमतोप पैदा होता है, या जब सैनिक परिपद के अंदर ही, और परिपद में शामिल तथा उससे बाहर के व्यक्तियों के बीच गुटबंदी होने लगती है तो यह असंतोप और अधिक उभरकर सामने आता है। दिसंबर 1967 में दाहोमी में जो सफल क्रांति हुई थी वह बढ़ते हुए असैनिक प्रभाव के प्रति असंतोप और विरोध भावना का उदाहरण है। दक्षिण कोरिया और घाना में क्रांति के जो प्रयत्न हुए उनमें सैनिक परिपदों की आंतरिक गुटबंदी का पता चलता है।

ऐसी परिस्थितियों में सेना को नागरिक शासन के संचालन में हटा लेना एक संभावना बन जाती है। ऐसा भी होता है कि जब सेना के विशिष्ट व्यक्ति प्रारंभ में शासन प्रणाली पर प्रभावशाली नियंत्रण नहीं रख पाते तो वह उससे बिल्कुल अलग हो जाने की बात सोचने लगें।²⁴ लेकिन बहुधा ऐसी स्थिति होती है कि उनके पास वास्तव में कोई विकल्प ही न हो। सबसे पहले जिन परिस्थितियों के कारण सेना को शासन के काम में उलझना पड़ा वे अल्पविकसित राज्यों की राजनीतिक प्रक्रिया में बराबर बनी रहती हैं। इसके परिणामस्वरूप सैनिक शासकों का सत्ता से हटने का प्रयत्न बहुधा अफल नहीं रहा है।²⁵

आम तौर पर सत्तारूढ़ सैनिक विशिष्ट व्यक्तियों ने, राजनीतिक केंद्र और संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली को नया रूप देने के सतत प्रयत्न किए हैं, जिसमें इनका प्रभुत्व बना रहे। कई पहलुओं से, प्रधानता की यह धोज, नागरिक प्रशासनों के अंदर राजनीतिक दृष्टीकरण के प्रयत्नों जैसी ही है।

असैनिक विशिष्ट व्यक्तियों की क्रांति सत्तारूढ़ सैनिक विशिष्ट व्यक्ति भी, सरकारी साधनों पर नियंत्रण और केंद्रीयकरण के लिए इन साधनों के उपयोग पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। शासक सैनिक विशिष्ट व्यक्तियों और उनके द्वारा नियुक्त किए गए लोगों के बीच व्यक्तिगत निष्ठा भाव और पैतृक संबंधों के माध्यम से ही, राजनीतिक केंद्र के दृष्टीकरण और नियंत्रण के प्रयत्न होते रहे हैं।

यह बात मेना के अंदर उस समय तुरंत स्पष्ट हो जाती है जब कोई एक सैनिक नेता, मारी सैनिक परिपद पर अपनी व्यक्तिगत प्रधानता स्थापित कर नेता है। मित्र में जिन अधिकारियों के विचार नासिर से नहीं मिलते थे, उनके निष्कासन के बाद 1967 तक, नासिर अपने धनिष्ठ मित्र अब्दुल हकीम अमीर पर निर्भर रहे। सेनाध्यक्ष और रक्षामंत्री के रूप में अब्दुल हकीम अमीर ने सेना को नियंत्रित रखने में नासिर की सहायता की। दक्षिण कोरिया में पार्क चुंग ही की सरकार ने बहुत से लोगो को समय से पहले ही अनिचाय रूप से रिटायर कर दिया, जिससे 1961 की क्रांति के प्रमुख व्यक्ति नियंत्रण के पदों पर आ सके। यह व्यक्ति आफिसर्स कैंडिडेट स्कूल का दूसरी और आठवीं कक्षाओं के थे।²⁶ पार्क के व्यक्तिगत साथियों को मेना की काउंटर इंटेलेजेंस एजेंसी और अन्य नियंत्रण वाले महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। यह एजेंसी सभी बड़े अधिकारियों पर कड़ी नजर रखने और उनके आपसी संबंधों पर भी निगरानी रखने के लिए बनाई गई थी।²⁷ इंडोनेशिया में इस तरह की गतिविधियों का स्वरूप कुछ अधिक जटिल रहा है। इसका मुख्य कारण यह था कि मेना के अंदर ही विभिन्न गुटों के गठन की प्रक्रिया पेशीदी थी लेकिन फिर भी मूल ममानता थी। सुहार्तो ने वामपंथी सैनिक-कमांडरों को पदों से हटाने और साथ ही स्वयं राष्ट्रपति, रक्षामंत्री और सशस्त्र सेनाओं के कमांडर के पद मंभानने (जिसने मेना को उन विशिष्ट व्यक्तियों के संपर्क से दूर रखा जा सके जो संभवतः सुहार्तो के मुकाबले खड़े हो जाते) के अलावा, अपने नियुक्तिया करने के व्यापक अधिकारों का इस्तेमाल, अपने गुट के सदस्यों को सेना में प्रमुख पदों पर लाने, और अन्य गुटों का समर्थन प्राप्त करने के लिए किया।²⁸ सुहार्तो ने विरोधी गुटों के नेताओं को दूर दूर के क्षेत्रों या अन्य देशों में भेज दिया, या उन्हें अपेक्षाकृत साधारण पदों पर रखा।²⁹

प्रधानता की खोज के प्रयत्न, विभिन्न सैनिक शासकों और राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों के बीच बदलते हुए संबंधों में भी नजर आते हैं। जिन राज्यों में राजनीतिक पार्टियां बंध बनी रही हैं, वहां सैनिक शासकों ने अपना प्रभाव डालकर पार्टियों के ऐसे नेताओं का निर्वाचन कराने का प्रयत्न किया है, जो सैनिक सरकार का अधिक पक्ष ले सकें। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से इंडोनेशिया में है।³⁰ आम तौर पर तो सत्तारूढ़ सैनिक विशिष्ट व्यक्ति, सरकार द्वारा प्रेरित राजनीतिक पार्टियों की स्थापना के माध्यम से नए राजनीतिक विशिष्ट व्यक्ति बनाने के प्रयत्न करते हैं। सैनिक शासक इस तरह की पार्टियों को तत्कालीन विशिष्ट व्यक्तियों और अपने बीच आदान-प्रदान के आधार पर संबंधों की स्थापना के लिए उपयोग में लाने के वजाय इन विशिष्ट व्यक्तियों को आम तौर पर अनदेखा कर देते हैं, और नए राजनीतियों पर निर्भर करने हैं जो कम से कम सिद्धांत रूप में तो शासन के लिए समर्थन जुटा सकेंगे। यह

समर्थन जुटाने के लिए नए राजनीतिज्ञ जनता को संरक्षण के लाभ और अन्य सरकारी लाभ देते हैं। इस तरह की पार्टियाँ, उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया की डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी, पाकिस्तान की (रुढ़िवादी) मुस्लिम लीग, और मिस्र की लिबरेशन रैली, नेशनल यूनियन और अरब सोशलिस्ट यूनियन, जनसमर्थन प्राप्त करने के माध्यम उपलब्ध कराने की सेना की कोशिश का प्रतिनिधित्व करती हैं, और इस बात का खतरा नहीं होता कि ये माध्यम शासन से बिल्कुल ही अलग हो जाएँ।³¹ हालांकि उपलब्ध आकड़े बहुत कम हैं, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सैनिक शासकों ने राजनीतिक दृढीकरण के दो प्रमुख तरीके अपनाने के प्रयत्न किए हैं। पहला तो यह कि उन्होंने प्रशासनिक भूमिकाओं की संख्या बढ़ाकर और राजनीतिक कार्यों की संख्या घटाकर, राजनीतिक प्रणाली को 'राजनीतिविहीन' बनाने का प्रयत्न किया है। दूसरा यह कि विस्तृत अधिकारीतंत्र की स्थायता कम करने के लिए उन्होंने प्रशासनिक ढाँचे पर अपना 'व्यक्तिगत' नियंत्रण रखने का प्रयत्न किया।

पहला तरीका इन दो बातों से विदित है कि अधिकारीतंत्र में संख्या, एजेंसियाँ, और गतिविधियाँ, सामान्य रूप से बढ़ा दी गईं और राजनीतिक भूमिकाओं को प्रशासनिक पदों में बदल दिया गया। मिस्र में सरकारी पदों की संख्या 1954-55 में तीन लाख 81 हजार 6 सौ पंद्रह थी जो 1964-69 में बढ़कर 12 लाख 55 हजार हो गई।³²

दक्षिण कोरिया में केवल आधिक मंत्रालयों में ही विभागों की संख्या 21 से बढ़कर 34 तक जा पहुँची है।³³ अधिकांश राजनीतिज्ञों के स्थान पर सभी स्तरों पर सरकारी कर्मचारी लाए गए हैं और राजनीतिक पद या तो बिल्कुल समाप्त कर दिए गए हैं या अधिकारीतंत्र के अंतर्गत इनके कार्य फिर से निश्चित किए गए हैं। इस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है पाकिस्तान का वेंसिक डिमाक्रेसीज सिस्टम। इसमें परिपदों के पंचस्तरीय प्रबंध के अंतर्गत केवल स्थानीय बोर्डों (यूनियन कार्ड्स-सिल) का चुनाव सीधे वयस्क मतदान द्वारा किया गया, और ऊपर के अन्य सभी स्तरों पर उन 'निर्वाचित' सदस्यों को लिया गया, जो अगले निचले स्तर पर परिपद के अध्यक्षों में से चुने गए थे। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों को भी सरकारी सदस्यों के रूप में अधिक अनुपात में लिया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य सरकारी संगठनों की, लगभग पूर्णरूप में राजनीतिविहीन व्यवस्था स्थापित करना था। यद्यपि इस प्रणाली से जनसहयोग के लिए एक माध्यम बनाया जाना था, लेकिन वेंसिक डेमोक्रेटो (जो स्थानीय परिपदों के लिए चुने गए थे) को वास्तव में कोई राजनीतिक कार्य नहीं सौंपा गया। जैसा एक विद्वान ने कहा है :

इस बात का फंसला सरकार करती है न कि कोई लोकप्रिय निर्वाचनक्षेत्र कि कौन से निर्वाचित पाप्यों को वास्तव में जिला, खंड (डिवीजन), और जून 1962 तक प्रातीय स्तर पर 'प्रतिनिधित्व' करने का मौका दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आठ हजार तीन सौ पचपन यूनियन काउंसिल अध्यक्ष हैं, जिनमें से 76 जिला और एजेंसी परिपदों, 15 डिवीजनल परिपदों और दो प्रातीय परिपदों में नियुक्तियों के लिए लोगों को चुना जाना है। इस प्रकार यह मान लेना अत्यंत अव्यावहारिक होगा कि जिला या डिवीजन परिपद में 'प्रतिनिधि' सदस्य की सत्ता का आधार उसका अपना निर्वाचन क्षेत्र है, न कि नियुक्ति करने वाला अधिकरण। और यह मान लेना भी बुद्धिमता नहीं होगी कि जनता के 'प्रतिनिधि' इस बात को नहीं ममसते।³¹

दूसरे तरीके का मतलब यह है कि मत्तारूढ सैनिक विशिष्ट व्यक्तियों ने विस्तृत प्रशासनिक ढांचे में विशेषकर उच्च स्तर पर प्रशासक रखने के लिए, नियमित नागरिक सेवा में बाहर के लोगों को लिया है। इस प्रकार ऐसे विशेषज्ञों की भर्ती से जिनको बहुधा प्रशासन का कोई वास्तविक अनुभव नहीं होता, विस्तृत अधिकारीतंत्र पर नियंत्रण बनाए रखने का मौका मिलता है, क्योंकि जिन लोगों को चुना गया वे या तो मत्ताधारो विशिष्ट व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते थे (क्योंकि वे नियमित नागरिक सेवा से बाहर के लोग थे) या अपने पदों के लिए सैनिक शासकों पर निर्भर थे। इस प्रकार घाना में जिन वरिष्ठ नागरिक कर्मचारियों ने सेना द्वारा सत्ता संभालने के बाद मरकारी मंत्रालयों का कामकाज प्रारंभ में संभाला उन्हें राजनीति-विहीन विशेषज्ञों के लिए स्थान खाली करने पड़े। 1967 में नियुक्त किए गए नागरिक आयुक्तों में से आधे लोग उन्हीं मंत्रालयों के काम के विशेषज्ञ थे जिनका उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया।³⁵ बीस आयुक्तों में से केवल पांच, भूतपूर्व नागरिक कर्मचारी थे।³⁶

मिस्र में, जहा क्रांति के बाद ही वास्तव में आधुनिक नागरिक सेवा का गठन किया गया था, अधिकारीतंत्र पर तकनीकी विशेषज्ञ हावी हो गए हैं, जिनके पास सत्ता का अपना कोई आधार है ही नहीं, या बहुत कम है।³⁷ अपने सारे शासनकाल के दौरान नासिर ने अधिकारीतंत्र पर अपना 'व्यक्तिगत' नियंत्रण बनाए रखा। प्रारंभ में तो महत्वपूर्ण मंत्रालयों का नियंत्रण क्रांतिकारी कमान परिपद के सदस्यों के हाथ में रखा गया, लेकिन जब विशेषज्ञ वर्ग विकसित हुआ तो नासिर ने विभिन्न स्तरों के महत्वपूर्ण पदों पर अपने ही ममसकों को नियुक्त करके और समय समय पर पुनर्गठन करके, अपना नियंत्रण बनाए रखने का प्रयत्न किया।

पाकिस्तान में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर पाकिस्तान सिविल सर्विस के विशिष्ट व्यक्तियों के परंपरागत एकाधिकार को तोड़ने के लिए अय्यूब खान सेना और अर्सेनिक व्यक्तियों, दोनों पर निर्भर रहे। मार्शल ला की घोषण के बाद (7 अक्टूबर 1958) 272 सैनिक अधिकारियों को या तो अर्सेनिक विभागों अथवा एजेंसियों का सीधा प्रशासन चलाने के लिए, या उस समय पदों पर आसीन नागरिक अधिकारियों के कार्य पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया गया।³⁷ 1959 में केंद्र सरकार ने एक आर्थिक निकाय की स्थापना की। यह एक उपरि प्रशासनिक (सुप्रा ऐड-मिनिस्ट्रेटिव) सेवा थी जिसमें सभी नागरिक सेवाओं में से सदस्य लिए जा सकते थे और इन्हें वित्त, वाणिज्य और अर्थ मंत्रालयों में प्रमुख पदों पर रखा जा सकता था।³⁹ 40 प्रतिशत सदस्यों को सिविल सर्विस आफ पाकिस्तान के बाहर से भर्ती किया जाना था। जब सेना को वापस लौटा लिया गया और नागरिक प्रशासन की जिम्मेदारी फिर से पाकिस्तान सिविल सर्विस को सौंप दी गई तो भी यह तरीका चलता रहा क्योंकि युवा सैनिक अधिकारियों को पाकिस्तान सिविल सर्विस में भर्ती किया गया। एक अध्ययन के अनुसार, '1960 और 1963 के बीच पाकिस्तान सिविल सर्विस में शामिल होने वाले 14 सैनिक और नौसैनिक अधिकारियों में से आठ अधिकारियों के सबंध, उच्च सैनिक व्यक्तियों के साथ बहुत घनिष्ठ थे।'⁴⁰

जेरे में जोसफ मोब्तू के अधीन 'विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति के सीधे निरीक्षण में' काम करते हुए अपनी भूमिका का बहुत अधिक विस्तार किया है।⁴¹ 1967 के अंत तक मंत्रिमंडल में राजनीतिविहीन विचारधाराओं वाले भूतपूर्व विश्वविद्यालय छात्रों और तकनीकी जानकारों का बोलबाला हो गया।⁴² मोब्तू ने प्रशासनिक पदों की संख्या काफी बढ़ाकर और ऐसे पदों से प्रशासकों को हटाकर, जहां वे अपनी व्यक्तिगत सत्ता के आधार का विकास कर सकते थे, प्रशासन पर अपने व्यक्तिगत नियंत्रण को और अधिक मुदृढ़ किया है। गवर्नर और उनके द्वारा नियुक्त किए गए प्रांतीय आयुक्त और प्रांतीय सचिवों को उनके पुस्तैनी इलाकों से स्थानांतरित कर दिया गया और उन्हें राष्ट्रपति के प्रति सीधे उत्तरदायी बना दिया गया। यह नियम मध्यम नीचे यानी जिलास्तर तक लागू हुआ।⁴³

दृढ़ीकरण के इन विभिन्न प्रयत्नों का परिणाम स्पष्ट नहीं है क्योंकि इससे संबद्ध पर्याप्त मूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रयत्न आम तौर पर सफल नहीं रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जब यह समझा गया कि शासन की प्रारंभिक अस्थिरता की अवधि समाप्त हो गई है, उसके बाद भी काफी लंबे समय तक इन शासनों में विभिन्न सैनिक परिपदों के बीच गुटबंदी का रोग जारी रहा। उदाहरण के लिए मिन में क्रांति का मंचालन करने वाले फ्री अफसर ग्रुप की अपनी आंतरिक

सुदृढ़ता और एकता 1950 और 1960 के दशकों में बहुत क्षीण हो गई।⁴⁴ दक्षिण कोरिया में व्यक्तिगत वैमनस्य और झगड़ों के कारण सैनिक परिपद के सदस्यों में आमूल परिवर्तन आया है। परिपद के कम से कम 7 सदस्य, वर्तमान नेता पार्क चुंग ही को अपदस्थ करने के विफल प्रयत्नों से संबद्ध रहे हैं। इन लोगों में क्रांति के समय के सेनाध्यक्ष भी शामिल थे। दक्षिण कोरिया और अन्य स्थानों पर भी, इस प्रकार की क्रांतियां उन कठिनाइयों का प्रमाण हैं जो सैनिक शासनों के सामने पूर्ण नियंत्रण स्थापित करते समय सामने आई है। अफ्रीका और एशिया में थोड़े थोड़े समय बाद क्रांतियों की संख्या बढ़ते जाने का कारण न केवल नागरिक सरकारों और सेना के बीच संबंधों का उत्तरोत्तर बिगड़ते जाना है, बल्कि ये क्रांतियां, गुटों के संघर्षों में सैनिक विशिष्ट व्यक्तियों के उलझने और सैनिक सरकार तथा शेष सेना के बीच आपसी तनावों का भी परिणाम हैं।

इसके अलावा, राजनीति के प्रति सैनिक शासकों के संदेह बने रहने के कारण इन सैनिक शासकों द्वारा नए राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों का वर्ग तैयार करने या पुराने राजनीतिज्ञों को शासनसमर्थित राजनीतिक पार्टियां बनाकर सरकार में लाने के प्रयत्नों में बाधा पड़ी है। राजनीतिज्ञ चाहे वे नए हों अथवा पुराने, आम तौर पर शासन से अलग रखे जाते हैं। अविश्वास की यह बात सी० आई० यूजीन किम के उस विवरण में स्पष्ट है जो उन्होंने दक्षिण कोरिया में डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी के साथ राष्ट्रपति पार्क के संबंधों के बारे में दिया है :

पार्टियों और राजनीति में बहुत अधिक उत्साह न रखने वाले राष्ट्रपति पार्क, अपनी सरकार को विशेषज्ञों और प्रशासकों की सरकार मानते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के प्रति स्पष्ट शब्दों में अविश्वास व्यक्त किया है। वे पार्टी संबंधी राजनीति को, प्रशासन और नीति निर्धारण से अलग रखना चाहते हैं। जब पार्टी के नेताओं और मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच तनाव पैदा हुआ तो राष्ट्रपति पार्क ने आम तौर पर अपने मंत्रियों का साथ दिया और पार्टी की भूमिका को गौण माना। उनके लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी, चुनावों में सफलता का एक लाभकारी माध्यम है, लेकिन यह प्रशासनिक कार्य चलायाने के योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं करा सकती। जब कभी उन्हें कोई निर्णय लेने होते हैं, तो उनके मुख्य सलाहकार राष्ट्रपति के सचिवालय और मंत्रिमंडल में पाए जाते हैं। उनका राष्ट्रपति सचिवालय, उनके कार्य का एक अभिन्न अंग बन चुका है और उसे कभी कभी 'छोटा मंत्रिमंडल' कहा जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति का सचिवालय पार्टी से बाहर के व्यक्तियों से भरा हुआ है जिसमें निर्णय लेने का उत्तरदायित्व, पार्टी को इस सचिवालय को सौंप देना पड़ा।⁴⁵

अंतिम बात यह है कि विभिन्न प्रशासनिक एजेंसियों के अव्यक्त पद पर आसीन विशिष्ट व्यक्तियों की यह प्रवृत्ति है कि वे अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाना और अपने अपने विभागों को व्यक्तिगत पुस्तैनी संस्था के रूप में विकसित करना चाहते हैं। यह बात सैनिक शासनो में और भी अधिक है। कुछ हद तक यह इस बात का परिणाम है कि सैनिक शासक, आम तौर पर अपने पूर्ववर्ती शासकों की तुलना में कम चतुर नेता सिद्ध हुए हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन नेताओं ने राजनीतिक प्रणाली को राजनीतिविहीन बनाने और प्रशासनिक पदों की संख्या बढ़ाने के जो प्रयत्न किए, उससे एक ऐसे अधिकारीतंत्र का जन्म होता है, जो किसी भी नेता के नियंत्रण से बाहर हो जाता है, चाहे मारे प्रशासनिक ढांचे में व्यक्तिगत अनुयायियों की संख्या कितनी भी हो। जहाँ वास्तव में नियमित नागरिक सेवा को मोहित किया जाना था या उसे अनदेखा किया जाना था, वहाँ प्रशासनिक विभागों का विस्तार होने से अंत में नियमित नागरिक सेवा को अपनी स्वायत्ता फिर से स्थापित करने का अवसर मिल गया क्योंकि अन्य प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव था। इस प्रकार पाकिस्तान में जहाँ बेसिक डेमोक्रेसीज प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली का अधिकारीतंत्र बनाने का एक प्रयत्न थी, वहाँ उम्मेद पाकिस्तान सिविल सर्विस की सत्ता को भी पुनर्स्थापित किया।

1959 के बेसिक डेमोक्रेसीज आदेश ने डिवीजनों और जिलों में काम करने वाले नागरिक कर्मचारियों को नई स्थानीय मन्थ्याओं पर 'नियंत्रण के अधिकार' दे दिए हैं। इस आदेश के अंतर्गत बनाई गई प्रणाली में पाकिस्तान सिविल सर्विस के कमिश्नर, डिवीजनल परिपदों की अध्यक्षता करते हैं, और प्रांतीय सिविल सर्विस के डिप्टी कमिश्नर जिला परिपदों के अध्यक्ष हैं। बेसिक डेमोक्रेसीज प्रणाली ने पाकिस्तान सिविल सर्विस के अधिकारों और सत्ता को कम नहीं होने दिया। स्थानीय संप्रदायों के अविवादात्मक नेता होने के नाते नागरिक सेवा के कर्मचारियों को कानून और व्यवस्था संबंधी प्रशासन के एजेंटों के रूप में सत्ता नहीं मिली है, बल्कि एक घोषित 'जनहितकारी राज्य' के प्रतिनिधियों के रूप में वे इस सत्ता का उपभोग करते हैं। और फिर 1962 में स्थानीय परिपदों को अधिक सक्रिय बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के उद्देश्य में एक व्यापक ग्राम निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इससे पाकिस्तान सिविल सर्विस के डिवीजनल और जिला प्रशासकों की सत्ता और बढ़ गई क्योंकि विकास पर खर्च की जाने वाली राशि पर उन्हीं का नियंत्रण था।⁴⁶

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि सैनिक शासकों के बड़े बड़े भाषणों, सत्ता का केंद्रीकरण करने के लिए उनके गंभीर प्रयत्नों, और समाज के अंदर फूट पड़ने के संदेहों के

चावगूद, सत्तारूढ़ मैनिक विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा गठित राजनीतिक केंद्र के पहले की अपेक्षा कहीं अधिक विकेंद्रीकृत होने की संभावना है। केन्द्रीकरण के 'नरेशों' और विकेंद्रीकरण के अधीनस्थ अधिकारियों के बीच खींचतान पहले से ज्यादा तजर आने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया में -

निर्दिष्ट लोकान्त्र (गाइडेड डेमोक्रेसी) के अधीन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विगडती गई, सभी सरकारी विभागों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सरकारी वेतन, जीवनयापन के लिए अत्यंत आवश्यक स्तर से बहुत नीचे चले गए। इसके अलावा पुराने उतकरणों के रखरखाव, और नए उपकरणों को खरीदने के लिए, धन दिनोदिन कम होता गया। अन्य विभागों की भांति मेना को भी इस समस्या में जूझना पड़ा। स्थानीय यूनिटों को अपने अपने तरीकों में धन इकट्ठा करने की काफी स्वतंत्रता दी गई (उदाहरण के लिए तस्कारी, गैर सरकारी कर और मेना द्वारा आरंभ किए गए उद्योग आदि), जबकि राज्य निगमों में सक्रिय अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे राशि को मीधे मेना तक पहुंचाएं। 1966 में और उसके बाद (क्रांति के बाद की अवधि) भी ये समस्याएं बनी रहीं। पर्तमीना (राज्य तेल निगम) वेरदिकारी (एक बड़ा व्यापार निगम) और बुलांग (चावल की सरकारी खरीद और विक्री में संबद्ध) जैसे प्रतिष्ठानों के उच्चतम पद पर जनरलों को नियुक्त किया गया जो संबद्ध विभाग के मंत्री के बजाय मीधे मुहातों के प्रति उत्तरदायी थे। यदि वे संबद्ध विभाग के मंत्री के प्रति उत्तरदायी होने तो उन्हें प्रशासनिक निरमों के अंतर्गत कार्य करना होता। ऐसा लगता है कि इन जनरलों का काम सेना के लिए राशि उपलब्ध कराना था। साथ ही स्थानीय मैनिक यूनिटों ने अपनी ओर से अपने लिए राशि जमा करना जारी रखा। जनरलों ने इन गतिविधियों में काफी हद तक चीनी व्यापारियों (टजूकांग) के साथ सहयोग किया। इन व्यापारियों के पास व्यापारिक सूझबूझ और पूंजी थी, और ये जनरल उन्हें नीकरशाही तक उनकी पहुंच आमान बना सकते थे। इस प्रकार सभी स्तरों पर जकार्ता में लेकर क्षेत्रीय कस्बों तक सेना और चीनी व्यापारियों के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित हो चुके हैं। इससे ऐसे क्षेत्रों में पूंजी लगाने की प्रवृत्ति को बल मिला है जिनमें शीघ्र अधिक लाभ मिलने की आशा है। इसके विपरीत आर्थिक विकास के लिए स्थाई महत्व की लंबी अवधि की योजनाओं में पूंजी लगाने की प्रवृत्ति कम हो गई है।

जब मेना को राज्य के बजट में धनराशि नहीं मिली तो उसके पास अपने ही तरीकों में धन इकट्ठा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और इसका एक परिणाम यह

हुआ कि कई सैनिक अधिकारियों को ऐसे पदों पर नियुक्त किया गया जहाँ वे अपने लिए भी काफी मुनाफा पैदा कर सकें। यह भूमिका परंपरागत महसूलदार (टैक्स कलेक्टर) जैसी ही है, जो शासक को उसका हिस्सा दे देने के बाद बाकी बची हुई राशि अपने पाम रख सकता है। स्वाभाविक है कि सेना के केंद्रीय नेता उन लोगों पर सोच-समझकर अनुशासन का अंकुश लगाते थे, जो उसे काफी धनराशि जमा करके देते थे।⁴⁷

परिधि क्षेत्र में एकता और संघर्ष

व्यापक राजनीतिक प्रणाली पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के प्रयत्नों में सैनिक शासन को मूलतः उसी समस्या का सामना करना पड़ता है जो उससे पूर्ववर्ती नागरिक प्रशासन के समक्ष थी। यह समस्या थी, अत्यंत खंडित राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणाली में राज्य की सत्ता का विस्तार और दृढीकरण करना लेकिन इस समस्या को हल करने के सैनिक शासन के तरीके कई तरह से अनोखे रहे हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर राजनीति के प्रति सदैव संदेहात्मक दृष्टिकोण रखने वाले सत्तारूढ़ सैनिक विशिष्ट व्यक्ति परिधि क्षेत्र के साथ सीधे संपर्क स्थापित करने के लोभ में बचते रहे हैं। इससे केंद्र और परिधि के बीच संपर्कों की एक परोक्ष प्रणाली का उदय हुआ है जिसमें अधिकारीतंत्र निर्णय लेने और सरकार की ओर से मिलने वाले लाभों का वितरण करने का प्रमुख साधन बन गया है।

केंद्रीय राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों से जबरदस्ती हटाने से केंद्र सरकार और राजनीतिक परिधि के बीच वे मूल संपर्क टूट जाते हैं जो इन नेताओं और इनके व्यक्तिगत अनुयायियों के बीच थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये लोग नेता नहीं रहते। इस संबंध में उपलब्ध अत्यंत सीमित शोध कार्य से यह पता चलता है कि वास्तव में ये संपर्क बने ही रहते हैं। मैनिंग नैश द्वारा बर्मा के एक गांव नांदिन के अध्ययन में बताया गया है कि स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने जनरल ने विन द्वारा ऊ नू को सत्ता से हटा दिए जाने के बाद भी अपने पृथक संबंध ऊ नू के साथ बनाए रखे।⁴⁸ यह संपर्क अब राजनीतिक केंद्र के विशिष्ट व्यक्तियों (यानी सत्ता के महत्वपूर्ण पदों वाले व्यक्तियों) और परिधि क्षेत्र के बीच नहीं, बल्कि उन विशिष्ट व्यक्तियों के बीच रहते हैं जो केंद्र से अलग कर दिए गए हैं या कई मामलों में केंद्र के विरोधी हैं।

जिन मामलों में सत्तारूढ़ सैनिक विशिष्ट व्यक्तियों ने परिधि के साथ संपर्क विकसित करने के प्रयत्न किए हैं वहाँ कई अपवादों को छोड़कर मुख्यतः वे विफल रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि उन्होंने बड़े अस्पष्ट अवयवों और

अक्सर परस्पर विरोधी ढंग से ये संपर्क स्थापित करने के प्रयत्न किए। इसके ज्वलंत उदाहरण वे राजनीतिक पार्टियाँ हैं जिन्हें सैनिक प्रशासनो ने स्थापित करने की कोशिश की। इन पार्टियों के गठन का बाह्य उद्देश्य तो जनसमर्थन जुटाना और कुछ मामलों में सेना के अलावा अन्य लोगों की ओर से शासन के लिए समर्थन का आधार तैयार करना है, लेकिन जैसा पहले कहा जा चुका है, उनके ये प्रयत्न शुरू से ही इसलिए मंकाट में पड़ गए क्योंकि सैनिक विशिष्ट व्यक्ति इस तरह की पार्टियों को शासन में कोई वास्तविक भूमिका नहीं निभाने देना चाहते।

सरकार द्वारा चलाई गई इन पार्टियों को न केवल शासन में निर्णय लेने के काम से अलग रखा जाता है, और इस प्रकार परिधि में विशिष्ट व्यक्तियों और दलों की पहुंच केंद्र तक बनाने के माध्यम के रूप में उनकी कोई उपयोगिता नहीं रहती, बल्कि राजनीतिक पार्टी के रूप में उनके क्रियाकलाप भी सीमित रहते हैं। यह सच है कि सरकारी साधनों का विस्तार समर्थन जुटाने या कभी कभी जबरदस्ती समर्थन लेने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया में :

गालूर उपजिले में 'गोलकार' का अध्यक्ष एक स्थानीय सैनिक कमांडर था, और सात गांव में से हर एक . . . में सेना का कोई वरिष्ठ व्यक्ति या अधिसैनिक अधिकारी 'गोलकार' का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था . . . , सेना ने छिपे हथियारों की खोज के लिए विपक्ष के प्रमुख पार्टी नेताओं के मकानों की तलाशी ली। यह कार्यवाही चुनावों से ठीक पहले की गई, और सारे उपजिले में मतदान केंद्रों पर सेना तैनात कर दी गई और गिरफ्तारियों की अफवाह फैल गई . . . गालूर के मतदाताओं को 'गोलकार' के खिलाफ वोट देने के लिए बहुत साहम की आवश्यकता थी।⁴⁹

लेकिन जनसमर्थन प्राप्त कर लेने या जबरदस्ती इसे जुटाने के बाद सरकारी पार्टियाँ परिधि क्षेत्रों में विभिन्न व्यक्तियों और दलों को सरकारी लाभ पहचानने का माध्यम नहीं रहती। इंडोनेशिया सरकार ने गोलकार को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में विकसित करने का फैसला किया तो उसने सभी सरकारी और ग्रामीण अधिकारियों को पार्टी में शामिल होने या नौकरी छोड़ देने के लिए बाध्य किया। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पीछे पार्टी को दृढ़ बनाने का उद्देश्य नहीं था बल्कि लक्ष्य यह था कि ये अधिकारी जिनमें से अधिकांश विपक्षी पार्टियों के समर्थक थे, विपक्षी पार्टियों को मदद करने के लिए अपने पदों का उपयोग न कर सकें। मिस्र में सरकार की ओर से बनाई गई विभिन्न पार्टियों को, केवल जनसहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया गया, अन्य किसी काम के लिए नहीं।⁵⁰ दूसरे शब्दों में, सरकार द्वारा

गठित पार्टियां पूर्ववर्ती नागरिक शासनो की तुलना में कहीं अधिक आंतराधिक (इंटर मिटेड) थीं, कम से कम परिधि क्षेत्र को साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से।

इन अपेक्षाकृत अप्रभावशाली पार्टियों की स्थापना के अलावा सत्ताधारी सैनिक विशिष्ट व्यक्ति, परिधि क्षेत्र के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर पाए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये नेता बड़े बड़े अलंकारपूर्ण भाषणों और प्रतीकात्मक बातों द्वारा जनमत जुटाने को बहुत अधिक महत्व देते हैं। नासिर ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए जो मतसंग्रह और रैलियां कराईं उनके बारे में सभी जानते हैं। इसी तरह अन्य सैनिक शासकों, जैसे पाक चुंग ही, अबूब खान और मोबतू ने भी अपनी जनता के साथ पुस्तैनी सपकों पर ही विशेष बल दिया। लेकिन नासिर को छोड़कर इनमें से बाकी कुछ ही नेता ऐसे थे जिन्होंने व्यापक और लोकप्रिय समर्थन प्राप्त किया।

सैनिक नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रणाली में केंद्र और परिधि क्षेत्र के बीच मूल सपकों का केन्द्रविन्दु सैनिक परिपद नहीं प्रतीत होती। सेना द्वारा सत्ता संभालने के बाद आम तौर पर अधिकारीतंत्र का जो विस्तार होता है और विशेषज्ञों पर सेना की निर्भरता हो जाती है, उससे अधिकारीतंत्र के अंदर ही निर्णय लेने के प्रमुख साधनों को निश्चित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप केंद्र और परिधि के परस्पर आदान-प्रदान के संबंध (संरक्षक-संरक्षित संबंध आदि), नागरिक और सैनिक अधिकारीतंत्र में महत्वपूर्ण पदों पर आरूढ़ व्यक्तियों और उनके व्यक्तिगत साथियों तथा अनुयायियों के बीच के संबंधों के मदर्भ में सुनिश्चित होते हैं। मूर ने अल्जीरिया के अपने अध्ययन और आधुनिक मिस्र के संस्थात्मक जीवन पर हाल में जो विचार व्यक्त किए हैं, उनमें इस प्रक्रिया का विवरण है।⁵¹ जैसा पाकिस्तान में बेसिक डेमोक्रेसीज प्रणाली के प्रभावों में संबद्ध उद्धरण में कहा गया है, अधिकारीतंत्र, साधनों और उनके वितरण पर अपना नियंत्रण बढ़ाता चला जाता है।

इस प्रकार सैनिक शासकों के आपसी संपर्क और परिधि क्षेत्र के साथ उनके संपर्क सीमित या अधिक में अधिक परोक्ष प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के परोक्ष संबंध अस्थिरता पैदा न भी करे तो इस बात की संभावना तो है ही कि राजनीतिक केंद्र में पहले से सक्रिय विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां और जोर पकड़ लेंगी।

अतः में एक और बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सेना के प्रभुत्व वाली राजनीतिक प्रणाली में सांप्रदायिक भावनाओं के बारे में यद्यपि बहुत कम आंकड़े और जानकारी उपलब्ध है, फिर भी ऐसा लगता है कि इन प्रणालियों में राजनीतिक समूहीकरण के लिए कोई ढांचा न होने के कारण विभिन्न मांगों पृथक रूप में होती हैं। इसके

अलावा चूँकि आधुनिक स्वयंसेवी संस्थाओं पर या तो पूर्ण प्रतिवध लगा होता है या उनकी गतिविधियों पर कड़ा अंकुश होता है इसलिए इस प्रकार की मांगें फिरसे परंपरागत बातों को लेकर होती हैं। दूसरे शब्दों में, मांगें रखने के प्रमुख सव्यात्मक माधन बनते हैं, जातीय और वंशानुगत सामाजिक ढाँचे। यह बात फ्रांस ने घाना के संबंध में विशेष रूप से कही है और आस्ट्रीस्माक ने नाईजीरिया की ईबो यूनियनों के अध्ययन में भी इसका उल्लेख किया है।⁵² राबर्ट पिकानी ने घाना की 1966 की सैनिक क्रांति के बाद के मक्षिप्त अध्ययन में परंपरागत ढाँचों का महत्व बने रहने का एक और कारण बताया है। चूँकि सेना के लिए जनसमर्थन का नाममात्र का आधार भी नहीं होता इसलिए सैनिक सरकार और उसके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एकमात्र राजनीतिक मंच, परंपरागत भावनाओं के कारण प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा ही उपलब्ध होता है।⁵³ सैनिक शासनों से संबंधित सूचनाओं के बारे में बार बार यह कहा जा रहा है कि सूचनाएँ बहुत कम मिल रही हैं इसी से स्पष्ट है कि इस तरह के शासनों के संबंध में निष्कर्ष भी अनिवार्य रूप से अस्थायी ही होंगे जिन्हें अंतिम नहीं माना जा सकता। लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीति को दूर रखकर इस प्रकार के शासन, अल्पविकसित राजनीतिक प्रणाली का और अधिक विखंडन कर देते हैं। सशस्त्र सेनाओं का समर्थन प्राप्त होने पर कोई भी सैनिक सरकार अपने शासनकाल के प्रति निश्चित हो सकती है, लेकिन इस तरह का समर्थन आम तौर पर अल्पकालिक होता है। जहाँ यह समर्थन निश्चित रूप से प्राप्त है वहाँ भी शासनकाल में कोई वास्तविक सत्ता नहीं बनी है और जिस निश्चित ढंग से सैनिक शासन चलाए जाते हैं उससे यह प्रतीत होता है कि सत्ता में एक ऐसी प्रक्रिया आरंभ होती है जिसमें राजनीतिक प्रणाली के सामंत्ववादी बन जाने की संभावना होती है। राजनीतिक दृढीकरण और शासन चलाने की क्षमता दोनों ही सैनिक नेताओं के लिए भी उतने ही अग्राह्य बन जाने की संभावना होती है, जितने कि वे असैनिक शासकों के लिए थे।

संदर्भ

1. जोसेफ मोबुतू, जैरे के राष्ट्रपति का भाषण, 12 दिसंबर 1965 जे० सी० विल्हेम पैट्रिमोनियन-निग्य एंड पालिटिकल चेंज इन कांगो (स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1972), पृ० 132 में उद्धृत
2. क्लाड बैल्च, जूनियर . दि अफ्रीकन मिलिटरी एंड पालिटिकल डेवलपमेंट, हेनरी विएनन (संपादित) . दि मिलिटरी गेज़ माडर्नाइजेशन (शिकागो एंलडाईन-गैथडेन, 1971), पृ० 213.
3. 'पूयक औद्योगिक अस्तित्व की विशेषताओं के विवरण के लिए देविग, सुसियन डब्ल्यू० पार्ई': 'आर्मीज इन दि प्रोग्रेस आफ पालिटिकल माडर्नाइजेशन', जान जे० जानसन (संपादित) : दि रोल आफ मिलिटरी इन अडरडेवलपड कंट्रीज, (प्रिस्टन : प्रिन्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1962), पृ० 76.

4. डंकवार्ट ए० रस्तोव : ए वलडे आफ नेशंस : प्राइमरि आफ पालिटिकल माडर्नाइजेशन (वाशिंगटन डी० सी० दि बुकिंग्स इन्स्टीट्यूशन, 1967), पृ० 187.
5. ऐन ह्य लिनर : 'पर्सपेक्टिव्स आन मिलिटरी एलीट्स ऐंड हलस ऑड वील्डस आफ पावर, 'जर्नल आफ कम्पेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन 2' (1970), 262.
6. एम० डी० फ्रेड . 'प्रोफेशनलिज्म, नेशनलिज्म ऐंड दि एलियनेशन आफ दि मिलिटरी', याक वान डूर्न (संपादित) : आम्डे फोमिज ऐंड सोसायटी (दि हेग . मारुउन ऐंड कनी, 1966), पृ० 68
7. एरिस्टिड जोलवर्ग 'मिलिटरी इटरवेंशन इन दि न्यू स्टेट्स आफ ट्रापिकल अफ्रीका' हेनरी बिएनन (संपादित) : दि मिलिटरी इटरवोस (न्यूयार्क रसल सेज फाउंडेशन, 1968), पृ० 87
8. उदाहरण के लिए देखें जेम्स हीकी 'दि आर्गनाइजेशन आफ ईजिप्ट . इनएडोक्वेमीज आफ ए नान पालिटिकल माडल फार नेशन बिल्डिंग', बग्डे पालिटिक्म, XVII, 2 (1966), पृ० 177-183.]
9. पार्क चुंग-ही, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, उदाहरण के लिए देखिए जान कार्ई-चांग ओङ् कोरिया : डेमोक्रेसी आन ट्रायल (इयाका कौन्सल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1968), पृ० 134.
10. निर्वाचित सभ्या (अभ्योयता) आदेश यानी इलैक्टिव चाडीज (डिसकवालिफिकेशन) आर्डर के ब्योरे के लिए देखिए, पाकिस्तान सरकार दि गजट आफ पाकिस्तान, (एम्प्ट्राआर्डिनरी), अगस्त 1959 दक्षिण कोरियाई कानून और इसके प्रभावो के बारे में देखिए, जान कार्ई-चांग ओङ्, पृ० 138-141
11. एम० जे० डेंट 'दि मिलिटरी ऐंड दि पालिटिशियन', एम० के० पैटरब्रिक (संपादित) नाई-जीरियन पालिटिक्म ऐंड मिलिटरी हल प्रिन्सिपल्स टु मिथिल वार (लंदन : ऐथिलोन प्रेस, 1970), पृ० 82-83.
12. बेमिक डेमोक्रेसीज प्रणाली के बारे में देखिए पाकिस्तान सरकार 'दि बेमिक डेमोक्रेसीज आर्डर 1959', दि गजट आफ पाकिस्तान, अक्टूबर 1959 इस प्रणाली के संबंध में विचारो के लिए देखिए, कार्ल वान बोरोज . पालिटिकल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, (प्रिन्टन : प्रिन्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1965), पृ० 196-207.
13. हेरल्ड शाउव . 'मिलिटरी पालिटिक्म अंडर इन्वेन्शियाज न्यू आर्डर', पैमिफिक अफेयर्स, XLV, 2 (1972), 214-215
14. देखिए सांविधानिक समिति की रिपोर्टें, अकरा, 1968.
15. जैड० ए० मुलेरी : प्रधान संपादक, पाकिस्तान टाइम्स, लारेंस जार्जरिंग . दि अयूब इयसे (मिराबयूज : सिराबयूज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1970) में पृ० 11 पर उद्धृत.
16. हीफी, पृ० 187.
17. नूर मलमान . 'इटरवेंशन ऐंड एकस्ट्रीकेशन . दि आफिपर कोर इन दि टर्किश आइमि', बिएनन, पृ० 134-135 पर.
18. रस्तोव, पृ० 189.
19. मुहम्मद अयूब खान : फ्रैंड्स, नाट मास्टर्स (लंदन : आरमफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1967), पृ० 77.

- 20 एडवर्ड फीट : 'मिलिटरी कूज ऐंड पालिटिकल डेवलपमेंट', वर्ल्ड पालिटिक्स, XX, (1968), 188.
21. इन ममितियों में बहुत थोड़े से राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तिगो को लिया गया देखिए नीचे
22. जाईरिंग, पृ० 12-13
23. श्राऊच, पृ० 213.
24. यह तर्क, क्लाड वैल्च के मत से भिन्न है वैल्च का कहना है कि सेना द्वारा स्वयं को शासन के संचालन कार्य से हटा लेना या तो इस बात का परिणाम है कि सैनिक प्रशासन परिपद में एक ऐसे सैनिक गुट का बोलबाला हो जाता है जो 'नागरिक की सर्वोच्च मत्ता का आदर', करता है, या फिर इसका दूसरा कारण हो सकता है सैनिक शासन का 'नागरीकरण', अर्थात् सत्तारूढ सैनिक विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा सेना से त्यागपत्र दे देना 1960 की श्राति के तुरत बाद के तुर्की, और अन्य स्थानों पर कुछ एक सैनिक विशिष्ट व्यक्तियों के सभावित अपवादो को छोड दें तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि 'नागरिक की सर्वोच्च मत्ता का आदर' व्यापक रूप से है यदि सेना स्वयं को शासन कार्य से अलग करती है तो सम्भव है कि वह इस बात को समझती है कि वह वास्तव में स्थिति को नियंत्रण में नहीं रख सकती लेकिन वैल्च ने जो दूसरा विकल्प बताया है उसमें वही उतारकर सामान्य कपडे पहन लेने को, शासन का परिवर्तन मान लेने की गलती की गई है इन 'नागरीकृत' शासनो के अदर सैनिक शासन की यह विशेषता विद्यमान रहती है कि मत्ता में बने रहने के लिए वे सेना पर बराबर निर्भर करते हैं। 'नागरीकरण' का सबंध, राजनीतिक केंद्र और परिधि पर हावी होने के उद्देश्य से बनाई जाने वाली व्यवस्था से तो है ही इसलिए यह शासन कार्य में हटने का नहीं बल्कि अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न है।
- 25 अस्वाई श्रातियों, जिनमें सेना एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है (पचायत श्राति या रैफोरी कू), और अत्यंत स्थाई परिणामो वाली श्रातियों (सेना द्वारा मत्ता सभाज लेना) के बीच विभेद करना अब एक परंपरा सी बन गई है। लेकिन वास्तव में इन दोनों के बीच विभेद करना कठिन हो सकता है। सैनिक विशिष्ट व्यक्ति, राजनीतिक प्रणाली को बिल्कुल बदल देने के इरादे में हस्तक्षेप कर सकते हैं लेकिन फिर पीछे हट सकते हैं क्योंकि यह परिवर्तन लाने में वे स्वयं को, असमर्थ पाते हैं। इस प्रकार की श्राति को प्रेक्षकगण पचायत श्राति समझ सकते हैं लेकिन इनका वास्तविक लक्ष्य मध्यस्थता करना नहीं था. भाराश यह है कि श्रातियों की भिन्नता पहचानने के लिए हस्तक्षेप करने वाले सैनिक विशिष्ट व्यक्तियों के इरादे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें समझना आम तौर पर कठिन है
- 26 मे-जिन किम : दि पालिटिकल आफ मिलिटरी रिवालयुशन इन कोरिया, (चैपल टिन : यूनिवर्सिटी आफ कैरोलीना प्रेस, 1971), पृ० 155
27. वही, पृ० 156.
- 28 देखिए, उल्फ सुदामेन : 'दि फंशनिंग आफ यूनिटी इन दि इंडोनेशियन आर्मी,' एशिया क्वार्टर्ली (ब्रसेल्स, 1971-72); और ऐन श्रेगरी 'फंशनिंग इन दि इंडोनेशिया आर्मी,' जर्नल आफ कपेरेटिव ऐडमिनिस्ट्रेशन, II, 3 (नवंबर 1970), 341-354 इंडोनेशियाई सेना की कमांड में परिवर्तन सबंधी मामलों के लिए देखिए, इंडोनेशिया (कोर्नल भाइलें इंडोनेशिया प्रोजेक्ट) (अप्रैल, 1967) 205-216. IV (अक्टूबर 1967), 227-229; VII (अप्रैल 1969), 195-201; X (अक्टूबर 1970), 195-208.

29. ग्रेगरी, पृ० 349-350
30. ऐमे एक प्रयत्न के लिए देखिए, ऐलन ए० सैमसन 'आर्मी ऐंड इस्लाम इन इंडोनेशिया,' पैमिफिक अप्पेयर्स, XLIV, 4 (1971-1972), 545-565
31. मुस्लिम लीग के बारे में देखिए, वान बोरोज, पृ० 255-259 डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी के संघ में देखिए, सी० आई० यूजीन किम : इंस्टीट्यूशन बिनिडिंग ऐंड ऐड्रैडेशन 'दि केम आफ दि डी० आर० पी० इन माउण्ट कोरिया,' वाशिंगटन डी० सी० में अमरीकन पॉलिटिकल सायम एमोमिगेशन की 1972 की वार्षिक बैठक में पढ़ा गया निबंध, मिश्र की पार्टियों के लिए देखिए नियोनाईड बिडर 'पॉलिटिकल रिफूटमेंट ऐंड पार्टीसिपेशन इन इजिप्ट,' जोजफ ला पैलांबरा और माथरन बीनर (संपादित) पॉलिटिकल पार्टीज ऐंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट (प्रिन्टन प्रिन्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1966), पृ० 217-240 पर.
32. इलिया एफ० हैरिक 'मोबिलाइजेशन पॉलिसी ऐंड पॉलिटिकल चेंज इन सरल इजिप्ट,' रिचर्ड एनून और इलिया हैरिक (संपादित) सरल पॉलिटिकल ऐंड सोशल चेंज इन दि मिडिल ईस्ट (एन्यूमिगटन डिप्लोमा यूनिवर्सिटी प्रेस, 1972), पृ० 293 पर
33. इन-यूथ बाग 'नोडरशिप ऐंड आर्गनाइजेशनल डेवलपमेंट इन दि इकोनामिक मिनिस्ट्रीज आफ दि कोरियन गवर्नमेंट,' एशियन सर्वे, XI, 10 (1971), 992-1004
34. वान बोरोज, पृ० 203-204
35. राबर्ट पिन्नी घाना अंडर मिनिटरॉ मल, 1966-1969, (लंदन मैथ्यून ऐंड को० लिमिटेड, 1972) पृ० 77. जून 1967 में 14 नागरिक आयुक्त नियुक्त किए गए थे इन बांगो ने, नेशनल लिबरेशन काऊंसिल के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में काम किया टम ममिति पर घाना सरकार का सामान्य कामकाज चलाने का उत्तरदायित्व था
36. वही
37. मिश्र के अधिकारीत्व के बारे में देखिए, मोरो बर्जर यूरोपेमी ऐंड सोमायटी इन माइने इजिप्ट, (प्रिन्टन प्रिन्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1957)
38. शाहिद जावेद बर्की 'टुवेटी ईयर्स आफ मिडिल एरबिक आफ पाकिस्तान ए रिवाल्यूएशन,' एशियन सर्वे, IX, 4 (1969), 247.
39. वही, पृ० 248
40. वही
41. जीन क्लाड बिन्नेम 'कांगो-किनशामा जनरल मोबिलिटी ऐंड टु पॉलिटिकल जेनरेशन,' वैल्व, पृ० 144-145 पर
42. वही
43. जे० सी० बिन्नेम रैट्रोमोनिवालिसम ऐंड पॉलिटिकल चेंज इन दि बांगो (स्टैनफोर्ड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1972), पृ० 135-136
44. देस्टिए, आर० ह्लेथर डेकमेजियन इजिप्ट अंडर नागिर (अलबानी न्यूयार्क : स्टेट यूनिवर्सिटी आफ न्यूयार्क प्रेस, 1971).
45. सैन्ड्रिन विस, पृ० 9-10
46. बर्की, पृ० 250.

47. श्राऊच, पृ० 217.
48. मैनिंग नैश : दि गोल्डन रोड टु मार्टिनी (न्यूयार्क जान वाईली एंड सम, 1965) पृ० 87-89
49. आर० विलियम दिडिन 'दि 1971 इंडोनेशियन इलैक्शन ए ध्यू फ्राम दि विनेज,' एशिया, न० 27 (1972), 14
50. लियोनार्ड बिडर ईरान . पार्लिटिकल टेक्लपमेंट इन ए चेंजिंग सोसायटी (वर्कने एंड लान एजिल्स यूनिवर्सिटी आफ कैलीफोर्निया प्रेस, 1964) पृ० 218-221, 229-232, 238-240
51. क्लोमेंट एच० मूर० पार्लिटिकम इन नार्य अफ्रीका (बोस्टन लिटिल ब्राउन एंड कंपनी |1970); और वाशिंगटन डी० सी० में अमरीकन पार्लिटिकल सायस एसोसिएशन की 1972 की वार्षिक बैठक में पढ़ा गया उनका ही निबन्ध, 'आथारिटेरियन पार्लिटिकम इन अनइन्फार्पी-रेटेड सोसायटी एक केम आफ नासिस इजिप्ट.
52. श्राम, पृ० 204, और आइटी सी० स्माक डबो पार्लिटिवस, (कैम्ब्रिज, मैसाच्यूसेट्स : हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1971), पृ० X
53. पिकनी, पृ० 27

6

निष्कर्ष

अल्प विकास एक भयकर स्थिति है - गदगी, बीमारी, अनावश्यक मृत्यु और यह सारी निराशाजनक स्थिति। आज अल्प विकास के कारण व्यक्तिगत और सामाजिक असहायता की भावना व्याप्त है, विशेषकर बीमारी और मृत्यु के सदभ्रं में। जब कोई व्यक्ति परिवर्तनों को समझने के प्रयास करता है तो उसे केवल अव्यवस्था और अनिश्चितता तथा अज्ञान का हीनभाव महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि वह उन व्यक्तियों के सामने बिल्कुल निरीह प्राणी है जिनके निर्णयों से घटनाक्रम संचालित होते हैं। वह भूख और दैवी प्रकोप के समक्ष स्वयं को अत्यंत दुर्बल और अकिंचन पाता है। चिरकालिक गरीबी एक अत्यंत क्रूर नकं है...।¹

—डेनिस गूले

राजनीति के अध्ययन में कई शताब्दियों से एक ही समस्या बनी रही है। वह समस्या है राजनीतिक दृढीकरण और शासन के लिए पर्याप्त सत्ता जुटाने की। इसके बावजूद यह समस्या तुलनात्मक राजनीति के समकालीन अध्येताओं के लिए आश्चर्यजनक कठिनाइयों में भरी हुई है। किसी हद तक इसे, जैसा डब्ल्यू० हावर्ड रिग्स ने कहा है, आधुनिक विद्वान की इस प्रवृत्ति का परिणाम माना जा सकता है कि 'जैसे जैसे आदर्श अधिक अमूर्त और सूक्ष्म बनते जाते हैं वैसे वैसे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के श्रमसाध्य और विवादास्पद मामलों को विचार की परिधि से बाहर रखा जाए।'²

लेकिन इससे भी अधिक, 'श्रमसाध्य और विवादास्पद' मामलों के प्रति हाल की

इस अरुचि का कारण, अल्पविकसित राज्य के प्रति वर्तमान दृष्टिकोण में ही देखा जा सकता है। आज के राजनीतिशास्त्र के वैज्ञानिक मुख्यतः राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने में ही लगे हुए हैं और ये वैज्ञानिक, जैसा एक विद्वान ने कहा है, 'प्राक विकास' को 'विकास' समझने लगे हैं, यानी एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली का सृजन करने की समस्या जो इस प्रणाली को आधुनिक विश्व की जटिलताओं के अनुसार ढालने की समस्या के बिल्कुल विपरीत है।³

हालांकि इन दो समस्याओं के बीच भेद करने के कुछ प्रयत्न किए गए हैं, (उदाहरण के लिए आलमंड और पावेल का, राज्य निर्माण के विपरीत राष्ट्रनिर्माण का सिद्धांत)⁴। फिर भी चूँकि ये दोनों समस्याएं आम तौर पर अफ्रीका और एशिया के राज्यों पर एक साथ थोपी गई हैं, इसलिए इन लोगों ने इन समस्याओं को एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई मान लिया है, कि इन्हें अविभाज्य समझा जाने लगा।

प्राक विकास या अल्प विकास की राजनीति को विकास की राजनीति समझने के कारण विद्वानों ने यह मान लिया है कि अल्पविकसित राज्यों के सामने प्रमुख समस्या, किसी राज्य का शासन चलाने के लिए गठित कुछ निश्चित राजनीतिक संस्थाओं को वैधता प्रदान करने की है।⁵ जहाँ इन समाजों में राजनीतिक संस्थाएँ मूलतः बाह्य प्रभाव से आईं वहाँ मुख्य प्रयत्न यही रहा है कि उस प्रक्रिया को समझा जाए जिसके द्वारा ये विदेशी संस्थाएँ पुनर्गठित हुईं और इन्हें नई परिस्थितियों और वातावरण में वैधता मिली। जिन तरीकों से ऐसी मस्याओं को वैध बनाया जा सकता है, परंपरा, करिश्मा, विधिसम्मत ताकिकता, मंडातिक विचारधारा, उन्हीं पर विश्लेषणात्मक ध्यान दिया जा रहा है। इसी में निहित यह तर्क है कि वैधता का मतलब है प्रभावशीलता या, यदि एक पुराने मुहावरे को उलट दिया जाए तो इसका मतलब होगा, अधिकार से शक्ति बनती है अर्थात् जिसकी भैंस उसकी लाठी।⁶

कार्य का स्तर ऊँचा उठाने के काम में नेतृत्व के अत्यधिक महत्व को जब चर्चा की जाती है तो हम राष्ट्रीय विकास के काम में सत्ता के महत्व की ओर संकेत करते हैं। यदि नेताओं को जनता को प्रेरित करना है और समाज को कार्य के उच्च स्तर की ओर अग्रसर करना है तो उनकी कथनी और करनी में वैधता की झलक मिलनी चाहिए। यदि लोगों को शासक वर्ग के कार्यों से संतोष उपलब्ध कराना है तो उन्हें पहले यह पूरी तरह से मान लेना चाहिए कि राजनीतिक प्रणाली में निहित कार्य नए तरीकों से किए जाने हैं। संक्षेप में हम यही कहेंगे कि यदि शासक वर्ग को अपने पृथक अस्तित्व के संकट को

और अधिक प्रभावशाली सरकारी कार्यों और राजनीतिक क्षमताओं का स्तर, ऊंचा करके हल करना है तो उसे बंधता संबंधी मामलों को भी सुलझाना होगा।⁷

हाल के इतिहास ने इस प्रकार के विश्लेषण को अपरिपक्व मिट्ट किया है। कई राज्यों में, जैसा बहा की बार बार की अस्थिरता से पता चलता है, नेताओं का कोई एक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणालियों पर प्रारंभिक नियंत्रण को भी सफलतापूर्वक सुदृढ़ नहीं कर पाया है और शासन चलाने के अपने बंध अधिकार को तो वे स्थापित कर ही नहीं सके। जहाँ सरकार की नई संस्थाओं ने कुछ हद तक बंधता और जन-समर्थन प्राप्त किया है वहाँ भी वे बहुत सीमित रूप से प्रभावकारी हो सके हैं, चाहे इन नेताओं का अपना व्यक्तित्व या उनकी विभिन्न नीतियाँ कितनी ही आकर्षक क्यों न रही हों।⁸ राजनीतिक प्रक्रिया का विखंडन बराबर होता जा रहा है, जिनसे इन राज्यों में राजनीतिक दृढीकरण एक स्वप्नमात्र बना हुआ है।

यहाँ यह नहीं कहा जा रहा कि अल्पविकसित राज्यों का अध्ययन करते हुए हम उस पुराने युग में पहुँच जाएँ जिसमें इन राज्यों में सब ओर राष्ट्रीयविघटन का बोल-बाला था।⁹ वास्तव में स्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है। यदि इन राज्यों में अधिकार में सामाजिक एकता नहीं लाई जा सकी है और 'पृथक अस्तित्व का संकट' उम मीमा तक नहीं सुलझाया जा सका है, जितना विद्वान लोग आवश्यक समझते हैं, तो इस बात को स्वीकार करना होगा कि अब असली समस्या इन राष्ट्र-राज्यों के पृथक अस्तित्व की नहीं है, (वैसे कुछ उल्लेखनीय अपवाद भी हैं)। लेकिन यह बात भी माननी होगी कि इन राज्यों में राष्ट्रीय विशिष्ट व्यक्तियों के बीच केंद्रीय संघर्ष, इस मवाल को लेकर उठे हैं कि राज्य के शासन पर किमका नियंत्रण होगा और उसके लक्ष्य कौन निर्धारित करेगा। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय विशिष्ट व्यक्तियों का कोई एक दम इतनी शक्ति नहीं जुटा पाया है कि वह राज्य की शासन प्रणाली पर अपना प्रभावशाली नियंत्रण रख सके।

इन सब बातों में एक बार फिर बंधता का प्रश्न उठ खड़ा होता है। राजनीतिक संस्थाओं की किमी प्रणाली के लिए बंधता के स्रोत चाहे ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और चरित्रमे वाले रहे हों, लेकिन इन संस्थाओं को अंत में इमी बात में परखना जाएगा कि उनमें समाज की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की कितनी क्षमता है। अल्पविकसित राज्यों में बंधता के संकट के मूल में राजनीतिक दृढीकरण का संकट है। प्रभावशाली दृंग में शासन चलाने की शक्ति प्राप्त करना एक अप्राप्य बात बनी हुई है।

समाजशास्त्र के वैज्ञानिकों के लिए प्रारंभ में जो बात एक समस्या थी अब वरदान समझी जा रही है। 1960 के दशक के मध्य में जब इन राजनीतिक प्रणालियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हुई तो इन प्रणालियों के पहले वाले आदर्श खत्म हो गए, और उनका स्थान नए आदर्शों ने लिया, जिनमें यह माना गया कि अत्यंत एकसंतीभ्य और मैदातिक विचारधारा वाले शासन में भी सत्ता एक अग्राह्य लक्ष्य बनी रहती है। पुरानी प्रणालियां जनसमर्थन बनाम ममझीता शासन, आमूल परिवर्तन बनाम हृद्विवादी शासन आदि के आदर्शों पर आधारित थीं। नए आदर्शों का एक उदाहरण है राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धान्त। इस सिद्धान्त पर आधारित आदर्श कई विद्वानों के लिए एक निराशाजनक वास्तविकता सिद्ध हुआ, क्योंकि उन्हें आशा थी कि अल्पविकसित देश लोकतंत्र और आधुनिकीकरण की ओर तेजी से प्रगति करेंगे। अंततः इस नई व्यवस्था के कारण नया लेकिन सतर्कतापूर्ण आशावाद उत्पन्न हुआ। राजनीतिशास्त्र के कुछ वैज्ञानिक नई प्रणालियों की क्षमता के बारे में न तो उत्साही थे और न ही निराश। फिर भी उन्होंने तर्क दिया कि इन राजनीतिक प्रणालियों से कुछ स्थिरता और राजनीतिक विकास किया जा सकेगा। राजनीति कोठारी, मायरन वीनर और जेस सी० स्काट ने ऐसी प्रणालियों के खुले स्वरूप और स्थानीय दवावों को ग्रहण करने की उनकी क्षमता पर बल दिया है।¹⁰ वीनर ने भारत की कांग्रेस पार्टी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि स्थानीय दवावों को ग्रहण करने की इसी क्षमता के कारण, कांग्रेस के प्रभुत्व वाली राजनीतिक प्रणाली 'आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में उपजे तनावों को कम करने' की विशेष क्षमता रखती है।¹¹ हेनरी विएनन का कहना है कि इन नई मशीनी प्रणालियों की विशेषता है, विकेंद्रीकरण, और ये प्रणालियां प्रभावशाली स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं का सृजन करा सकी हैं।¹² जोलबर्ग का मत है :

इस तरह का शासन मरल और कारगर नहीं है; इसमें गौरव की भावना नहीं है और यह निश्चिन्त नहीं है कि मानव की परिस्थितियों में तुरंत ही कोई आमूल परिवर्तन होगा। लेकिन यह पश्चिम अफ्रीका में मरुतारुंरक चली है। यह वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन इसमें व्यर्थ की क्रूरता और अत्याचार नहीं होने दिया जाता। इसके अलावा यह प्रणाली अनुकरण और अत्मसंदेह के भारी बोझ से मुक्ति दिलाने में सहायक हो सकती है। इसी बोझ में अफ्रीकी जनता लंबे अरसे में दबी चली आ रही है। अब यह जनता इस प्रणाली के कारण, स्वशासन की अपनी क्षमता में फिर से विश्वास प्राप्त कर पाएगी।¹³

अल्पविकसित राज्यों की राजनीति के सक्षिप्त अध्ययन में पता चलता है कि आदर्श शासन व्यवस्था की स्वच्छता और मुगटन नया इस व्यवस्था के प्रति मनकंता-

पूर्ण आशावाद के बारे में कुछ बढ़ा-चढ़ाकर ही कहा गया है। राजनीतिक केन्द्र में किसी तरह का सुगठन और एकता स्थापित करना अत्यंत कठिन सिद्ध हुआ है और वहाँ सत्ता का दृढीकरण करने की तो बात ही और है। राजनीतिक केन्द्र में अलग अलग खंड अथवा विभाजन बने रहते हैं। विभिन्न राज्यों के नेताओं को, पृथक गुटों को मिलाकर संयुक्त सरकारें बनाने और उनका संचालन करने की आवश्यकता रही है। केन्द्रीकरण के सीमित साधन होने के कारण इस प्रकार की सरकारों में परस्पर आदान-प्रदान के संबंधों के टूटने की हर समय ही आशंका बनी रही है। इसके अलावा केन्द्र की जटिलता, और नेताओं के केन्द्रीकरण के सीमित साधनों पर बोझ उसी अनुपात में बढ़ता गया है जिस गति से सरकारी कामकाज के क्षेत्र का विस्तार हुआ है। इस तरह की वृद्धि से केन्द्र में सत्ता की भूमिकाओं की संख्या और पुस्तैनी मत्ता बनाने की क्षमता दोनों का विस्तार होता है। इस प्रणाली को किसी एक व्यवस्था के समान इतना नहीं माना जाएगा जितना बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाओं के समान समझा जाएगा जो अक्सर एक दूसरे के साथ होड़ लगाती रहती हैं। इसका व्यावहारिक परिणाम यह हुआ है कि सत्ता और अधिक खंडित हुई है और राजनीतिक दृढीकरण अधिक अप्राप्य हो गया है।

अतः यह प्रश्न अवश्य पूछा जाना चाहिए कि इस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली वास्तव में कितनी 'अफ़ूर' है। यह सच है कि दबाव डालकर काम कराने की इसकी क्षमता न्यूनतम है। अपने नागरिकों की आकांक्षाएँ पूरी करने की इसकी क्षमता भी उतनी ही कम है। राजनीतिक प्रणाली पर अपने नियंत्रण को सुदृढ़ करने की विशिष्ट व्यक्तियों के किसी एक वर्ग की असमर्थता गतिहीनता उत्पन्न कर सकती है। सत्ता के अत्यंत खंडित होने के कारण विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के वर्गों के सम्मिलन से बनी सरकारों के भी उतने ही गतिहीन रहने की आशंका है।¹⁴ इतना ही नहीं, वल्कि जहाँ केन्द्र में काफी सुगठन और एकता होती है वहाँ भी केन्द्र और परिधि के बीच सपकों के उतार चढ़ावों के कारण, परिधि की समस्याओं से निपटने की केन्द्र की क्षमता भी सीमित होती है। अल्पविकसित राज्यों की अर्थव्यवस्था के दोहरे स्वरूप (विस्तृत हो रहा आधुनिक क्षेत्र और गतिहीन तथा बहुधा विगड़ती स्थिति वाला परंपरागत क्षेत्र) के विस्तार से यह समस्या और भी चिंता का विषय बन जाती है, और संपूर्ण आर्थिक विस्तार निरर्थक हो जाता है और राजनीतिक प्रणाली के सामने गंभीर आर्थिक तथा राजनीतिक चुनौतियों की संभावना उठ खड़ी होती है।¹⁵ स्थानीय सरकारी संस्थाएँ भी इसके समुचित विकल्प के रूप में विकसित नहीं हो पाई हैं। केन्द्रीय प्रशासन के एजेंटों के माध्यम से परिधि क्षेत्र पर अधिकाधिक नियंत्रण रखने के केन्द्रीकरण समर्थक विशिष्ट व्यक्तियों के प्रयत्न आम तौर पर सफल नहीं हुए हैं और इसकी बजाय स्थानीय संस्थाएँ दुबल हो गई हैं।¹⁶ इसके परिणामस्वरूप अल्पविकसित

राज्यों की प्रमुख व्याधि खंडित, बाधित राजनीतिक प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति अनुपलब्ध रहती है। इसके अभाव में न केवल कोई सरकार अपनी जनता की मानवीय परिस्थितियों को बेहतर बनाने का काम नहीं कर सकती, बल्कि वह अपने आपको भी नहीं बचा सकती।

संदर्भ

1. डेनिस गूने - दि न्यूअल चाइम : ए न्यू कासेप्ट इन दि थ्योरी आफ डेवलपमेंट, (न्यूयार्क : एथेनियम, 1973), पृ० 23
2. डब्ल्यू हावर्ड रिगिस : दि क्लसिंग इंपरेटिव (न्यूयार्क : कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1969), पृ० 4.
3. यूगवान एनेग्जडर किम 'दि पालिटिक्स आफ प्रिडेवलपमेंट,' कपेरेटिव पालिटिक्स V, 2 (1973), 213
4. मैत्रील आल्मड और जी० बी० पावेल कपेरेटिव पालिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच (बोस्टन - लिटिल, ब्राउन एंड कंपनी, 1966), पृ० 35-36.
5. मैमुअल हटिंगटन पालिटिकल आर्डर इन चेंजिंग स्टेट्स (न्यू हैवन येस यूनिवर्सिटी प्रेस, 1968), इस मत का सबसे अच्छा उदाहरण है.
6. विशेष रूप से देखिए, डक्वार्ट ए० रस्तांव ए वर्ल्ड आफ नेशंस प्रान्त्वम्स आफ पालिटिकल माडर्नाइजेशन (बाशिंगटन, डी० सी० दि ब्रुकिंग्स इन्स्टीच्यूशन, 1967), पृ० 157 जहां उन्होंने निम्नलिखित समीकरण मुद्राएँ हैं .

राजनीतिक स्थिरता = सस्याओ की वैधता
 + शासको की व्यक्तिगत वैधता
 राजनीतिक वैधता = परंपरागत वैधता
 + तार्किक विधि सम्मत वैधता
 + चमत्कारी वैधता

- 7 लूसियन, डब्ल्यू पाई - 'आइडेण्टिटी एंड पालिटिकल कल्चर,' लियोनार्ड बिंडर तथा अन्य : ब्राह्मि-सिम एंड सीबर्वेसिज इन पालिटिकल डेवलपमेंट (प्रिस्टन : प्रिस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1971), पृ० 134.
8. राजनीतिक दृढीकरण की नीतियों के लिए देखिए, रिगिस.
9. उदाहरण के लिए देखिए, सेलिंग हैरिसन : इंडिया . दि डेंजरस डिफेन्स (प्रिस्टन . प्रिस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1957).
- 10 रजनी कोठारी : पालिटिक्स इन इंडिया (बोस्टन - लिटिल, ब्राउन एंड कंपनी, 1970); मायरन वीनर, पार्टी विल्डिंग इन ए न्यू नेशन (शिकागो : यूनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस, 1967); और जैम्स सी० स्वाट : कपेरेटिव पालिटिकल करप्शन (एगलवुड क्लिफ्स एन० जे० प्रेंटिस हाल, 1972)
11. वीनर, पृ० 16.

12. हेनरी बिएनन : 'व्हाट इज पालिटिकल डेवलपमेंट मोन इन अफ्रीका'? वर्ल्ड पालिटिक्स, XX 1, (1967), 140.
13. एरिस्टिड जोलबर्ग . क्रियेटिंग पालिटिकल आर्टर : दि पार्टी स्टेट्स आफ बेस्ट अफ्रीका (शिकागो : रेड, मैकनेली ऐंड कंपनी, 1966), पृ० 160
- 14 एक दूसरे के साथ समझौते की भावना में कार्य करने की राजनीति से उत्पन्न समस्याओं के संबंध में देखिए, आर० ग्रैनफोर्ड प्राट . 'दि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इकोनामिक प्लानिंग इन ए न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट दि त्रान्जिशन एक्सपीरियेंस, 1963-1966', दि जर्नल आफ कामनवेल्थ पालिटिकल, स्टडीज, V, 1 (1967); 38-59; और देखिए, जोनाथन एम० बार्कर : 'दि पैराडाक्स ,आफ डेवलपमेंट : रिफ्लैक्शंस आन ए स्टडी आफ लोकल-सेंट्रल पालिटिकल रिलेशंस इन सेनेगल,' माइकिल लाफचार्ड (संपादन) : दि स्टेट आफ नेशंस : कंस्ट्रेंट्स आन डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट अफ्रीका (बर्कने ऐंड लास एजिट्स . यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया प्रेस, 1971), पृ० 47-63.
- 15 आइवरी कोस्ट में इस मामले पर विचारों के लिए देखिए, रिचर्ड ई० स्ट्राईकर . 'ए लोकल पर्सपेक्टिव आन डेवलपमेंट स्ट्रैटिजी इन दि आइवरी कोस्ट,' लाफचार्ड, पृ० 119-139.
16. यह बात आइवरी कोस्ट में देखी जा सकती है; देखिए वही, पृ० 138-139.

अनुक्रमणी

- अजीज अहमद, 42
अपरवोल्टा, 31, 98
अफ्रीका, 6, 10, 11, 14, 17, 22,
28, 30, 41
अब्दुल हकीम, 117
अल्जीरिया, 37, 44, 97
अल्बर्ट मारगाई, 83, 88
अमरीकी विद्वानों, 9
अय्यब खान, 97, 111, 120
अहरदेन, 38
अहोमदेश, 97
- आइवरीकोस्ट, 31, 33, 34, 52, 54,
60, 61, 62
आचार्य कृपलानी, 85
आधुनिकतावाद, 2, 14
आरेड लिजफाट, 92, 93
आस्टिन डेनिम, 41
आल्मंड गैब्रील, 12
आशावाद, 10, 11
- इंडोनेशिया, 97, 98, 111, 115, 117
- इस्कंदर मिर्जा, 97
इस्लाम, 37
इस्तिकलाल, 88
- ईरान लियोनाड विडर, 13
ईसेस्टाट एस० एन०, 12, 100
- उत्तर एटलांटिक पूजावाद, 26
उत्तर भारत, 29
उत्तर प्रदेश, 37
- एंजिला बर्जर, 88, 102
एडगर शोर, 52, 71
एडवर्ड शिल्स, 6, 13, 69
एन्क्रूमा, 46, 52, 53, 67, 82, 83,
97
एण्टोन आर्नल्ड, 90, 103
एन्लो निर्धिया एच०, 104
एन० पी० सी०, 59
एशिया, 6, 10, 14, 17, 22, 30, 121
- एंगलवुडक्लिस्स एन० जे०, 12

ऐष्टर ई० डेविड, 12, 46, 70
 ऐमर्सन हफ्टे, 17
 ऐरिक बुल्फ, 25, 43
 ऐरिस्टिड जोलबर्ग, 69, 70, 100

 ओलसन मैनकर, 105
 ओगिगा ओडिगा, 85, 86
 ओबोटे मिल्टन, 97

 कम्युनिस्ट पार्टी, 35
 कवामे एन्क्रुमा, 82
 कबीले, 6, 24, 30, 34, 39
 कांगो, 23, 35, 103, 111
 कांठिषम कनीमेट, 74
 काटस्की जान, 100
 काटराईट जान० आर०, 101
 काफोडेयंग, 21
 कालं लैडे, 62
 कालं ड्यून्यु० डायश, 40, 100
 कालंडयूश, 15
 काल्टेन हेज, 40
 किल्सन मार्टिन, 40
 कीनिया, 85, 102
 कोनल जेम्स ओ०, 17, 49, 100
 कोलमैन एस० जेम्स, 12, 17, 40,
 41, 112
 कोहन डेनिस एल०, 73, 101
 कोहन हैन्स, 40

 खलीफा, 28
 खान मुहम्मद अय्यूब, 106

 गतंजेल चैरी, 102
 गस्फील्ड जोसफ आर, 12
 गाधीजी, 37
 गिनी, 37
 गील्स, 103
 गील्स किलफर्ड, 41
 गुजरात, 82
 गैलनर, 102
 गोपाल कृष्ण, 41

पाना, 25, 31, 43, 46, 63, 65,
 67, 82, 88, 112, 114

 जनरल मोबतू, 111
 जनरल इरोगी, 111
 जान मूनिषा, 7
 जाबिया, 30
 जान शम, 106
 जानवाटरबरी, 70
 जाजं शेपरन, 42
 जियानिस्ट, 28
 जूनियम न्येरेरे, 36
 जैरल्ड ए० हीगर, 13, 71
 जैरे, 120, 127
 जोंग केन्नेथ, 42
 जोंगेफ मोबतू, 120, 127
 जोलबर्ग ऐरिस्टिड, 43, 106

 ट्यूनिया, 23
 टागानिका, 22, 23, 24, 36, 37, 68
 टाम एंबोया, 82
 टिबकटू, 37
 टी० एच० सिलकोक, 82, 101

 डाऊज राबर्ट, 106
 डोनाल्ड रायचाईल्ड, 103

 तंजानिया, 30, 70, 81
 तवाया एडमाफियो, 82
 तापुग घटना, 27
 तानू मंगठन, 36
 तुर्की, 98
 तूरे, 52

 धाईलैंड, 16, 51, 71, 93
 थामस जे बेल्लोज, 101

 दक्षिण एशिया, 29
 दक्षिण कोरिया, 99, 118, 121
 दारेसलाम, 69
 दाहीमी, 97

न्यासालैंडवासी, 90
 नाइजर, 31
 नाइजीरिया, 31, 60, 81, 109, 127
 नानद्विन, 63
 नार्थ राबर्ट सी०, 98, 106
 निस्वेट राबर्ट, 12, 41
 नेपाल, 52
 नेहरू, 44
 नैश मैनिंग, 63, 73, 123

 पश्चिमी अफ्रीका, 24, 34, 53, 69
 पाई लूसियन, 12, 40
 पाल बोमानी, 36
 पालब्रास, 44, 102
 पावेल जान डंकन, 43
 पावेल जी० बी०, 12
 प्रिचर्ड ई० ई० ईवांस, 13
 पूर्वी अफ्रीका, 29
 पेट्रिस लुमंबा, 35

 फर्नैंडो जेम्स डब्ल्यू०, 42
 फ्रांसीसी क्रांति, 14
 फाल्स लायड, 71
 फिलीपीस, 27, 62
 फोर्टस् मायर, 13
 फोर्स ऊव्रियेर, 24
 फोस्टर जाज एम०, 43

 वर्मा, 27, 28, 98, 115
 विंडर लियोनार्ड, 44, 72
 विऐनन हैनरी, 13, 70, 73, 100, 127
 विचौलियों, 28, 31
 बुहंडी के गनवा, 31
 बुगामा, 31
 बुर्गीन्वा, 52
 बंगत संडक्लेर, 28
 बेलैंडियर ज्यार्जिस, 41
 बैनफील्ड, 72

भंडारनायके एस० डब्ल्यू० आर० टी०, 84
 भारत 23, 25, 28, 33, 41, 62

 माइकेल बंटन, 42
 मारगार्ड अल्वर्ट, 83, 88
 मारगार्ड मिल्टन, 83
 मार्टिन किलसन, 44, 104
 मार्टिन स्टानीलैंड, 102
 मिचेल राबर्ट सी०, 42
 मेलसन राबर्ट, 100, 105
 मैग्वायर, 30, 36, 41
 मैसूर, 85
 मोपला विद्रोह, 27, 28, 29
 मोरक्को, 23, 51, 61, 88, 102, 124
 मोरी टानिया, 31
 मोहनदास करमचंद गांधी, 33

 यग क्राफोर्ड, 41
 युगाडा, 97

 रजनीकोठारी, 70, 102
 राईनहांड बंडिवम, 54, 71
 रिम्स फ्रैंड, 101
 रिगिस डब्ल्यू० हावर्ड, 44
 रिचर्ड ई० स्ट्राइकर, 73
 रिचर्ड स्कालर, 90, 104
 रियान सोल्विन, 72
 रुवाडा, 93
 रुडालफ लायड आई०, 12, 41, 102
 रुडालफ सूसन होबर, 12, 14, 41, 103
 रेनेलियमरचंद 43, 44, 69
 रोसेनपाल डोनाल्ड बी०, 44

 सरनर डेनियल, 17, 40, 106
 लिजफार्ट, 104
 लिडल आर० विलियम, 44
 लियोने सीयैरा, 44, 60
 लैमरचंद, 31, 43, 72, 93, 104, 129
 लौह कंकाल, 11

वाटरबरी, 73
 वारेन डब्ल्यू० एम, 41
 बालस्टीन इमैनुअल, 103
 बिलनर एन रुथ, 8
 ब्रिटेकर सी० एस०, 100
 बीनर मायरन, 72
 बुडवर्ड काल्विन, 102
 बुल्फ ऐरिक आर०, 27, 41
 बैस्ट लैक, 37
 वैल्च क्लाड, 105, 107, 108, 127,
 132

थीलंका, 38, 50, 70, 84
 थ्रेणीगत, 62

संडकलेर बेग्न, 42
 सकडल विद्रोह, 27
 साऊथाल ए० डब्ल्यू, 13
 साजा, 31
 सायासान, 27
 सिगापुर, 83
 सिडनी बर्वा, 72
 सियाल अनिल, 44
 सियेरालियोने, 38, 70
 सिसन रिचर्ड, 44

सी० एफ० टी० सी०, 24
 सी० जी० टी०, 24
 सुकूमा, 24, 30, 36
 सुहार्तो, 117
 सूडान, 25, 37
 सुघोर, 52, 99
 सेकेतूर, 37
 सैनगल के शेख, 31
 सैमुअल हंटिंगटन, 5, 12, 17, 37, 39,
 44, 53, 69, 74, 127, 128
 सोमालिया, 51, 98, 106, 127
 स्काट जेम्स सी०, 41, 101
 स्टैनलेवील, 35
 स्मिथ एम० जी०, 13

हंटिंगटन, 43, 74
 हसन, 31
 हाइमसाथ चार्ल्स, 42
 हार्डइन गोरन, 44
 हाजरवाल्टर, 42
 हाजकिन टामस, 41
 हालपन मैन्फ्रेड, 12
 हार्वे वोल्फ, 100
 हीगर जैरल्ड ए०, 44, 102, 104
 हुफुए बोइनी, 44, 52, 54, 61

